प्रेरणा

जीवन में अपने लिए किसी नई रणभूमि से कभी डरो मत। - **इलॉन मस्क**, उद्यमी

संपादकीय

यूएस से पाक का मेलजोल चीन को खटकने वाला है

पाकिस्तान ने अपना रेयर-अर्थ भंडार अमेरिका और ट्रम्प की निजी कंपनियों के लिए पेश कर दिया है। यह सब करते हुए शाहबाज और मुनीर, ट्रम्प को एक बार फिर शांति का मसीहा बताना नहीं भूले। बहरहाल दुनिया पाकिस्तान जैसे 'रोग-स्टेट' (दुष्ट-राष्ट्र) के हुक्मरानों के कहने से किसी को शांतिदूत नहीं मानती, ना ही घुटने टेक कर युद्ध रोकने की पाकिस्तान की अपील को उसकी जीत कहा जा सकता है। लेकिन अपने आका ट्रम्प को खुश करने के लिए शाहबाज-मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान के रेयर-अर्थ एलीमेंट्स ट्रम्प को प्रस्तुत किए और उसकी तस्वीर दुनिया से साझा की। लेकिन फरेब की नींव और रहम की याचना की बुनियाद पर निर्मित अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की इमारत जल्द ही कूटनीतिक नासमझी का भूकम्प झेलने जा रही है। कारण, चीन ने पाकिस्तान को 70 अरब डॉलर और सामरिक मदद यूं ही नहीं दी थी। दूसरी ओर शी जिनपिंग ने रेयर-अर्थ की सप्लाई अमेरिका को झुकाने के लिए ही बंद की थी। अगर पाकिस्तान चीन के एहसानों को भूलकर अपना रेयर-अर्थ बेचने और तेल-भंडार खोजने का काम अमेरिका को दे देता है तो जाहिर है कि अमेरिका वहां पर अपने अड्डे भी बनाएगा। इससे चीन की सभी योजनाएं कमजोर पड़ेंगी। इस आपाधापी में चीन और भारत पहले की तुलना में और नजदीक भी आ सकते हैं।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अत्यधिक मोल दें

दुनिया ने हमारी आर्थिक घेराबंदी कर दी है। ऐसे में हमारे कर्णधारों ने स्वदेशी अभियान प्रकट किया है और हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए। स्वदेशी वस्तुएं कह रही हैं कि 'आंखों के अश्क ले लो और नजरों के नूर दे दो!' यह सही वक्त है कि हम अपने देश में निर्मित वस्तुओं को अत्यधिक मोल दें। हमारी खर्च करने वाली राशि का बड़ा हिस्सा स्वदेशी वस्तुओं पर व्यय करें। इसका एक उदाहरण है। दुर्योधन ने जब पांडवों को सुई की नोक जितना भी धरती का टुकड़ा नहीं देने की बात कही, तो कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए पांडवों को द्वारका से धन लाकर दिया। यहीं से हम अपने स्वदेशी संस्कार को जाग्रत करें और अपना धन इंद्रप्रस्थ पर खर्च करें। इस प्रसंग में इंद्रप्रस्थ स्वदेश है। आज एक देश का राष्ट्रपति दुर्योधन की तरह भूमिका निभा रहा है। हम अपने भीतर का कृष्ण जाग्रत करें और स्वदेशी अभियान का हिस्सा बनें। क्योंकि अपने देश में एक और दिक्कत है, बाजार इतना बेईमान हो गया है कि वो स्वदेशी को भी धक्का दे देगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • आज हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं

हमें अपने संस्थानों को मजबूत बनाने पर ध्यान देना होगा

राष्ट्रनीति

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com

जीएसटी दरों में कटौती के बाद पिछले सप्ताह कई बड़े औद्योगिक संगठनों और व्यवसाय समूहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए मीडिया में पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए। हरेक विज्ञापन में प्रधानमंत्री की बड़ी-सी तस्वीर थी। इससे कुछ ही दिन पहले 19 सितंबर को भी व्यवसाय घरानों और व्यापार संगठनों ने ऐसे ही विज्ञापन देकर पीएम को 75वें जन्मदिन की बधाई दी थी। देखें तो यह सब ठीक ही है। भाजपा-शासित राज्यों- खासकर यूपी के पास बुनियादी ढांचे, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। वो तेजी से विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका केंद्र में बैठे ऐसे दूरद्रष्टा प्रशासक की है, जो हर राज्य को घरेलू और विदेशी निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

लेकिन इस सब के बीच इंदिरा गांधी जैसे पर्सनैलिटी कल्ट के निर्मित होने का जोखिम भी है। 1974-75 में इंदिरा गांधी के साथ ऐसा ही हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरूआ ने तो तब यह नारा भी दे दिया था कि 'इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया।' भले ही भाजपा में अभी तक किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं कह पाए।

एक सफल देश व्यक्ति-पूजा नहीं, अपने सशक्त संस्थानों से संचालित होता है। मोदी भी इस बात को समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पीएमओ और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया था कि सभी सार्वजनिक संदर्भों में उनके लिए 'माननीय प्रधानमंत्री' शब्द को हटा दिया जाए। तभी से केंद्र के सभी संवादों में मोदी के लिए महज 'प्रधानमंत्री' शब्द ही काम में लिया जाता है। लेकिन निजी व्यापारिक घरानों और औद्योगिक संगठनों पर यह लागू नहीं होता। उनके लिए तो मोदी अभी भी 'माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी' ही हैं। उनके सभी विज्ञापनों में ये शब्द शामिल थे।

यह बाल की खाल निकालना लग सकता है, लेकिन यह सब देश के लिए बहुत मायने रखता है। मोदी का तीसरा कार्यकाल एक महत्वपूर्ण चरण में है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में 2020-2022 तक कोविड की त्रासदियों से गुजरने के बाद 2022 और 2023 में यूक्रेन और गाजा के युद्ध परेशानी बने।

अब तीसरे कार्यकाल के पहले साल में ही मोदी तीन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पहला, अमेरिकी टैरिफ। दूसरा, पाकिस्तान से निपटना, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मिली हार के कारण तिलमिलाया हुआ है। तीसरा, नेपाल और बांग्लादेश की तरह जेन-जी हिंसा के जरिए लद्दाख और अन्य सीमावर्ती इलाकों में परेशानी पैदा करने के सुनियोजित प्रयास।

लद्दाख हिंसा में पाकिस्तान की सांठगांठ साफ नजर आई है। सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते और ऑपरेशन सिंदूर में चीन, तुर्किए और अजरबैजान से मिले खुले समर्थन के बाद पाकिस्तान सोच रहा है कि भू-राजनीतिक तौर पर अब वह मजबूत स्थिति में है। असीम मुनीर के तौर पर पाकिस्तान को 1947 से लेकर अब तक का सबसे बड़ा जिहादी विचारधारा का सेनाध्यक्ष मिला है। यकीनन, जिया उल हक से भी बड़ा। हाल ही मुनीर रेयर-अर्थ का वादा कर ट्रम्प को भी लुभाकर आए हैं।

इस खंडित विश्व में मोदी को चाहिए कि वे संस्थानों को मजबूत बनाएं और पार्टी के चापलूसों द्वारा खुद के महिमामंडन के प्रयासों को खारिज करें।

अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी तीन चुनौतियों से जूझ रहे हैं। 50 प्रतिशत का ट्रम्प-टैरिफ। पाकिस्तान से निपटना। और नेपाल व बांग्लादेश की तरह जेन-जी विद्रोहों के जरिए भारत के लिए परेशानी पैदा करने के सुनियोजित प्रयास।

उद्योगों के मामले में भारत आज दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक, सबसे बड़ा चावल और दूध उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा यात्री कार निर्माता और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है। उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और इंटरनेट बाजार है। रक्षा विनिर्माण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई क्षेत्र की एक उभरती शक्ति है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी भारत परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ रहा है। 2028 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा।

इसीलिए आश्चर्य नहीं कि अमेरिका और चीन उभरते भारत को दुनिया में अपने दबदबे के लिए दीर्घकालिक खतरा मानते हों। इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए भारत को अपने संस्थानों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। साथ ही अर्थव्यवस्था को अधिक बेहतर और देश के प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना होगा। इसी में देश और मोदी, दोनों का हित है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

नया विचार • युवाओं की भाषा बोलें पर उपदेश ना दें

जेन-जी का दिल कैसे जीतें? ये 6 तरीके आजमाकर देखें

युवामन

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

एक अन्यथा उनींदे-से पहाड़ी देश में हुए विद्रोह ने दुनिया को सबसे शक्तिशाली सामाजिक समूह के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया। यह समूह है- जेन-जी। नेपाल में सरकार का तख्ता पलट करने वाले हालिया प्रदर्शन इसलिए हुए थे, क्योंकि युवा पीढ़ी ने आंदोलन की बागडोर सम्भाल ली थी। और वह भी इसलिए कि सरकार ने उनसे उनका इंटरनेट छीन लिया था। एक जमान था, जब फावड़ा-कुदाल लेकर आते किसानों से राजनेता खौफ खाते थे। लेकिन अब उन्हें रिंग लाइट्स लेकर आए युवाओं से डरना पड़ेगा। पहला सबक ये है कि युवाओं से उनका इंटरनेट कभी न छीनें।

भारत में भी तभी से विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश में हैं कि हमारे अपने देश के जेन-जी आखिर क्या कर रहे हैं, और आगे क्या करेंगे। वे खुश हैं या उनमें ऐसी कोई सामूहिक निराशा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। 1997 और 2012 के बीच जन्मे युवाओं को जेन-जी माना जाता है। आज की बात करें तो ये 13 से 28 वर्ष के युवा हैं। फैसले लेने की हैसियत को लेकर अकसर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता, फिर भी ब्रांड्स, एंटरटेनर्स, मीडिया के लोग, शिक्षक, राजनेता- सभी उन्हें लुभाने की कोशिश में रहते हैं। राहुल गांधी का जेन-जी तक सीधे पहुंच बनाने का हाई प्रोफाइल प्रयास सबसे नया है। भारत की जनसांख्यिकी में जेन-जी ना केवल बड़ी संख्या में हैं, बल्कि डिजिटली-कनेक्टेड भी हैं। वे हमेशा इंस्टाग्राम, रेडिट, डिस्कोर्ड, एक्स पर आपस में बातचीत करते रहते हैं और बड़े बदलाव लाने में सक्षम हैं।

अलबत्ता, ब्रांड्स या राजनेताओं के लिए जेन-जी का दिल जीतना आसान नहीं। कइयों ने ऐसी कोशिशें कीं, लेकिन विफल रहे। कुछ ने तो जेन-जी का गुस्सा तक मोल ले लिया। और जेन-जी का गुस्सा बहुत भारी पड़ता है। वे आपके मीम्स बनाएंगे, आपको कैंसल करेंगे, आपके बिजनेस मॉडल को नष्ट कर देंगे, चुनाव हरा देंगे, फिल्म फ्लॉप करेंगे और जैसा कि नेपाल में हुआ- सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मान लीजिए कि जेन-जी कोड का कोई 'क्रैक' नहीं है। फिर भी कोई ऐसा करना चाहे तो उसके लिए ये छह गाइडलाइन्स हैं।

1. **उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करें** : जब आप जेन-जी को इमोजी के जरिए बातें करते देखते हैं, तो उन्हें जज करना मुश्किल है। या तब जब वे घंटों रील्स देखते हैं, या किसी कोरियाई शो या लाबुबु टॉय के लिए दीवाने हो जाते हैं। लेकिन वे स्मार्ट हैं। वे गूगल के साथ बड़े हुए हैं और अब तो उनके पास चैटजीपीटी भी है। वे समस्या को जल्द हल करने पर दिमाग चलाते हैं। वे ट्रिप अरेंज कर सकते हैं। सामान की डिलीवरी करवा सकते हैं। यह पता लगा सकते हैं कि कौन उन्हें झूठे और भ्रामक डेटा से बहकाने की कोशिश कर रहा है। इस सबके लिए वे इंटरनेट का उपयोग करते हैं।

2. **वास्तविक रहें** : जाने कितने ब्रांड्स ने इन युवाओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जी तोड़ मेहनत की है। लेकिन जेन-जी को लेकर कोई समझ नहीं होने से वे उनसे कनेक्ट होने के लिए हाथ-पैर मारते रह गए। राजनेताओं को भी जेन-जी के प्रति कोरे दिखावे और खोखले सिम्बॉलिज्म से सावधान रहना चाहिए। महज युवाओं जैसे कपड़े पहनने, स्लैंग बोलने और 'मुझे युवा लोग पसंद हैं' कहने भर से उनका दिल नहीं जीता जा सकता है। वास्तव में जो चीज काम आएगी, वह है वास्तविकता। सच्ची वास्तविकता, जिसमें आप अपनी ताकत के साथ अपनी सीमाओं और खामियों को भी बताने को तैयार हों।

3. **उनसे बातें करें, ज्ञान ना दें** : पुरानी पीढ़ी के लोगों को उपदेश देने की आदत होती है। लेकिन जैसे ही जेन-जी को लगता है कि यह एकतरफा भाषण है, वे ध्यान देना बंद कर देते हैं। यदि आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो ज्ञान ना बांटें।

जेन-जी आज दुनिया की सबसे ताकतवर सामाजिक और राजनीतिक शक्ति है। उनका दिल जीतना आसान तो नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ा-सा सम्मान, सच्ची केयर और वास्तविकता बहुत कारगर साबित हो सकती है।

4. **प्रोग्रेसिव बनें** : अधिकतर उम्रदराज भारतीय ऐसे रूढ़िवादी मूल्यों में जकड़े हैं, जो जेन-जी के लिए मायने नहीं रखते। लेकिन जेन-जी का अपना वैल्यू-सिस्टम है, जो अधिक समावेशी और भविष्योन्मुखी है। रूढ़िवादी होकर आप उनका दिल नहीं जीत सकते।

5. **जेन-जी की भाषा बोलें** : यह हिंदी, अंग्रेजी या कोई स्थानीय भाषा नहीं- यह डिजिटल भाषा है। यदि आप जेन-जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको यह भाषा आना जरूरी है। अगर आप यह नहीं बोल सकते तो फिर जेन-जी को भूल जाइए।

6. **ह्यूमर का उपयोग करें** : जेन-जी को मीम्स, व्यंग्य और हास्य पसंद है। यदि आप खुद पर हंस सकते हैं, तो वे आपको पसंद करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें डराने, नियंत्रित करने या खारिज करने की कोशिश करते हैं, तो वे आपको बेतहाशा रोस्ट करने से नहीं चूकेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

4 अक्टूबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने कवर स्टोरी में यूरोपीय देशों के खिलाफ रूस की आक्रामक हलचल के पीछे छिपे इरादों की पड़ताल की है। मैग्जीन ने भारत-अमेरिका में जारी गतिरोध पर भी खबर की है।

The Economist

दैनिक भास्कर
अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

72% इजराइली ट्रम्प की गाजा योजना से सहमत

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 29 अक्टूबर को गाजा में युद्ध की समाप्ति के लिए पेश योजना को इजराइली जनता का भारी समर्थन मिला है। इस पर हुए पहले सर्वेक्षण में 72% लोगों ने कहा कि वे ट्रम्प के प्रस्ताव से सहमत हैं। सिर्फ 8% लोगों ने विरोध किया है। योजना का तेलअवीव के शेयरमार्केट में अच्छा असर देखा गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रस्ताव को सही बताया है। वैसे, नेतन्याहू के पूव संचार मंत्री ने ओमेर दोस्तरी ने ट्रम्प के प्रस्ताव को नाकाम बताया है।

ब्रिटेन: रात नौ से पहले नहीं दिखेंगे जंक फूड विज्ञापन

ब्रिटेन में 1 अक्टूबर से सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली खाने-पीने की चीजों की ऑनलाइन एडवरटाइजिंग पर रोक लगा दी गई है। इन्हें रात नौ बजे से पहले टीवी पर भी नहीं दिखाया जा सकेगा। बड़े सुपरमार्केट्स एक खरीदो, एक मुफ्त जैसे प्रमोशन नहीं कर सकेंगे। ये नियम अधिक फैट, साल्ट और शुगर की ज्यादा मात्रा के फूड पर लागू होंगे। ब्रिटेन के सुपरमार्केट्स में 20% से अधिक ऐसे फूड और ड्रिंक्स की खरीद होती है। अधिक फैट, नमक, शुगर वाली खाने-पीने की चीजों के 60 प्रतिशत विज्ञापन ऑनलाइन होते हैं।

सऊदी अरब बड़ी वीडियो गेम कंपनी खरीद रहा है

सऊदी अरब के सॉवरेन वेल्थ फंड ने वीडियो गेम डेवलपर इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स को खरीदने का ऐलान किया है। ईए के बैटलफील्ड और मैडेन एनएफएल जैसे टाइटल बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन 2.21 लाख करोड़ रुपए के सौदे को बहुत महंगा माना जा रहा है। विश्लेषकों का कहना है, इससे सालाना दो अंकों में रिटर्न मिलना मुश्किल है। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान की खेलों में गहरी दिलचस्पी है। उनके फंड ने न्यूकैसल यूनाइटेड, पोकेमॉन गो खरीदे हैं। एक अन्य गेम डेवलपर टेक-टू में उनकी छोटी हिस्सेदारी है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

समरनीति — यूक्रेन के सहयोगियों पर निशाना बना रहा रूस, नाटो को कमजोर करने की भी कोशिश

यूरोप की एकजुटता तोड़ने में लगे पुतिन, अप्रत्यक्ष युद्ध भड़का रहे, उनके कदमों पर ट्रम्प की भी चुप्पी

रूस ने यूरोपीय देशों के खिलाफ जबर्दस्त अभियान छेड़ दिया है। पोलैंड पर मंडराते ड्रोन, एस्टोनिया की सीमा में मिग विमानों की घुसपैठ, बाल्टिक सागर में टेलीकॉम केबलों को नुकसान, साइबर हमलों से ठप विमानतल, चुनावों में बाधा जैसी घटनाओं को अलग करके देखें तो सामान्य लगती हैं। लेकिन मिलाकर देखें तो ये बेहद खतरनाक है।

अमेरिका, नाटो के खिलाफ पुतिन यूरोप को अस्त-व्यस्त करना चाहते हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्त्ज कहते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन शांति में भी नहीं हैं। पुतिन को अहसास है कि वे सीधे युद्ध में नाटो को नहीं हरा सकते हैं। उनके तीन खास मकसद हैं- **1.** नाटो की एकता में दरार डालना। **2.** यूक्रेन के सहयोगियों पर निशाना **3.** उदार लोकतांत्रिक देशों के लिए मुश्किल पैदा करना।

पुतिन चाहते हैं कि यूरोपीय देश नाटो के प्रति अमेरिका की वचनबद्धता पर सवाल उठाएं। ऐसी धारणा बने कि एक पर हमले को सभी देशों पर हमला मानने के अनुच्छेद 5 से भरोसा टूट जाए। वे अमेरिका को यूरोप से अलग करना चाहते हैं। पुतिन कहते हैं नाटो रूस का विभाजन चाहता है। लिहाजा उसे अंदर से तबाह करना चाहिए।

रूस की आक्रामक कार्रवाइयों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कमजोर प्रतिक्रिया से यूरोप में अविश्वास बढ़ा है। ट्रम्प ने पोलैंड में रूसी ड्रोन्स की घुसपैठ को गलती करार दिया। एस्टोनिया की सीमा में तीन मिग-31 विमानों के घुसने पर भी कुछ नहीं कहा। विश्लेषक महसूस करते हैं, ट्रम्प को जरूरत पड़ने पर यूरोप में सैनिक कार्रवाई के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना चाहिए। यदि हवाई सीमा का उल्लंघन और तोड़फोड़ जैसी कार्रवाइयों को सामान्य मान लिया जाएगा तो सैनिक कार्रवाई का भय कमजोर होगा।

पुतिन का एक अन्य मकसद यूक्रेन से जुड़ा है। उनका नया हमला नाकाम हो गया है। लिहाजा वे यूक्रेन की सेना को सहयोग देने वाले यूरोपीय देशों के लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं। वे यूक्रेन के बड़े सहयोगी पोलैंड, एस्टोनिया और डेनमार्क को ड्रोन हमलों, जीपीएस जैमिंग और तोड़फोड़ के जरिए निशाना बना रहे हैं। जर्मनी की डिफेंस और इंफ्रा कंपनियों पर साइबर हमले किए हैं। रूस से लगे मोलदोवा, रोमानिया के चुनावों में दखल दिया गया।

रूस को लेकर ट्रम्प का रुख अनिश्चित है। इस साल उन्होंने कहा कि वे नाटो के साथ हैं। पहले कह चुके हैं कि वे चाहेंगे कि रूस जैसा चाहता है, वैसा करे। जाहिर है, पुतिन इन शब्दों पर गौर कर रहे होंगे।

चीन पैदा कर रहा संदेह

चीन भी पूर्व एशिया से अमेरिका की विदाई चाहता है। इसलिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध जैसा अभियान चला रहे हैं। ताइवान पर कार्रवाई के जरिये चीन अमेरिका के एशियाई सहयोगियों के मन में संदेह पैदा करना चाहता है।

उदार देशों से नफरत

पुतिन उन उदार लोकतांत्रिक देशों से नफरत करते हैं, जिनकी समृद्धि और मजबूती उनकी विफलता और दमन पर रोशनी डालती है। ऐसे देश आर्थिक रूप से आगे हैं। रूसी जीडीपी इटली से कम है जबकि उसकी आबादी उससे दोगुनी है।

नर्वा पर कब्जे की आशंका

एफ-35 विमानों से मिग विमानों का पीछा, ड्रोन्स के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल खर्चीला है। इससे यूरोप की जवाबी क्षमता कम होगी। पुतिन एस्टोनिया के नर्वा पर कब्जा कर सकते हैं। यहां रूसी भाषी लोग अधिक संख्या में हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

बिजनेस

अमेरिका, चीन में रोबोटैक्सी की रफ्तार में कई बाधाएं

अमेरिका में सैनफ्रांसिस्को और चीन के शेनझेन में सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी तेजी से दौड़ रही हैं। अप्रैल-जून के बीच अमेरिकी कंपनी वायमो ने कैलिफोर्निया में रोबो टैक्सी की 22 लाख ट्रिप लगाई हैं। यह 2024 से पांच गुना अधिक है। चीनी कंपनी बाइडू ने चीन के 16 शहरों में इन तीन महीनों में 22 लाख ट्रिप लगाई हैं। ड्राइवर विहीन टैक्सी में कम दुर्घटनाएं होती हैं। फिर भी कई बाधाएं हैं। नियम, कानून सेल्फ ड्राइविंग टैक्सियों के आड़े आते हैं। अमेरिका में कंपनियों को नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडिमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी लेना पड़ती है। एजेंसी हर साल एक कंपनी को सिर्फ 2500 रोबो कार बनाने की अनुमति देती है। न्यूयॉर्क में ऑटोनॉमस वाहनों को टैक्सी सेवाओं में चलाने की इजाजत नहीं है। केवल कुछ यूरोपीय देशों में रोबो टैक्सी की टेस्टिंग हो रही है। जर्मनी में रोबो टैक्सी हमेशा मनुष्य की निगरानी में रहती हैं। वायमो और इंश्योरेंस कंपनी स्विस रे की स्टडी में पाया गया कि वायमो की टैक्सियों में मानवों की तुलना में संपत्ति को नुकसान के 88 प्रतिशत और घायलों को मुआवजे के 92 प्रतिशत कम दावे आए हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

विश्लेषण — रूसी तेल के मुद्दे पर अटका विवाद जल्द सुलझ सकता है

एक-दूसरे को रियायत दे सकते हैं भारत-अमेरिका

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार विवाद जल्द सुलझ सकता है। भारत अमेरिका से विमान, हथियार और तेल खरीदने की तैयारियां कर रहा है। दोनों देशों के अधिकारी मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच व्यक्तिगत विवाद सुलझे बगैर कुछ नहीं होगा।

पाक-भारत टकराव के वक्त विवाद बढ़ गया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने युद्धविराम कराया है। पाकिस्तान ने जल्द ही नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रम्प का समर्थन कर दिया। ट्रम्प चाहते थे कि मोदी भी ऐसा ही करें। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम ट्रम्प ने नहीं करवाया है।

एक माह बाद ट्रम्प ने मांग की कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। मोदी इसे मान सकते थे बशर्ते वह प्राइवेट बातचीत में किया गया होता। रूसी तेल पर अब कम डिस्काउंट मिलता है। लिहाजा तेल न खरीदने से भारत को बहुत आर्थिक नुकसान नहीं होता। भारत के तैयार न होने पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया।

ट्रम्प को राक्षस रूप में दिखाया

पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत में दूसरी तरह से छाए रहे। बिहार और बंगाल में दुर्गा पूजा समारोहों में ट्रम्प की मौजूदगी दिखाई पड़ रही थीं। दुर्गा जी की झांकियों में अमेरिकी राष्ट्रपति के पुतले को राक्षस का रूप दिया गया। देवी दुर्गा उनका संहार कर रही थी। ये झांकियां भारत में जनता के अमेरिका विरोधी मूड का खुलासा करती हैं।

अब दोनों मजबूत नेताओं के बीच गतिरोध है। ट्रम्प शोरशराबे में यकीन करते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री समर्थकों की नजर में बराबरी की स्थिति में दिखना चाहते हैं। इसलिए सार्वजनिक तौर पर पीछे हटना मुश्किल लगता है। थिंक टैंक कार्नेगी एनडोमेंट इंटरनेशनल पीस के एशले टेलिस को आशा है भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ट्रम्प को अपनी मांगों पर ढील देने के लिए मना सकते हैं।

तेल विवाद सुलझ जाए तो दोनों देश अमेरिका के अन्य देशों से बेहतर समझौता कर सकते हैं। जुलाई में हुई वार्ता की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार भारत ने खेती पर रियायतों का ऑफर दिया है। अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं पर टैरिफ में कमी हो सकती है। दोनों देशों के बीच हथियार सौदे से मदद मिल सकती है। सितंबर में बोइंग के अधिकारी पी-8 निगरानी विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर की उम्मीद में भारत आए थे। लेकिन वे खाली हाथ लौट गए।

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी के राजेश राजगोपाल का कहना है, अमेरिका और पश्चिमी देशों से मजबूत रिश्तों का समर्थन करने वाले लोग भी अभी चुप हैं। बहरहाल, भारत-अमेरिका के नजदीकी संबंधों से चीन के उदय को रोकने में मदद मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार अमेरिका है। दोनों देशों के बीच पिछले साल 212 अरब डॉलर का कारोबार हुआ था। दिल्ली में होने वाले क्वाड देशों के सम्मेलन में भारत सुरक्षा करार को अंतिम रूप दे सकता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन — नियंत्रण के नियम अस्पष्ट

स्टेबल कॉइंस चर्चा में जरूर लेकिन इनके फायदों से ज्यादा नुकसान

ज्यां टायरोल | अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता

अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी स्टेबल कॉइन्स फाइनेंस की मुख्य धारा में आ गए हैं। जुलाई में पास जीनियस एक्ट ने इन डिजिटल टोकन्स को कानूनी जामा पहना दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके परिवार के क्रिप्टो वेंचर ने स्टेबल कॉइन यूएसडी1 जारी किया है। सबसे अधिक प्रचलित टेथर के स्टेबल कॉइन का मूल्य पिछले 12 माह में 46% बढ़कर 15.44 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स के साथ फायदों से ज्यादा जोखिम अधिक हैं। उसके नियमन के नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं।

स्टेबल कॉइन्स को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी समस्याओं का हल बताया जाता है। डॉलर या अन्य सुरक्षित एसेट के साथ अपने मूल्य को जोड़कर डिजिटल दक्षता और स्थिरता का दावा करते हैं। वे स्वयं को बैंकों, वीसा, पेपाल, स्विफ्ट पेमेंट प्लेटफार्म का प्रतिद्वंद्वी कहते हैं। पहली नजर में ये तरक्की जैसा लगता है। लेकिन सुरक्षा का अहसास कराने वाले फाइनेंशियल इनोवेशन संकट के बीज बो चुके हैं।

स्टेबल कॉइन्स के समर्थक जोर देते हैं कि उन्हें डॉलर का समर्थन है। नियमित ऑडिट से उनके सुरक्षित धन की पुष्टि की जाती है। वैसे, टेथर पर अपने सुरक्षित कोष की गलत जानकारी देने के लिए जुर्माना हो चुका है। स्टेबल कॉइन्स जारी करने वाली एक अन्य कंपनी सर्किल के 8% रिजर्व फंड सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से खत्म हो गया था। 2022 में स्टेबल कॉइन टेरायूएसडी धराशायी हो गया। चिंता की बात है कि जीनियस एक्ट में कॉइन होल्डर के पैसा वापस होने के संबंध में साफ प्रावधान नहीं हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल

उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे पर आई लव मोहम्मद को लेकर हुए बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ी तक दंगा करना भूल जाएगी। एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में सरकार के सख्त संदेश के बाद योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है, मैंने बोला जाम नहीं होगा, न ही कर्फ्यू लगेगा। यह चेतावनी इत्तेहाद-ए-मिल्लद काउंसिल के प्रमुख मौलवी तौकीर रजा खान के लिए बताई जा रही है जिन्होंने आई लव मोहम्मद अभियान के नाम पर विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया था। रजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और चौदह दिन के लिए जेल भेज दिया गया। उनतालिस अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि बाराबंकी में शुक्रवार को देर रात आई लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ने के बाद हंगामा हो गया था। दरअसल, बारावफात के जुलूस के दौरान कानपुर के कुछ मुस्लिम इलाकों में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर/बैनर रास्ते में लगाने से हिन्दूवादी संगठनों ने आपत्ति की थी। कुछ लोगों के खिलाफ शिकयत दर्ज होने और पंद्रह अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज होने पर मामले ने तूल पकड़ लिया। देश के अन्य इलाकों में भी लोग आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। विरोधस्वरूप कुछ हिन्दुत्ववादियों ने आई लव महादेव/महाकाल जैसे बैनर लगाने चालू कर दिए। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि रजा पंद्रह साल पहले हुए दंगों की तर्ज पर शहर को सुलगाने की साजिश कर रहा था। भड़काऊ बयानों द्वारा भीड़ को इक_I करने और पत्थरबाजी कराने, चाकू-डंडे आदि से दहशत फैलाने के सबूत पाए गए हैं। मौके से अवैध हथियारों का मिलना इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जानबूझकर शहर को दंगों में झोंकने की साजिश की जा रही थी। चूंकि नमाज के वक्त स्थानीय पुलिस इलाके में मुस्तैद थी, इसलिए उसने फौरन उपद्रवियों को काबू में कर लिया। बता रहे हैं कि फसाद करने वालों को इंटरनेट के माध्यम से निर्देशित किया जा रहा था। उपद्रवियों ने पुलिस वालों पर भी हमला किया और उनके उपकरण छीनने के प्रयास किए। निःसंदेह राज्य के मुखिया द्वारा दी गई यह धमकी कतई उचित नहीं कही जा सकती। मगर यदि वास्तव में शहर में उपद्रव फैलाना किसी का मकसद था तो उसे खुला भी नहीं छोड़ा जा सकता। यह बात धर्म विशेष तक नहीं सीमित रहनी चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रहों के बगैर किसी भी उपद्रवी, साजिशकर्ता और दहशतगर्द के साथ मुलायमियत से पेश आने की जरूरत नहीं है।

विकास ही लोकतंत्र की असली जीत

आरती कुमारी

विधानसभा चुनाव अपने आप मे बहुत महत्वपूर्ण है।लेकिन 2025 बिहार का यह चुनाव विशेषतौर पर राज्य के लिए निर्णायक हो गया है।क्योंकि लम्बे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर थी।कांग्रेस सोच समझ कर आगे बढ़ रही है। भविष्य का रास्ता देखकर उम्मीदवार चुनने में लग गए है।राजद चुनाव में जोर लगा रही है।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीस वर्ष से लगातार सत्ता में है और अपने अनुभवों से सिख कर परिपक्व बन गए है।बीस साल पहले बिहार में राजद की सरकार रही थी।सूबे की जनता एक नई आस से मतदान करती है।कई बार देखा गया था कि प्रदेश की जनता ने मनखोलकर मतदान किया ,लेकिन राज्य की जनता को दुःख, दर्द दूर करने का भरोसा दिलाते रहे।जनता को हरबार छलावा ही मिलता रहा है।जनता यह सोचकर मतदान करेगी।इस बार भले राजनीतिक दलों का आक्रामक प्रवेश है,लेकिन बिहार की जनता समझदार होते हुए अपने भले बुरे का निर्णय करके ही मतदान करेगी।राजद,कांग्रेस सरकारों की विकास के दावों की सच्चाई क्या है?विकास के चलते बिहार की खूबसूरत दिखाई देने वाली तस्वीर क्या राज्य की जनता भूल गई है?बीस साल पहले बदरंग तस्वीरों को मतदाता आज दिन तक नही भूल पाया है।हवा हवाई होते राजनेताओ के वादे हमेशा जनता को मजबूर करने और उनका फायदा उठाने के लिए ही होते थे।कई जिले में लालू की अनदेखी के चलते लोग गरीबी,भुखमरी, दीनता, महामारी बेरोजगारी का दंश झेल चुके थे। बिहार चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन में बिहार में विकास की बुनियादी झड़े बिछाने का प्रयास किया था।वह अविरल चल रहा है।बीस वर्ष के शासन की धुरी संभालने वाले नीतीश कुमार को बिहार में सुशासन बाबू का तमगा लोगो ने दिया है।राजद के राज में जंगलराज का उपनाम सरकार की बदतर कानून अव्ययस्था ने दिलाया था।राजद के राज में नौकरियों की नीलामी और जमीने गिरवी रखकर नौकरियां हासिल करने के कई मुद्दे चर्चा का विषय बने थे।चारो तरफ अराजकता के बीच जनता त्राहिमाम पुकार उठी थी।भाजपा के शासन में स्वरोजगार के अवसर तैयार करने के साथ 90 प्रतिशत आरक्षित करने का फैसला लिया गया था।वो धीरे धीरे सफलता की राह में आगे बढ़ा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री और संसाधन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर छात्र को लैपटॉप और डाटा भी आवंटित किए गये ।सरकार की निःशुल्क शिक्षा का सफर अभी बन्द नही हुआ है।शिक्षा और शिक्षण के प्रति सरकार का अभिगम जनता हित मे है।छात्रवृत्ति और गरीब बच्चों के लिए कोष बनाया गया।सरकार के विकास कार्यो को हाथ की अंगुली पर नही गिन सकते है।लघु सीमांत किसानों का फसली ऋण माफ कर फसली ऋण देने का भाजपा का वादा उन्नति के पथ पर किसानों को लाकर खड़ा कर दिया है।चीनी मिल मालिकों के हितार्थ कार्य कर नीतीश कुमार सरकार ने एक सुगम मार्ग प्रशस्त किया है। भाजपा सरकार में गुंडाराज और भ्रष्टाचार की कोई जगह नही है।विकास का चुनाव लोकतंत्र का पर्व बनता जा रहा है।भूमाफिया और भ्रष्टाचारियो के पैर धरती पर टिकते ही नही है।सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दास्त नही करती है।महिलाओ को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार कटिबद्ध है।हिंसा ,ब्लात्कार, हमला,छेड़छाड़ लूटपाट,छिनैती जैसे अपराध में कमी आई है।महिलाओ को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार हर कदम पर अपने वादे को भुनाती रहती है।विकास के लिए परिवहन, ऊर्जा महत्वपूर्ण होते है।सरकार ने बदलाव किया है। बिहार चुनाव के पहले ओपीनियन पोल में जेडीयू की सीटें बढ़ने की खबर है।जबकि बीजेपी और राजद बराबर है।राज्य में नीतीश कुमार पहली पसंद है।जबकि तेजस्वी की लोकप्रियता में गिरावट आई है।कांग्रेस को झटका लगता दिखाई दे रहा है।सीट शेयर में नीतीश कुमार को सबसे आगे बताये जा रहे है।बिहार में कांग्रेस पिछले तीस वर्षों से सत्ता के बाहर है।बिहार में एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।विकास के नाम पर कांग्रेस से किनारा कर चुके मतदाताओ को फिर से जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी होगी।बिहार में एनडीए के करीब 30 से ज्यादा वर्तमान विधायको पर गाज गिरती अटकलें तेज हो गई है।बिहार का चुनाव नवम्बर महीने में होगा।अन्याय यात्रा और न्याय यात्रा के लिए राहुल और तेजस्वी दोनो नेता मतदाताओ को जोड़ने के लिए निकले थे।भाजपा की निंदा और आरोप से जनता का विश्वास जितने के लिए कहा तक सफल हुए है यह चुनाव नतीजे ही निश्चित करेंगे।बिहार में एनडीए अपनी चुनाव रणनीति में बदलाव करने का रहा है।जिन विधायक से बेहतर फीडबैक नही है।उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।बिहार चुनाव निर्यायक साबित होंगे।इस चुनाव के बाद तेजस्वी अपनी रणनीति तय करने और बिहार में कांग्रेस अपनी तैयार की गई स्क्रिप्ट में कितनी कामयाब होती है।यह समय की बलिहारि है।चुनाव का मुख्य पहलू होता है।राज्य की मूलभूत सुविधा।और इस मूलभूत सुविधाओ के आधार पर ही जीत हार का निर्णय होता है।बिहार एक ऐसा प्रदेश है,जो आजादी के बाद भी पिछड़ा ही रहा था।अभी पिछले कुछ वर्षों में कुछ बदलाव हुआ है।

हैवानियत :दो जून की रोटी के एवज में अस्मत का सौदा

मनोज कुमार अग्रवाल

इंसान सबसे बड़ा हैवान है शायद जंगल के कानून भी इंसान के व्यवहार को देख कर जानवरों ने सीखा हो क्यों कि जानवर भूख शांत करने के लिए हिंसा कर सकता है लेकिन इंसान किसी की भूख शांत करने की एवज में किसी का यौन शोषण कर सकते हैं यह घिनौना हैवानियत इंसान और इंसानियत के नाम पर बेहद हैवानियत भरा बर्बरता भरा अत्याचार है, गाजा इस हैवानियत से जूझ रहा है यह दुनिया का वह हिस्सा जो अपनी बर्बादी की कहानी खुद ब खुद अब बयां करने लगा है. पिछले दो सालों से यहां जारी युद्ध ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. यूं तो यहां से कई कहानियां दो सालों से लगातार सामने आ रही हैं लेकिन जो जानकारी अब आई है, उसके बाद तो एक पल को इंसानियत पर से भी भरोसा उठ सकता है. गाजा में भूख, पैसे और पानी से लेकर हर जरूरी चीज का संकट है और इसका फायदा स्थानीय पुरुष और एड वर्कर्स कैसे उठा रहे हैं. इसकी कहानी खुद यहां की महिलाओं ने बयान की है। गाजा में इस समय गंभीर मानवाधिकार संकट है. यहां की महिलाओं ने बताया है कि कैसे खाना, पानी, पैसे और यहां तक कि हर बुनियादी चीज का संकट बढ़ता ही जा रहा है. इस संकट के बीच ही यहां पर महिलाओं का यौन शोषण यहां के स्थानीय पुरुष और कुछ एड वर्कर्स कर रहे हैं. इन महिलाओं को दो वक्त की रोटी और पीने के पानी का लालच देकर उन पर यौन संबंधों का दबाव डाला जा रहा है. उन्हें अभद्र मैसेज किए जा रहे हैं और उन्हें देर रात तक उन्हें परेशान किया जा रहा है.एक प्रतिष्ठित न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार हर महिला ने अपने परिवारों या पुरुषों के डर से और यौन उत्पीड़न को एक टैबू माने जाने की वजह से अपना नाम न बताने की शर्त पर अपनी कहानी बयां की है. इन महिलाओं ने बताया कि कभी-कभी तो पुरुष उनके पास आते और साफ-साफ दो टूक शब्दों में कहते, ' मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, मुझे ऐसा करने दो.' कभी-कभी यह सबकुछ शादी के नाम पर होता था. उनसे कहा जाता, 'मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं' या 'चलो कहीं साथ चलते हैं.'

महिलाओं के लिए विकट स्थिति - विशेषज्ञों के अनुसार यह पहली बार नहीं है जब ऐसी खबरें सामने आई हैं. अक्सर संघर्षों के काल में इस तरह की खबरें सामने आई हैं. गाजा से पहले दक्षिण सूडान, बुर्किना फासो, कांगो, चाड और हैती में आपात स्थितियों के दौरान दुर्व्यवहार और शोषण की खबरें सामने आई थीं. विशेषज्ञों की मानें तो जब लोग विस्थापित होते हैं और मदद पर निर्भर होते हैं तो महिलाओं को सबसे विकट स्थिति से गुजरना पड़ता है। ह्यूमन राइट्स वॉच में वीमेन राइट्स डिविजन की एसोसिएट डायरेक्टर हीथर बर्र ने कहा, 'यह एक खतरनाक सच्चाई है कि मानवीय संकट लोगों को कई तरह से कमजोर बना देते हैं, यौन हिंसा में इजाफा अक्सर इसका परिणाम होती है.' उन्होंने आगे कहा, 'गाजा में आज की स्थिति अकल्पनीय है खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए.' गाजा में महिलाओं के साथ काम करने वाली चार साइकोलॉजिस्ट्स ने मरीजों की आपबीती सुनाई। एक ने कहा कि उनके संगठन ने ऐसे दर्जनों मामलों का निपटारा किया है. इनमें पुरुषों ने कमजोर महिलाओं का यौन शोषण किया और यहां तक कि कुछ महिलाएं गर्भवती तक हो गईं. गाजा में स्थानीय संगठनों के लिए काम करने वाली सभी फिलिस्तीनी मनोवैज्ञानिकों ने, महिलाओं की गोपनीयता की चिंताओं और मामलों की संवेदनशील प्रकृति के कारण, नाम न छापने की शर्त पर बात की. गाजा में जहां एक रूढ़िवादी संस्कृति है, किसी भी संदर्भ में एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल रिलेशंस एक गंभीर अपराध माने जाते हैं. उन्होंने कहा कि उनका कोई भी मरीज सीधे बात नहीं करना चाहता. अपनी कहानियां शेयर करने वाली पांच महिलाओं ने कहा कि उन्होंने पुरुषों के साथ यौन संबंध नहीं बनाए. मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उनके पास आने वाली कुछ महिलाओं ने पुरुषों की मांगों पर सहमति जताई, जबकि बाकियों ने इनकार कर दिया. छह मानवाधिकार और राहत संगठनों का कहना है कि उन्हें मदद मुहैया कराने के नाम पर जुड़े यौन दुर्व्यवहार और शोषण की रिपोर्ट्स की जानकारी है। एड वर्कर्स ग्रुप्स का कहना है कि गाजा की परिस्थिति, करीब दो साल के युद्ध, कम से कम 90 फीसदी का विस्थापन, और सहायता तक पहुंच को लेकर उथल-पुथल - ने कमजोर लोगों के लिए मानवीय कार्य को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बना दिया है. जैसे-जैसे इस क्षेत्र में भूख और हताशा बढ़ती जा रही है, विशेष रूप से महिलाओं का कहना है कि उन्हें असंभव निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जा रहा हैमहिला ने युद्ध के एक साल बाद, अक्टूबर में शुरू हुई फोन कॉल्स के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि शुरुआत में उस शख्स के सवाल सीधे-सादे थे. उसने महिला से पूछा था कि उसके पति का क्या हुआ? उनके कितने बच्चे हैं? लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका लहजा बदल गया. अब वह शख्स उससे पूछता कि उसने कौन सा अंडरवियर पहना हुआ था? उसका पति उसे कैसे खुश करता था? उसने बताया कि वह उस व्यक्ति से मुवासी में मिली थी, जो इजरायल की तरफ से घोषित एक मानवीय क्षेत्र है. जिस समय जब वह मदद पाने के लिए लाइन में खड़ी थी तभी वह एक एड वर्कर ने उन्हें अपना फोन नंबर दे दिया. वह एक फिलिस्तीनी था जिसने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी की यूनिफॉर्म पहनी थी. नंबर लेने के कुछ ही देर बाद, देर रात फोन कॉल्स शुरू हो गए. उसने बताया कि वह सेक्सुअल रिलेशंस के लिए उससे सवाल करता था और वह चुप रहती थी. उसने बताया कि एक बार तो उसने सेक्स के लिए उसके पास आने को कहा. उसने मना कर दिया. करीब एक दर्जन कॉल्स के बाद भी कोई मदद न मिलने पर उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। महिलाओं ने बताया कि जिन पुरुषों ने उनसे मदद मांगी थी, उन्होंने खुद को एड वर्कर बताया था. एक मामले में मदद का वादा करने वाले एक समुदाय के नेता के तौर पर. कई महिलाओं ने बताया कि यह सब रजिस्ट्रेशन करते या मदद के लिए रजिस्ट्रेशन की कोशिश करते समय हुआ, पुरुषों ने उनके नंबर लिए, जो अक्सर सहायता प्रक्रिया का एक चरण होता है, और बाद में फोन किया. महिलाओं ने बताया कि सभी पुरुष फ़िलिस्तीनी थे। कई महिलाओं ने कहा कि वे यह नहीं पहचान पाईं कि वे पुरुष किस सहायता समूह से जुड़े थे। संयुक्त राष्ट्र और हेल्प ग्रुप्स आम तौर पर स्थानीय समुदायों के साथ काम करते हैं. ये लोगों को ठेकेदार के तौर पर भुगतान करते हैं, स्वयंसेवकों का प्रयोग करते हैं, या समुदाय की तरफ से नियुक्त नेताओं को प्वाइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के तौर पर नियुक्त करते हैं. छह बच्चों की मां ने बताया कि जिस व्यक्ति ने उसे नौकरी का वादा किया था, वह संयुक्त राष्ट्र के प्रतीकों वाली कार चलाता था. उन्होंने बताया कि बातचीत के बाद, मैसेज आते रहे जिनमें उनके लेट नाइट सेक्सुअल रिलेशंस बनाने वाले कॉल और तस्वीरों के लिए रिक्वेस्ट्स की गई थीं. उन्होंने बहाने बनाकर उन्हें टालने की कोशिशें कीं. वह अक्सर उसे कहती कि वह बिजी हैं या फिर उनका फोन खराब है या बात नहीं कर सकती हैं। महिला ने बताया कि उसने गाजा मे मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि सबूत के तौर पर उन्हें बातचीत की रिकॉर्डिंग की जरूरत है, लेकिन उनके पास पुराना फोन था, जो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकता था.जांच एजेंसी की कम्युनिकेशंस डायरेक्टर जूलियट तौमा का कहना है कि एजेंसी यौन शोषण के प्रति जीरो-टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है. उनकी मानें तो इससे ऐसे मामलों से जुड़ी हर रिपोर्ट को गंभीरता से लिया जाता है. उनका दावा है कि एजेंसी को किसी भी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या कर्मचारियों को इस घटना की जानकारी दी? गाजा पट्टी में जारी इजराइल-हमास युद्ध ने न सिर्फ घरों को उजाड़ा है, बल्कि महिलाओं की जिंदगी को एक ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया है. युद्ध की आग में जलते हुए उस मां का दिल कितना टूटता होगा, जब अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए उसे अपने शरीर को कसिी के सामने परोसना पड़े? भूखे बच्चों का पेट भरने के लिए उसे उन मर्दों की भूख मटिानी पड़े, जो उसे 2 नविाले देने का वादा करता है.... गाजा पट्टी में जारी इजराइल-हमास युद्ध ने न सिर्फ घरों को उजाड़ा है, बल्कि महिलाओं की जिंदगी को एक ऐसी अंधेरी गली में धकेल दिया है, जहां भोजन के बदले शारीरिक संबंध बनाने की मजबूरी बन गई है. ऐसी एक-दो नहीं बल्कि कई महिलाओं ने अपनी आंसू भरी आंखों से ये दास्तां सुनाई कि कैसे भूख और बेबसी ने उन्हें इस दलदल में फंसा दिया।

मेष राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। कुछ लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरों की बातों में न आकर अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखें, इससे आपके कार्य बड़ी ही आसानी से पूरे होंगे। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान देने से आप सम्मान के पात्र बने रहेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को आज ज्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। किसी कार्य को पूरा करने में पुरानी कम्पनी का अनुभव काम आएगा।

वृष राशिः आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आप अपने काम पर पूरा फोकस बनाये रखें, जल्द ही भविष्य में अच्छा लाभ मिलेगा। बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालेंगे, बच्चे अपने मन की बात आपसे शेयर करेंगे। लवमेट एक-दूसरे पर विश्वास बनाए रखें, रिश्ते में मजबूती बनी रहेगी। छात्रों को थोड़ी और मेहनत की जरूरत है।

मिथुन राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अपनी बातों से किसी को प्रभावित कर देंगे। समाज में किये गए सराहनीय काम को देखकर लोग आपसे कुछ अच्छा सीखेंगे, जिससे आपको गर्व होगा। शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों को ज्यादा लाभ होगा। स्टूडेंट अपने आप पर भरोसा बनाए रखें, जल्द ही सफलता मिलेगी।

कर्क राशिः आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपका कोई काम जो काफी दिनों से रुका था, आज पूरा हो जाएगा। साथ ही आप काम करने के नए तरीकों पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों द्वारा की गई मेहनत का शुभ परिणाम मिलेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, इससे बना बनाया काम बिगड़ सकता है। मित्रों की सलाह भी ले सकते हैं। किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसे ही अनुभव मिलेंगे।

सिंह राशिः आज आपका दिन अच्छा रहेगा। मानवहित में किये गये कार्यों के कारण आपको सम्मान मिलेगा। गैर-जरूरी खर्चों पर रोक लगाकर आप बचत पर ध्यान देंगे। व्यवसायिक गतिविधियां मन मुताबिक चलेंगी। काम करने के तरीकों में बदलाव लाएंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। अवसर मिलने पर उसका फायदा उठाएं। काम पर ध्यान बनाए रखें। जीवनसाथी घर के कार्यों में मदद करेंगे।

कन्या राशिः आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें। किसी से बहस की स्थिति बन सकती है, ऐसे में मौन रहना बेहतर होगा। पब्लिक प्लेस पर छवि खराब न होने दें। लवमेट के रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कॉस्मेटिक का व्यापार कर रहे लोगों को बड़ा मुनाफा होगा। पिता से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा।

तुला राशिः आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके काम करने के तरीकों से लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। बातचीत के दौरान अपनी निजी बातें शेयर न करें। जिस काम की शुरुआत करेंगे, वह समय पर पूरा होगा। कोर्ट से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसके सुलझने की पूरी उम्मीद है।

वृश्चिक राशिः आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। मित्रों से मन की बात शेयर करने से सुकून मिलेगा। आपको नई जानकारियां भी हासिल होंगी। रिश्तेदार से शुभ संदेश मिलेगा, जिससे खुशी दोगुनी होगी। बिजनेस में खास एग्रीमेंट होगा, लेकिन कॉम्पटीशन के दौर में कार्य करने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और सीनियर आपके काम से खुश रहेंगे और तारीफ करेंगे। सभी जरूरी काम आसानी से पूरे होंगे।

धनु राशिः आज आपका दिन सामान्य रहेगा। निजी कामों पर बाहरी लोगों का दखल न होने दें। भावनाओं में आकर कोई फैसला न लें। ज्यादा काम के कारण थकान हो सकती है।छोटी-छोटी परेशानियां जल्द दूर होंगी। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। व्यापार में मिली जिम्मेदारियों को सफलता से निभाएंगे। फर्नीचर व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा।

मकर राशिः आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। शाम का समय माता-पिता के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिससे अच्छा समाधान मिलेगा। किसी काम की शुरुआत करने से पहले शुभ मुहूर्त देखना बेहतर होगा। समाज में किये गए कार्यों से मान-सम्मान बढ़ेगा। कोई विश पूरी होगी जिससे खुशी मिलेगी।

कुम्भ राशिः आज का दिन परिवार के लिए नई खुशियां लेकर आया है। किसी अनुभवी से मिली सलाह फायदेमंद साबित होगी। काम को लेकर आपके सपने काफी हद तक पूरे होंगे। स्वयं को साबित करने के लिए बेहतर दिन है। परिवार में सामंजस्य से शांति का माहौल रहेगा। प्रकृति के बीच समय बिताने से फ्रेशनेस महसूस होगी। आपके कार्यों की प्रशंसा दूर-दूर तक होगी।

मीन राशिः आज का समय आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक समस्या हल होगी और रुके काम में गति आएगी। सकारात्मक लोगों की सलाह फायदेमंद होगी। मेहनत का उचित फल जल्द मिलेगा। अफवाहों पर ध्यान न दें। ऑफिसियल यात्रा संभव है, जो शुभ होगी। जीवनसाथी के साथ डिनर प्लान करेंगे। छात्रों के लिए सफलता का दिन साबित होगा, बस थोड़ी और मेहनत करें।

सियासत और आस्था

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना।

भारत की राजनीति एक विचित्र रंगमंच है। यहाँ हर पाँच साल में एक नया नाटक मंचित होता है। पहले के दौर में चुनाव सिर्फ विचारधारा, संघर्ष और नेताओं के व्यक्तिगत त्याग की कहानियों पर आधारित होता था। मतदाता अपनी सारी व्यथा, शिकायतें और दुःख-दर्द को भुलाकर उस कला से रिझ जाते थे, जिसे कोई नेता मंच से प्रस्तुत करता था। लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल अलग है। अब गाँव के खलिहान से लेकर शहर के किचन तक, सब जगह मोबाइल और सोशल मीडिया की रीलें छा चुकी हैं। नतीजा यह हुआ है कि जो कला कभी दिल जीत लेती थी, वह अब डिजिटल भीड़ में दब चुकी है। फिर भी सियासत अपनी पुरानी चालें छोड़ने को तैयार नहीं है। आस्था पर सियासत का अतिक्रमण कोई नया खेल नहीं है। देवी-देवताओं से लेकर धार्मिक त्योहारों तक को राजनीतिक मंच पर इस्तेमाल करने की परंपरा दशकों से चलती आई है। उसी कड़ी में हाल ही में प्रियंका गांधी का बिहार में तीज मनाना चर्चा का विषय बना। सवाल उठता है कि क्या यह आस्था का सम्मान था या चुनावी रणनीति का हिस्सा? भारत जैसे देश में आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। यहाँ हर गली-मोहल्ले में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च मिलेंगे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी को धार्मिक रीति-रिवाज़ों से जोड़कर जीते हैं। ऐसे में राजनीति ने हमेशा आस्था को अपने चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। आजादी के बाद से ही मंदिरों, मस्जिदों और धार्मिक आयोजनों का चुनावी मंचों पर इस्तेमाल होता रहा है। राम मंदिर आंदोलन से लेकर दुर्गा पूजा पंडालों में नेताओं की उपस्थिति, सब इस बात के गवाह हैं कि आस्था राजनीति का अहम आधार रही है। महिलाओं की आस्था और त्योहारों से जुड़ाव को राजनीति ने अक्सर भुनाया है। करवा चौथ, तीज, छठ जैसे पर्वों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहती है। इन मौकों पर राजनीतिक चेहरे जनता के बीच आसानी से पहुँच बनाते हैं। प्रियंका गांधी का बिहार में तीज करना इसी परंपरा का हिस्सा है। पहले नेता मंच पर भाषण देकर या जनता से आमने-सामने मिलकर संवाद करते थे। लेकिन अब मोबाइल फोन ने पूरी राजनीति को बदल दिया है। आज चुनावी रैलियों से ज्यादा असरदार मानी जाती हैं सोशल मीडिया की रीलें। नेता मंच से बोलते हैं लेकिन जनता व्हाट्सएप और फेसबुक से अपना मूड बनाती है। इस डिजिटल लहर में आस्था और त्योहारों की तस्वीरें, वीडियो और 'लाइव' इवेंट्स सबसे ज्यादा शेयर किए जाते हैं। हालांकि डिजिटल माध्यम ने राजनीति को आसान कर दिया है, लेकिन इसने वास्तविक जुड़ाव की कला को कमजोर कर दिया है। पहले नेता जनता के दुःख-दर्द सुनते थे, अब वे कैमरे के सामने तैयार स्क्रिप्ट बोलते हैं। यही वजह है कि मतदाता अक्सर भ्रमित रहते हैं कि आस्था और राजनीति के बीच वास्तविकता कहाँ है। बिहार धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों का गढ़ है। यहाँ छठ, तीज और सावन का महीना महिलाओं और परिवारों के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में किसी बड़े राजनीतिक चेहरे का इन त्योहारों से जुड़ना जनता में भावनात्मक प्रभाव डालता है। प्रियंका गांधी ने बिहार में तीज मनाकर महिलाओं से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। तीज को पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि से जोड़ा जाता है। महिलाओं का बड़ा वर्ग इससे भावनात्मक रूप से जुड़ा रहता है। प्रियंका का यह कदम चुनावी दृष्टि से एक संदेश था "मैं आपकी परंपराओं और भावनाओं का सम्मान करती हूँ।" लोगों को असली अचंभा तब होगा जब चुनाव 25 अक्टूबर के बाद घोषित हों। क्योंकि तीज और छठ जैसे पर्व बिहार की राजनीति में बड़ा असर डालता हैं। त्योहारों से पहले भावनात्मक माहौल बनाकर वोटरों पर असर डालना चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होता है। 2022 के पंजाब चुनाव को भला कौन भूल सकता है? उस चुनाव में 'बिहारी भैयों' पर हुई टिप्पणियों ने गहरी चोट दी थी। मंच से नेताओं की ताली की गूंज पर बिहारी मजदूरों की आस्तीनें चढ़ाई जा रही थीं। यह दृश्य आज भी बहुतों के दिल को चुभता है। बिहारियों को अक्सर "सस्ते मजदूर" या "पलायन करने वाले" कहकर राजनीति ने छोटा दिखाने की कोशिश की है। पंजाब में जब यह सियासी हथकंडा चला, तब बिहार की जनता ने इसे गहरी चोट की तरह महसूस किया। यही कारण है कि बिहार के मतदाता अब हर चुनाव में नेताओं की नीयत और भाषा को तौलते हैं। भारत में महिला मतदाता निर्णायक भूमिका निभाती हैं। कई राज्यों में महिला वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में त्योहार और आस्था के जरिये उनसे जुड़ना नेताओं की प्राथमिक रणनीति बन चुका है। महिलाओं का दिल कोमल माना जाता है। वे धार्मिक त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी रहती हैं। इसीलिए सियासी दल अक्सर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए आस्था से जुड़े कदम उठाते हैं। प्रियंका गांधी का तीज मनाना इसी दिशा का हिस्सा है। नेता जब आस्था से जुड़ते हैं तो सवाल यह उठता है कि उनका मकसद आस्था का सम्मान है या वोट की राजनीति। यही राजनीति का दोहरा चेहरा है। कई बार राजनीति में आस्था का अपमान भी वोट जुटाने का हथियार बनता है। किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाकर या किसी त्योहार की उपेक्षा करके भी वोट बैंक की राजनीति की जाती है। भारत की राजनीति में आस्था का हस्तक्षेप कोई नया नहीं है। लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया है। पहले जहाँ मंच और भाषण से जनता को रिझाया जाता था, वहीं आज मोबाइल और रीलों ने यह भूमिका ले ली है। लेकिन मतदाता अब ज्यादा सतर्क है। उसे पता है कि राजनीति आस्था को सिर्फ चुनावी औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। प्रियंका गांधी का बिहार में तीज करना इस बात का प्रतीक है कि त्योहारों का राजनीतिक महत्व आज भी बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जनता सिर्फ आस्था से प्रभावित होगी या फिर पंजाब 2022 जैसे अनुभवों को याद रखेगी? यही लोकतंत्र की असली परीक्षा होगी।

Machine Translated by Google

घरेलू जीवन शक्ति

घरेलू कंपनियों ने विदेशी निवेशकों की तुलना में भारत में अधिक विश्वास दिखाया

टी देश में निवेश घोषणाओं के नवीनतम आंकड़े मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं, जिसके नीतिगत निहितार्थ अलग-अलग हैं।

निजी क्षेत्र द्वारा घोषित नई परियोजनाओं की राशि इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में लगभग 15 महीने के उच्चतम स्तर 9.9 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

इस तरह के निवेश ऐतिहासिक रूप से भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संकेन्द्रण तेज हो गया है। जबकि भारतीय कंपनियों ने 2018-19 में निजी क्षेत्र की सभी घोषणाओं का 77% हिस्सा लिया था, यह हिस्सा चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में 94% था। एक साथ लिया जाए, तो ये डेटा बिंदु घरेलू और विदेशी फर्मों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक विपरीत दृष्टिकोण को रेखांकित करते हैं। घरेलू कंपनियां तेजी से आशावादी लग रही हैं। यह देखा जाना बाकी है कि इनमें से कितने घोषणाएं फलीभूत होती हैं, लेकिन डेटा दिखाता है कि भारतीय कंपनियों द्वारा वास्तव में पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य भी इस पैमाने पर लगभग 15 महीने के उच्च स्तर पर था। यह सरकार के लिए राहत की बात होनी चाहिए, जो निजी क्षेत्र को और अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित कर रही है। इन नए निवेशों का एक बड़ा हिस्सा 15 अगस्त को जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा से पहले ही घोषित कर दिया गया था, जिसका अर्थ है कि निजी क्षेत्र का भरोसा अस्थायी माँग वृद्धि की अपेक्षा से कहीं अधिक गहरा है। अगर निवेश सफल होता है, तो सरकार के पास विकास और रक्षा संबंधी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए अधिक गुंजाइश होगी, जिन दोनों पर उसे ध्यान देने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर, विदेशी कंपनियां भारत की कहानी से पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिखतीं। विदेशी कंपनियों द्वारा परियोजना घोषणाओं का मूल्य वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में घटकर ₹0.6 लाख करोड़ रह गया, जो इस अवधि के दौरान लगातार तीसरे वर्ष गिरावट का संकेत है और पांच साल का निचला स्तर भी है। कोविड-19 महामारी के बाद से कई वैश्विक कारकों ने निश्चित रूप से निवेशकों की भावना को कम किया है, लेकिन तथ्य यह है कि वैश्विक निवेश प्रवाह 2024 में 11% और 2023 में 3% बढ़ा है। हालांकि अमेरिका के साथ नवीनतम नीतिगत घर्षण ने इस वर्ष निवेश गंतव्य के रूप में भारत में कुछ विश्वास को हिला दिया होगा, सरकार को यह पता लगाने की जरूरत है कि विदेशी कंपनियां पहले ही कहीं और क्यों देख रही थीं। आंकड़े यह भी बताते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकार द्वारा नई घोषणाएं ₹1.5 लाख करोड़ रहीं, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 71% कम है। यह केंद्र सरकार की उस चेतावनी के अनुरूप है कि वह अपने पूंजीगत व्यय में पहले जितनी तेज़ी से वृद्धि नहीं कर पाएगी। हालाँकि, सरकार और विदेशी कंपनियों के पीछे हटने से भारतीय कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही, व्यापार सुगमता सुधारों के माध्यम से इस गति को बनाए रखने की ज़रूरत भी बढ़ रही है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद समुद्री सिग्नलिंग

हेली देसाई

एक शोध है
सहयोगी
सामरिक और रक्षा परिषद
अनुसंधान, नई दिल्ली

डब्ल्यू पाकिस्तान के साथ गतिरोध के बावजूद मई 2025 में वायु क्षेत्र में संलग्नता के साथ, बाद के घटनाक्रमों ने समुद्री रंगमंच की ओर ध्यान आकर्षित कर लिया है, जैसा कि भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से प्रमुख नौसैनिक गतिविधियों, क्षमता प्रदर्शनों और आधिकारिक बयानों में देखा जा सकता है, जिसमें उनकी नौसेनाएं अपनी स्थिति में सुधार कर रही हैं और संभावित वृद्धि के लिए तत्परता का संकेत दे रही हैं।

2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 1965 के युद्ध का हवाला देते हुए, पाकिस्तान को एक "जबरदस्त प्रतिक्रिया" की चेतावनी दी जो उसके "इतिहास और भूगोल" को बदल सकती है यदि सर क्रीक क्षेत्र में कोई भी दुस्साहस होता है - पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, एक विकास जो 2023 से जारी है।

ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान को इस क्षेत्र में एक सैन्य बढ़त हासिल है। यह अगस्त में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के बयान के बाद है, कि भविष्य में किसी भी संघर्ष में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने वाली सेवा पहली होगी। ऑपरेशन सिंदूर को नौसेना के अग्रिम निवारक रुख के लिए डिज़ाइन किया गया बताया गया था, जो मई में स्टैंडो के दौरान की तुलना में 'अधिक सक्रिय भूमिका' के लिए तत्परता पर प्रकाश डालता है। पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल, आईएनएस निस्तार, और दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के साथ भारत के पहले संयुक्त गश्त

पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सुरक्षा भी मजबूत की है। सिग्नलिंग। मई में, इसने अपनी कमज़ोरियों को कम करने के लिए कराची से ग्वादर तक अपनी सामग्रियाँ तैनात कर दीं। तब से, इसने चीन निर्मित हंगोर-श्रेणी की पनडुब्बी, पीएनएस मैंग्रो, का प्रक्षेपण किया है और घरेलू स्तर पर विकसित पी282 जहाज-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। इसके बाद के महीनों में, कई बार ओवरलैपिंग नोटैम, मिसाइल परीक्षण और लाइव-री अभ्यास भी हुए हैं —कभी-कभी केवल 60 समुद्री मील की दूरी पर—जिससे अरब सागर में अलर्ट और परिचालन घर्षण का एक चक्र बना रहा।

नौसैनिक सिग्नलिंग का रणनीतिक महत्व : ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की गतिविधियों में आई तेज़ी एक बुनियादी सवाल खड़ा करती है: क्या ये समानांतर अभ्यास सिर्फ़ नियमित गतिविधियाँ हैं या फिर नौसेना के क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान के निवारक समीकरण में बदलाव का संकेत देने वाला एक सोचा-समझा बल प्रदर्शन। इसका जवाब इसलिए मायने रखता है क्योंकि मौजूदा संकट, हालाँकि हवाई क्षेत्र में हल हो गया है, समुद्र में रणनीतिक अनिश्चितता का एक अवशेष छोड़ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत और पाकिस्तान अपनी नौसैनिक स्थिति को नए सिरे से संतुलित कर रहे हैं, न केवल निवारक क्षमता के लिए, बल्कि इस संभावना के लिए भी कि समुद्री क्षेत्र में टकराव का अगला चरण शुरू हो सकता है।

इस बदलाव को क्षमताओं के व्यापक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भी समझा जाना चाहिए। वायु क्षेत्र की तरह, समुद्री संतुलन को भी अब कारगिल युद्ध की विषमताओं जैसा नहीं माना जा सकता। 1999, या 1971 में भारत की निर्णायक श्रेष्ठता। भारत संख्यात्मक और भौगोलिक बढ़त बरकरार रखता है, लेकिन उसकी नौसैनिक क्षमता पुरानी होती जा रही है, जिससे आधुनिकीकरण की चिंताएँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान लगातार अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, चीनी डिज़ाइन की पनडुब्बियों और तुर्की से बाबर श्रेणी के युद्धपोतों को शामिल कर रहा है। उन्नत रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण और बहुमुखी वायु-रोधी तथा सतह-रोधी हथियारों के साथ, ये सुविधाएँ महत्वपूर्ण हैं।

इस बदलाव को स्वीकार करते हुए, भारत के नौसेना प्रमुख ने पाकिस्तान की नौसैनिक शक्ति में "आश्चर्यजनक वृद्धि" की ओर भी इशारा किया था। हालाँकि भारत की बढ़त अभी भी बरकरार है, लेकिन यह अंतर कम होता जा रहा है, जिससे हिंद महासागर में निर्विवाद प्रभुत्व की धारणाएँ जटिल होती जा रही हैं। कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम तीन कारणों से महत्वपूर्ण हैं: तनाव पर नियंत्रण, बाहरी हस्तक्षेप और दोनों पक्षों के बदलते सिद्धांत।

प्रथम, समुद्र में तनाव को नियंत्रित करना कहीं अधिक कठिन है। हवाई झड़पों के विपरीत, जिन्हें संतुलित करके पीछे हटा जा सकता है, किसी भी नौसैनिक मुठभेड़ (जहाज-पर-जहाज या जहाज-पर-जमीन) में युद्ध की दहलीज पार करने का अधिक जोखिम होता है।

1971 की यादें, जब भारतीय नौसैनिक अभियानों ने निर्णायक रूप से युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ दिया था, अतिरिक्त संवेदनशीलता पैदा करती हैं - यहां तक कि सीमित समुद्री कार्रवाई भी पाकिस्तान की रणनीतिक कल्पना में अस्तित्व के जोखिम से जुड़ी है।

तब से, पाकिस्तान की मुख्य समुद्री चिंता भारतीय नौसैनिक अभियानों के प्रति अपनी कमजोरी की पुनरावृत्ति को रोकना रही है, जो एंटी-एक्सेस/एरिया-डिनायल (ए2/एडी) क्षमताओं की खोज और निषेध-द्वारा-निवारण की ओर उन्मुख सिद्धांत की क्रमिक अभिव्यक्ति में दिखाई देती है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के ढाँचे के तहत ग्वादर के विकास को भी इसी निवारक तर्क के अंतर्गत समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान के नीति-निर्माता लंबे समय से कहते रहे हैं कि ग्वादर की उत्पत्ति बीजिंग की बजाय इस्लामाबाद की अपनी रणनीतिक गणनाओं में निहित है। इस प्रकार, ग्वादर और कराची केवल परिचालन या आर्थिक केंद्र ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बिंदु भी प्रतीत होते हैं। इस पृष्ठभूमि में, यदि भविष्य में भारतीय नौसेना को प्रत्यक्ष अभियानों में शामिल किया जाता है, तो युद्ध के अलावा किसी भी प्रकार के दबाव की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी, और भारत को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी (PLAN) की उपस्थिति और उसके हितों पर भी विचार करना होगा।

बाह्य आयाम: दूसरा, दोनों पक्षों द्वारा समानांतर अभ्यास और मिसाइल परीक्षण, छिटपुट अभ्यासों से कहीं अधिक को प्रतिबिंबित कर सकते हैं, जो तत्परता प्रदर्शित करने और प्रतिद्वंद्वी के योजना चक्र को जटिल बनाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों की ओर इशारा करते हैं। भारत के लिए, यह पैटर्न दबाव बनाए रखने और संकट के बाद की कहानी को आकार देने के प्रयास का संकेत दे सकता है, जो सिंदूर के बाद के परिणामों को जिस तरह से देखा गया है, उससे बेचैनी को दर्शाता है। पाकिस्तान ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की है कि उसकी नौसेना अब 1971 जैसी कमजोर ताकत नहीं है और वह समुद्री क्षेत्र में दबाव को रोकने और भारतीय परिचालन योजना को जटिल बनाने के लिए तैयारी का संकेत दे रहा है। भारत स्पष्ट रूप से पहल बनाए रखने पर आमादा दिखाई देता है।

मई 2025 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच, सीमाएँ हवाई क्षेत्र से समुद्र की ओर स्थानांतरित हो रही हैं

क्षमता और जोखिम स्वीकृति का प्रदर्शन। यह समानता यह दर्शाती है कि दोनों पक्ष तैयारी का संकेत दे सकते हैं तथा समुद्र में भविष्य के "संघर्ष-टेम्पलेट" को आकार देने में सक्रिय रूप से निवेश कर सकते हैं।

तीसरा, बाह्य आयाम तीक्ष्णता है। कराची और ग्वादर बंदरगाहों में चीन की दखलंदाजी भारत के कथित प्रभुत्व को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि संकट के समय पाकिस्तान को पीएलएएन (PLAN) की मदद का खतरा बढ़ रहा है। तुर्की की उभरती भूमिका, भले ही आपूर्ति या प्रशिक्षण तक सीमित हो, अनिश्चितता की एक और परत जोड़ती है।

ये बदलाव इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि ये बदलते हैं कि बल प्रयोग और प्रतिरोध कारगर हैं। यह बताया गया है कि भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने पाकिस्तान को कराची से अपनी सेना हटाने पर मजबूर कर दिया था, जिससे उसने प्रभुत्व का प्रदर्शन किया और बिना तनाव बढ़ाए मनोवैज्ञानिक कीमत चुकाई, लेकिन अब यह रणनीति काम नहीं कर सकती। साथ ही, हालिया खरीद और उच्च-स्तरीय सैन्य प्रवेश के अनुमानों ने भविष्य में नौसेना की अधिक प्रमुख भूमिका की उम्मीदों को हवा दी है, जिससे एक दुविधा पैदा हो रही है - बल प्रयोग का विकल्प भले ही कम हो रहा हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ रहा है।

अंत में, रणनीतिक भटकाव की समस्या भी हो सकती है। दोनों सेनाएँ पिछले संकटों के उदाहरणों पर काम करती दिख रही हैं, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर ड्रोन तक की नई क्षमताएँ इस उतार-चढ़ाव को बदल रही हैं। अगर संकटकालीन निर्णय पुरानी मान्यताओं पर आधारित रहेंगे, तो गलत अनुमान लगाने का जोखिम बढ़ जाएगा। परिणामस्वरूप, समुद्री क्षेत्र वह क्षेत्र बनता जा रहा है जहाँ इस संज्ञानात्मक अंतर की परीक्षा होगी।

व्यापक दृष्टिकोण: अगले भारत-पाकिस्तान संकट का नौसैनिक पहलू शायद हाशिये पर ही रहेगा। दोनों पक्ष न केवल मंचों का परीक्षण कर रहे होंगे, बल्कि समुद्र में उन सीमाओं का भी संकेत दे रहे होंगे, जहाँ गलत अनुमान लगाने का जोखिम वायु क्षेत्र से गुणात्मक रूप से भिन्न है। हवाई झड़पों के विपरीत, नौसैनिक तैनाती निरंतर बनी रहती है, और इरादे और संकल्प की धारणाओं को आकार देती है।

फिर भी, विरोधाभासी रूप से, यही पैटर्न स्थिरता लाने वाले प्रभाव भी ला सकता है। एक-दूसरे की रणनीति, युद्धाभ्यास और क्षमताओं के नए अनुप्रयोगों का परीक्षण और अवलोकन करके, दोनों नौसेनाएँ आपसी जागरूकता का निर्माण कर रही हैं जो समय के साथ युद्ध के कोहरे को कम कर सकती है। इस अर्थ में, भारतीय नौसेना अपने पाकिस्तानी समकक्ष के बारे में उस तरह की जानकारी प्राप्त कर रही है जो वायु सेना ऑपरेशन सिंदूर से पहले शायद नहीं कर सकती थी।

भारत के लिए चुनौती यह तय करने की होगी कि समुद्री क्षेत्र को शुरुआती संकेत देने के क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाए या इसे तनाव बढ़ाने के एक आरक्षित क्षेत्र के रूप में रोका जाए। स्टील्थ फ्रिगेट का जलावतरण, व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त गश्त पर ज़ोर, और स्वदेशी क्षमता के लिए प्रयास, यह दर्शाते हैं कि नई दिल्ली दोनों संभावनाओं के लिए तैयारी कर रही है: एक विस्तारित क्षेत्रीय भूमिका और संकट-विशिष्ट दबावकारी उपाय। फिर सवाल यह है कि क्या नौसेना को पहले की तुलना में अग्रिम मोर्चे पर अभियानों में पहले शामिल किया जाएगा।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

शांति मृगतृष्णा

ट्रम्प की योजना इजरायल के लक्ष्यों की पूर्ति करती है और फिलिस्तीनियों के लिए बहुत कम है

पी गाजा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्री "शांति योजना" को इजरायल और प्रमुख अरब देशों से दुर्लभ अनुमोदन प्राप्त हुआ है। जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यह इजरायल के युद्ध उद्देश्यों के अनुरूप है, अरब और मुस्लिम नेताओं ने शांति की दिशा में एक कदम के रूप में इस पहल का स्वागत किया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण आवाज गायब है - फिलिस्तीनी लोगों के किसी भी प्रतिनिधि की। जब गाजा युद्ध का नवीनतम चरण शुरू हुआ, 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद, इजरायल ने इस्लामी आतंकवादी समूह को "नष्ट" करने की कसम खाई थी। दो साल बाद, इजरायल ने गाजा को धूल में बदल दिया है और पूरी आबादी को विस्थापित कर दिया है। फिर भी, हमास पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। कोई भी स्थायी शांति इजरायल और फिलिस्तीनियों के सच्चे प्रतिनिधियों के बीच समझौते पर निर्भर करती है

ट्रंप और श्री नेतन्याहू ने हमास को अल्टीमेटम दिया है: योजना स्वीकार करो या फिर लगातार इज़राइली हमलों का सामना करो। ट्रंप की योजना में सभी बंधकों की रिहाई के बदले तत्काल युद्धविराम का वादा किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि फ़िलिस्तीनियों को जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अस्थायी आश्रयों में रहने वाली आबादी के लिए, युद्धविराम और वहीं रहने की अनुमति एक राहत की बात होगी। लेकिन इस रियायत के अलावा, योजना का बाकी हिस्सा लगभग पूरी तरह से इज़राइली हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है।

इसमें गाजा को एक अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक निकाय के अधीन रखने का प्रस्ताव है, जिसकी देखरेख श्री ट्रंप की अध्यक्षता में एक 'शांति बोर्ड' द्वारा की जाएगी। इस योजना में गाजा में एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (आईएसएफ) की तैनाती का भी प्रस्ताव है, जबकि इज़राइली सैनिकों को "एक सुरक्षा घेरा" बनाए रखने की अनुमति दी गई है।

हमास को खुद को विघटित करना होगा। संक्षेप में, गाजा को एक नए औपनिवेशिक प्रशासन और एक विदेशी सैन्य बल के अधीन रखा जाएगा, जबकि इज़राइल एन्क्लेव के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करना जारी रखेगा। फिलिस्तीनियों को शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्थाओं से तब तक बाहर रखा जाएगा जब तक "फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार पूरे नहीं हो जाते"। यह रेत पर लिखी एक योजना है। भले ही हमास इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और खुद को भंग कर ले, या फिलिस्तीनी हमास को पूरी तरह से अस्वीकार कर दें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध खत्म हो जाएगा। फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय मार्ग के बिना, हिंसा किसी न किसी रूप में जारी रहेगी - 7 अक्टूबर का संदेश। इस योजना में अपने ऊँचे लक्ष्यों के लिए कोई समय-सीमा नहीं दी गई है; यह स्पष्ट नहीं करता कि कौन से देश आईएसएफ में सैनिक भेजेंगे; न ही यह स्पष्ट करता है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया या फिलिस्तीनी प्राधिकरण के भीतर "पुनर्गठन" की देखरेख कौन करेगा। अपने सहयोगी को फ़िलिस्तीनियों पर रोज़ाना हमले बंद करने और बंधकों के लिए संघर्ष विराम समझौते के ज़रिए पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बजाय, श्री ट्रम्प पहले से ही मुश्किल संघर्ष को और जटिल बना रहे हैं। इस प्रस्ताव से उन्हें शांति नहीं मिलेगी। बल्कि, यह उन्हें पश्चिम एशिया के दलदल में और भी ज़्यादा घसीट ले जाएगा।

स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि के लिए जलवायु वित्त विस्तार की आवश्यकता है

फ्लाविया लोपेस

कार्यक्रम, संयुक्त
राष्ट्र पर्यावरण
program'
(यूएनईपी) भारत

बालकृष्ण पिसुपति

प्रमुख, यूनाइटेड
राष्ट्र पर्यावरण
program'
(यूएनईपी) भारत

मैं भारत का स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन गति पकड़ रहा है। 2024 में, भारत 24.5% की वृद्धि करेगा। गीगावाट (जीडब्ल्यू) सौर ऊर्जा क्षमता के साथ, यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बन गया है, जिससे यह नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव की 2025 जलवायु रिपोर्ट में भारत को, ब्राज़ील और चीन के साथ, सौर और पवन ऊर्जा के विस्तार में अग्रणी विकासशील देश के रूप में मान्यता दी गई है। 2023 में, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने दस लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में 5% का योगदान देगा। इसमें से, अकेले ओ-ग्रिड सौर ऊर्जा ने 2021 में 80,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की स्थापना में भारत का नेतृत्व प्रशंसनीय है।

महत्वपूर्ण अंतर लेकिन इस प्रभावशाली गति को निरंतर गति देने की आवश्यकता है। सुर्खियों के पीछे एक महत्वपूर्ण अंतर छिपा है - वह वित्तीय प्रोत्साहन जो इस परिवर्तन को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

जलवायु वित्त में नाटकीय विस्तार के बिना, भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ेगा।

स्वच्छ ऊर्जा के आर्थिक पक्ष का ठोस आधार है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के अनुसार, यदि भारत 1.5°C के अनुरूप दिशा अपनाता है, तो वह 2050 तक 2.8% की औसत वार्षिक जीडीपी वृद्धि हासिल कर सकता है, जो जी-20 के औसत से दोगुनी से भी अधिक है। बैटरी-एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, विकेन्द्रीकृत ग्रिड और हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियाँ, सभी समावेशी और भविष्य-तैयार विकास के नए अवसर पैदा कर रही हैं।

फिर भी, यह गति जलवायु वित्त के लुप्त हिस्से पर निर्भर है।

भारत के जलवायु वित्त अंतर का आकार बहुत बड़ा है। हाल के अनुमानों के अनुसार, 1.5°C के लक्ष्य पर बने रहने के लिए 2030 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वित्त मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक यह राशि 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार, बिजली ग्रिड को मज़बूत करने,

इस के बिना, भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ेगा

बैटरी भंडारण, हरित हाइड्रोजन का विस्तार, और टिकाऊ परिवहन एवं कृषि की ओर संक्रमण। जलवायु वित्त का वर्तमान प्रवाह इस लक्ष्य से काफी कम है।

दिसंबर 2024 तक, भारत का संचयी संरेखित हरित, सामाजिक, सततता और सततता-संबंधी (GSS+) ऋण निर्गम 55.9 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जो 2021 से 186% की वृद्धि दर्शाता है, और कुल संरेखित निर्गम में ग्रीन बॉन्ड का योगदान 83% था। यह प्रगति अभी भी मज़बूत बनी हुई है, भारत में ग्रीन बॉन्ड निवेश 2025 में 45 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगा, और सतत वित्त पोषण लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का है, जो निजी क्षेत्र की मज़बूत भागीदारी का संकेत देता है।

हालाँकि, बड़े कॉर्पोरेट्स से आगे विस्तार की चुनौती अभी भी बरकरार है। हालाँकि कुल ग्रीन बॉन्ड जारी करने में निजी क्षेत्र का योगदान 84% रहा है, फिर भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कृषि-तकनीक नवप्रवर्तकों और स्थानीय बुनियादी ढाँचा विकासकर्ताओं की पहुँच को रियायती वित्त पोषण और जोखिम-साझाकरण तंत्रों के माध्यम से बढ़ाने की आवश्यकता है। सोलर पार्क योजना के तहत भारत की सफल सौर ऊर्जा नीलामी को निजी वित्त पोषण को आकर्षित करने में एक पहल के रूप में उद्धृत किया गया है। इसी प्रकार, भारत द्वारा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित सामाजिक बॉन्ड की सफलता ने निजी पूंजी को जलवायु कार्रवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में प्रवाहित किया है।

रणनीति में बदलाव: वित्त में इस अंतर को पाटने के लिए, भारत को अपनी जलवायु वित्त रणनीति में विविधता लानी होगी और उसे और गहरा करना होगा, जिसकी शुरुआत सार्वजनिक वित्त से होगी। राष्ट्रीय और राज्य सरकारें निजी पूंजी को आकर्षित करने और हरित निवेशों के जोखिम को कम करने के लिए बजट आवंटन और पैमाने के साधनों का उपयोग कर सकती हैं।

मिश्रित वित्त इस खाई को पाट सकता है। हालाँकि रियायती वित्त और जोखिम-साझाकरण तंत्र का अक्सर उल्लेख किया जाता है, फिर भी इसकी आवश्यकता है

यह जांचने के लिए कि वे विभिन्न क्षेत्रों, पैमाने और निवेशक प्रोफ़ाइल में कैसे काम करते हैं। आंशिक गारंटी या अधीनस्थ ऋण जैसे ऋण वृद्धि उपकरण हरित परियोजनाओं के जोखिम-प्रतिफल प्रोफ़ाइल में सुधार कर सकते हैं, जिससे वे निजी ऋणदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं। इसी प्रकार, प्रदर्शन या ऋण गारंटी, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में मध्यम आकार के स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे के लिए ऋण को खोल सकती है, जहाँ शासन और वितरण जोखिम निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं।

ऐसे मॉडलों को बढ़ाने के लिए पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और सॉवरेन वेल्थ फंडों से घरेलू संस्थागत पूंजी जुटाने की आवश्यकता होगी।

भारत भी अपने संस्थागत निवेशकों जैसे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या जीवन बीमा निगम को अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जलवायु-संरेखित निवेशों के लिए आवंटित करने में सक्षम बनाकर इसी तरह की क्षमता को अनलॉक कर सकता है।

इसके लिए विनियामक सुधारों की आवश्यकता होगी, जैसे कि स्पष्ट पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक निवेश दिशानिर्देश, जोखिम शमन उपकरण और दीर्घकालिक हरित परियोजना पाइपलाइन।

कार्बन बाजारों का दोहन करें नीति और संस्थागत समर्थन महत्वपूर्ण हैं। कार्बन बाज़ार एक और रास्ता खोल रहे हैं। भारत की नई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, अगर पारदर्शी, सुविनियमित और न्यायसंगत हो, तो वित्तपोषण के नए रास्ते खोल सकती है। अनुकूलन, हानि और क्षति के लिए वित्तपोषण भी उतना ही ज़रूरी है।

भारत को न केवल स्वच्छ ऊर्जा, बल्कि जलवायु वित्त नवाचार में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी, जिसमें दृश्यमान और मापनीय सफलताएँ शामिल हों। यह जलवायु वित्त पर नज़र रखने के लिए ब्लॉकचेन, हरित पोर्टफोलियो के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित जोखिम मूल्यांकन, या भारत की अनूठी सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले अनुकूलित मिश्रित वित्त मॉडल के माध्यम से हो सकता है।

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं

संपादक के नाम चिठी

असंगत

आरएसएस को श्रद्धांजलि

2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ-साथ ऐतिहासिक विडंबना के कुछ परेशान करने वाले प्रश्न भी उठते हैं। महात्मा गांधी अहिंसा, सर्वधर्म सद्भाव और सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, जबकि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन से खुद को अलग रखा। गांधी के विचारों के प्रति वैचारिक शत्रुता सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय श्रद्धांजलि सत्य के अनुरूप होनी चाहिए, राजनीतिक सुविधा के अनुरूप नहीं।

गोपालस्वामी जे., चेन्नई

पारदर्शिता ज़रूरी है । करूर

भगदड़ को लेकर चल रही राजनीति आँख में छाले की तरह है। मामले की तह तक पहुँचने के लिए एक जाँच आयोग गठित किया गया है।

तथ्यों की तह तक। एक बहुत बड़ी रैली के लिए असुविधाजनक स्थल की भी आलोचना हुई है।

संबंधित अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ईमानदारी बरतने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए।

मणि नटराजन,
चेन्नई

आगे बढ़ना

मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ

मेरे मोहल्ले के बच्चों को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे कस्बे के ज़्यादातर स्कूलों ने नौवीं कक्षा के बच्चों को दसवीं कक्षा के विषय पढ़ाना शुरू कर दिया है। यह इस साल अगस्त से हो रहा है। यह चिंता का विषय है क्योंकि नौवीं कक्षा में 'लोकतंत्र', 'फ्रांसीसी क्रांति', 'असहयोग आंदोलन' जैसे महत्वपूर्ण पाठ होते हैं।

'आंदोलन' और इस आयु वर्ग के लिए डिज़ाइन किए गए बहुत सारे बुनियादी गणित। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब स्कूल उन पर केवल बोर्ड परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का दबाव डालते हैं, तो छात्रों की एक पीढ़ी इन विषयों/विषयों को नज़रअंदाज़ कर देती है।

इस तरह की प्रवृत्ति समग्र शिक्षण अनुभव को भी प्रभावित करती है, तथा रटने की तैयारी पर अनावश्यक जोर देती है।

संकल्पनात्मक समझ। इसका छात्रों की विश्लेषणात्मक क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों, स्कूल प्रशासकों और अभिभावकों को इस प्रथा पर पुनर्विचार करना चाहिए।

भव्या काकरला, कुरनूल,
आंध्र प्रदेश

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 196

पायलट प्रशिक्षण में खामियां

भारत में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा पंजीकृत उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (एफटीओ) की पहली रैंकिंग एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक संदेश देती है। इनमें कोई भी संगठन या प्रशिक्षण केंद्र विमानन नियामक की शीर्ष दो श्रेणियों ' ए प्लस' और 'ए' में जगह नहीं बना पाया है। 22 संगठनों को 'बी' रैंकिंग और 13 को 'सी' रैंकिंग दी गई है। अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो भारत के अधिकांश एफटीओ 'औसत' या 'औसत से ऊपर' हैं। 'बी' रैंकिंग 70 प्रतिशत और 50 प्रतिशत के बीच अंक (स्कोर) दर्शाती है और बताती है कि केवल कुछ ही एफटीओ शीर्ष समूह में शामिल हैं। 'सी' श्रेणी में आए एफटीओ को 'आत्म-विश्लेषण और सुधार' के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और वे डीजीसीए की जांच के दायरे में भी आ सकते हैं। सरकार से समर्थन प्राप्त प्रायोजित एफटीओ रैंकिंग में काफी नीचे हैं। एफटीओ हर साल 800 से 1,000 वाणिज्यिक-पायलट लाइसेंस धारकों को स्नातक की उपाधि देते हैं लेकिन यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू एफटीओ के औसत एवं इससे थोड़े अधिक प्रदर्शन की रैंकिंग ऐसे समय में आई है जब पायलटों की मांग काफी बढ़ रही है। अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में पायलटों की संख्या मौजूदा कार्यरत 6,000 -7,000 से बढ़कर 30,000 तक पहुंच सकती है। इसका कारण यह है कि प्रमुख भारतीय विमानन कंपनियां नए विमानों के लिए भारी भरकम ऑर्डर दे रही हैं।

डीजीसीए ने रैंकिंग तय करने के लिए जो मानदंड लागू किए हैं। उन पर गहराई से विश्लेषण करें तो स्थिति काफी चिंताजनक लगती है। यह विश्लेषण बताता है कि मुख्य समस्या प्रशिक्षण संबंधित आवश्यक ढांचे की कमी और अपेक्षाकृत ढीले सुरक्षा मानकों से जुड़ी है। रैंकिंग तय करने में इन दोनों पहलुओं का भारांश 60 प्रतिशत है। उदाहरण के लिए नियामक 'परिचालन से जुड़े विषयों पहलुओं' को 40 प्रतिशत यानी सबसे अधिक भारांश देता है जिसमें छात्र-विमान अनुपात, छात्र- अनुदेशक अनुपात, बेड़े का आकार और ग्राउंड स्कूल और सिम्युलेटर की उपलब्धता जैसे मानदंड शामिल हैं। सुरक्षा मानकों का भारांक 20 प्रतिशत है और इनमें पिछले 12 महीनों में दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की संख्या शामिल है।

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये पाठ्यक्रम सस्ते नहीं हैं। उदाहरण के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी वाणिज्यिक पायलट के लाइसेंस के लिए 30 लाख रुपये अग्रिम फीस ले लेती है (जिसमें 200 घंटे की उड़ान शामिल है)। डीजीसीए ने इस अकादमी को 'सी ' रेटिंग दी है। इस फीस में 'टाइप रेटिंग' शामिल नहीं है, जो पायलटों को विशिष्ट विमान उड़ान के लिए अनिवार्य रूप से हासिल करनी होती है। इस तरह, पाठ्यक्रम का खर्च 15-20 लाख रुपये बढ़ जाता है। कुल मिलाकर, एक प्रशिक्षु पायलट के लिए 40-60 लाख रुपये खर्च आता है। जो लोग दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं वे विमानन कंपनियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम (डीजीसीए रेटिंग प्राप्त नहीं) चुन सकते हैं, लेकिन ये अच्छी गुणवत्ता के बावजूद अधिक महंगे हो सकते हैं यानी फीस 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। चिंता की दूसरी बात यह है कि पायलट प्रशिक्षण पर यह भारी खर्च (जिस पर परिवार अक्सर अपनी बचत का बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं) नौकरी की गारंटी नहीं देता है क्योंकि भारतीय विमानन उद्योग में अनुभवी पायलटों को अधिक तवज्जो दी जाती है, न कि नए प्रशिक्षित पायलटों की।

इस तरह की पहली रैंकिंग में निकल कर आए तथ्यों के बाद डीजीसीए ने उन सैकड़ों युवा महिलाओं और पुरुषों को एक महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है जो तेजी से बढ़ते भारतीय विमानन उद्योग में उड़ान भरने की आकांक्षा रखते हैं। यह रैंकिंग से जुड़ी कवायद वर्ष में दो बार 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी जिससे एफटीओ अपनी तरफ से कोई अनुचित कार्य व्यवहार नहीं कर पाएंगे। नियामक के लिए सभी संस्थागत रैंकिंग में निहित महत्त्वपूर्ण चुनौती सार्थक जांच के साथ प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखनी है ताकि यह पूरी कवायद केवल दिखावे एवं हल्की-फुल्की औपचारिकताएं निभाने तक सिमट कर नहीं रह जाए। तेजी से भीड़भाड़ वाले भारतीय विमानन उद्योग में गहन जांच एवं समीक्षा की जरूरत है।

लोकलुभावनवाद से रहना होगा सावधान

वैश्विक अनिश्चितता के बीच वृद्धि हासिल करने के लिए लोकलुभावन नीतियों में सुधार करना आवश्यक है। बता रहे हैं अजय छिब्बर

आर्थिक लोकलुभावनवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आर्थिक मुद्दों को आम जनता और भ्रष्ट या वास्तविकता से कटे हुए अभिजात वर्ग के बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। इसमें अक्सर राष्ट्रवाद की तीव्र भावना होती है, जो वैश्वीकरण का विरोध करती है। लोकलुभावनवाद दोबारा चलन में है, इस बार यह अमेरिका, हंगरी और दुनिया के कुछ गरीब देशों में हो रहा है। लोकलुभावनवादी दलों को यूरोप में, खासकर फ्रांस और जर्मनी में भारी लाभ हुआ है।

यूनाइटेड किंगडम (जो यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है) में बोरिस जॉनसन और लिज ट्रास के अधीन लोकलुभावनवादी और अक्षम सरकारों का एक दौर रहा जिसने मतदाताओं को कंजरवेटिव पार्टी से दूर कर दिया। ऋषि सुनक ने कंजरवेटिव पार्टी में भरोसा बहाल करने की कोशिश की लेकिन उन्हें लेबर पार्टी के हाथों तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। पोलैंड में 10 साल तक लोकलुभावनवादी सरकार रही और उसके बाद कहीं अधिक उदार डॉनल्ड टस्क सत्ता में आए। परंतु डॉनल्ड ट्रंप 2016-2020 के बीच अफरातफरी भरे कार्यकाल और महामारी के दौरान कुप्रबंधन के चलते 2020 का चुनाव हारने के बाद अमेरिका में दोबारा सत्ता में आ गए हैं। वहीं हंगरी में विक्टर ओर्बान के रूप में एक अन्य दक्षिणपंथी लोकलुभावनवादी मजबूत बने हुए हैं।

दुनिया में पहले भी लोकलुभावनवाद की लहरें आई हैं। अमेरिकन इकनॉमिक रिव्यू में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन में फुंके एवं अन्य1ने 1900 से 2020 के बीच दुनिया भर में लोकलुभावनवादी सरकारों के कार्यकाल का परीक्षण किया। 1930 के दशक में लोकलुभावन सरकारों की हिस्सेदारी बढ़ी। यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी का उभार हुआ। 1950 में लैटिन अमेरिका में इनकी संख्या बढ़ी। लोकलुभावनवाद बढ़ता है और फिर खत्म हो जाता है। 1930 के दशक के लोकलुभावनवाद ने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। सोवियत संघ के पतन के बाद लोकलुभावनवाद की दूसरी लहर दुनिया में नजर आई। अध्ययन से पता चलता है कि स्वतंत्र देशों में लोकलुभावन सरकारों की हिस्सेदारी 1991 में 5 प्रतिशत से कम थी, जो 2019 तक 25 प्रतिशत से अधिक हो गई, और अब यह लगभग 30 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है।

फुंके एवं अन्य ने 120 सालों के अपने अध्ययन में दिखाया कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके चलते सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 10 फीसदी की कमी देखने को मिली, सार्वजनिक ऋण 10 फीसदी बढ़ गया और संस्थागत गुणवत्ता में कमी आई। आगे उन्होंने पाया कि वाम धड़े का लोकलुभावनवाद भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि दक्षिणपंथी। उनके अध्ययन में कई वाम लोकलुभावनवादी शामिल हैं। उदाहरण के लिए अर्जेंटीना के जुआन और एवा पेरोन, भारत की इंदिरा गांधी, वेनेजुएला के हुगो चावेज और निकोलस मादुरो और मेक्सिको के आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडॉर। दक्षिणपंथ की बात करें तो ब्राजील के जैर बोल्सोनारो, तुर्किये के रेचेप तैय्यप एर्दोआन और भारत के नरेंद्र मोदी को लोकलुभावनवादी करार दिया जा सकता है। हालांकि कुछ लोग अध्ययन की श्रेणियों को लेकर छोटी-मोटी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन यदि कुछ नामों को हटा भी दिया जाए, तो व्यापक परिणामों में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा।

लोकलुभावन नेता, चाहे वे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, आमतौर पर आत्मनिर्भर नीतियों की ओर अधिक झुकाव रखते हैं, जो व्यापार को सीमित करती हैं और दुनिया को एक व्यापारिक शून्य-योग दृष्टिकोण से देखती हैं। ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्क इसके ताजे उदाहरण हैं। कुछ नेता केंद्रीय बैंक की ब्याज दर नीतियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी करते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता कमजोर होती है। एर्दोआन ने तुर्किये में ऐसा ही किया। दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद को अक्सर आव्रजन प्रतिबंधों से भी जोड़ा जाता है, जो इस गलत धारणा पर आधारित होते हैं कि प्रवासी स्थानीय लोगों की नौकरियां छीनते हैं, सेवाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं, और अपराध बढ़ाते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रवासी आर्थिक समृद्धि में योगदान करते हैं, कर चुकाते हैं, और अपराध की प्रवृत्ति कम होती है।

वे ऐसी औद्योगिक नीति का समर्थन करते हैं जहां सब्सिडी चुनी हुई कंपनियों को जाती है। उन्हें आयात संरक्षण भी हासिल होता है। जरूरत इस बात की है कि बाजार समर्थक नीतियां बनाई जाएं जहां मजबूत संस्थान विधि के शासन का ध्यान रखें। वे जो नीतियां लागू करते हैं, वे आमतौर पर कारोबार समर्थक होती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ संस्थाओं को कमजोर करती हैं और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देती हैं। वे राजकोषीय रूप से गैर-जिम्मेदार भी होते हैं। जहां दक्षिणपंथी लोकलुभावन नेता अमीरों को कर में छूट देना पसंद करते हैं, वहीं वामपंथी लोकलुभावन नेता गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं लागू करते हैं, जो अक्सर सही तरीके से लक्षित नहीं होतीं, जिससे बरबादी, भ्रष्टाचार, और सरकारी ऋण में वृद्धि होती है। इटली की 8,000 नगरपालिकाओं पर 20 वर्षों तक किए गए एक विस्तृत अध्ययन से यह सामने आया किलोकलुभावन सरकारों, चाहे वे स्थानीय स्तर पर ही क्यों न हों, उनके चलते परियोजनाओं की लागत बढ़ी, राजस्व संग्रह में कमी आई, ऋण चुकाना कम हुआ, अफसरशाही में बदलाव आया और उसकी गुणवत्ता में कमी आई।

हालिया अनुभव दर्शाता है कि विकासशील देशों के दक्षिणपंथी लोकलुभावन नेताओं को प्रतिष्ठा दर्शाने वाले बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स की ओर विशेष आकर्षण होता है। ठीक वैसे ही जैसे पहले के नेता, जैसे कि मुसोलिनी आदि, करते थे। ब्राजील में बोल्सोनारो ने एमेजॉन जंगल में सड़कें बनवाने की शुरुआत की। तुर्किये में एर्दोआन ने इस्तांबुल में नए हवाई अड्डे, पुल और सुरंगें बनवाईं और खराब गुणवत्ता वाले निर्माण कार्यों को मंजूरी दी, जो हालिया भूकंप में ढह गए। हालांकि इस तरह के बुनियादी ढांचे पर खर्च से आर्थिक गतिविधियां तेज़ होती हैं, लेकिन ये अकेले करोड़ों लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं होते, और इसके साथ-साथ देश का ऋण भी बढ़ता है।अधिकतर मामलों में, लोकलुभावन नेता संकट प्रबंधन (जैसे महामारी) में कमजोर साबित होते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति सलाह लेने या वैज्ञानिक प्रमाणों और विशेषज्ञता का पालन करने की नहीं होती, बल्कि वे अक्सर कड़े और कठोर आदेश जारी करते हैं।

कुछ लोग मोदी सरकार के लिए फुंके एवं अन्य के अध्ययन में दिए गए दक्षिणपंथी आर्थिक लोकलुभावनवाद के लेबल पर सवाल उठा सकते हैं। इसकी बुनियादी ढांचा योजनाओं ने बड़े पैमाने पर अनावश्यक प्रतिष्ठा परियोजनाओं से परहेज किया है और ये अर्थव्यवस्था के लिए काफी सकारात्मक रही हैं। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी संरचना ने सेवा वितरण और वित्तीय पहुंच को बेहतर बनाने में भारी लाभ प्रदान किया है। सरकार ने मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण व्यवस्था लागू की है और भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया है। इसके अलावा, सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी और ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता यानी आईबीसी जैसे सुधार भी लागू किए हैं। हालांकि, 2018 से आयात संरक्षण में वृद्धि और बड़े व्यवसायों के पक्ष में नीतियां दक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद की शैली से मेल खाती हैं, जबकि 60 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना वामपंथी लोकलुभावनवाद की ओर अधिक झुकती है। लेबल्स से परे, भारत को चाहिए कि वह लोकलुभावनवाद के इन पहलुओं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करे ताकि अर्थव्यवस्था अधिक प्रतिस्पर्धी और समावेशी बन सके।

यह स्पष्ट नहीं है कि दुनिया भर में लोकलुभावनवाद की यह लहर कब समाप्त होगी। सबक यह है कि आगे का रास्ता दुनिया के लिए अनिश्चित हो सकता है जिसमें भूराजनीतिक विभाजन, व्यापार युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आगमन, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां शामिल हैं। लेकिन अतीत के अनुभव हमें एक स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि लोकलुभावनवाद के मोहक गीत, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी उनसे सावधान रहना चाहिए।

(लेखक जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनैशनल इकनॉमिक पॉलिसी में प्रतिष्ठित विजिटिंग स्कॉलर हैं)

ट्रंप टैरिफ का प्रभाव और भारत के विकल्प

अमेरिका के खरीदारों को जल्द ही डॉनल्ड ट्रंप के आयात शुल्क (टैरिफ) का असर महसूस हो सकता है। अमेरिका में आयात किए जाने वाले उपभोक्ता सामान पर अधिक टैरिफ लगाए जाने से महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में समय के साथ इसका असर अधिकांश अमेरिकी नागरिकों पर पड़ेगा और अगर मांग घटती है तब वहां आर्थिक विकास रुक सकता है। इसके अलावा, जब दूसरे सामान बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतें बढ़ेंगी, तब अमेरिका में चीजों की लागत बढ़ने के साथ ही आखिरकार उनके दाम भी बढ़ जाएंगे।

इसके बावजूद, अमेरिका के घरेलू उत्पादक डॉनल्ड ट्रंप को राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए खुश हैं क्योंकि यह वास्तव में उपभोक्ताओं की समस्या है। लेकिन उत्पादकों के लिए कम प्रतिस्पर्धा का लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी।

हालांकि आयातित सामान की ज्यादा कीमतें वास्तव में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सकती हैं, पर यह साफ नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ओलिवेट्टी ने अपने टाइपराइटर बनाने वाले कारखानों को सिर्फ तीन महीनों में इतालवी सेना के लिए मशीन गन बनाने के लिए बदल दिया था। लेकिन वह सब देशभक्ति की भावना और मुसोलिनी के आदेशों के तहत किया गया था। सवाल यह है कि क्या ट्रंप वास्तव में अमेरिकी विनिर्माताओं के बीच ऐसा ही उत्साह जगा सकते हैं?

रूस से कच्चा तेल आयात करने के कारण हमारे सभी निर्यात पर अमेरिका द्वारा 25 प्रतिशत का अतिरिक्त आयात शुल्क लगाना भारत के लिए एक बड़ा बोझ साबित हो रहा है। हम रूस से सालाना लगभग 60 करोड़ बैरल तेल आयात करते हैं। अगर हम ऐसा करना बंद कर दें और दूसरे देश भी रूस से तेल लेना शुरू नहीं करते हैं, तब अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में अन्य तेल आपूर्तिकर्ताओं की मांग बढ़ जाएगी। चूंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, ऐसे में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। रूस से आने वाले तेल को अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाया जाता है, तब इससे वैश्विक बाजार में तेल की मांग 4 से 5 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि दाम 20 डॉलर प्रति बैरल बढ़ जाते हैं और भारत हर साल लगभग 168 करोड़ बैरल कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में, हमारे सालाना तेल आयात का बिल 34 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। अभी हमें रूस के कच्चे तेल पर 2 डॉलर प्रति बैरल का फायदा मिल रहा है। अगर हम वह फायदा खो देते हैं, तब भारत पर 1.2 अरब डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इसी तरह ट्रंप द्वारा रूस से तेल आयात को लेकर दबाव डालने के विरोध में उसकी दादागीरी के आगे न झुकने के अलावा एक आर्थिक तर्क भी है।

किरीट एस पारिख

सवाल यह है कि अमेरिका को इसका क्या फायदा होगा? वर्ष 2023 में, अमेरिका का पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध निर्यात रोजाना 16.4 करोड़ बैरल था, यानी सालाना लगभग 60 करोड़ बैरल। तेल की कीमत में 20 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि होने पर, इसे सालाना 12 अरब डॉलर का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। इसीलिए अमेरिका के नजरिये से ट्रंप के टैरिफ कुछ हद तक सही लग सकते हैं।

नीतिगत विकल्प

भारत को अपने निर्यात की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर बासमती चावल का थोक मूल्य लगभग 50 रुपये प्रति किलोग्राम है जबकि अमेरिका में इसकी कीमत पहुंचने के बाद लगभग 100 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। 50 प्रतिशत के आयात शुल्क के साथ इसी चावल की वहां पहुंचने पर इसकी कीमत बढ़कर लगभग 150 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगी। इसकी तुलना में, पाकिस्तान से आने वाले बासमती पर सिर्फ 19 प्रतिशत आयात शुल्क लगेगा, जिससे उसकी लागत लगभग 120 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। अभी, अमेरिका के वॉलमार्ट में इसकी खुदरा कीमत लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम है।

भारतीय निर्यातकों को लगभग 20 किलोग्राम की सब्सिडी (आर्थिक सहायता) देने से हमारा बासमती, अमेरिका के बाजार में पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ता हो जाएगा। हम लगभग 23.5 करोड़ किलो चावल निर्यात कर रहे हैं। 20-25 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देने पर सरकार को लगभग 5 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। सब्सिडी कई तरीकों से दी जा सकती है, जैसे वास्तविक निर्यात शिपमेंट पर नकद हस्तांतरण, कर्ज को आगे बढ़ाना और अमेरिका को किए गए निर्यात से हुई कमाई पर कर में छूट देना आदि। हालांकि मुश्किल बात यह है कि अगर एक बार सब्सिडी दे दी जाए तो उसे वापस लेना अक्सर मुश्किल होता है। इसलिए, इसे ऐसे रूप में होना चाहिए जो अपने आप ही खत्म हो जाए। एक विकल्प यह है कि सब्सिडी की राशि को, अमेरिका के अन्य प्रमुख निर्यातकों की तुलना में, भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से जोड़ा जाए।

झींगा मछली के निर्यात के लिए भी इसी तरह की सब्सिडी दी जा सकती है ताकि किसानों और मछुआरों को सुरक्षा मिल सके। अंतरराष्ट्रीय बाजार से तेल खरीदने के बजाय इस तरह की सब्सिडी को रूस से तेल आयात करके होने वाली बचत से वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

इसके साथ ही, बड़े पैमाने पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए आयात शुल्क को कम किया जाना चाहिए। टैरिफ और आयात प्रतिबंधों को शुरू में नए उद्योगों की रक्षा के लिए पेश किया गया था। हालांकि, जैसा कि बताया गया है कि एक बार लागू होने के बाद इन्हें हटाना मुश्किल था। इसका परिणाम यह हुआ कि यह पुराने उद्योगों के साथ भी बना रहा।

उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक्स की लागत कम हुई है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हालांकि सरकार ज्यादा कर जमा कर रही है लेकिन यह ईमानदार करदाताओं को इतना परेशान करती है कि वे हतोत्साहित हो जाते हैं।

जब मेरी कंसल्टिंग से जुड़ी आमदनी 20 लाख रुपये से ज्यादा हो गई थी, तब मैंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नंबर लिया था। हालांकि मुझे जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए बार-बार याद दिलाया जाता रहा। आखिरकार परेशान होकर मैंने साल में 20 लाख रुपये से अधिक के कंसल्टिंग असाइनमेंट छोड़ देने का फैसला किया और अपना जीएसटी नंबर वापस कर दिया।

टीमलीज रेगटेक की एक रिपोर्ट बताती है कि एक सौर ऊर्जा संयंत्र को सालाना कुल 2,735 कामों पर अमल करना पड़ता है जिनमें से 83 में जेल की सजा का प्रावधान है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कई उद्योगपति भारत के बजाय, विदेश में निवेश करना पसंद करते हैं। हमें ट्रंप के टैरिफ को अपनी व्यवस्था को सुधारने के एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए।

(लेखक इंटीग्रेटेड रिसर्च ऐंड एक्शन फॉर डेवलपमेंट (आईआरएडी) के चेयरमैन हैं)

आपका पक्ष

वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता

जीएसटी सुधार, आयकर को सरल बनाने की कोशिश और निवेश आकर्षित करने के सरकार के उपाय सही दिशा में संकेत करते हैं। अब जरूरत है कि आयात शुल्क को तार्किक बनाया जाए ताकि उद्योग प्रतिस्पर्धी बन सकें। कृषि और डेरी उत्पादों को अपवाद बनाकर शेष क्षेत्रों में शुल्क घटाना अनिवार्य है। इससे न केवल उत्पादन लागत कम होगी, बल्कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति हासिल कर पाएंगे। विनिर्माण, कृषि और डेरी को उन्नत करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' जैसे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और अवसंरचना सुधार के माध्यम से भारत अपनी वैल्यू चेन में ऊपर चढ़ सकता है। हालांकि, असली चुनौती श्रम और न्यायिक सुधारों की है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत की श्रम उत्पादकता जी-20 देशों में सबसे कम है।

विनिर्माण, कृषि और डेरी को उन्नत करने के लिए 'मेक इन इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए

इसका कारण कार्य संस्कृति की कमजोरियां हैं अत्यधिक अवकाश, कम कार्य घंटे और मुफ्त सुविधाओं पर निर्भरता। अगर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो कार्य घंटों में वृद्धि, अतिरिक्त काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन और अनावश्यक छुट्टियों की कटौती जैसे कदम उठाने होंगे। न्यायिक सुधार भी उतने ही जरूरी हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत में किसी अनुबंध को लागू कराने में औसतन चार साल और भारी खर्च लगता है। यह देरी निवेशकों का विश्वास तोड़ती है और कारोबारी माहौल को प्रभावित करती है। अगर व्यापक सुधारों को लागू किया जाए, कार्य संस्कृति बदली जाए और राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई जाए तो भारत न केवल 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकता है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका भी निभा सकता है।

विभूति बुपक्या, दिल्ली

प्रकृति से हमारी खुशहाली

विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व प्रकृति संगठन (डब्ल्यूएनओ) ने वर्ष 2010 में प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की थी। आज धरती पर हर तरह का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो कि प्राणी जाति को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश इस बार जब मॉनसून में प्रकृति के प्रकोप से जूझ रहा था तब उच्चतम न्यायालय ने भी आपदा की मुख्य चुनौतियों पर चिंता जताई। उनमें मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन, फोरलेन, सुरंगों का निर्माण और प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ है। राज्य सरकार और हरेक व्यक्ति को अदालत की चिंता को गंभीरता से लेना चाहिए। आज प्रकृति से खिलवाड़ कारण ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और दिन प्रतिदिन धरती पर गर्मी बढ़ रही है। भारत पूरी दुनिया में प्राकृतिक सौंदर्य में शीर्ष पर माना जाता है। प्रकृति की सुंदरता जंगली-जीव जंतुओं से भी होती है। लेकिन आज जीव-जंतुओं का जीना भी दुश्वार हो गया है। बहुत से जंगली-जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त होने के कगार तक पहुंच चुकी है। हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए गंभीर होना होगा और विशेष अभियान चलाना होगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर (बाएं) से परिचय पत्र स्वीकार किए। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने के आरोपों को लेकर द्विपक्षीय संबंधों में खटास आने के लगभग एक साल बाद कूटर ने राजनयिक पद का कार्यभार संभाला है।

मेहनत की कमाई में सेंध

कैसी विडंबना है कि भोले-भाले लोगों से छल करके खून-पसीने से हासिल जीवन भर की पूंजी ऑनलाइन डकैती में लूट ली जाती है। जिसकी वापसी के लिए तंत्र की कोई जवाबदेही और कानून-व्यवस्था से कोई गारंटी सुनिश्चित नहीं है। जब तंत्र लगातार ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग के लिये प्रेरित करता है तो उसे जनधन की सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी द्वारा जारी हालिया आंकड़े इस संकटपूर्ण स्थिति का खुलासा करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट खुलासा करती है कि वर्ष 2023 में साइबर क्राइम की घटनाओं में 31.2 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई है। जिसके आने वाले वर्षों में और अधिक होने की आशंका जतायी जा रही है। जो इस बात का प्रमाण है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटने अब दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। निश्चित रूप से साइबर क्राइम से जुड़े अपराधों के आंकड़े जुटाने की एनसीआरबी की पहल महत्वपूर्ण है, जो इस संकट से निपटने की अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन अपराधों से निपटने के लिये कैसे रणनीति बनाते हैं। साथ ही आम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि कैसे वे साइबर अपराधियों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। यूं तो डेटा सुरक्षा के लिये तमाम दिशा-निर्देश सरकार के विभिन्न संगठनों की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन आज भी पुरानी पीढ़ी के तमाम लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन सुविधाओं के उपयोग को लेकर पर्याप्त रूप से साक्षर नहीं होते। ऐसे में लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि दैनिक जीवन में ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हुए अपने गोपनीय डेटा की सुरक्षा कैसे करें। लेकिन विडंबना यह है कि साइबर अपराधी नित नए तौर-तरीकों से लोगों को लूटने लगते हैं। कुछ समय पहले साइबर लुटेरों ने स्पूफिंग तकनीक से लोगों को शिकार बनाना शुरू किया। वे सोशल मीडिया अकाउंट में घुसपैठ करके धन की उगाही करने लगते। व्यक्ति को संकट में दिखाकर उसके रिश्तेदारों से धन ऐंठने लगते। विडंबना यह है कि साइबर ठगी की तकनीक उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों और ई-मेल खातों तक भी पहुंच गई। दरअसल, कभी हैकिंग, तो कभी स्पूफिंग के कपटपूर्ण छल का मकसद लोगों की जमा-पूंजी को निशाना बनाना ही रहा है। दरअसल, जब तक लोग ठगी के इन तौर-तरीकों को समझ पाते, साइबर ठग नई तकनीक के सहारे लोगों को भ्रमित कर चूना लगाने की नई कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के बीच सवाल उठता है कि हमारा तंत्र इन घटनाओं में पर प्रभावी रोक लगाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता। आखिर फोन व कंप्यूटर में मजबूत एंटी वायरस और इंटरनेट सुरक्षा सॉफ्टवेयर क्यों कामयाब नहीं होते। आखिर क्यों साइबर घुसपैठ के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती। इन पर रोक के लिए कोई कारगर व्यवस्था व मैकेनिज्म क्यों नहीं बन पा रहा है। दूरसंचार नियामक ट्राई की अपनी सीमाएं हैं। संकट यह भी है कि ज्यादातर साइबर अपराध की घटनाएं प्रॉक्सी यानी छद्म सर्वर या फिर वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिये अंजाम दी जाती हैं। ज्यादातर अपराध भारत के बाहर से संचालित होते हैं। यही वजह है कि जालसाज विदेश में बैठकर भी भारत के अपराधियों की मदद से धोखाधड़ी का नेटवर्क बना लते हैं। इससे वे भारतीय नागरिकों को चपत लगाने में सफल हो जाते हैं। निस्संदेह, ऐसे मामलों में व्यक्तिगत सावधानी और सजगता-सतर्कता मददगार साबित हो सकती है। खासकर इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते वक्त अतिरिक्त सावधानी से ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लोगों को याद रखना चाहिए कि कभी बैंक का कोई अधिकारी खाताधारक से निजी व गोपनीय जानकारी नहीं पूछता है। वो कभी फोन व ई-मेल से ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। इसलिए जरूरी है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक खाते की सुरक्षा से जुड़े पासवर्ड,पिन, सीवीवी तथा खाता नंबर की जानकारी मेल या फोन से मांगता है तो उसे नजरअंदाज करना चाहिए। ऐसी ही सावधानी हाऊस अरेस्ट के मामलों में भी बरतनी चाहिए। साथ ही असली-नकली वेबसाइट की सावधानी से जांच करनी चाहिए।

बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए समन्वित प्रयास अनिवार्य तथ्य

गणेश दत्त पाठक

मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह (04 से 12 अक्टूबर) के संदर्भ में विशेष आलेख

वर्तमान डिजिटल क्रांति के दौर में मानसिक व्याधियों का दायरा भारत में भी बढ़ता जा रहा है। विभिन्न रिपोर्टों की मानें तो भारत में करीब 15 फीसदी लोग यानी तकरीबन 19.73 करोड़ लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। तनाव, चिंता, अवसाद, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों की हकीकत है। मानसिक व्याधियां जिस तरह से शरीर को कमजोर कर रही है और उसका दुष्प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ रहा है। उसको देखते हुए अब मानसिक सशक्तिकरण वैश्विक पहल बन चुका है। कई अंतराष्ट्रीय वैश्विक सामुदायिक संस्थाएं जन जागरूकता जैसे बड़े अभियानों को संचालित कर रही है। इस बार 04 से 12 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत जागरूकता के विविध आयोजन होने जा रहे हैं, जो समय की आवश्यकता भी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है, जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने और काम करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। परन्तु मानसिक अस्वस्थता की स्थिति अपने देश में चिंतनीय स्तर पर पहुंचती जा रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015- 16 के मुताबिक भारत में लगभग 10.6 फीसदी आबादी मानसिक रुग्णता की शिकार है। कई लोग यह मानते ही नहीं कि उन्हें कोई मानसिक व्याधि भी है जबकि वह किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं। एक अन्य अनुमान के मुताबिक देश में 7.22 लाख से अधिक लोग मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं जबकि 15 लाख से अधिक लोगों में बौद्धिक अक्षमता है। युवा का बढ़ता स्क्रीन टाइम और डिजिटल एडिक्शन मानसिक व्याधियों के एक नए दौर को जन्म देता दिख रहा है। युवा पीढ़ी की नींद डिजिटल उपकरणों के प्रयोग करने के कारण पूरी नहीं होने के वाकए सामने आ रहे हैं। डिजिटल उपकरणों का अधिक इस्तेमाल तनाव और अवसाद को बढ़ा रहा है। 2021 में देश में आत्महत्या की दर जो 4.2 प्रतिशत थी वह बढ़कर 2022 में 12.4 प्रतिशत प्रति एक लाख जनसंख्या हो गई। इस संदर्भ में एक नकारात्मक तथ्य यह भी है कि इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री के अनुसार देश में प्रति एक लाख नागरिकों पर मात्र 0.75 फीसदी मनोचिकित्सक हैं। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कम से कम एक लाख नागरिकों पर तीन मनोचिकित्सक होने चाहिए। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का आवंटन कुल सरकारी स्वास्थ्य व्यय का मात्र 1.3% है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और भी कम है। महंगे इलाज और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता का अभाव भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत में मानसिक व्याधियों के विस्तार के प्रमुख कारण बढ़ता तनाव, और दवाब, खराब जीवनशैली, शारीरिक सक्रियता का अभाव, अनियमित खान पान, जागरूकता का अभाव है।

ये मानसिक अक्षमता देश के भविष्य पर बेहद नकारात्मक असर डाल रही है। मानसिक अस्वस्थता व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर रही है। पारिवारिक रिश्तों में तनाव, सामाजिक अलगाव को हर स्तर पर महसूस किया जा रहा है। मानसिक तनाव आदि का नकारात्मक असर सेहत पर पड़ रहा है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग के मुख्य कारक के तौर पर तनाव एक वैज्ञानिक तौर पर स्थापित तथ्य है। तनाव, अवसाद का नकारात्मक असर शिक्षा, कौशल विकास और कैरियर निर्माण पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। अपने देश में मानसिक व्याधियों को कलंक के तौर पर माना जाता रहा है। मानसिक व्याधियों से ग्रस्त व्यक्तियों को पागल करार दे दिया जाता है जो बेहद गलत अवधारणा है। खराब मानसिक स्वास्थ्य का नकारात्मक असर उत्पादकता, दक्षता पर भी पड़ता है।

हालांकि मानसिक विकारों के बढ़ते बोझ को देखते हुए भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक देशव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देकर छात्रों में आत्महत्या को बढ़ावा देकर घटाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों मसलन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची सहित 47 सरकार संचालित मानसिक अस्पताल सेवारत हैं। आयुष्मान भारत के तहत सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्रथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है। दिव्यांग जनों के अधिकार अधिनियम, जिसने दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 का स्थान लिया, ने मानसिक बीमारी को शामिल करने के लिए दिव्यांगता की परिभाषा का विस्तार किया और मनोसामाजिक दिव्यांगजन के लिए मजबूत कानूनी सुरक्षा की मदद की। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भी पारित कर मानसिक बीमारियों के व्यक्तियों की गरिमा और उनके अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए 2020 से आई जी ओ टी दीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ काम किया जा रहा है। 2022 से नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यानी टेली मानस भी योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 भी संचालित की जा रही है जिसका उद्देश्य आत्महत्या की दर को कम करना है। परन्तु राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 की माने तो देश में मानसिक विकारों से पीड़ित 85 फीसदी लोग उपचार से वंचित हैं। जबकि गंभीर मानसिक व्याधियों से ग्रस्त 73.6 फीसदी लोगों को उपयुक्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। आवश्यकता भारत में जागरूकता के अभियान को मजबूत करने कार्यबल के प्रशिक्षण व्यवस्थाओं को सहेजने, डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य समाधानों में निवेश करने, सामुदायिक मानसिक आरोग्य संरक्षण पहलों को प्रोत्साहित करने की हैं।

भारत वर्तमान में डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में डिजिटल समाधानों से व्यापक स्तर पर मानसिक विकारों से पीड़ित मरीजों को सहायता पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल माध्यम से उपचार की व्यवस्था सस्ती, सुलभ और व्यापक होती है। किरण हेल्पलाइन, मानस मित्र, टेली मानस जैसे डिजिटल समाधान अच्छे परिणाम दे रहे हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि शैक्षणिक संस्थानों के लिए विशेष योजनाओं के संचालन की दरकार है। बच्चों में मानसिक व्याधियों के बारे में जागरूकता के संचार के लिए नियमित तौर पर निबंध, भाषण, चित्रकला, पेंटिंग आदि स्पधाओं का आयोजन होना चाहिए। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के स्तर पर नियमित अंतराल पर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है।

आवश्यकता सामुदायिक संस्थानों के योगदान के प्रोत्साहन की भी है। सिवान जैसे छोटे शहर में डॉक्टर शाहनवाज आलम के नेतृत्व में संचालित यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के तत्वावधान में संचालित सर सैय्यद रिफॉर्मेशन सेंटर द्वारा मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन के संदर्भ में बेहतरीन प्रयास किया जा रहा हैं। इस संस्था द्वारा मानसिक विकार से ग्रस्त मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा और परामर्श सुविधा प्रदान किया जा रहा है। जिसका लाभ प्रतिवर्ष हजारों लोग उठा रहे हैं। यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, संस्कार भारती, विद्याभारती जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों को और सराहना की दरकार है।

सबसे बड़ी पहल परिवार के स्तर पर करने की आवश्यकता है। परिवार के सभी सदस्य डिजिटल उपकरणों के साथ व्यस्त रहते हैं। पारिवारिक संवाद की प्रथा को बढ़ाने की दरकार है।

साथ ही बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में युवाओं के स्तर पर स्वबोध को जागृत करने के प्रयास हो तो इसके भी सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। स्वबोध से आशय यह है कि हर युवा अपने खूबियों और कमियों को पहचाने और आत्म मूल्यांकन का प्रयास करे। इससे युवा का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तनाव का सामना करने की शक्ति भी हासिल होगी। साथ ही हर युवा को स्व के शरीर पर ध्यान देने यानी व्यायाम, प्राणायाम, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद लेने की आदत, स्वच्छता के पालन, अच्छी किताबों और डिजिटल कंटेंट को पढ़ने की आदत विकसित करने की जरूरत है। स्वच्छ हवा में श्वास लेने से उसके प्राण तत्व को भी शक्ति हासिल होगी। मेडिटेशन आदि से उसके मन पर नियंत्रण की स्थितियां भी सृजित होंगी।

मानसिक विकारों से ग्रस्त व्यक्तियों का दायरा बढ़ना एक बेहद नकारात्मक तथ्य है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के योगदान से ही राष्ट्र सशक्त और जीवंत बन सकता हैं। मानसिक व्याधियों को कलंक समझने की अवधारणा को दूर करने, जागरूकता के प्रसार की नितांत आवश्यकता है। समन्वित और सार्थक प्रयास देश में मानसिक सशक्तिकरण की दिशा में अच्छे परिणाम दिला सकते हैं। व्यक्तिगत कल्याण, आर्थिक विकास और राष्ट्र की उन्नति के लिए मानसिक रूप से सक्षमता एक अनिवार्य तथ्य है।

संगीत-अध्यात्म एकाकार हो जाते थे उनकी ठुमरी में

विजय विनीत

लेखक वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार हैं

भारतीय संगीत की परंपरा ऐसी है जिसमें हर स्वर केवल ध्वनि नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव होता है। यह अनुभव पीढ़ी-दर-पीढ़ी बहता आया है, जैसे गंगा की धारा कभी सूखती नहीं, वैसे ही राग-रागिनियों की धारा भी प्रवाहित रहती है। इसी प्रवाह में एक स्वरयोगी थे–पंडित छन्नूलाल मिश्र। जिनका जाना भारतीय संगीत-जगत के लिए एक गहरी रिक्तता है। वे केवल गायक नहीं थे, बल्कि संगीत के उस भावलोक के रक्षक थे, जहां शास्त्र और लोक एक-दूसरे में घुल-मिल जाते हैं।

मिश्र जी के निधन से ऐसा लगा मानो बनारस की गलियों से कोई दीप अचानक बुझ गया हो। लेकिन उनकी आवाज का उजाला कभी खत्म नहीं होगा। उनकी गायकी, उनकी ठुमरियां, उनके भजन और उनकी अमर रचनाएं पीढ़ियों तक सुनाई देती रहेंगी।

पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म उ.प्र. के आजमगढ़ की साधारण भूमि पर हुआ। संगीत उनके परिवार की परंपरा नहीं थी। बचपन के दिनों में गांव के आंगन में गूंजते भक्ति गीत, मां-बहनों की मधुर स्वर-लहरियां और मंदिरों में उठते कीर्तन उनकी आत्मा में गहरे उतरते गए। यह वही बीज थे, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें स्वर-साधना की ओर मोड़ा। पंडित छन्नूलाल का बचपन मिट्टी की सोंधी गंध और गांव की सहज संस्कृति में बीता। तभी उनकी गायकी में हमेशा मिट्टी की सुगंध रही। एक ऐसी सुगंध, जो श्रोता को सीधे उसकी जड़ों तक पहुंचा देती थी।

गुरुजनों की शरण में पहुंचकर उन्होंने किराना घराने की बारीकियों को आत्मसात किया। यहां उन्होंने सीखा कि एक स्वर मात्र ध्वनि नहीं, बल्कि साधना है। किराना घराना स्वर की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है और मिश्र जी ने इसे जीवन भर अपने गले में संजोए रखा। लेकिन उनकी आत्मा को असली घर मिला बनारस में। बनारस की गलियां, घाट और मंदिर उनके जीवन का संगीत बन गए। पंडित मिश्र ने एक बार कहा कि ह्वबनारस की मिट्टी और गंगा का जल यदि गले में उतर जाए तो आवाज अपने आप पवित्र हो जाती है ह्ल यह उनका अनुभव था। वे जब ठुमरी गाते, तो उसमें केवल सुर ही नहीं होते, बल्कि बनारस का समूचा वातावरण उतर आता।

कल्पना कीजिए–गंगा की लहरों पर डूबते सूरज की किरणें, घाटों पर गूंजती आरती और गलियों से आती ठहाकों की आवाजें। यही बनारस है और यही बनारस उनकी ठुमरी में बसा रहता था। उनकी आवाज सुनकर श्रोता को लगता कि वह स्वयं गंगा किनारे बैठा है, जहां संगीत और अध्यात्म एकाकार हो जाते हैं।भारतीय शास्त्रीय संगीत में ठुमरी को सबसे कोमल विधा माना जाता है। इसमें शृंगार का रस भी है और भक्ति का आह्वान भी। पंडित छन्नूलाल ने ठुमरी को केवल गाया नहीं, बल्कि जिया। उनके गायन में ह्वपुरब अंग की ठुमरीह्ल की झलक सबसे अधिक मिलती थी। यह ठुमरी भोजपुरी लोक संवेदना से उपजी थी, जिसमें लोक की मिठास और सहजता समाई रहती है।

जब वे गाते, ह्वमोरे सैयां बुलावे अदरसियाङ्गह्ल, तो श्रोता के हृदय में एक कंपन उठता। ऐसा लगता मानो यह गीत केवल गले से नहीं, आत्मा से निकला हो। वह सुरों को सिर्फ साधते नहीं थे, उन्हें आत्मा में जीते थे।पंडित छन्नूलाल की गायकी का सबसे अनोखा और अमर योगदान था, ह्वमसाने की होली ह्ल यह गीत केवल एक रचना नहीं, बल्कि बनारस की संस्कृति का जीवंत दर्शन है। बनारस वह शहर है, जहां मृत्यु भी जीवन का उत्सव बन जाती है। जहां श्मशान भी साधना का स्थान है। जब होली जैसी रंगों की बौछार वाला पर्व इस संस्कृति से मिलता है तो जन्म लेती है-मसाने की होली।

पंडित मिश्र की आवाज में जब यह गीत गूंजता, तो श्रोता खुद को श्मशान घाट पर पाता–जहां राख में भी रंग है और मृत्यु में जीवन का उल्लास। इस गीत ने यह सिद्ध कर दिया कि होली केवल गुलाल और रंगों की मस्ती नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लेने वाला उत्सव है। ह्वमसाने की होलीह्ल वर्षों से होली मिलन समारोहों, सांस्कृतिक मंचों और लोक उत्सवों का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। इसका श्रेय पंडित मिश्र को जाता है।

पंडित छन्नूलाल की गायकी का सबसे बड़ा गुण यह था कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन मानस से जोड़ा। उनकी ठुमरियों में भोजपुरी और अवधी का रस होता था। यह लोकजीवन की आत्मा थी। जब वे इन भाषाओं में गाते, तो गांव-गली का श्रोता भी उनसे जुड़ जाता। फलतः वे हर घर-आंगन के गायक बन गए।

पंडित छन्नूलाल सिर्फ गायक नहीं, बल्कि कथावाचक भी थे। उनके गायन में हमेशा संवाद की छटा होती थी। जब वे गाते, तो श्रोता को लगता कि जैसे कोई उनसे सीधे बातें कर रहा है। यही कारण था कि उनकी ठुमरियां कहानी जैसी प्रतीत होती थीं–कभी श्रृंगार की, कभी विरह की तो कभी भक्ति की। उनकी आवाज में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सहज संगम था। वे भजन गाते तो लगता कि ईश्वर हमारे सामने खड़े हैं और ठुमरी गाते तो लगता कि प्रेमिका अपने प्रिय की बाट जोह रही है।

पंडित मिश्र को वर्ष 2010 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत किया। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जनता का प्रेम था। पंडित मिश्र के शिष्य आज देश-विदेश में भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ठुमरी को लोक से जोड़ा।

आज जब पंडित छन्नूलाल हमारे बीच नहीं हैं, तो यह एक युग का अंत है। उनकी गायकी आने वाली पीढ़ियों के लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाती रहेगी। जब भी गंगा किनारे कोई ठुमरी गाई जाएगी, जब भी कोई मंच पर ह्वमसाने की होलीह्ल गूंजेगी, तो लगेगा मानो पंडित मिश्र वहीं बैठे हों, अपनी मुस्कान के साथ, सुरों की तपस्या करते हुए। सच यही है–वे नहीं गए। वे तो हर ठुमरी, हर भजन और हर गली की गूंज बनकर अमर हो गए हैं।

https://t.me/AllNewsPaperSPaid1

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

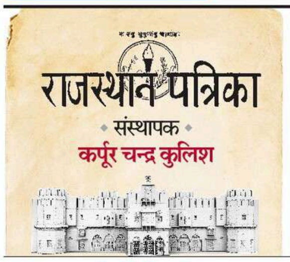

दवा निर्माण की निगरानी में सख्ती ज्यादा जरूरी

दवा जब जहर बन जाए तो मरीजों की जान मुसीबत में पड़ सकती है। राजस्थान व मध्यप्रदेश में जानलेवा कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मामले सचमुच झकझोरने वाले हैं। बच्चों की मौत की इन घटनाओं ने फार्मा कंपनियों व दवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने वाली एजेंसियों पर सवाल खड़ा किया है। साफ लगता है कि लालच को सिर चढ़ाकर बैठी फार्मा कंपनियों को सिर्फ अपने मुनाफे की परवाह है इसलिए वे निगरानी तंत्र को भी अपने जाल में फांसने से नहीं चूकतीं। एक के बाद एक जानलेवा बनी दवा के सेवन से होने वाले घटनाओं के बाद भी जिम्मेदारों पर सख्ती नहीं होना तो और भी चिंताजनक है।

जानलेवा कफ सिरप से राजस्थान में दो और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नौ बच्चों की मौत को सामान्य घटना नहीं माना जाना चाहिए। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र(एनसीडीसी) की जांच में सिरप के नमूनों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक कूलेंट पाया गया। यह किडनी फेलियर का कारण भी बनता है। हैरत की बात यह है कि जांच में सवाल खड़े होने पर भी दवाओं को जहर के रूप में बदलने वाली फॉर्मा कंपनियां अपने बचाव के तमाम दांवपेच बनाने में जुटी रहती हैं। राजस्थान में तो जिस कंपनी का कफ सिरप बच्चों की मौत की वजह माना जा रहा है वह तो पिछले पन्द्रह बरस से जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में जुटी है। दवा की गुणवत्ता को लेकर यह कंपनी तीन साल पहले भी विवाद में आई थी और 2022 में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (आरएमएससी) ने इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसे मिलीभगत का ही खेल कहा जाएगा कि ब्लैकलिस्ट कंपनी फिर से सरकारी योजनाओं में घुसपैठ करने में कामयाब हो गई। दरअसल फार्मा लॉबी के नियामक एजेंसियों पर भारी पड़ने के एक नहीं, कई उदाहरण हैं। वर्ष 2019-20 में जम्मू के रामनगर में भी एक फार्मा कंपनी के बनाए सिरप से 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया था। कंपनी पर मुकदमा चला, लेकिन चार साल बाद भी अभी तक किसी को सजा नहीं हुई। वर्ष 2022 में ही हरियाणा की एक फार्मा कंपनी के सिरप से गाम्बिया में 70 व उज्बेकिस्तान में 65 बच्चों की मौत का मामला सुर्खियों में आया था। इसके चलते न केवल इस फार्मा कंपनी का आयात लाइसेंस रद्द हुआ बल्कि उसे लाखों डॉलर हर्जाना भी देना पड़ा। जबकि हमारे यहां इस कंपनी पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं हुई।

चिंता इस बात की भी है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत सिरप में डीईजी जैसा तत्त्व वर्जित है फिर भी दवा कंपनियां इस्तेमाल कर रहीं हैं। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के पास महज 100 ही इंस्पेक्टर हैं। मजबूरन केंद्र ने जांच की जिम्मेदारी राज्यों पर ही छोड़ दी है। ऐसे मामलों में हर मौत पर आपराधिक मुकदमा तो हो ही, मुआवजे का प्रावधान जरूरी करने के साथ दवा निर्माण की निगरानी की व्यवस्था भी सख्त करनी होगी।

माया प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति ही ब्रह्म और माया को आवृत रखती है ताकि इनके स्वरूप को जाना न जा सके। प्रकृति से पार पाना मुक्ति का द्वार खोलता है। त्रिगुणमयी प्रकृति के कारण माया भी गुणयुक्त नजर आती है, किन्तु वह गुणातीत है।

माया का उछाल

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

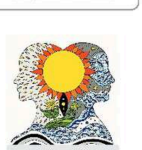

शरीर ही ब्रह्माण्ड

ब्रह्म और माया ही शक्तिमान और शक्ति रूप में विश्व निर्माण में प्रवृत्त होते हैं। ये दोनों अभिन्न हैं। इनका समन्वय ही पूर्णता है। ब्रह्म और माया दोनों में ही कर्ता भाव नहीं हैं। माया की भूमिका चूंकि ब्रह्म के विस्तार से जुड़ी है, अतः इसका कार्यक्षेत्र दाम्पत्य कर्म से (प्रजनन कर्म) से जुड़ा रहता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है-

अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्।
इह प्रजामिह रयिं रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम॥ (10.183.1)

पति से पत्नी कह रही है–मैंने बुद्धि से कर्मों को अत्यधिक रूप से जानने वाले, दीक्षा रूप व्रत से पुनः उत्पन्न हुए (दूसरे पूर्व जन्मों के अनुष्ठान किए हुए पुण्य से उत्पन्न हुए) तथा अनुष्ठान किए जाते हुए यज्ञों के कारण सर्वत्र विख्यात तुम्हें देखा। हे पुत्रों की कामना करने वाले! वही तुम इस लोक में पुत्र पौत्रादि संतान का आनन्द लेते हुए गर्भाधान के द्वारा पुत्र-पौत्रादि के रूप से प्रजा उत्पन्न करो।

पति उत्तर देता है–हे पत्नी! अपने सौन्दर्य से दीप्तियुक्त शरीर में गर्भाधान रूप कर्म के लिए पति समागम की याचना करते हुए तुम्हें मैंने बुद्धि से देखा। हे पुत्रों की कामना करने वाली! मेरे समीप आकर अत्यधिक तरुणी हो जाओ। तरुणी होकर गर्भाधान के द्वारा पुत्रों को उत्पन्न करो। (10.183.2)

अगला मंत्र कहता है–मैं होता रूप शाल्यादि औषधियों में फल के लिए गर्भाधान करता हूं। मैं ही अन्य सभी प्राणियों में गर्भ धारण करता हूं तथा भूमि पर सब मनुष्यों को उत्पन्न करता हूं। अन्य स्त्रियों में भी मैं पुत्रों को उत्पन्न करता हूं। मेरे द्वारा किए जाने वाले यज्ञ से सब की उत्पत्ति होने के कारण मैं सबकी उत्पत्ति का मूल स्रोत हूं। (10.183.3)

प्रजा उत्पत्ति कर्म सभी 84 लाख योनियों में होता है। माया तय करती है कि जीवात्मा को किस योनि में जाना है। जीव किसी भी योनि में जन्म ले किन्तु सृष्टि के सभी तत्व उसके उपादान बनते हैं। देह का निर्माण एक असाधारण प्राकृतिक प्रक्रिया है। दैहिक अंगों के निर्मापक देव भिन्न-भिन्न होते हैं। जीव किस योनि में कौनसी देह धारण करेगा, उसी के अनुरूप देवता अपने-अपने कर्म में जुट जाते हैं। प्रजनन क्रिया कहने को स्थूल क्रिया मात्र है किन्तु सभी देव, पितृ, ऋषि प्राण रूप में इस कर्म में जुड़ते हैं। ब्रह्म सृष्टि रूप में गर्भस्थ होने को, अवतरित होने को उन्मुख हो रहे हैं। ऋग्वेद में वर्णित है कि-

व्यापक देव विष्णु योनि का निर्माण करें। शरीर निर्माता त्वष्टा देव स्त्री-पुरुष के व्यंजक चिह्नों को अंग रूप प्रदान करें। प्रजापति वीर्य सींचन करे। हे पत्नी धारण करने वाले धाता देव तुम्हारे गर्भरूप को धारण करे। तुम स्रावपात वाली और गर्भपात वाली न हो। (10.184.1)

हे सिनीवाली देवी! स्थापित गर्भ को धारण करो। हे सरस्वती! तुम गर्भ को स्थापित करो। हे पत्नी! स्वर्ण कमल के आभूषण धारण करने वाले दोनों अश्विनी कुमार तुम्हारे गर्भ का उत्पादन करें। प्रक्षेपण करें। (10.184.2)

हे पत्नी! तुम्हारे जिस गर्भ को उद्देश्य बनाकर दोनों अश्विनी कुमार देवों ने स्वर्णमयी अरणियों का मंथन किया, 'तुम्हारे लिए' हम उस गर्भ का दसवें माह में प्रसव होने के लिए आह्वान करते हैं। (ऋ. 10.184.3)

ऋग्वेद के ये मंत्र सृष्टि के सार्वभौमिक, सार्वकालिक सूत्र हैं। यही 'यथाण्डे तथा ब्रह्माण्डे' का रूप है। यहां ब्रह्म-माया ही दाम्पत्य भाव में हैं। विभिन्न देव सृष्टि को स्वरूप देते हैं, रक्षा करते हैं। यहां सिनीवाली देवता विशेषतः प्रजनन क्षमता और सहज प्रसव की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। संतति प्राप्ति में ये दोनों कर्म अति महत्त्वपूर्ण हैं। यहीं एक अन्य मूल तत्त्व का स्पष्टीकरण भी हो जाना चाहिए कि सृष्टि किसी भी योनि की हो, दाम्पत्य भाव केवल ब्रह्म और माया का ही होगा।

गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्॥ (गीता 9.18)

अर्थात् प्राप्त करने वाला परम धाम, भरण-पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ देखने वाला, बिना अपेक्षा के हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति-प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, अविनाशी कारण (बीज) भी मैं हूं (गीता 9.18)। कैसा आश्चर्य है?

सभी शास्त्र एक ही बात कहते हैं–ब्रह्म और माया ही 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। माया ही किसी भी योनि तक पहुंचने का साधन बनती है। वह ब्रह्म को एक योनि से दूसरी योनि तक पहुंचाती है। वह मोक्ष की ओर धकेलने की शक्ति भी बनती है। माया का आश्रय कारण शरीर है। जब तक जीवन परा-अपरा के हाथों चलता रहता है, माया दर्शक बनी रहती है।

पंचमहाभूत मन, बुद्धि, अहंकार को अपरा प्रकृति कहा है। दूसरी ओर जीवरूप पराप्रकृति है। माया प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति ही ब्रह्म और माया को आवृत रखती है ताकि इनके स्वरूप को जाना न जा सके। प्रकृति से पार पाना मुक्ति का द्वार खोलता है। त्रिगुणमयी प्रकृति के कारण माया भी गुणयुक्त नजर आती है, किन्तु वह गुणातीत है। क्योंकि माया तो ब्रह्म के साथ रहती है, कामना रूप में।

व्यक्ति संकल्प करके अपरा के बाहर जाने अथवा जीने का प्रयास करता है, प्राणों की क्रिया के माध्यम से। इसी से परा प्रकृति के हृदय में स्थित तीनों गुणों में भी स्पन्दन शुरू हो जाता है। हृदय में ब्रह्मा, विष्णु और इन्द्र की शक्तियों के साथ परम गुरु की भी स्थिति होती है। वही गुणातीत अवस्था का प्रेरक तत्त्व होता है। जीवात्मा अश्वत्थ के ऊपरी अमृत भाग की ओर अग्रसर होता है। यही माया के क्षेत्र में प्रवेश है। मुक्ति साक्षी क्षेत्र शरीर में भी प्राण गुणातीत होकर हृदय से ऊपर उठते हैं तो भ्रू-मध्य में द्वि-दल कमल रूप अथवा प्रकृति के आगे परात्पर तत्त्व का प्रवेश द्वार है। यहीं चारों ओर गहन अंधकार का समुद्र है। यही माया का बुद्बुद् रूप-अव्यय पुरुष है। यहां यजुः पुरुष होते हुए भी ऋत भाव में है। ऋक् केन्द्र, परिधि (वाक्) ही साम है। स्वयं की यह वाक् ही ऋत रूप ब्रह्म की प्रथम सत्यावाक् है। ऋत ही मानसिक सत्य है। संकल्प ऋत है, यथार्थ वाणी सत्य है। **'ऋतं च सत्यं चाभीद्धात...'** का भी अर्थ यही है कि ब्रह्मा ने तप करके (ज्ञानमय) ऋत और सत्य उत्पन्न किए। उसी से जल समुद्र उत्पन्न हुआ। तप प्राणों का होता है। मन की कामना का, रचना करने योग्य का पर्यालोचन करना है। ''ब्रह्मा ने तप द्वारा इस सबको रचा।'' तै.आ.। यजुः ही प्रथम सत्य रूप अव्यय बना। यही मायाधिष्ठान भूत अव्यय भावी सृष्टि का उपादान बनता है।

भ्रू-मध्य का तप विशेष होता है। क्योंकि यह कारण शरीर का क्षेत्र है। माया का तप के प्रभाव से चलन होता है। बुद्बुद् की परिधि तप से संकुचित होती जाती है। बुद्बुद् जल शरीर है। यह जल ही श्रद्धा कहलाता है जो कि माया का ही पर्याय है। यही बुद्बुद् माया रूप आवरण है, ब्रह्म का। तप के प्रभाव से छोटा होते-होते मातरिश्वा वायु के द्वारा ब्रह्म के बिन्दु भाव में समा जाता है। अर्द्धनारीश्वर बन जाते हैं। षोड़शकल जीवात्मा की सारी कलाएं लीन हो जाती हैं। परात्पर की अर्द्धकला नई सृष्टि की ओर पुनः उद्बुद् हो उठती है।

-क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

स्त्रीः देह से आगे

विषय विवेचन

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ***गुलाब कोठारी*** के संबोधन का वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

आपकी बात

शक्ति और स्त्री तत्त्व का समन्वय

'मां ही संस्कृत है- संस्कृति है!' शीर्षक से पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के आलेख में स्त्री तत्त्व को ब्रह्म तत्त्व के साथ अद्भुत रूप से समाहित किया गया है। यह दृष्टि विलक्षण और प्रेरणादायी है। आलेख में वेद-आधारित स्त्री-तत्त्व को केवल सीमित परिभाषाओं तक ही नहीं रखा गया बल्कि उसे सर्वव्यापी, विराट और अनन्त आयाम प्रदान किए गए हैं। कोठारी के आलेखों के माध्यम से शक्ति और स्त्री तत्त्व का ऐसा गहन समन्वय मिलता है, 'जहां शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शक्ति' इसमें अद्वैत सत्य का आलोक जगमगाता है। यह सामंजस्य हृदय और बुद्धि दोनों को एक साथ आंदोलित करता है।

- स्वामी अवधेशानंद गिरि, *जूनापीठाधीश्वर आचार्यमहामण्डलेश्वर*

गरबा का गीता से जुड़ाव

गुलाब कोठारी के 'गरबाः जीवन की गीता' शीर्षक आलेख में बताया गया है कि निराकार ब्रह्म को माया के द्वारा ही सत्य और साकार रूप प्रदान किया गया है। गरबा नृत्य के छिद्र-कलश और आत्मा का माया निर्मित शरीरस्थ इन्द्रियों के माध्यम प्रकाशित होने से जुड़ा तथ्य गीता के व्यावहारिक और वैज्ञानिक उपदेशों का तादात्म्य निरूपण करता है। आलेख में सही कहा है कि इस भौतिक सृष्टि में मां और माया निर्मित साकार ब्रह्मा तथा निराकार ब्रह्म की अद्वितीय भूमिका है। आत्मा सूर्य है विवस्वान् है। आत्मा वै जायते पुत्रः। अतः हम सब सूर्य पुत्र हैं। अपने इसी स्वरूप को समझ गीता को समझा जा सकता है। इस तरह के आलेख भविष्य की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक परम्परा में एक समन्वयात्मक क्रांतिकारी स्वरूप में प्रतिष्ठित होंगे।

- प्रो. राम सेवक दुबे, *पूर्व वाइस चांसलर, ज.रा.रा. संस्कृत विश्वविद्यालय*

बुक इनसाइट

क्लाउन टाउन

मिक हेरॉन की किताब क्लाउन टाउन एक रोमांचक जासूसी उपन्यास है। मिक हेरॉन पहले से ही अपनी स्लो हॉर्सेज सीरीज के लिए प्रसिद्ध हैं और इस नई किताब में भी उन्होंने वही तेज-तर्रार अंदाज और गहरी कहानी कहने की शैली बरकरार रखी है। यह किताब अपने तेज कथानक और रहस्यमयी माहौल के लिए खास है। कहानी एक गहरे षड्यंत्र के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां जासूस और खुफिया एजेंट्स की दुनिया में अनोखे मोड़ आते हैं। मिक हेरॉन ने अपने पात्रों को इतनी

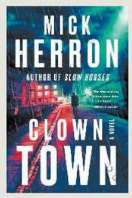

खूबसूरती से गढ़ा है कि पाठक उनके साथ हर कदम पर चलता है। किताब में एक छोटे से शहर की पृष्ठभूमि है, जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं और हर पन्ने पर रहस्य गहराता जाता है। लेखक की शैली में हल्का व्यंग्य और तीखी टिप्पणियां भी मिलती हैं, जो इसे रोचक बनाती हैं। कहानी आधुनिक जासूसी दुनिया की परतों को खोलती है।

वीजा संकट हमने उनकी सेवा की, अब वे हमें नहीं चाहते

एच-1बी वीजा जो एक आसान अवसर था, फंदा साबित हुआ

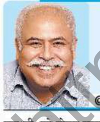

जगदीश रत्तनानी
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

अमरीकी राष्ट्रपति के आदेश से हर एचवबी वीजा प्रविष्टि पर एक लाख डॉलर का भारी-भरकम शुल्क अभी तक मजबूत और स्थिर दिखती रही व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। आदेश का मकसद भले ही भारत को चोट पहुंचाना न हो, लेकिन इससे जो झटका, पीड़ा और अनेक चुनौतियां पैदा होंगी। इससे आइटी सेवाक्षेत्र जैसे बड़े उद्योग की गाड़ी पटरी से उतर सकती है।

अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उस समय पांच लाख 83 हजार 420 एचवबी वीजाधारक अमरीका में कार्यरत थे। परिवार और आश्रितों सहित यह संख्या दस लाख से अधिक आंकी गई। चूंकि इनमें से लगभग तीन-चौथाई भारतीय हैं। इससे समस्या की गहराई और उसका भारत-केंद्रित स्वरूप स्पष्ट होता है। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण आया कि शुल्क केवल नए वीजा पर लागू होगा (हर साल लगभग 85,000 नए एचवबी दिए जाते हैं), मौजूदा वीजा पर नहीं।

भारत के विदेश मंत्रालय ने सही ही कहा है कि इससे कामगारों और उनके परिवारों पर मानवीय असर पड़ेगा। भले ही वर्तमान वीजा धारक तुरंत प्रभावित न हों, लेकिन तीन साल पर होने वाले नवीनीकरण की अनिवार्यता से उनका भविष्य अधर में है। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों में एचवबी को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। यह धारणा मजबूत हो रही है कि इस वीजा का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर प्रतिभाओं को आकर्षित करने के मूल उद्देश्य के बजाय अमरीकी श्रमिकों की जगह विदेशी श्रमिकों से कम लागत में काम कराने के लिए हो रहा है। 2023 में राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में दोनों दलों के सांसद मिलकर एचवबी सुधार का विधेयक लाए थे, जिसका उद्देश्य था- अमरीकी श्रमिकों की रक्षा और नौकरियों की आउटसोर्सिंग पर रोक।

यही नाराजगी हालिया आदेश में झलकती है, जिसमें कहा गया- कंपनियां सस्ती विदेशी मजदूरी का लाभ लेने के लिए अपने आइटी डिवीजन बंद कर रही हैं, अमरीकी कर्मचारियों को निकाल रही हैं और नौकरियां विदेशियों को आउटसोर्स कर रही हैं। इससे अमरीकी स्नातकों के लिए आइटी क्षेत्र में रोजगार पाना और कठिन हो गया है। भारत को कठिनाई जरूर होगी, लेकिन हालिया हालात का एक कारण बड़ी अमरीकी कंपनियां भी हैं, जिन्होंने वीजा का फायदा उठाकर लागत घटाई। भारतीय कंपनियों ने हाल के वर्षों में एचवबी पर निर्भरता घटाई है और अमरीकी नागरिकों को रखना शुरू किया है। फिर भी माहौल बदलने से पूरा सेक्टर प्रभावित होगा। 2025 की पहली छमाही के अमरीकी आंकड़े बताते हैं कि टॉप 10 में अब टीसीएस के अलावा शेष सभी नाम अमरीकी दिग्गजों अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट आदि के हैं। इससे साफ है कि समस्या धीरे-धीरे बन रही थी। भारतीय कंपनियों ने आंशिक तौर पर स्थिति से निपटने की कोशिश की, पर अब हालात एक नई चुनौती बन चुके हैं।

भारत और भारतीय कंपनियां आसान अवसरों को चुनते रहे हैं। एचवबी वीजा भी ऐसा ही एक अवसर था, जो अंततः फंदा साबित हुआ। इसने भविष्य के लिए नए उत्पाद और सेवाएं तैयार करने के असली काम से ध्यान भटकाया। आज स्थिति यह है कि भारत और उसका आइटी सेक्टर कहीं भी क्रांतिकारी काम के मोर्चे पर नहीं है। हमने दूसरों की सेवा की, लेकिन अब वे हमें नहीं चाहते और हम खुद नहीं जानते कि आगे किस दिशा में बढ़ें। इसी बीच एआइ की आंधी पूरी दुनिया में नई संभावनाएं रच रही है। यही वे गहरी चिंताएं हैं, जिनके साथ भारत को एचवबी की इस उथल-पुथल से जूझना है।

प्रकृति व तकनीक का बेहतरीन सामंजस्य
जापान की अनोखी पार्किंग

***जापान** में एक सामान्य पार्किंग स्थल को फ्लोटिंग गार्डन में परिवर्तित किया गया है, जो तकनीक और प्रकृति के सामंजस्य का जीवंत उदाहरण है। कारों के ऊपर लगे फूलों और पौधों की छत न केवल दृश्य को खूबसूरत बनाती है, बल्कि इसका एक व्यावहारिक उद्देश्य भी है। गर्म दिनों में ये हरियाली प्राकृतिक छाया प्रदान करके कारों और आसपास के फुटपाथ का तापमान कम करती है। सिर्फ यह ही नहीं, हरे छत वाले बगीचे शहर के पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये वायु को शुद्ध करने में मदद करते हैं और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान देते हैं।*

आर्ट एंड कल्चर

वस्त्र का संस्कृति निर्माण में योगदान

भारतीय संस्कृति में वस्त्र महज एक वस्तु भर नहीं है, बल्कि इसका संस्कृति निर्माण में भी असाधारण योगदान रहा है। बुनाई विश्वभर में विकसित सबसे पुरानी तकनीक है। इसकी शुरुआत आदिम मनुष्य के घर बनाने के साथ ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले मनुष्य ने अपने निवास के लिए लकड़ियों आदि को एकसाथ जोड़ना प्रारंभ किया। धीमे-धीमे घुमंतु प्रजातियों ने बकरी के बालों से अपने लिए तंबुओं का निर्माण किया। शुरुआती दौर में वस्त्र गर्मी और ठंड से बचने मात्र का साधन था। परंतु धीरे-धीरे पोशाकें विकसित होती चली गई और उसका अपना संसार विकसित होता चला गया।

चिन्मय मिश्र
वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी
@patrika.com

भारत में बुनाई की परंपरा अनादि काल से विद्यमान रही है। एक समय यह जीवन का इतना महत्त्वपूर्ण हिस्सा था कि इस तकनीक को कई दार्शनिक और धार्मिक-आध्यात्मिक नाम तक दिए गए। हम सभी 'सूत्र' तो जानते हैं। यह प्राचीन वैदिक और बौद्ध धार्मिक ग्रंथों के कथोपकथन का माध्यम है। यह सूत्र शब्द 'सूत' से लिया गया है, जिससे कि धागों को एकदूसरे से जोड़कर कपड़ा बनता है। ठीक वैसे ही 'गुरु ग्रंथ साहब' का नामकरण भी इसी तकनीक की देन है। ग्रंथ का एक अर्थ गूंथना या बांधना भी होता। सूत को गूंथा जाए तो वह वस्त्र बनता है और यदि ज्ञान गूंथा जाए तो वह भी ग्रंथ में परिवर्तित हो जाता है। पूरे भारत में बुनाई की अनेक तकनीकें विद्यमान हैं। वहीं दूसरी ओर 'रंगाई' को लेकर भी भौगोलिक, सांस्कृतिक प्रभाव को देखा और महसूस किया जा सकता है। रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़, नदी घाटी के साथ तमाम सांस्कृतिक समायोजन और प्रवासी प्रजातियों ने भी वस्त्र के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसे इन उदाहरणों से समझते हैं। भारत के दो दूरस्थ अंचल बंगाल और केरल जबरदस्त हरितिमा वाले जंगलों से भरे पड़े हैं, यहां के पहनावे में 'सफेद' रंग की प्रधानता है। वहीं दूसरी ओर रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें, तो सिंध (अब पाकिस्तान) कच्छ, गुजरात और राजस्थान के अनेक हिस्से जो कमोबेश विस्तारित होकर हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचते हैं, इन इलाकों में बेहद गहरे चटख लाल और गहरे पीले रंग की बहुतायत नजर आएगी। गौरतलब है भारत की लुप्त होती इस बुनाई कला को महात्मा गांधी ने 'खादी' के माध्यम से नई प्राणवायु दी। उन्होंने इस कला और इसमें निहित अपार संभावनाओं को पहचाना और वह इसे भारत की आजादी के संघर्ष में एक 'अहिंसक अस्त्र' की तरह उपयोग में लाए।

समसामयिक विषयों पर पाठकों के विचार आमंत्रित हैं। चुनिंदा विचार प्रकाशित किए जाएंगे।

ईमेल करें: edit@epatrika.com

संघ शताब्दी वर्ष संघ जीवन का सबसे विलक्षण आयाम उसकी प्रचारक परंपरा रही है

राष्ट्रधर्म साधना से अनुशासित व समरस समाज तक की यात्रा

घनश्याम तिवाड़ी
राज्यसभा सांसद
@patrika.com

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा केवल एक संगठन का इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की चेतना का विस्तार और आत्मस्वरूप की नवप्रतिष्ठा है। यह संगठन जन्म के क्षण से ही विचार और साधना का पर्याय रहा है। संघ जीवन का सबसे विलक्षण आयाम उसकी प्रचारक परंपरा रही है।

संघ का प्रचारक अपने व्यक्तिगत जीवन का परित्याग कर संपूर्ण अस्तित्व को राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित करता है। न परिवार की चिंता, न व्यक्तिगत अभिलाषा, केवल राष्ट्रधर्म की तपस्या। यही त्याग संघ की आत्मा रहा। प्रचारक ग्राम और नगर-नगर पहुंचे और संघ की शाखाओं के बीज बोए। संघ का इतिहास चुनौतियों से भी भरा रहा है। तीन बार उस पर प्रतिबंध लगाया गया। संघजन कभी केवल विचार तक सीमित नहीं रहे। जब-जब राष्ट्र पर आपदा आई, संघ के स्वयंसेवक संकटमोचक बनकर खड़े हुए। 1947 के विभाजन में शरणार्थी शिविरों में सेवा से लेकर 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सैनिक परिवारों के सहयोग तक 1975 की आपातकालीन घड़ी में लोकतंत्र की रक्षा से लेकर प्राकृतिक आपदाओं और भूकंप-बाढ़ के समय राहत कार्यों तक, स्वयंसेवकों ने सेवा को ही संगठन का प्राण तत्त्व सिद्ध किया।

इस सेवा ने यह स्पष्ट किया कि शाखा सिर्फ खेल और अनुशासन का स्थान नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में समाज और राष्ट्र के लिए सजग करने का साधन है। संघ की प्रेरणा से अनेक संगठन जन्मे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को एकजुट कर राष्ट्रीय चेतना का संस्कार दिया। विश्व हिंदू परिषद ने धर्म और संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाया। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक परिदृश्य पर राष्ट्रवादी दृष्टि को स्थापित किया।

इस यात्रा में सरसंघचालकों ने भी अपनी-अपनी छाप छोड़ी। संघ की दृष्टि कभी संकुचित नहीं रही। राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई मानना उसके लिए उचित नहीं था। संघ का विचार है कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, जिसकी आत्मा धर्म और संस्कृति से पोषित है। संघ की दृष्टि में अंत्योदय और सामाजिक समरसता सर्वोपरि स्थान रखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सफलता और उसका वैश्विक विस्तार उसकी विशिष्ट कार्यपद्धति में निहित है। यह कार्यपद्धति-समर्थ संगठन, आर्थिक स्वायत्तता, अनुशासन तथा समाज आधारित कार्य ही वह आधार बिंदु है, जिसने संघ को विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बनाया है। संघ की आर्थिक स्वतंत्रता भी इसकी ताकत रही है। कोई भी सरकारी या बाहरी अनुदान स्वीकार किए बिना, 'गुरुदक्षिणा' की परंपरा द्वारा स्वयंसेवकों, नागरिकों और समाज के सहयोग से आवश्यक संसाधन जुटाना, इसकी निस्वार्थ भावना और पारदर्शिता का प्रमाण है। संघ से निकले लोगों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में अद्वितीय योगदान दिया है।

शताब्दी वर्ष स्मृति का नहीं, संकल्प का पर्व है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह यात्रा इस तथ्य का उद्घोष करती है कि राष्ट्र की आत्मा तभी प्रखर होती है जब समाज संगठित, अनुशासित और समरस होता है।

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 4 अक्टूबर 2025

तालमेल चाहिए

मशीनें तो आएंगी, पर इंसान भी रहेंगे

क्या मशीनें इंसानों की जगह ले लेंगी? आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तेज तरक्की के बाद यह सवाल और भी गंभीर हो उठा है। ऐसे वक्त में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल अमर प्रीत सिंह का बयान मशीनों को लेकर फैले डर को कम करने वाला है।

इंसानों की भूमिका । टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने कुछ दिनों पहले ट्वीट किया था कि युद्ध का भविष्य ड्रोन हैं, इंसानों द्वारा संचालित एयरक्राफ्ट नहीं। वायु सेना प्रमुख ने इसी ट्वीट पर साफ किया कि इंसानों की भूमिका बनी रहने वाली है। मानवरहित सिस्टम डिवेलप होंगे, उनका उपयोग बढ़ेगा, लेकिन वे खुद से काम नहीं कर सकते। उनको चलाएगा कोई इंसान ही।

एयर चीफ का बयान

मैन्ड प्रॉजेक्ट । दुनिया के कई देशों में छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम चल रहा है। ब्रिटेन, इटली और जापान मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में लगे हुए हैं। वहीं अमेरिका ने NGAD लॉन्च किया है। चीन के बारे में भी चर्चा है कि वह Chengdu J-36 डिवेलप कर रहा है। और ये सारे प्रॉजेक्ट मैन्ड हैं।

साझेदारी का कमाल । कोई भी युद्ध बेहतर तालमेल और साझेदारी से जीता जाता है - फिर भले ही वह इंसानों और मशीनों के बीच क्यों न हो। भारत समेत कई देशों में अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल वीकल या ड्रोन पर प्रॉजेक्ट चल रहे हैं। इनको लड़ाकू विमानों के साथ टीम में काम करने के लिए ही तैयार किया जा रहा।

ड्रोन का इस्तेमाल । रूस-यूक्रेन युद्ध में ड्रोन की भूमिका दिखी। इसी तरह, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान टकराव में भी ड्रोन अहम भूमिका में रहे। लेकिन, दोनों जगह ड्रोन्स ने तभी बेहतर परिणाम दिया, जब उनका इस्तेमाल सही ढंग से हुआ।

पाकिस्तान को जवाब । वायु सेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को भी दोहराया। हालांकि सेना और सरकार की तरफ से पहले भी देश को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन एयरफोर्स चीफ के बयान की जरूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच तक का इस्तेमाल किया। कोरे दावे संघर्ष में हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते। भारतीय सेना ने तो सबूत सामने रख दिए, पाकिस्तान के पास अगर कुछ है, तो दिखाना चाहिए, वरना झूठे नैरेटिव से उसे ही घाटा होगा।

अंतर्दृष्टि

ये पांच पूंजियां ही देती हैं आपको असली अमीरी

सुंदर चंद ठाकुर

हमारे समय का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अमीरी का अर्थ केवल पैसों से है। जिनके पास करोड़ों हैं, वही लोग अमीर कहे जाते हैं। पर सच यह है कि दुनिया में अनगिनत लोग हैं, जिनके बैंक खाते भरे हैं लेकिन वे भीतर से खाली हैं। वे धन के ढेर पर बैठे हैं, लेकिन जीवन की सबसे कीमती संपत्ति उनसे छिन चुकी है। सबसे पहली और सबसे अनमोल संपत्ति है - शरीर। अगर शरीर थका हुआ है, अस्वस्थ है, तो सोने की थाली में परोसा भोजन भी विष जैसा लगता है। असली अमीरी यह है कि आपका शरीर हर उम्र में चुस्त और फुर्तीला रहे। अगर जीवनभर सही आहार, नियमित व्यायाम और अनुशासन बना रहे, तो सौ साल की उम्र में भी आदमी दौड़ सकता है। बूढ़ा होना स्वाभाविक है, पर कमजोर होना नियति नहीं - यह हमारी जीवनशैली का परिणाम है। फौजा सिंह को याद करें, जो सौ की उम्र में भी मैराथन दौड़ रहे थे।

दूसरी संपत्ति है - ज्ञान। धन अगर खो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, पर ज्ञान अगर भीतर है तो कोई भी परिस्थिति आपको गरीब नहीं बना सकती। ज्ञान ही है जो हर अंधेरे में रास्ता दिखाता है। किताबें, अनुभव और विचार - ये सब मिलकर मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं। तीसरी अमीरी है - जीवन का उद्देश्य। बिना उद्देश्य के पैसा बोझ बन जाता है। आदमी लाखों कमाकर भी बेचैन रहता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जी क्यों रहा है। उद्देश्य से जुड़ा इंसान हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ उठता है। चाहे उसका बैंक खाता कितना भी छोटा हो, वह भीतर से समृद्ध रहता है।

रिश्तों का संबंध भी अमीरी से है। जो व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज से कटकर केवल पैसे बटोरता है, वह अंत में अकेला पड़ जाता है। असली धन यह है कि आपके पास ऐसे लोग हों, जिनके साथ आप अपनी खुशी और दुख बांट सकें। जिनकी मौजूदगी आपको यह अहसास दिलाए कि जीवन केवल लेने का नहीं, देने का भी नाम है। अंत में ईश्वर या परम सत्ता से जुड़ाव। यह जुड़ाव किसी विशेष धर्म या पूजा-पाठ तक सीमित नहीं। यह वह अनुभव है जब मनुष्य यह महसूस करता है कि वह अकेला नहीं, बल्कि एक विराट चेतना का हिस्सा है। जो यह जुड़ाव पा लेता है, वह परिस्थितियों के तूफानों में भी स्थिर रहता है। उसके लिए जीवन शिकायत नहीं, उत्सव बन जाता है।

तो अमीरी का सच्चा अर्थ यह नहीं कि आपके पास कितने घर, कितनी गाड़ियां और कितनी संपत्ति है। अमीरी का असली अर्थ है - एक स्वस्थ और फुर्तीला शरीर, एक जागृत और उत्सुक मन, एक स्पष्ट उद्देश्य, सच्चे रिश्ते और आत्मा का ईश्वर से संवाद। जिसने यह पा लिया, वही सबसे अमीर है। असली अमीरी वह है, जब सौ बरस की देह भी फुर्तीली हो, मन ज्ञान से भरा हो, रिश्ते प्रेम से खिले हों और आत्मा परम सत्ता से जुड़ी हो।

ऑफ़ दि ट्रैक

रोबॉट का नया अवतार

दिलीप लाल

चीन की रोबॉटिक्स कंपनी AheadForm ने हाल ही में एक ऐसा रोबॉटिक चेहरा पेश किया है, जिसे देखकर लगता है मानो कोई इंसान सामने बैठा हो। यह चेहरा पलकें झपकाता है, सिर हिलाता है और भाव बदलता है, बिल्कुल इंसानों की तरह। कंपनी द्वारा यूट्यूब पर जारी किए गए विडियो में यह रोबॉटिक हेड अपने आसपास को देखते हुए मानवीय भावों की नकल करता दिखाई देता है। AheadForm का उद्देश्य इंसान और रोबॉट के बीच संवाद को अधिक स्वाभाविक और सहज बनाना है। कंपनी ऐसे ह्यूमनॉइड रोबॉट हेड विकसित कर रही है, जो इंसानों से बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकें। इसके लिए वे AI और बड़े भाषा मॉडल्स (LLMs) को रोबॉटिक सिरों से जोड़ रहे हैं। कंपनी ने कई मॉडल तैयार किए हैं। इनमें Elf Series खास है, जिसके नुकीले कान और सटीक नियंत्रण प्रणाली इसे अलग पहचान देते हैं। वहीं Lan Series को इंसानों जैसा दिखने और किफायती लागत पर सहज गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कस्टमर सर्विस जैसी इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है। Science Robotics जर्नल में एक ऐसा रोबॉट प्रस्तुत किया, जो इंसानी चेहरे के भावों को रियल-टाइम में समझ सके।

लाहौर की शान कहलाने वाला शायर शरणार्थी बन भारत आया

फ़लक की नज़रों में गांधी

अखिलेश झा

9 नवंबर, 1921 को लाहौर के मियां मीर रेलवे स्टेशन पर जब महात्मा गांधी उतरे, तो लगा कि पूरा पंजाब ही उनके स्वागत में वहां उमड़ आया हो। पूरा शहर गेंदे के फूलों से मुअत्तर सजा था। हर कदम पर लोग माला लिए गांधीजी के स्वागत में खड़े थे। बड़ी मुश्किल से वे लाला लाजपत राय के घर पहुंचे। उन्हीं के निमंत्रण पर गांधीजी लाहौर आए थे। शाम में 'नैशनल कॉलेज', लाहौर का पहला दीक्षांत समारोह था लाहौर के 'ब्रैडलॉ हॉल' में। उसी साल मई, 1921 में नैशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी।

नोटबुक खोलने की जगह नहीं । दोपहर में महिलाओं की एक सभा को संबोधित कर गांधीजी का काफिला लगभग ढाई बजे के आसपास ब्रैडलॉ हॉल की तरफ बढ़ा। उधर ब्रैडलॉ हॉल में लाला लाजपत राय दीक्षांत समारोह की तैयारी देखने के लिए गांधीजी के आने से पहले पहुंचे, तो उनको खुद अंदर पहुंचने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हॉल के अंदर भी भीड़ का ये आलम था कि एक पत्रकार ने लिखा, हॉल में नोटबुक खोलकर लिखने तक की जगह नहीं थी।

लालाजी की धमकी । लाजपत राय परेशान हो गए। गांधीजी के वहां पहुंचने का समय हो रहा था। वे मंच पर माइक लेकर लोगों से शांत रहने, सीट की संख्या के हिसाब से बैठ जाने का आग्रह करने लगे। परंतु कोई उनकी सुननेवाला नहीं था। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि मैं देख सकता हूं, पंजाब अभी स्वराज के लिए तैयार नहीं है। गुस्सा बढ़ा, तो कहने लगे, यदि यहां व्यवस्था बहाल नहीं हुई, तो कार्यक्रम ही स्थगित कर देंगे।

शायर का कमाल । तभी आयोजकों में से एक ने लाहौर के एक युवा शायर को अपनी कविता सुनाने के लिए मंच पर बुलाया। उस शायर ने अपनी पगड़ी संभाली और पहला ही शेर पढ़ा कि सारा ब्रैडलॉ हॉल ऐसे शांत हुआ, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। वह पहला शेर था- *एजाज-ए-क़ौम, माया-ए-जान-ए-वतन है तू/ क्यूं ख़म न हो जहां का सर तेरे रू-ब-रू।*

भारत का लाल, हिंद का फरज़ंदे-अर्जमंद/ है आज भी मेहर-ओ-माह से रुतबा तेरा बुलंद।।

बुत बने खड़े रहे लोग । लाला लाजपत राय को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही लोग जो कुछ पल पहले कुछ सुनने-समझने को तैयार नहीं थे, अब ऐसे सम्मोहित-स्तंभित थे जैसे बुत खड़े हों। उसी ग़ज़ल के पढ़े जाते हुए महात्मा गांधी ने ब्रैडलॉ हॉल में प्रवेश किया। पूरा हॉल फिर 'महात्मा गांधी की जय' के नारों से गुंजायमान हो गया।

देशभक्त शायर
- क्रांतिकारी शायर की थी काफी इज्जत
- अंग्रेजों के हाथों बार-बार जेल भेजे जाते रहे
- भगत सिंह को नौजवान सभा बनाने में दी मदद

कई बार जेल गए । ब्रैडलॉ हॉल में जादू करने वाले उस शायर का नाम था लालचंद फ़लक। उन्होंने गांधीजी की प्रशंसा में एक लंबी ग़ज़ल लिखी थी, जिसका शीर्षक था- 'शेरदिल गांधी'। वे सिर्फ शायर नहीं थे, क्रांतिकारी थे, पत्रकार थे और प्रकाशक भी। पंजाब में क्रांति फैलाने के आरोप में कई बार जेल जा चुके थे। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने जिन क़ैदियों को रिहा किया था, उनमें एक लालचन्द फ़लक भी थे।

स्वदेशी की पढ़ाई । गांधीजी ने उस दिन लाहौर के 'नैशनल कॉलेज' के पहले बैच के सफल छात्रों को उपाधि दी। उस कॉलेज में स्वदेशी शिक्षा दी जा रही थी भारत का सुनहरा भविष्य बनाने के लिए। पढ़ाई का माध्यम था हिंदुस्तानी। पढ़ाने वाले प्राध्यापक ऑक्सफर्ड और दुनिया के अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से पढ़कर आए थे। इसी कॉलेज में दो साल बाद सरदार भगत सिंह भी आए छात्र बनकर। और जब भगत सिंह ने 'नौजवान भारत सभा' की स्थापना की, तब उनकी मदद करने वालों में लाल चंद फ़लक भी थे, जो भगत सिंह के पिता और चाचा के मित्र थे।

शरणार्थी बने लाहौर की शान । जब देश आज़ाद हुआ और बंट गया दो हिस्सों में, तब लाहौर की शान रहे लाल चंद फ़लक शरणार्थी के रूप में दिल्ली आने को मजबूर हुए जहां गुमनामी में उनका निधन साल 1967 में हुआ। अपनी शायरी में फ़लक साहब अल्लामा इक़बाल की परंपरा के शायर माने जाते थे। 'शेरदिल गांधी' ग़ज़ल में पहले शेर के मिसरा-ए-ऊला का दूसरे शेर के मिसरा-ए-ऊला के साथ और उसी तरह दो अलग शेरों के मिसरा-ए-सानी का जो युग्म फ़लक साहब ने बनाया है। महात्मा गांधी पर इस तरह का क़सीदा लिखने वाला कोई दूसरा शायर न हुआ-

करते हैं वसफ तेरी शुजात का लोग कुल/ सिदक-ओ-सफा के तूने खिलाए हैं खूब गुल।
ज़िन्दा किया है तूने ज़माने में नाम-ए-हिन्द/ निगहत से हो गया है मुअत्तर मशाम-ए-हिन्द।।
तू एक मुहब्ब-ए-मुल्क है इंसा का ख़ैरख़्वाह/ सब रहरवान-ए-मंजिल-ए-हस्ती की नेक राह।
एहसान कुल जहां पे है बेश-ओ-कम तेरे/ दिखलाएंगे चमक के ये नक्शे- कदम तेरे।।

(लेखक संस्कृतिकर्मी हैं और ग्रामोफोन-आधारित इतिहास-लेखन करते हैं)

6.8%... क्या काफ़ी है?

भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। रिजर्व बैंक ने विकास अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मॉनसून भी अच्छा गुजरा है और ऊपर से GST सुधार, लेकिन क्या विकसित भारत के लिए इतना पर्याप्त है?

5 पॉइंट

1 सरकार का अनुमान
भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्रालय के ही मुताबिक, इसके लिए कम से कम एक दशक तक 8% की ग्रोथ हासिल करनी होगी। ग्रोथ जितनी कम होगी, रिक्वायर्ड रेट बढ़ता जाएगा।

2 टैरिफ का असर
अमेरिकी टैरिफ की सबसे ज्यादा मार भारत पर पड़ती दिख रही है। करीब 50 अरब डॉलर के निर्यात पर चोट पहुंचेगी। ट्रेड डील पर भी बात अटकी है। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए नए व्यापारिक साझेदार बनाने होंगे।

3 रोजगार का संकट
Morgan Stanley के मुताबिक, भारत में कृषि क्षेत्र में रोजगार बढ़ा है यानी युवाओं के लिए नौकरियों की कमी है। 2023-24 में रोजगार में कृषि का योगदान 46.1% था, जबकि अमेरिका में यह केवल 1.2% है।

4 मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा
GDP में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 2023-24 में केवल 15.9% रहा। रोजगार बढ़ाने के लिए इस सेक्टर पर ध्यान देना होगा। मैन्युफैक्चरिंग के जरिये ही पहले अमेरिका और फिर चीन ने अपने लोगों की तरक्की की है।

5 कितनी हो ग्रोथ?
अगले एक दशक में भारत में 8.4 करोड़ युवा वर्किंग एज तक पहुंच जाएंगे। इन्हें काम दिलाना बड़ी चुनौती होगी। Morgan Stanley का अनुमान है कि 12.2% की ग्रोथ पर ही भारत लक्ष्य पा सकता है।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

संविधान जहां चुप है, उसकी भी अहमियत

पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों और बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे हैं। राम मंदिर मामले में उनके फैसले पर हाल में सोशल मीडिया पर खासी चर्चा हुई। ऐसी बहसों पर उनका क्या रुख है, और दूसरे अहम मुद्दों पर उनसे बात की हमारे लीगल एडिटर ***राजेश चौधरी*** *ने।*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

■ राम मंदिर पर दिए गए आपके फैसले को लेकर हाल में एक इंटरव्यू में चर्चा हुई और फिर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया। फैसले और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना है?

इंटरव्यू में दो लोगों के बीच बात होती है, राम मंदिर वाला जजमेंट पांच जजों का था। पूरा फैसला 1045 पेज में आया। 5 मिनट के सवाल जवाब से एक जजमेंट की व्याख्या नहीं की जा सकती। अभी मैं जज के तौर पर नहीं, एक नागरिक के तौर पर बोल रहा हूं। राम मंदिर पर लिए गए फैसले के आधार जजमेंट में बताए गए हैं। अब कोई कुछ भी कहे, वह अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन हकीकत में जजमेंट में लिखा आधार ही आखिरी निर्णय है। इसके अलावा बाकी लोगों की अपनी-अपनी व्याख्या है।

■ अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के अधिकार को लेकर आप काफी मुखर रहे हैं। इसे लेकर कितनी जागरूकता की जरूरत है?

अलग-अलग स्तर पर नागरिकों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर किसी को वसीयत करनी है तो उसे इसके बारे में पता हो। जॉइंट प्रॉपर्टी है तो क्या वसीयत की जा सकती है, किसी महिला को परिवार ने अलग कर दिया है तो वह क्या करे - इस तरह के मामले रोजाना अदालतों में आते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं हैं, मसलन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो कौन से डॉक्युमेंट देखें? ये सब रोजाना की समस्याएं हैं, जिनके बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। 75 बरसों में हमारा समाज कितना बदला है, यह इतिहास पता होना चाहिए। जून 1975 में इमरजेंसी की घोषणा हुई, तब मैं 15 साल का था। इमरजेंसी में जो कुछ भी हुआ, खासतौर पर संविधान, सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर, उसके बारे में आज की पीढ़ी को बताने की जरूरत है। यह अभी यंग इंडिया है। 50-60 साल बाद यही मिडल एज कंट्री होगा। हर समय की समस्याएं अलग होती हैं। अभी यह देखना है कि युवा पीढ़ी आधारित समाज में जीवन कैसे बेहतर और सार्थक हो।

■ इन सबमें संविधान का रोल कितना अहम है?

श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक, देखिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसके बावजूद हमारे देश में स्थिरता है। मुझे लगता है कि हमारे देश और समाज में इस स्थिरता की वजह संवैधानिक संतुलन है। आर्थिक, राजनीतिक , सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन बेहद अहम है। राष्ट्रहित में हर स्तर पर संतुलन बेहद जरूरी है। देश का संविधान संतुलित और बैलेंस अप्रोच रखता है, इसी कारण हमारा देश स्थिर है। भारत के संविधान में अलग-अलग पहलू हैं, जैसे साउंड एंड साइलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कई चीजों में संविधान की आवाज आपको महसूस होती है। वहीं, कई पहलू ऐसे हैं, जहां संवैधानिक परिभाषा शांत है - वहां संविधान ने सीधे आपको नहीं बताया कि इसका हल कैसे तलाशना है। जहां संविधान चुप है, वह भी एक अहम पहलू है।

■ देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता में संतुलन के लिए सहिष्णुता कितना जरूरी है?

सहिष्णुता बेहद अहम पहलू है। किसी भी राज्य को देखें, हर 100 किमी पर भाषा बदल जाती है। तमाम विविधताओं के बाद भी हम एक हैं और यही इस देश की ब्यूटी है। देखें तो हर व्यक्ति में अच्छाई है, बुराई है। हमें एक-दूसरे को जानना बेहद जरूरी है। यह देश विविधताओं से भरा है। भाषा, खानपान, पहनावा और शैली - सब में भिन्नता है। ऐसे में सहिष्णुता ने देश के विविधता वाले ताने-बाने को मजबूती से जोड़ रखा है।

> **श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक, देखिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। इसके बावजूद हमारे देश में स्थिरता है। मुझे लगता है कि हमारे देश और समाज में इस स्थिरता की वजह संवैधानिक संतुलन है। चूंकि देश का संविधान संतुलित और बैलेंस अप्रोच रखता है, इसी कारण हमारा देश स्थिर है**

देश की विविधताओं को मैंने खुद महसूस किया है। एक जज के तौर पर आपके लिए कानून और संविधान के साथ-साथ देश की विविधताओं को भी समझना जरूरी है।

■ आपने हाल में एक किताब लिखी है। इस किताब में भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या अहम है?

'Why the Constitution Matters' किताब लिखने का उद्देश्य यह था कि संविधान का जो स्थान है, वह आम लोगों के जीवन में उनके सामने आए। नागरिकों को यह नहीं लगना चाहिए कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, जो सिर्फ राजनीतिक लोगों, वकीलों, जजों और कोर्ट-कचहरी के लिए है। संविधान नागरिकों के लिए बना है। यह किताब संविधान के तहत नागरिकों से संवाद करती है। 75 साल बाद नागरिकों के जीवन में संविधान का क्या महत्व है, इसे सरल भाषा में बताने की कोशिश है। हमारे मूलभूत हकों, महिला अधिकारों के बारे में बात है - कैसे आधी आबादी को आगे ले जाएं ताकि उन्हें समान अधिकार मिल सकें। जेंडर जस्टिस अहम है। इसके अलावा फ्रीडम टु आर्ट, लॉ एज स्टोरी टेलिंग जैसे विषय मेरे दिल के बेहद करीब हैं।

■ हाल के दिनों में विरोधी दल के नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर चल रहे हैं। वह संविधान बचाने की बात कर रहे। संविधान बहस के केंद्र में है। इस पर क्या कहना है?

राजनीतिक बहस क्या हो रही है, उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि संविधान को ऑप्टिक्स के सहारे नहीं जान सकते। संविधान मूलभूत दस्तावेज है, जो गवर्नेंस को दिशा दिखाने के लिए बना है। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है।

www.nbt.in

आओ देवी! स्वागत है

वह मेरी पड़ोसन थी। नाम था देवी। पति और बहन के साथ अपनी मां के खपरैल घर में रहती थी। बाद में उसके पति ने पक्का घर बनवा दिया। खुशहाली आ गई। मगर सुख जाते देर नहीं लगती! एक दिन अचानक उसके पति को ब्रेन हैमरेज हुआ और चौबीस की उम्र में देवी विधवा हो गई। जिंदगी किसी तरह आगे घिसटने लगी। पर एक दिन अचानक वह घर से गायब हो गई। मां ने देवी को खोजने की जरा भी कोशिश नहीं की। जैसे उसे पता हो वह कहां गई है। अब देवी की जगह उस घर में उसकी बहन छवि अपने पति के साथ रहने लगी। देवी को सब भूल गए।

उधर देवी ने दूसरी शादी कर ली। मगर ससुराल वालों ने उसे स्वीकार नहीं किया। बाद में परिवार के कहने में आकर लड़का भी ताने-उलाहने देने लगा। फिर लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ। देवी रोज पिटने लगी। सात साल तक झेलने के बाद एक दिन उसने अपना झोला उठाया और पहुंच गई अपने पुराने घर। मगर उसकी मां, बहन ने घर में घुसने नहीं दिया। खूब गालियां दीं। अपनी मर्जी से शादी करने के ताने कसे और जाकर कहीं डूब मरने की सलाह दी। देवी शायद उसी दिन मर भी जाती अगर उसकी मौसेरी बहन ने उसे रोका न होता। उसने देवी को अपने घर में पनाह दी। लेकिन वह भी आखिर कब तक रखती। जल्द ही देवी को वहां रहना असहज लगने लगा।

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

मुझे दो महीने बाद देवी के बारे में पता चला। मैंने उससे फोन पर संपर्क किया। उसकी आवाज बहुत निराश और टूटी हुई थी। उसकी बातों से लगा उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय आत्महत्या के। मैंने उससे कहा, 'देवी हिम्मत रखो। कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा।' आश्वासन दे, मैंने फोन रख दिया। कई दिनों तक देवी के बारे में सोचती रही। आखिर देवी ने ऐसा क्या कर दिया है, जिसके लिए उसे आत्महत्या करनी पड़े। देवी गलत है या उसकी मां, बहन। बहुत सोचने के बाद मैंने उसे फिर फोन किया, 'देवी तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए काम खोज दूंगी।' मेरी बात सुनकर देवी खुश हो गई। फोन पर ही कहने लगी, 'दीदी मुझे तो जैसे नई जिंदगी मिल रही है।' मैं देवी की कोई नहीं, फिर उसे अपने पास क्यों बुला रही हूं? किसी ने पूछा। इस पृथ्वी पर हर चीज एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर देवी मुझसे कैसे अलग हुई। मैंने जवाब दिया। नवरात्र पर देवी की मां हर साल चंदा जुटाकर मुहल्ले के ग्राउंड में दुर्गा मां की प्रतिमा स्थापित करती है। फिर धूमधाम से प्रतिमा का विसर्जन करती है। कैसा पाखंडी समाज है हमारा। असली देवी को दुत्कार कर भगा देता है और मिट्टी से बनी देवियों की पूजा करता है। लेकिन मैं खुश हूं। जब देवी की मां मिट्टी से बनी प्रतीकात्मक देवी को धूमधाम से विदा कर रही थी, मेरे घर असली देवी आई। आओ देवी! तुम्हारा स्वागत है।

चलते-चलते...

एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि अमेरिका में जंगल की आग से होने वाले धुएं के कारण सन 2050 तक मौतों की संख्या बढ़कर प्रति वर्ष 70,000 से अधिक हो सकती है। इसका असर स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक लागत पर पड़ेगा, जो लगभग 608 अरब डॉलर तक होगी। यह राशि अन्य सभी जलवायु समस्याओं से होने वाले नुकसानों से अधिक है।

रीडर्स मेल

महात्मा गांधी के विचार

महात्मा गांधी के विचार इस युग में आदर्श हैं। उनके विचार सत्य और अहिंसा के साथ जीवन जीने की सलाह देते हैं। उनका मानना था कि व्यक्ति लालच और हिंसा से गलत रास्ते पर चला जाता है। वह चाहते थे कि व्यक्ति को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ईमानदार, अहिंसक, नैतिक व्यवहार वाला और शुद्ध आचरण से परिपूर्ण होना चाहिए। इससे जीवन को नई दिशा मिलती है। आज गांधी के विचार पर चलने की जरूरत है। इसके लिए प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों को शिक्षित करने की पहल करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराए। हमें गांधी के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। आज ज्यादातर युवा गलत रास्ते पर जाकर मदिरापान, धूम्रपान, गांजा इत्यादि का शिकार हो गए हैं। यह युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। इन्हें बर्बाद होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम हर हाल में उठाने की जरूरत है। इसके लिए पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, नैतिक मूल्य का पाठ, सामाजिक नवाचार, सामाजिक आदर्श एवं कल्याणकारी मनोभाव को विकसित करके इसमें सुधार किया जा सकता है। युवाओं को चाहिए कि बड़े-बुजुर्गों का आदर करें।

देव कुमार राय, ईमेल से

सरकार से उम्मीद

जीएसटी की नई घटी हुई दरों से उपभोक्ता मांग में वृद्धि होगी। वहीं अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले एमएसएमई क्षेत्र मजबूत होंगे। कुछ मौजूद जीएसटी संबंधित उलझनें हैं, जिनके समाधान के प्रयास हो रहे हैं। नई योजनाएं, अनुपालन बोझ में कमी, जीएसटी दरों में सरलता पर ध्यान देना जरूरी होगा। सरकार से कई उम्मीदें बंधी हैं, जैसे महिलाओं, ग्रामीण उद्यमियों और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी रोजगार को बढ़ावा देना जरूरी है।

अंजनी कुमार दाधीच, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • शनिवार • 4 अक्टूबर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

'जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता है।'

जीएसटी सुधार : महिलाओं की नई ताक़त

हालिया जीएसटी सुधार केवल कर संरचना का तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि सरकार कर नीतियों को सीधे सामाजिक जीवन से जोड़कर देख रही है। भारत में कुल कार्यबल का लगभग 27 प्रतिशत महिलाएं है और कृषि क्षेत्र में यह हिस्सा 60 से 65 प्रतिशत तक पहुँच जाता है। परंतु इनकी आय अक्सर अस्थिर और सीमित होती है। ऐसे में जब रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर घटते है और जटिल स्लैब्स सरल हो जाते है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन महिलाओं तक पहुँचता है, जो कृषि कार्य करते हुए घर का बजट भी सँभालती है। रोटी और पराठे पर कर का भेद मिटाकर उन्हें शून्य श्रेणी में डालना महज प्रतीकात्मक राहत नहीं है। ग्रामीण परिवारों में खाद्य खर्च आय का 50 प्रतिशत तक होता है। यदि इसमें थोड़ी भी कमी आती है तो महिलाओं के हाथ में अतिरिक्त बचत होती है, जिसे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च करती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, ग्रामीण महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया की दर 54 प्रतिशत से अधिक है। जब रसोई पर दबाव घटेगा, तो पोषण में सुधार होगा और परिवार की समग्र सेहत बेहतर बनेगी।

इतना ही नहीं, दरअसल निजी स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने का निर्णय भी विशेष महत्व रखता है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी सीमित है। नेशनल सैंपल सर्वे-2019 के अनुसार, आधी आबादी से अधिक ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में वित्तीय बाधाओं का सामना करती है। अब जब बीमा सस्ता होगा, तो महिलाएं अपने और परिवार के लिए बीमा कवरेज लेने की स्थिति में होंगी। इससे उनका स्वास्थ्य जोखिम कम होगा और परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। यह दीर्घकालिक रूप से महिला श्रम भागीदारी को बनाए रखने और बढ़ाने में सहायक होगा। वहीं दूसरी ओर, तम्बाकू और कैफीन आधारित पेय पर कर 28 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करना सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से दूरगामी है। तम्बाकू पर भारत हर वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का स्वास्थ्य बोझ झेलता है। ग्रामीण परिवारों में पुरुषों की तम्बाकू खपत आय का बड़ा हिस्सा खा जाती है। जब इन उत्पादों पर भारी कर लगेगा, तो खपत घटेगी और आय परिवार की प्राथमिक आवश्यकताओं पर खर्च होगी। महिलाओं को घरेलू हिंसा और आर्थिक असुरक्षा, दोनों से राहत मिलेगी, क्योंकि नशे और अस्वास्थ्यकर आदतें कम होंगी।

सरकार का दावा है कि सरल कर ढांचा उपभोग को प्रोत्साहित करेगा और मैन्युफैक्चरिंग को गति देगा। जब उपभोग बढ़ेगा, तो वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्र विस्तारित होंगे। इन उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी परंपरागत रूप से अधिक रही है। उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण स्वयं सहायता समूह पहले से ही खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प क्षेत्र में सक्रिय है। सरल कर व्यवस्था और कम लागत उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाएगी। इससे महिलाओं की आय में सीधा इज़ाफ़ा होगा। उद्यमिता के स्तर पर भी यह सुधार महिलाओं के लिए नया अवसर है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 80 लाख महिलाएं छोटे व्यवसाय चला रही हैं, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से हैं। कर की जटिलता अब तक उनके लिए बड़ी बाधा थी। अब जब स्लैब्स घटेंगे और भ्रम की स्थिति समाप्त होगी, तो महिलाएं अपने कारोबार को आसानी से पंजीकृत और संचालित कर सकेंगी। पारदर्शिता बढ़ने से भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी और महिला उद्यमिता को नई गति मिलेगी।

वित्त मंत्री का यह कहना कि इसे रेवेन्यू लॉस नहीं बल्कि रेवेन्यू इम्प्लिकेशन कहा जाए, यह संकेत है कि सरकार अल्पकालिक राजस्व की जगह दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक लाभ पर ध्यान दे रही है। जब ग्रामीण महिलाएं सशक्त होंगी, तो उनकी आय और खर्च दोनों में वृद्धि होगी। इससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी और अंततः सरकार को राजस्व भी अधिक मिलेगा। इन सारे सुधारों की परतें खोलने पर स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं, विशेषकर कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं, को केंद्र में रखकर नीतिगत सोच विकसित की है। रोज़मर्रा की वस्तुएं सस्ती करके उनके घरेलू जीवन को सहज बनाया गया है, बीमा सुलभ बनाकर उनकी सुरक्षा मजबूत की गई है, और हानिकारक उत्पादों पर कर बढ़ाकर परिवार की बचत और सेहत दोनों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही, उद्यमिता और रोजगार के नए अवसर देकर उनकी आर्थिक भूमिका को विस्तारित करने की नींव रखी गई है। ऐसे में यह सुधार केवल कर दरों का पुनर्गठन नहीं, महिलाओं की मजबूती और ग्रामीण भारत के भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह साबित करता है कि दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से महिला शक्ति को सशक्त किए बिना आर्थिक विकास की परिकल्पना अधूरी है।

राष्ट्र साधना के 100 वर्ष

100 वर्ष पूर्व विजयदशमी के महापर्व पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। ये हजारों वर्षो से चली आ रही उस परंपरा का पुनर्स्थापन था जिसमें राष्ट्र चेतना समय-समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए-नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। ये हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने मिल रहा है। मै इस अवसर पर राष्ट्रसेवा के संकल्प को समर्पित कोटि-कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं। मै संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। संघ की 100 वर्षो की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के भी जारी किए है।

जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती है, उसी तरह संघ के किनारे भी सैकड़ों जीवन पुष्पित-पल्लवित हुए है। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है उन क्षेत्रों को अपने जल से समृद्ध करती है वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। जिस तरह एक नदी कई धाराओं में ख़ुद को प्रकट करती है संघ की यात्रा भी ऐसी ही है। संघ के अलग.अलग संगठन भी जीवन के हर पक्ष से जुड़कर राष्ट्र की सेवा करते है। शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, आदिवासी कल्याण, महिला सशक्तिकरण, समाज जीवन के ऐसे कई क्षेत्रों में संघ निरंतर कार्य करता रहा है। विविध क्षेत्र में काम करने वाले हर संगठन का उद्देश्य एक ही हैए भाव एक ही है राष्ट्र प्रथम। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र निर्माण का विराट उद्देश्य लेकर चला। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण रास्ता चुना और इस चलने के लिए जो कार्यपद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखाएं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है, जहां से स्वयंसेवक की अहम से वयं की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञवेदी हैं।

राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य, व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्यपद्धति यही संघ की सौ वर्षो की यात्रा का आधार बने। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ा रहे है।

संघ जब से अस्तित्व में आया संघ के लिए देश की प्राथमिकता ही उसकी अपनी प्राथमिकता रही। आज़ादी की लड़ाई के समय परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई में कितने ही स्वतन्त्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। आजादी के बाद भी संघ निरंतर राष्ट्र साधना में लगा रहा। इस यात्रा में संघ के खिलाफ साजिशें भी हुई, संघ को कुचलने का प्रयास भी हुआ। ऋषितुल्य

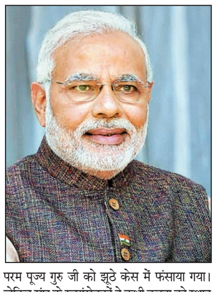

परम पूज्य गुरु जी को झूठे केस में फंसाया गया। लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया। क्योंकि वो जानते है, हम समाज से अलग नहीं है, समाज हमसे ही तो बना है। समाज के साथ एकात्मता और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आस्था ने संघ के स्वयंसेवकों को हर संकट में स्थित प्रज्ञ रखा है। समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखा है।

प्रारंभ से संघ राष्ट्रभक्ति और सेवा का पर्याय रहा है। जब विभाजन की पीड़ा ने लाखों परिवारों को बेघर कर दिया, तब स्वयंसेवकों ने शरणार्थियों की सेवा की। हर आपदा में संघ के स्वयंसेवक अपने सीमित संसाधनों के साथ सबसे आगे खड़े रहते रहे। यह केवल राहत नहीं थी यह राष्ट्र की आत्मा को संबल देने का कार्य था। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। आज भी प्राकृतिक आपदा में हर जगह स्वयंसेवक सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक रहते है।

अपनी 100 वर्षो की इस यात्रा में संघ ने समाज के अलग-अलग वर्गों में आत्मबोध जगाया, स्वाभिमान जगाया। संघ देश के उन क्षेत्रों में भी कार्य करता रहा है जो दुर्गम है, जहाँ पहुंचना सबसे कठिन है। संघ दशकों से आदिवासी परंपराओं, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी मूल्यों को सहेजने-संवारने में अपना सहयोग देता रहा है अपना कर्तव्य निभा रहा है। आज सेवा भारतीविद्या भारती एकल विद्यालय वनवासी कल्याण आश्रम आदिवासी समाज के सशक्तिकरण का स्तंभ बनकर उभरे हैं।

समाज में सदियों से घर कर चुकी जो बीमारियाँ है जो ऊंच.नीच की भावना है जो कुप्रथाएं है ये हिन्दू समाज की बहुत बड़ी चुनौती रही है। ये एक ऐसी गंभीर चिंता है जिस पर संघ लगातार काम करता रहा है। डॉक्टर साहब से लेकर आज तक संघ की हर महान विभूति ने हर सर संघचालक ने भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। परम पूज्य गुरु जी ने निरंतर न हिन्दू पतितो भवेत्ष की भावना को आगे बढ़ाया। पूज्य बाला साहब देवरस जी कहते थे छुआछूत अगर पाप नहीं तो दुनिया में कोई पाप नहीं! सर संघचालक रहते हुए पूज्य रज्जू भैया जी और पूज्य सुदर्शन जी ने भी इसी भावना को आगे बढ़ाया। वर्तमान सर संघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने भी समरसता के लिए समाज के सामने एक कुआं एक मंदिर और एक श्मशान का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। जब 100 साल पहले संघ अस्तित्व में आया था तो उस समय की आवश्यकताएं उस समय के संघर्ष कुछ और थे। लेकिन आज 100 वर्षो बाद जब भारत विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है तब आज के समय की चुनौतियां अलग है, संघर्ष अलग है। दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता, हमारी एकता को तोड़ने की साजिशें, डेमोग्राफी में बदलाव के षड़यंत्र हमारी सरकार इन चुनौतियों से तेजी से निपट रही है। मुझे ये खुशी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रोडमैप भी बनाया है।

संघ के पंच परिवर्तन, स्व बोध, सामाजिक समरसता, कुटुम्ब प्रबोधन, नागरिक शिष्टाचार और पर्यावरण ये संकल्प हर स्वयंसेवक के लिए देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को परास्त करने की बहुत बड़ी प्रेरणा है।

स्व बोध की भावना का उद्देश्य गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व और स्वदेशी के मूल संकल्प को आगे बढ़ाना है। सामाजिक समरसता के जरिए वंचित को वरीयता देकर सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रण है। आज हमारी सामाजिक समरसता को घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी में आ रहे बदलाव से भी बड़ी चुनौती मिल रही है। देश ने भी इससे निपटने के लिए डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। हमें कुटुम्ब प्रबोधन यानी परिवार संस्कृति और मूल्यों को भी मजबूत बनाना है। नागरिक शिष्टाचार के जरिए नागरिक कर्तव्य का बोध हर देशवासी में भरना है। इन सबके साथ अपने पर्यावरण की रक्षा करते हुये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। अपने इन संकल्पों को लेकर संघ अब अगली शताब्दी की यात्रा शुरू कर रहा है। 2047 के विकसित भारत में संघ का हर योगदान देश की ऊर्जा बढ़ाएगा, देश को प्रेरित करेगा। पुनः प्रत्येक स्वयंसेवक को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

लेखक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जिस तरह विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं पनपती हैं, उसी तरह संघ के किनारे भी सैकड़ों जीवन पुष्पित-पल्लवित हुए हैं। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती हैं उन क्षेत्रों को अपने जल से समृद्ध करती हैं वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है।

बख्शी का तालाब क्षेत्र के नंदना गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 लखनऊ सीतापुर पर स्थित 51 शक्ति पीठ का धाम मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण रघराज दीक्षित 'रघु' ने करवाया था। इस मंदिर में 51 शक्ति पीठ जो कि देश ही नहीं विदेशों में भी स्थापित है। उनकी ही रज (मिट्टी) को लेकर निर्माण करवाया था। रघराज दीक्षित की मृत्यु के उपरांत उनकी बेटी इस मंदिर की देखरेख करती है। उन्होंने बताया कि 51 शक्ति पीठ मंदिर देश ही नहीं बल्कि विश्व में एकमात्र मंदिर ऐसा है जहां पर 51 शक्ति पीठ की रज स्थापित है। राजा दक्ष जो सती माता के पिता ने शंकर जी के बारे में उल्टी-सीधी बातें कहीं थीं। सती माता पति के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने योगाग्नि में कूदकर अपने शरीर को जला दिया।

इस बात की जानकारी जब भगवान शंकर जी को हुई तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा वीरभद्र ने माता सती की दशा देखकर राजा दक्ष का सर काट के हवन कुंड में डाल दिया। इस हवन में ऋषि मुनि भी मौजूद थे। जानकारी पाकर शंकर भगवान जी पहुंचे और कुंड से मां सती का शरीर हाथों में उठा कर तांडव नृत्य शुरू कर दिया।

51 शक्ति पीठ में 41 शक्तिपीठ भारत में लिहाजा 51 शक्ति पीठ में 41 शक्तिपीठ भारत में स्थापित है, चार बांग्लादेश, 1 श्रीलंका, एक पाकिस्तान में, एक तिब्बत में तथा शेष नेपाल में है। मंदिर के संस्थापक रघुराज दीक्षित ने सभी स्थानों पर जाकर वहां से रज लाकर 51 शक्ति पीठ के मंदिर की स्थापना कर भक्तों के लिए आस्था का केन्द्र स्थापित किया।

नवरात्रि 9 दिन नौ रंगों के फूलों से अलग-अलग दिन में श्रृंगार : नवरात्रि के अवसर पर इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने के लिए दूरदराज से भक्तगण आते है। इस मंदिर में नवरात्रि 9 दिन नौ रंगों के फूलों से अलग-अलग दिन में श्रृंगार होता है और नवरात्रि के आखिरी दिन 11 सौ कन्याओं को भोज कराया जाता है।

विचार | स्वामी विवेकानंद

युवाओं का जागरण ही परम उद्देश्य

स्वामी विवेकानंद का नाम भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत में प्रेरणा का पर्याय माना जाता है। उनका व्यक्तित्व केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता रहा है। उन्होंने अपने विचारों और आचरण से यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समाज और मानवता की सेवा में निहित है। उनके सकारात्मक विचार आज भी युवाओं को जाग्रत करते है और जीवन में नई दिशा प्रदान करते है।

स्वामी विवेकानंद का सबसे प्रमख सकारात्मक संदेश है-'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।' यह वाक्य आज भी हर युवा के लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत है। उनका मानना था कि मनुष्य अपने भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य रखता है, केवल आत्मविश्वास और परिश्रम से ही उस शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। वे कहते थे कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है।

उनके विचारों में चरित्र निर्माण को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उनका विश्वास था कि यदि व्यक्ति का चरित्र मजबूत है तो वह किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। वे बार-बार इस बात पर जोर देते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा से आत्मनिर्भरता, आत्मबल और नैतिकता विकसित होनी चाहिए।

स्वामी विवेकानंद का एक और सकारात्मक दृष्टिकोण था- 'ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है।' उन्होंने सिखाया कि जब हम दूसरों की सेवा करते है, तो वास्तव में हम ईश्वर की सेवा कर रहे होते है। उनके इस विचार ने समाज में मानवता और परोपकार की भावना को बल प्रदान किया। यही कारण है कि उन्होंने 'दरिद्र नारायण' की सेवा को सर्वोच्च धर्म माना।

उन्होंने यह भी कहा कि निर्भय बनो, तभी जीवन में बड़ी उपलब्धियाँ मिलेंगी।' भय को वे प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनका विश्वास था कि जो व्यक्ति निर्भीक होकर अपने जीवन का सामना करता है, वही महान कार्य कर सकता है।

स्वामी विवेकानंद के सकारात्मक विचारों का एक और पहलू था - युवाओं पर विश्वास। उनका मानना था कि यदि भारत को पुनः महान बनाना है तो यह काम युवाओं की शक्ति से ही संभव है। वे युवाओं से आह्वान करते थे कि अपने शरीर, मन और आत्मा को सशक्त बनाओ और समाज को नई दिशा दो।

उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा सकारात्मक दृष्टिकोण कठिनाइयों को अवसर में बदल देता है। उन्होंने विश्व धर्म महासभा, शिकागो (1893) में अपने विचार रखकर पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से परिचित कराया। उनके शब्दों ने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत शांति, सहिष्णुता और बंधुत्व का प्रतीक है।

ब्रह्माग्नि/ डॉ ज्ञानानंददास स्वामी

ब्रह्म-परब्रह्म के प्रति समर्पण

शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करता है, तब उसके भीतर एक दिव्य अध्यात्मरूप ज्वाला प्रज्वलित होती है, जिसे ब्रह्माग्नि कहा गया है। यह ब्रह्माग्नि कोई लौकिक अग्नि नहीं, बल्कि ब्रह्मज्ञान से उत्पन्न वह अलौकिक शक्ति है, जो हमारे अहंकार, आसक्ति और पापरूपी वासनाओं को जला देती है। जैसे अग्नि में डाला हुआ कोई भी पदार्थ राख हो जाता है, वैसे ही जब कर्म ब्रह्माग्नि में अर्पित होते है, तो उनका बंधन शून्य हो जाता है। सामान्य कर्म हमें बार-बार जन्म-मरण के चक्र में बाँधते है, क्योंकि उनमें फल की आसक्ति जुड़ी रहती है। परंतु जब वही कर्म ब्रह्म-परब्रह्म के प्रति समर्पणभावना से किए जाते है, सारे दुष्कर्म जलकर राख हो जाते है।

समर्पण का अर्थ केवल शब्दों से कहना नहीं कि 'सब भगवान को अर्पित है', बल्कि भीतर से यह भावना दृढ़ करना है कि कर्ता मै नहीं, भगवान है। कर्म का फल मेरा नहीं, भगवान का है। मै तो उनकी इच्छा का उपकरण मात्र हूँ। इस स्थिति में मनुष्य के सभी कर्म चाहे छोटे हों या बड़े पवित्र यज्ञ में आहुति समान हो जाते है। भगवद्गीता कहती हैः जिसके सब कर्म ज्ञानाग्नि में दग्ध हो गए है और जो आसक्ति से रहित है, वही ज्ञानी कहलाता है। वह ब्रह्मज्ञान का पात्र बन जाता है और अंततः मुक्त पंक्ति में स्थान प्राप्त करता है। जब हम सेवा, पूजा, अध्ययन, प्रवचन, या साधारण कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते है, तो वे कर्म बंधन नहीं बनते।

मिथिला के महाराज जनक ब्रह्मज्ञानी राजा थे। वे अपने राज्य का शासन बड़ी निष्ठा और कुशलता से करते थे, लेकिन उनके हृदय में यह दृढ़ भावना रहती थी कि मै कर्ता नहीं हूँ, सब प्रभु की शक्ति और इच्छा से हो रहा है। मै तो केवल निमित्त हूँ। राज्य, प्रजा, परिवार, वैभव सब भगवान का है। एक बार उनके दरबार में आग लग गई। मंत्री और सैनिक घबराकर दौड़ पड़े और राजा से बोले महाराज! आग पूरे महल को जलाकर राख कर देगी, आप चलिए। लेकिन जनक हरिकथा में शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा महल और वैभव मेरा नहीं, सब भगवान का है। जो उनका है, वही उसे बचाएँगे या भस्म करेंगे। मै क्यों व्याकुल होऊँ? उनका यह समर्पण देखकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ। बाद में आग बुझ गई और कोई हानि न हुई। यह देखकर सबको विश्वास हो गया कि समर्पण करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और मुक्त रहता है। महंत स्वामी महाराज कहते है- जब मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को हे प्रभु, यह सब आपको समर्पित है की भावना से करता है, तब कर्मबंधन से मुक्त होकर, परब्रह्म के प्रेम और आनंद में स्थिर हो जाता है।

समाज सहयोग से संघ शताब्दी यात्रा सुगम बनी

मुद्दा | दत्तात्रेय होसबाले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को अभी सौ वर्ष पूर्ण हो रहे है। इस सौ वर्ष की यात्रा में कई लोग सहयोगी और सहभागी रहे है। यह यात्रा परिश्रम पूर्ण और कुछ संकटों से अवश्य घिरी रही, परंतु सामान्य जनों का समर्थन उसका सुखद पक्ष रहा। आज जब शताब्दी वर्ष में सोचते है तो ऐसे कई प्रसंग और लोगों का स्मरण आता है, जिन्होंने इस यात्रा की सफलता के लिए स्वयं सब कुछ समर्पित कर दिया।

प्रारंभिक काल के वे युवा कार्यकर्ता एक योद्धा की तरह देश प्रेम से ओत-प्रोत होकर संघ कार्य हेतु देशभर में निकल पड़े। अप्पाजी जोशी जैसे गृहस्थ कार्यकर्ता हों या प्रचारक स्वरूप में दादाराव परमार्थ, बालासाहब व भाऊराव देवरस बंधु, यादवराव जोशी, एकनाथ रानडे आदि लोग डॉक्टर हेडगेवार जी के सान्निध्य में आकर संघ कार्य को राष्ट्र सेवा का जीवनव्रत मानकर जीवन पर्यन्त चलते रहे।

संघ का कार्य लगातार समाज के समर्थन से ही आगे बढ़ता गया। संघ कार्य सामान्य जन की भावनाओं के अनुरूप होने के कारण शनैः शनैः इस कार्य की स्वीकार्यता समाज में बढ़ती चली गई। स्वामी विवेकानंद से एक बार उनके विदेश प्रवास में यह पूछा गया कि आपके देश में तो अधिकतम लोग अनपढ़ है, अंग्रेज़ी तो जानते ही नहीं है, तो आपकी बड़ी-बड़ी बातें भारत के लोगों तक कैसे पहुंचेगी? उन्होंने कहा कि जैसे चीटियों को शक्कर का पता लगाने के लिए अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मेरे भारत के लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान के चलते किसी भी कोने में चल रहे सात्विक कार्य को तुरंत समझ जाते है व वहीं वो चुपचाप पहुंच जाते है। इसलिए वे मेरी बात समझ जायेंगे। यह बात सत्य सिद्ध हुई। वैसे ही संघ के इस सात्विक कार्य को धीरे क्यों न हो, सामान्य जन से स्वीकार्यता व समर्थन लगातार मिल रहा है।

संघ कार्य के प्रारंभ से ही संपर्कित व नये-नये सामान्य परिवारों द्वारा संघ कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद व आश्रय प्राप्त होता रहा। स्वयंसेवकों के परिवार ही संघ कार्य संचालन के केंद्र रहे। सभी माता-भगिनियों के सहयोग से ही संघ कार्य को पूर्णता प्राप्त हुई। दत्तोपंत ठेंगड़ी या यशवंतराव केलकर, बालासाहेब देशपांडे तथा एकनाथ रानडे, दीनदयाल उपाध्याय या दादासाहेब आपटे जैसे लोगों ने संघ प्रेरणा से समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में संगठनों को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। ये सभी संगठन वर्तमान समय में व्यापक विस्तार के साथ-साथ उन क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे है। समाज की बहनों के मध्य इसी राष्ट्र कार्य हेतु राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से मौसी जी केलकर से लेकर प्रमिलाताई मेढ़े जैसी मातृसमान हस्तियों की भूमिका इस यात्रा में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

संघ द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय हित के कई विषयों को उठाया गया। उन सभी को समाज के विभिन्न लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिनमें कई बार सार्वजनिक रूप से विरोधी दिखने वाले लोग भी शामिल रहे। संघ का यह भी प्रयास रहा कि व्यापक हिंदू हित के मुद्दों पर सभी का सहयोग प्राप्त किया जाए। राष्ट्र की एकात्मता, सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द तथा लोकतंत्र एवं धर्म-संस्कृति की रक्षा के कार्य में असंख्य स्वयंसेवकों ने अवर्णनीय कष्ट का सामना किया और सैकड़ों का बलिदान भी हुआ। इन सबमें समाज के संबल का हाथ हमेशा रहा है।

1981 में तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम में भ्रमित करते हुए कुछ हिंदुओं का मतांतरण करवाया गया। इस महत्वपूर्ण विषय पर हिंदू जागरण के क्रम में आयोजित लगभग पाँच लाख की उपस्थिति वाले सम्मेलन की अध्यक्षता करने हेतु तत्कालीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. कर्णसिंह उपस्थित रहे। 1964 में विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना में प्रसिद्ध संन्यासी स्वामी चिन्मयानंद, मास्टर तारा सिंह व जैन मुनी सुशील कुमार जी, बौद्ध भिक्षु कुशोक बकुला व नामधारी सिख सद्गुरु जगजीत सिंह इनकी प्रमुख सहभागिता रही। हिन्दू शास्त्रों में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं है यह पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से श्री गुरूजी गोलवलकर की पहल पर उडुपी में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन में पूज्य धर्माचार्यों सहित सभी संतों-महंतों का आशीर्वाद व उपस्थिति रही। जैसे प्रयाग सम्मेलन में न हिंदुः पतितो भवेत (कोई हिन्दू पतित नहीं हो सकता) का प्रस्ताव स्वीकार हुआ था वैसे ही इस सम्मेलन का उद्घोष था - हिंदवः सोदराः सर्वे अर्थात सभी हिन्दू भारत माता के पुत्र है। इन सभी में तथा गौहत्या बंदी का विषय हो या राम जन्मभूमि अभियान, संतों का आशीर्वाद संघ स्वयंसेवकों को हमेशा प्राप्त होता रहा है।

स्वाधीनता के तुरंत पश्चात राजनीतिक कारणों से संघ कार्य पर तत्कालीन सरकार द्वारा जब प्रतिबंध लगाया गया, तब समाज के सामान्य जनों के साथ अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी संघ के पक्ष में खड़े होकर इस कार्य को संबल प्रदान किया। यही बात आपातकाल के संकट समय में भी अनुभव में आई। यही कारण है कि इतनी बाधाओं के पश्चात भी संघ कार्य अक्षुण्ण रूप से निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन सभी परिस्थितियों में संघ कार्य एवं स्वयंसेवकों को सँभालने का दायित्व हमारी माता-भगिनीयों ने बड़ी कुशलता से निभाया। यह सभी बातें संघ कार्य हेतु सर्वदा प्रेरणास्रोत बन गयी है।

भविष्य में राष्ट्र की सेवा में समाज के सभी लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के लिए संघ स्वयंसेवक शताब्दी वर्ष में घर-घर संपर्क के द्वारा विशेष प्रयास करेंगे। देशभर में बड़े शहरों से लेकर सुदूर गाँवों के सभी जगहों तक तथा समाज के सभी वर्गो तक पहुंचने का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। समूचे सज्जन शक्ति के समन्वित प्रयासों द्वारा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की आगामी यात्रा सुगम एवं सफल होगी।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 20, अंक 6792
आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पीओके में हिंसक आन्दोलन

1947 में आजादी मिलने के साथ ही पाकिस्तान का निर्माण होने पर जिस तरह इस नये देश ने जम्मू-कश्मीर रियासत पर आक्रमण किया उससे यह रियासत दो हिस्से में बंट गई क्योंकि पाकिस्तान ने इस रियासत का एक तिहाई हिस्सा कब्जा लिया था। यह बंटवारा 1948 में दोनों देशों की फौजों के बीच युद्ध विराम होने के बाद किस प्रकार हुआ इसकी कहानी बहुत बार दोहराई जा चुकी है जिसे बार–बार लिखने से कोई लाभ नहीं है मगर यह ऐतिहासिक सत्य है कि पाकिस्तान उस जम्मू-कश्मीर का एक हिस्सा अपने कब्जे में तभी से लिये बैठा है जब इस रियासत के महाराजा हरिसिंह ने अपनी पूरी सल्तनत का विलय भारतीय संघ में कर दिया था। पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर इसी रियासत का अभिन्न अंग है और यहां के लोगों की संस्कृति भी वही है जो भारत के जम्मू-कश्मीर के लोगों की है। मगर पाकिस्तानी शासकों ने इस हिस्से को अपने कब्जे में लेने के बाद से इसे आजाद कश्मीर कहना शुरू किया और बराये नाम यहां एक हुकूमत भी कायम कर दी जो इस्लामाबाद के शासकों की कठपुतली की तरह काम करती है।

इतना ही नहीं इस इलाके में पाकिस्तान के दूसरे भागों से ला-लाकर लोग बसाये गये जिससे कश्मीरी लोगों और उनकी संस्कृति को कुचला जा सके। यहां के कश्मीरियों पर 1948 से ही पाकिस्तानी सरकार जुल्मों- सितम का बाजार गर्म किये हुए है जिसका विरोध करने पर यहां के स्थानीय लोगों को गोलियों से भूना तक जाता रहा है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर को आतंकवादियों का अड्डा बना डाला है और इस इलाके में उसने आतंकवादी शिविर खोल रखे हैं। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए अक्सर इसी इलाके का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने यहां के लोगों की कश्मीरी भाषा तक को बेजुबान बना डाला है और बाहर से जिला हुक्मरान ला-लाकर बैठाये हैं जिन्हें इलाके के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता। इस्लामाबाद की हुकूमत कश्मीरियों पर उर्दू थोप कर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहती है। ध्यान रहे यही काम इस्लामाबाद के शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान (जिसे अब बंगलादेश कहा जाता है) में भी किया था। यहां के लोगों की बांग्ला भाषा पर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उर्दू थोपी थी जिसकी वजह से यह इलाका 1971 में बंगलादेश बन गया। मगर पाक के कब्जे वाले कश्मीर में केवल भाषा की समस्या नहीं है बल्कि नागरिक समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है। यहां के लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर तो सुलभ कराये जाते ही नहीं हैं साथ ही मूलभूत नागरिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता है।

यहां के कश्मीरियों पर 1948 से ही पाकिस्तानी सरकार जुल्मों– सितम का बाजार गर्म किये हुए है जिसका विरोध करने पर यहां के स्थानीय लोगों को गोलियों से भूना तक जाता रहा है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर को आतंकवादियों का अड्डा बना डाला है और इस इलाके में उसने आतंकवादी शिविर खोल रखे हैं। पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए अक्सर इसी इलाके का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान ने यहां के लोगों की कश्मीरी भाषा तक को बेजुबान बना डाला है और बाहर से जिला हुक्मरान ला–लाकर बैठाये हैं जिन्हें इलाके के बारे में कुछ मालूम ही नहीं होता।

पाकिस्तानी सेना और पुलिस आये दिन उन पर अत्याचार करती रहती है। यहां नामचारे के चुनाव कराये जाते हैं और चुन-चुन कर इस्लामाबाद अपने गुर्गों को पदों पर बैठाता रहता है। अतः अक्सर इस इलाके के लोग भारत के कश्मीर के लोगों की स्थिति से अपनी तुलना करते हैं तो उनमें भारी खिसियाहट पैदा होती है। क्योंकि भारत के कश्मीरी भारतीय संविधान के साये में खुली हवा में सांस लेते हैं और अपने नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पाकिस्तान के कश्मीरियों के लिए लोकतान्त्रिक तरीके से अपनी मांगों का इजहार करना भी दुष्कर होता है। इनके द्वारा जब भी कोई आन्दोलन होता है तो उसे पुलिस व सेना द्वारा कुचल दिया जाता है और जेलें भर दी जाती हैं। अतः कभी-कभी हमें ये खबरें भी पढ़ने को मिल जाती हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर या 'पी ओ के' के लोगों ने भारत के समर्थन में नारे लगाये। पाकिस्तानी शासक अपने कब्जे वाले कश्मीर में मानवीय अधिकारों को जिस तरह अक्सर रौंदते हैं उसका मुकाबला केवल सैनिक शासन वाले देशों से ही हो सकता है जबकि पाकिस्तान में कहने को लोकतन्त्र है। ताजा हालात ये हैं कि पीओके में पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र की परिस्थितियों में सुधार व बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की मांग को लेकर इलाके की संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी हड़ताल या आन्दोलन कर रही है ।

इस आन्दोलन को समाप्त करने के लिए पाकिस्तानी शासकों ने सारी हदें पार कर डाली हैं और लोगों पर सरेआम पुलिस गोलियों की बौछार कराई जा रही है जिसकी वजह से छह लोगों की मौत हो गई। आन्दोलन जब हिंसक हो गया तो तीन पुलिस वाले भी गुस्से का निशाना बने और हलाक हो गये। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जबकि गैर सरकारी आंकड़े इससे बहुत ज्यादा बताये जा रहे हैं। एक्शन कमेटी के आह्वान पर पूरे इलाके में सभी तिजारती इदारे बन्द रहे और संचार व्यवस्था भी ठप्प रही। नागरिकों के सब्र का बांध जब टूटा तो गुलाम कश्मीर के कई शहरों में लोग हिंसा पर भी उतारू हो गये। विभिन्न शहरों में पुलिस व लोगों के बीच हिंसा की झड़पों में 172 पुलिस कर्मियों का घायल होना बताता है कि लोगों में पुलिस के खिलाफ कितना गुस्सा है। हालांकि इनमें 50 नागरिक भी घायल हुए हैं। हड़ताल इतनी सफल रही कि मुजफ्फराबाद से लेकर धीरकोट, मीरपुर, पुंछ, नीलम, भीम्बरव पालन्दी तक में जनजीवन पूरी तरह अस्त- व्यस्त हो गया और सड़कें सूनी हो गईं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि एक्शन कमेटी के लोग हिंसक हो गये थे, खास कर धीरकोट में जहां तीन पुलिस कर्मियों को हलाक कर दिया गया। मगर पुलिस की बर्बरता तो गुलाम कश्मीर के लोग पिछले 76 सालों से सहते आ रहे हैं और अपने जन्नत जैसे इलाके को जहन्नुम में तब्दील होते देख रहे हैं। पाकिस्तानी शासकों ने इस इलाके में बसे गैर कश्मीरी भाषी कथित अभिजात्य वर्ग के लोगों को विशेष नागरिक अधिकार दे रखे हैं। स्थानीय सेवाओं में 12 प्रतिशत का आरक्षण उन लोगों को दे रखा है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से आकर घाटी में बसे हैं। एक्शन कमेटी मांग कर रही है कि इस आरक्षण को समाप्त किया जाये और इलाके के सभी लोगों को एक समान व मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाये। मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी हर नागरिक को उपलब्ध हो। ये मांगें पूरी तरह जायज हैं क्योंकि इलाके में किसी प्रकार का उद्योग – धंधा है ही नहीं। इसके पीछे मंशा यही है कि पाकिस्तान कश्मीरियों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है।

कोई सच्ची दास्तां सुनाता नहीं

"चौपाल पर अब बुजुर्गों और लड़कों का वह जमघट नजर आता नहीं,
हंसते तो है लोग ,पर दिल से कोई घर मुस्कुराता नहीं,,
विदेश गया बेटा अब गांव लौटना चाहता नहीं,
सूने आंगनों में हवा का झोंका भी ठहर पाता नहीं,,
बर्फ में कैद उस तस्वीर की कोई सच्ची दास्तां सुनाता नहीं,
कि अपनी जड़ों से कटकर कोई सुकून का पल बिताता नहीं...।।"

गीता पाढा

पोस्टल बैलेट गणना और चुनाव आयोग

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

बाबा साहेब अम्बेडकर जब भारत का संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने संविधान सभा के संरक्षण में चुनाव आयोग का गठन किया और इसे सरकार का अंग न बनाकर इसकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की। इसके साथ ही भारत में न्यायपालिका की भी स्वतन्त्र संवैधानिक सत्ता स्थापित की गई और इसे भी सरकार से अलग रखा गया, तब बाबा साहेब ने कहा कि भारत का लोकतन्त्र चार पायों पर टिका होगा। इसके चार पाये विधायिका, कार्यपालिका, न्याय पालिका व चुनाव आयोग होंगे। इनमें चुनाव आयोग का काम प्राथमिक स्तर पर पूरे भारत में लोकतन्त्र की उर्वरा जमीन तैयार करने का होगा जिस पर विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के तीनों मजबूत खम्भे खड़े होंगे। इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए कि संविधान में स्वतन्त्र पत्रकारिता या मीडिया को चौथा खम्भा बताया गया था। वास्तव में संविधान में प्रेस का कहीं कोई जिक्र नहीं है और इसकी उत्पत्ति संविधान के अनुच्छेद 19(1) की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार से होती है। इसी अधिकार से स्वतन्त्र व निर्भीक पत्रकारिता का जन्म होता है, क्योंकि लोकतन्त्र में आजाद अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में आता है। भारत की स्वतन्त्रता के बाद 1967 तक चुनाव आयोग न तो कभी विवाद में आया और न ही लोकचर्चा में क्योंकि यह अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निर्भीकता व निष्पक्षता के साथ करता था। अतः समाजवादी चिन्तक स्व. डा. राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस पार्टी की पूरे देश में जबर्दस्त पकड़ और उठते हुए विपक्ष के सन्दर्भ में कहा कि स्वतन्त्र प्रेस अर्थात मीडिया लोकतन्त्र का चौथा खम्भा होता है, जो सरकार के कामकाज की सतत समीक्षा करता रहता है और उसकी खामियों की तरफ निशानदेही करता रहता है। डा. लोहिया ने जो चौखम्भा राज लोकतन्त्र में बताया उसमें चुनाव आयोग की जगह उन्होंने स्वतन्त्र प्रेस को रख दिया। इसकी वजह यह थी कि स्वतन्त्र प्रेस के परिवेश में पत्रकारों की जिम्मेदारी राजनीतिज्ञों की भांति ही आम जनता के प्रति होती है और केवल जनहित ही उनकी लेखनी का लक्ष्य होता है, परन्तु कालान्तर में मीडिया एक व्यापार के रूप में विकसित होता गया और पत्रकारों की जिम्मेदारी मीडिया मालिकों के प्रति होने लगी जिसमें जनहित का पक्ष गौण होता चला गया, मगर दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बढ़ने लगी, क्योंकि विधानसभा व लोकसभा चुनाव अलग- अलग होने लगे। 1967 तक पूरे देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे जिन्हें चुनाव आयोग बखूबी किया करता था, मगर इस वर्ष पूरे देश के विधानसभा चुनाव परिणामों में मूलभूत अन्तर आया और भारत के तब के कुल 15 राज्यों में से नौ राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। इनमें से जहां मिला भी वहां कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने विद्रोह कर कुछ विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टियां बना लीं। इन नौ राज्यों में सभी कांग्रेस विरोधी दलों ने आपस में हाथ मिला कर खिचड़ी सरकारें बनाईं, जिन्हें संयुक्त विधायक दलों की सरकार कहा गया। बेशक कुछ राज्यों में दो या तीन से अधिक विपक्षी दलों ने मिलकर भी सरकारें बनाई थीं। ये सरकारें टिक नहीं सकीं और अपने ही अन्तर्विरोधों के चलते पांच साल से बहुत पहले ही गिर गईं जिसकी वजह से ऐसे राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए। तभी से भारत में लोकसभा व विधानसभा चुनाव अलग-अलग होने लगे मगर इससे भारत का लोकतन्त्र मजबूत ही हुआ क्योंकि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मतदाताओं की पसन्द में अन्तर आने लगा। चुनाव आयोग ने मध्यावधि चुनाव भी बहुत सफलता के साथ कराये और ये चुनाव केन्द्र में कांग्रेस की स्व. इन्दिरा गांधी की सरकार रहते हुए, परन्तु पूरे भारत में 1969 में चुनाव आयोग पहली बार

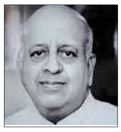

तब लोकचर्चा या जन विमर्श में आया जब इस वर्ष में कांग्रेस पार्टी का पहली बार विभाजन राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर हुआ। इन्दिरा जी ने प्रधानमन्त्री रहते हुए अपनी पार्टी कांग्रेस से इस मुद्दे पर विद्रोह कर दिया था। तब कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च संस्था कार्य समिति ने इन्दिरा जी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से ही अलग कर दिया। इस पर इन्दिरा जी ने कांग्रेस के अपने अनुयाई सांसदों व विधायकों के साथ एक समानान्तर दूसरी कांग्रेस पार्टी की घोषणा कर दी और इसे ही असली कांग्रेस बताया। मगर उस समय कांग्रेस के सभी बड़े नेता कांग्रेस कार्य समिति के फैसले के साथ थे जबकि इन्दिरा जी के साथ अधिकतर दूसरे पायदान पर रहने वाले नेता थे। तब कांग्रेस विघटन का मसला तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त स्व. एस.पी. सेन वर्मा के पास गया, क्योंकि कांग्रेस के दोनों ही गुट अपने-अपने को असली कांग्रेस बता रहे थे। दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय 10 जन्तर-मन्तर रोड कार्यसमिति के नेताओं के कब्जे में था, तो सरकार पर इन्दिरा गुट का कब्जा था हालांकि उनकी सरकार कांग्रेस के दोफाड़ होने की वजह से अल्पमत में आ गई थी, मगर तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने इन्दिरा गांधी का साथ दिया और उनकी सरकार को थामे रखा। श्री सेनवर्मा के सामने दोनों ही कांग्रेस गुटों ने दलील दी कि वे ही असली कांग्रेस हैं अतः पार्टी के चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी पर उनका ही दावा ही सही है। ऐसे ही दावे पार्टी के मुख्यालय 10 जन्तर-मन्तर रोड के बारे में किये गये। श्री वर्मा के समक्ष यह मुकद्दमा बहुत लम्बा चला। उन्होंने अन्त में अपना फैसला दिया कि चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी जब्त (सीज) किया जाता है और दोनों गुटों द्वारा सुझाये गये अन्य चुनाव चिन्हों पर विचार करने के बाद कार्यसमिति वाले कांग्रेस गुट को संगठन कांग्रेस व इन्दिरा गुट को कांग्रेस (ई) का नाम दिया जाता है तथा संगठन कांग्रेस को चरखा कातती हुई महिला व इन्दिरा कांग्रेस को गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है तथा 10 जन्तर-मन्तर कार्यालय संगठन कांग्रेस को दिया जाता है। जब तक चुनाव आयोग का यह फैसला आया तब तक पूरे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एस.पी. सेन वर्मा का नाम बच्चे- बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था और लोगों को पता चल चुका था कि प्रधानमन्त्री होने के बावजूद इन्दिरा गांधी को चुनाव आयोग की चौखट पर कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद 1977 में इमरजैंसी हटने के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो चुनाव आयोग के प्रति विपक्ष आशंकित तो हुआ मगर उसने भरोसा नहीं खोया। चुनाव परिणामों ने सिद्ध कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग ऐसे खरे सोने की तरह है जिसमें रंचमात्र भी मिलावट नहीं है, क्योंकि इन चुनावों में इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री होने के बावजूद अपना लोकसभा चुनाव हार गई थीं, परन्तु वर्तमान में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जिस तरह संकट गहरा रहा है वह भारत के लोकतन्त्र के हित में नहीं है। बहुत मामूली सी बात है कि जब भी चुनाव में मतगणना शुरू होती है तो वह पोस्टल बैलेटों की गिनती से ही शुरू होती है। पहले आम चुनावों 1952 में यह परम्परा पड़ी थी जिस पर बाद के दशकों पर ईमानदारी से अमल होता रहा मगर पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जमाने में इसमें अचानक परिवर्तन आ गया और इनकी गणना सबसे बाद में की जाने लगी जिस पर विपक्षी दलों ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया और इसे चुनाव परिणामों में हेर-फेर करने वाली गतिविधि तक कहा। जब राजीव कुमार से विपक्षी दलों न शिकायत की तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है अतः वह चुनावों के मौके पर कोई नया फैसला नहीं कर सकते हैं। यही मसला जब नये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के सामने आया तो उन्होंने फैसला दिया कि पोस्टल बैलेटों की गिनती गणना का अंतिम चक्र पूरा होने से पहले कर ली जायेगी। आखिरकार उनकी कौन सी मजबूरी है कि वह यह नहीं कह सकते कि पोस्टल बैलेटों की गिनती सबसे शुरू में ही पूरी कर ली जायेगी जिससे किसी भी प्रकार के सन्देह की गुंजाइश ही न रहे। चुनाव आयोग के कामकाज को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की नैतिकता से मुख्य चुनाव आयुक्त बंधे रहते हैं।

उन्हें आयोग के हर कार्य को पूरी तरह पारदर्शी इसलिए भी बनाना होता है, क्योंकि इस देश के लोगों के सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार के वह संरक्षक होते हैं और यह अधिकार एक वोट का होता है। अतः सभी चुनाव आयुक्तों को अपने पुराने समकक्षों के कामकाज को ध्यान में रखना चाहिए। बेशक इस सिलसिले में टी.एन. शेषन का नाम भी लिया जा सकता है।

हरियाणा में कांग्रेस का दिलचस्प दांव

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

कांग्रेस हरियाणा में एक दिलचस्प जातिगत दांव के साथ अपनी किस्मत आजमा रही है। 47 सालों में पहली बार, उसने राज्य में अपने शीर्ष दो नेतृत्व पदों के लिए जाट-ओबीसी की जोड़ी को चुना है। पुराने दिग्गज जाट नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा विधानसभा में विधायक दल के नेता होंगे, जबकि ओबीसी नेता राव नरेंद्र सिंह राज्य इकाई के अध्यक्ष होंगे। इस जोड़ी में दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं है, जो हरियाणा में पार्टी के समर्थन की रीढ़ रहा है। पिछले 18 सालों से, कांग्रेस यह सुनिश्चित करती रही है कि दोनों में से एक पद दलित के पास हो। ओबीसी चेहरे को आगे बढ़ाने का

फैसला राहुल गांधी के ओबीसी तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा प्रतीत होता है। यह एक ऐसा एजेंडा है जिस पर वह पिछले कुछ समय से काम कर रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में उत्तर भारत में पिछड़ी जातियों के विशाल समुदाय पर भाजपा के कब्ज़े को तोड़ने के लिए इसमें नई तेज़ी आई है। कांग्रेसी खेमे को चिंता है कि यह नया जातिगत दांव उसके पारंपरिक दलित वोट बैंक को हिला देगा। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के विधानसभा चुनावों में कई दलित समूहों ने भाजपा को वोट दिया, जिससे पार्टी की राज्य पर कब्ज़ा करने की उम्मीदें धराशायी हो गईं। जनमत सर्वेक्षणों में कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त दी गई थी। हालांकि, नतीजे इसके विपरीत साबित हुए और भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट आई।

भागवत के संबोधन में दूसरे देशों को भी नसीहत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के पारंपरिक विजयादशमी भाषण में अतीत से एक उल्लेखनीय बदलाव दिखा। पहली बार, आरएसएस प्रमुख ने अपने संबोधन को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए तैयार किया, जिसमें दिवंगत अमेरिकी राष्ट्रपति

अब्राहम लिंकन, वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई, जो फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन के पतन का कारण बनी, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ युद्धों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आई रुकावटों का भी उल्लेख किया गया। दिलचस्प बात यह है कि भाषण का 15 विदेशी भाषाओं और 22 भारतीय भाषाओं में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में विशेष आमंत्रितों में पश्चिमी मीडिया के विचारक शामिल थे। भागवत ने पड़ोस में हाल ही में सत्ता परिवर्तन करने वाली उथल-पुथल के बारे में भी बात की और "अराजकता के व्याकरण" को समाप्त करने का आह्वान किया। लद्दाख में हुए घटनाक्रम के बाद उन्होंने पर्यावरण संबंधी चिंताओं की अनदेखी करने वाले विकास मॉडल में सुधार का आह्वान किया। इसे मोदी सरकार के लिए इस नाज़ुक हिमालयी क्षेत्र में अपनी विकास परियोजनाओं पर पुनर्विचार करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लद्दाख में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व जाने-माने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक कर रहे हैं। आंदोलनकारी सड़क निर्माण की उन योजनाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि इससे क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा।

दस ब्रिटिश स्कूल खोलेंगे भारत में अपना कार्यालय

दस प्रसिद्ध ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल भारत में अपना कार्यालय खोल रहे हैं। वे न केवल ब्रिटेन का स्कूली पाठ्यक्रम अपने साथ लाएंगे, बल्कि छात्रों को पूरी तरह से ब्रिटिश अनुभव देने के लिए इन स्कूलों से जुड़े पारंपरिक वास्तुशिल्प तत्वों को भी शामिल कर रहे हैं। तीन स्कूल पहले ही शुरू हो चुके हैं, जिनमें प्रसिद्ध हैरो इंटरनेशनल स्कूल भी शामिल है, जिसके पूर्व छात्रों में जवाहरलाल नेहरू और विंस्टन चर्चिल जैसे दिग्गज शामिल हैं। हैरो

2023 में बेंगलुरु में खुला। इन स्कूलों के प्रशासक भारत में अपार अवसर देखते हैं। उन्हें लगता है कि अभिजात वर्ग और धनी वर्ग चाहते हैं कि उनके बच्चे वैश्विक मानकों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करें और वे इस भावना का लाभ उठाना चाहते हैं। ज़ाहिर है, स्कूलों का उद्देश्य ब्रिटिश अनुभव को भारतीय संदर्भ में समाहित करना है। उदाहरण के लिए, श्रूज़बरी इंटरनेशनल स्कूल ने हाल ही में एक गरबा संध्या का आयोजन किया, जिसके लिए उसके एक डच शिक्षक ने घाघरा-चोली खरीदी। श्रूज़बरी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। स्वाभाविक रूप से, फीस बहुत ज़्यादा है और अभिभावकों को सालाना 20 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन भीड़ को देखते हुए, ऐसा लगता है कि अभिभावक अपने बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाने में मदद करने के लिए बड़ी रकम खर्च करने को तैयार हैं।

बंगाल विजय के लिये शाह का कोलकाता प्रवास

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हर महीने कम से कम दस दिन पश्चिम बंगाल में बिताने का फैसला इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मायावी राज्य

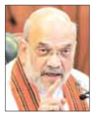

पर कब्ज़ा करने को लेकर कितनी गंभीर है। दरअसल, वह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए इतने दृढ़ हैं कि पार्टी कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में किराये के आवास की तलाश कर रही है। चुनाव खत्म होने तक यही उनका ठिकाना रहेगा। यही मध्य प्रदेश का फॉर्मूला है। 2023 में, राज्य में चार कार्यकाल के बाद भाजपा सरकार पर ज़बरदस्त सत्ता-विरोधी लहर का बोझ था। चुनाव से आठ महीने पहले, शाह ने चुनाव प्रचार की निगरानी के लिए कम से कम आधे महीने राज्य में रहने का फैसला किया। यह रणनीति कारगर रही और भाजपा अब तक की सबसे बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापसी कर गई। अब देखना यह है कि क्या शाह पश्चिम बंगाल में भी मध्य प्रदेश जैसा प्रदर्शन दोहरा पाते हैं, जहां भाजपा का मुकाबला बनर्जी जैसी मज़बूत प्रतिद्वंद्वी से है।

मानव जीवन से कम कीमती नहीं पशुओं का जीवन

योगेश कुमार गोयल

> विश्व पशु कल्याण दिवस (4 अक्तूबर) पर विशेष

पशुओं के कल्याण मानकों में सुधार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 4 अक्तूबर को 'विश्व पशु कल्याण दिवस' मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस पहली बार बर्लिन में 24 मार्च 1925 को पशु कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया गया था। पशुओं की लुप्तप्राय प्रजातियों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए इटली के फ्लोरेंस में 1931 में आयोजित पारिस्थितिकीविदों के एक सम्मेलन में विश्व पशु दिवस की शुरुआत की गई और तब असीसी के सेंट फ्रांसिस के पर्व के कारण यह दिवस मनाने के लिए प्रतिवर्ष 4 अक्तूबर को ही चुना गया। 2003 में पहली विश्व पशु दिवस वेबसाइट यूके स्थित पशु कल्याण चैरिटी 'नेचर वॉच फाउंडेशन' द्वारा लांच की गई थी। इस दिन पशु अधिकारों को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों का समर्थन करके जानवरों के प्रति प्यार, देखभाल, स्नेह और सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। पशुओं के अधिकारों के लिए यह एक ऐसी वैश्विक पहल है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पशु कल्याण के लिए बेहतर मानक सुनिश्चित करना है।

पशु प्रेम के बारे में महात्मा गांधी कहते थे कि किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पशु मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो न केवल हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं बल्कि हमें बेहतर इंसान भी बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जानवर प्रकृति की पारिस्थितिकी को संतुलित रखते हुए हमारे पर्यावरण की रक्षा करने और मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मनुष्य और पशु न केवल एक-दूसरे पर निर्भर हैं बल्कि एक-दूसरे के पूरक भी हैं। सही मायनों में दोनों का अस्तित्व ही खुशहाली का प्रतीक है और यदि जंगल से किसी एक जीव की प्रजाति भी लुप्त होती है तो उसका असर सम्पूर्ण पर्यावरण पर पड़ता है। विश्व पशु दिवस विश्वभर में कल्याण मानकों के मिशन के साथ जानवरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक ऐसा सामाजिक आन्दोलन है, जो प्रतिवर्ष एक निर्धारित थीम के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 'विश्व पशु कल्याण दिवस' की थीम है 'जानवरों को बचाओ, ग्रह को बचाओ!'। भारत में करीब 70 फीसद आबादी कृषि तथा कृषि संबंधी व्यवसायों पर निर्भर है। प्राचीन काल से ही पशुपालन और कृषि व्यवसायों का आपस में गहरा संबंध रहा है। गरीबी से त्रस्त परिवारों के लिए तो पशुधन ग्रामीण मुद्राएं हैं, जो खासकर गरीब परिवारों के लिए बीमा विकल्प के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि यह उनके लिए ऐसी सम्पत्ति है, जिसे संकट के समय बेचा जा सकता है। यही कारण है पालतू पशुओं को 'पशुधन' कहा जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी पशुधन की बड़ी भागीदारी रही है। मानव और पशुओं के आपसी संबंध मानव जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पशुओं का मानवीय समाज में विभिन्न रूपों में योगदान होता है। पशुओं के साथ रहने से हमें स्वभाविक संवेदनशीलता, प्यार, सहयोग और उन्नति का अनुभव होता है।

बहुत से पशु-पक्षी तो ऐसे हैं, जो यदि धरती पर नहीं हों तो पृथ्वी पर मनुष्य का जीना ही मुश्किल हो जाएगा।अनेक मामलों में देखा जाता है कि मानवीय स्वार्थ के लिए कई जानवरों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। दरअसल इन पशुओं के विभिन्न अंग तथा उनके मल-मूत्र इत्यादि दवाइयां बनाने से लेकर खेतीबाड़ी तक में काम आते हैं और इनके कंकाल उर्वरक का काम करते हैं। हाथियों को हाथी दांत और गैंडे को उसके सींगों के लिए बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है जबकि उनकी प्राकृतिक मौत होने पर ये चीजें वैसे ही मिल जानी होती हैं। हाथी और गैंडे कीचड़ में रहकर दूसरे जानवरों के पीने के लिए किनारे पर पानी का इंतजाम करते हैं और सूखा नहीं पड़ने देते। हाथी जमीन को उपजाऊ बना सकता है जबकि गैंडा कीचड़ में रहकर मिट्टी की अदला-बदली का काम करता है और प्रतिदिन करीब पचास किलो वनस्पति की खुराक होने से जंगल में कूड़ा-कर्कट नहीं होने देता। उसके शरीर पर फसल के लिए हानिकारक कीड़े जमा हो जाते हैं, जो पक्षियों का भोजन बनते हैं। इस प्रकार गैंडे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। वैसे तो सभी पशु-पक्षी मनुष्य के सहायक होते हैं लेकिन उनके व्यवहार को समझे बगैर यदि उनके रहने की जगहों को उजाड़ने के प्रयास किए जाते हैं तो वे हिंसक होकर विनाश कर सकते हैं। तुर्की के विख्यात नाटककार, उपन्यासकार और विचारक मेहमत मूरत इल्डन का कहना था कि दुनिया में वन्यजीवों की रक्षा केवल दयालु दिलों के प्यार से ही की जा सकती है।

वाइल्ड हार्ट वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के संस्थापक पॉल ऑक्सटन कहते थे कि जब तक आपके भीतर प्रकृति के बीच रह रहे जंगली जीवों के प्रति ढेर सारा प्यार, दया और लगाव नहीं रहेगा, तब तक आप सच्चा सुख हासिल नहीं कर पाएंगे। मानव जाति को यह समझना होगा कि पशुओं का जीवन किसी भी तरह से हमारे जीवन से कम कीमती नहीं है। 'जैव विविधता के जनक' के नाम से विख्यात आधुनिक काल के डार्विन कहे जाने वाले हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पूर्व जीवविज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता ईओ विल्सन के अनुसार पृथ्वी पर प्रत्येक प्रजाति अत्यधिक देखभाल एवं प्रतिभा के साथ बनाई गई रचना और एक उत्कृष्ट कृति है। वन्यजीव फोटोग्राफर, प्रकृतिवादी और 'जॉय ऑफ बीयर्स' सहित कुछ पुस्तकों की लेखिका सिल्विया डोल्सन कहती हैं कि हमारी ही तरह जानवर भी प्यार, खुशी, डर और दर्द महसूस करते हैं लेकिन वे बोले गए शब्द को समझ नहीं पाते, अतः यह हमारा दायित्व है कि हम उनकी ओर से बोलें और सुनिश्चित करें कि उनकी भलाई और जीवन का सम्मान एवं सुरक्षा हो। इसके लिए प्रकृति और पशुओं के साथ अपने संबंधों में मनुष्य को सभ्य बनाना आवश्यक है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

महान लोगों को हमेशा औसत बुद्धि वाले लोगों के हिंसक विरोध का सामना करना पड़ता है।
-अल्बर्ट आइंसटीन

पाकिस्तान का असल चेहरा

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में 38 प्रमुख मांगों को लेकर जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन के एक व्यापक आंदोलन का रूप लेने से पाकिस्तान की मुश्किलें जल्द खत्म होती नहीं दिख रही हैं। हालांकि, बीते कुछ वर्षों से वहां के नागरिक कभी पानी और बिजली की कीमतों पर, तो कभी रोजगार के अभाव और सुरक्षा बलों की बर्बरता के खिलाफ आवाजें उठाते ही रहे हैं। पीओके में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ताजा गोलीबारी में करीब बारह लोग मारे जा चुके हैं और कई घायल भी हुए हैं। हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान खुद को कश्मीर का हितैषी बताता आया है, वही वर्षों से इस क्षेत्र में लोकतंत्र और मानवाधिकारों का गला घोंट रहा है। हालांकि दशकों में शायद यह पहली बार है, जब पीओके के नागरिक सीधे तौर पर पाकिस्तानी सरकार और सेना पर निशाना साध रहे हैं। अब तो स्थानीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी इस मामले में दखल देने और उन्हें पाकिस्तानी फौज से बचाने की गुजारिश की है। दरअसल पाकिस्तान की समस्या यह है कि उसकी भारत-विरोधी नीति का दांव पीओके में चल नहीं पा रहा है। भारत में जम्मू-कश्मीर में जिस तेज गति से बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, उसे देखकर श्रीनगर से बमुश्किल डेढ़ सौ किलोमीटर दूर पीओके के लोग भी अपनी सरकार से स्वाभाविक ही यही उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री शरीफ अमेरिका यात्रा के बाद लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं और वहीं से शांति की अपील करते हुए उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों के साथ संयम और धैर्य बरतने का निर्देश दिया है। दिलचस्प यह भी है कि पाकिस्तान से पीओके संभल नहीं रहा है, लेकिन उसने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए विवादित सर क्रीक क्षेत्र में निर्माण के इरादे जताए हैं। इस पर भारतीय रक्षा मंत्री ने उसे उचित ही इतिहास और भूगोल बदलने की चेतावनी दे दी है। दुनिया के लिए यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पोषक होने के साथ अपने

कब्जे वाले क्षेत्रों में भी वैसा ही व्यवहार करता है। ऐसे में, भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पीओके की असलियत उजागर करे। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह कहना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मौजूदा स्थितियां पीओके पर पाकिस्तान की ढीली होती पकड़ का ही संकेत देती हैं।

एक लड़की की कहानी

अमूमन अफ्रीकी कहानियां गरीबी, बीमारियों और अभावों के बारे में होती हैं। लेकिन, कांगो में एल्बिनिज्म नामक बीमारी के साथ पैदा हुई 23 साल की जूजी की प्रेरणादायक दास्तान कुछ अलग है। पूरी दुनिया को यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए।

निकोलस क्रिस्टॉफ
द न्यूयॉर्क टाइम्स

मुझे इस बात की चिंता है कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिकी सहायता में कटौती के बारे में अफ्रीका से की गई मेरी रिपोर्टिंग से यह गलत धारणा बन सकती है कि यहां के ग्रामीण और शरणार्थी लोग असहाय हैं, जिनकी एकमात्र पहचान यही है कि वे वाशिंगटन द्वारा पैदा किए संकटों के शिकार हैं। पर यह सच नहीं है। सबसे गरीब देशों के लोग भी जरूरत पड़ने पर अक्सर अपनी ताकत दिखा जाते हैं।

वाशिंगटन के गैर-जिम्मेदार फैसलों के कारण अपने बच्चों की मौत पर वे भी हमारी तरह रोते हैं, लेकिन हम असंभव परिस्थितियों से लड़ने के उनके साहस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मसलन, चैंटल जूजी का ही उदाहरण ले लीजिए। जूजी का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। करीब 23 साल पहले वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के एक छोटे से गांव में एल्बिनिज्म (सफेद दाग जैसी बीमारी) के साथ पैदा हुई थी। उसकी नानी उसे मार डालना चाहती थीं, यह सोचकर कि उसकी सफेद त्वचा एक अभिशाप है। सौभाग्य से, उसके माता-पिता ने उसकी रक्षा की। अपने माता-पिता की दस में से पांचवीं संतान जूजी बेहतरीन छात्रा थी, लेकिन गांव का स्कूल बेहद भयावह था। शिक्षक छात्रों को पीटते थे। बच्चों के पास कोई पाठ्यपुस्तक नहीं थी। दूसरे छात्र जूजी को उसके रंग के कारण इस डर से छूते तक नहीं थे कि कहीं उसे भी एल्बिनिज्म का संक्रमण न हो जाए। फिर जून 2014 में, एक विरोधी जातीय समूह ने उसके गांव पर हमला किया, उसका घर जला दिया और उसके माता-पिता की हत्या कर दी। उसका सबसे बड़ा भाई बाकी नौ बच्चों को सुरक्षित युगांडा ले गया, जहां उनके पास पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। 13 साल की उम्र में जूजी अनाथ होकर शरणार्थी बस्ती में रहती थी और अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करती थी। चूंकि, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों को कभी-कभी मार दिया जाता है, ताकि उनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल जादू-टोने के लिए किया जा सके। इसलिए 16 साल की उम्र में असुरक्षित महसूस करते हुए जूजी नैरोबी (केन्या) भाग गई।

पासपोर्ट न होने के बावजूद, वह हिम्मत करके सीमा पार चली गई और किसी ने उसे रोका तक नहीं। नैरोबी में, उसने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी से संपर्क किया, जिसने उसे अन्य अनाथों के साथ रहने की जगह दी। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के खतरे को समझते हुए एजेंसी ने उसे अमेरिका में पुनर्वास के लिए एक उम्मीदवार के रूप में सूचीबद्ध किया। उसने बताया, 'एल्बिनिज्म के साथ पैदा होना मेरे लिए दुर्भाग्य था, लेकिन अब मेरे लिए देश छोड़ने का एक मौका था।' इसलिए 2018 में, लगभग 17 साल की उम्र में जूजी मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हुई। लगभग पांच साल तक नियमित स्कूल से बाहर रहने के बावजूद वह वॉर्सेस्टर, मैसाचुसेट्स में नौवीं कक्षा में दाखिल हो गई। जूजी ने अपनी कक्षाओं में पूरी लगन से पढ़ाई की और तेजी से अंग्रेजी सीख ली। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसने तीन साल में ए ग्रेड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की, और फिर वेलेस्ली कॉलेज में दाखिला लिया।

वेलेस्ली में रहते हुए जूजी हिलेरी क्लिंटन और एंजेलिना जोली के मार्गदर्शन में शरणार्थी कार्यकर्ता बन गई, संयुक्त राष्ट्र के साथ काम किया, सम्मेलनों में भाषण, टेड टॉक वगैरह दिए। चूंकि शिक्षा ने उसके जीवन को बदल दिया था, इसलिए उसने युगांडा की शरणार्थी बस्ती में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक गैर-लाभकारी संस्था 'रिफ्यूजी कैन बी' की स्थापना की, जहां वह कभी रहती थी। वह अमेरिकी नागरिक भी बन गई और उसने अपने नौ भाई-बहनों में से आठ को भी अमेरिका बुला लिया। जूजी अब अपनी संस्था का विस्तार करने के लिए पूर्णकालिक रूप से काम कर रही हैं। हाल ही में मैंने युगांडा में उसके साथ एक दिन बिताया, जहां उसका स्वागत एक लौटी हुई नायिका के रूप में किया गया। क्लाउड रुजिंडाना नामक एक शरणार्थी ने रोते हुए मुझे बताया कि कैसे इस गर्मी में उसने अपनी पत्नी को किसी बीमारी के कारण खो दिया। अस्पताल ने उसे बताया कि अमेरिकी सहायता में कटौती के कारण उसके पास दवाइयां खत्म हो गई हैं। अब उनका ध्यान छठी कक्षा में पढ़ने वाली बेटी एस्थर पर है, जो प्राथमिक स्कूल पूरा करने वाली परिवार की पहली लड़की बनेगी। उसने जूजी से कहा, 'तुम्हारे सहयोग की वजह से मैं उसे स्कूल भेज पा रहा हूं। उसे स्कूल बहुत पसंद है।'

मुझे नहीं मालूम कि जूजी का संगठन कितना कारगर होगा, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नया है। लेकिन मैं जूजी की कहानी तीन कारणों से साझा कर रहा हूं। पहला, दुनिया अब शरणार्थियों से भरी पड़ी है, जिनमें से ज्यादातर अवांछित और अक्सर तिरस्कृत हैं। जूजी हमें याद दिलाती है कि कैसे वे लोग अक्सर प्रतिभा, शक्ति, महत्वाकांक्षा, उद्यमशीलता और लचीलेपन का प्रतीक होते हैं, जो समाजों को समृद्ध बनाते हैं। मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा, जब मैंने युगांडा में ग्रामीण महिलाओं की एक कतार देखी, जो अपने बच्चों को टीका दिलवाने मीलों पैदल चलकर आई थीं, ठीक उसी समय, जब रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर अमेरिका में टीकों पर संदेह जता रहे थे। युगांडा की इन महिलाओं ने टीकाकरण के अभाव में बच्चों को मरते देखा था, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को जीवित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने का दृढ़ निश्चय किया। दूसरा, ऐसे वक्त में जब ट्रंप प्रशासन ने मानवीय सहायता में कटौती की है और इसके परिणामस्वरूप मर रहे बच्चों के प्रति घोर उदासीनता दिखाई है, जूजी एक वैकल्पिक नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। वाशिंगटन हाथ पर हाथ धरे बैठ सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई आम लोग शक्ति या साधन की कमी के बावजूद अपने मूल्यों को बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं। और इसलिए जूजी अमेरिकी विदेश मंत्री से बेहतर रोल मॉडल हो सकती हैं।

तीसरा, विकासशील देशों में सबसे बड़ा अप्रयुक्त संसाधन तेल, सोना या दुर्लभ मृदा खनिज नहीं हैं; ये गांव की लड़कियां हैं, जिन्हें अक्सर स्कूल जाने से रोक दिया जाता है, बचपन में ही शादी कर दी जाती है और उनसे पानी लाने और दूसरों की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है। क्रूर विरोधाभास यह है कि कांगो के एक सुदूर गांव में हुए भीषण नरसंहार के कारण ही चैंटल जूजी नाम की एक अनाथ लड़की को खुद को विकसित करने का रास्ता मिला।

जूजी का उदाहरण बताता है कि अफ्रीका से केवल भयानक कहानियां ही पैदा नहीं होतीं और यह भी कि अवसर बेशक सर्वत्र उपलब्ध न हों, लेकिन प्रतिभाएं कहीं से भी पैदा हो सकती हैं, ये जगह देख कर नहीं पैदा होतीं। इन प्रतिभाओं को अगर थोड़े भी अवसर मिलें, तो ये दुनिया बदल सकती हैं।

©The New York Times 2025

आर्थिकी

रुपये की नई दिशा

आरबीआई द्वारा उठाए गए हालिया कदम केवल मौद्रिक सुधार नहीं हैं, बल्कि ये भारत की दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि और रणनीतिक महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं।

डॉ. सुरजीत सिंह

वैश्विक आर्थिक हालात से अवरोधित होते व्यापार एवं बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया है कि डॉलर पर अधिक निर्भरता सुरक्षित नहीं है। ऐसे में, यदि व्यापार का बड़ा हिस्सा भारतीय रुपये में निपटाया जाए, तो यह न केवल लेन-देन को सरल बनाएगा, बल्कि भारत की वित्तीय स्वायत्तता को भी मजबूत करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में कई नए प्रावधान लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत आरबीआई ने पड़ोसी एवं अन्य देशों को रुपये में ऋण की सुविधा दी है। अब भारतीय बैंक भूटान, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों की कंपनियों और संस्थाओं को रुपये में कर्ज दे सकेंगे। कर्ज की वापसी भी रुपये में ही होगी।

रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की शुरुआत वर्ष 2022 में आरबीआई ने स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट से की थी। इसके जरिये कोई भी विदेशी बैंक भारतीय बैंकों में खाता खोलकर सीधे रुपये में लेन-देन कर सकता है। भारत रूस के साथ व्यापार निपटान रुपये में कर चुका है। भारत और ईरान के बीच कुछ व्यापार लेन-देन रुपये में करने की तैयारी है। नेपाल और भूटान में रुपया पहले से मान्य है। बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, केन्या, मलयेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, सिंगापुर, रूस, श्रीलंका, ब्रिटेन सहित करीब 18 देशों को स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट व्यवस्था में शामिल किया गया है। ब्रिक्स देशों के एनडीबी बैंक ने घोषणा की है कि वह भारत का पहला रुपया-मूल्यवर्गित बॉन्ड जारी करने की योजना बना रहा है। भारत पहले ही कुछ द्विपक्षीय प्रयोग कर चुका है, और कई देश इसमें रुचि दिखा चुके हैं।

आरबीआई द्वारा रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में उठाए गए नवीनतम प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि आयात-निर्यात के लेन-देन में रुपये का उपयोग बढ़ने से विदेशी मुद्रा का जोखिम घटेगा। विदेशी निवेशकों को लेन-देन की अधिक सुविधा मिलेगी। वित्तीय बाजारों में कॉरपोरेट बॉन्ड और अन्य साधनों में निवेश से घरेलू वित्तीय तंत्र को मजबूती मिलेगी।

भारत के कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को बढ़ावा मिलने से रुपये की वैश्विक मांग और उपयोगिता बढ़ेगी। भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और आगामी दशकों में उच्च वृद्धि जारी रहने की संभावना है। यदि भारत निरंतर आर्थिक मजबूती दिखाए, तो उसकी मुद्रा को अधिक स्वीकार्यता मिल सकती है। यद्यपि डॉलर और यूरो जैसी मजबूत मुद्राओं से मुकाबले में कई जोखिम एवं चुनौतियां भी हैं, जिनको समझकर ही आगे बढ़ना होगा। भारत अभी पूर्ण पूंजी खाता खुलापन नहीं देता, पूंजी लेन-देन पर अभी प्रतिबंध हैं। भारत का व्यापार घाटा रुपये की वैश्विक मांग को सीमित करता है। विदेशी निवेशकों का विश्वास, मुद्रा स्थिरता, आर्थिक एवं राजनीतिक विश्वसनीयता, मुद्रा अवमूल्यन के डर आदि से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर, बुनियादी आर्थिक-संरचनात्मक सुधार जैसे बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय बाजार, विनियामक ढांचा इत्यादि को मजबूत करना होगा। इस दीर्घकालीन लक्ष्य को 10 से 20 वर्षों में हासिल करने के लिए रणनीतिक रूप से कार्य कर स्वयं को दक्षिण एशिया में एक वित्तीय नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। कुल मिलाकर, भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में आरबीआई द्वारा उठाए गए हालिया कदम केवल मौद्रिक सुधार नहीं हैं, बल्कि ये भारत की दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि और रणनीतिक महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं।

edit@amarujala.com

एआई के पास उपभोक्ता के बारे में ऐसी बातें जानने की अद्भुत क्षमता है, जिसके बारे में इन्सानों ने शायद ही कभी सोचा होगा।
-रियान बेजनेक

साहस ही खुशी का मंत्र है

जीवन में अक्सर ठोकरें मिलती रहती हैं, लेकिन उनसे ही हम सीखते हैं। इसलिए हर चीज को आजमाने का साहस होना चाहिए। यह साहस ही खुशी की ओर ले जाता है।

रुत वीनहोवेन

जीवन धारा

खुशी अत्यंत मूल्यवान चीज है। अधिकांश लोग यह भली-भांति जानते हैं कि जीवन का आनंद लेना, कष्ट सहने से बेहतर है, और वे ऐसी नीतियों का समर्थन करते हैं, जिनका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए खुशी पैदा करना है। खुशी को समझना आवश्यक है। खुशी के कई अर्थ हैं। हम जीवन की संतुष्टि के अर्थ में खुद को खुशी तक सीमित रखते हैं, लेकिन हरेक इन्सान के लिए इसका मतलब अलग-अलग होता है।

सबसे पहले, यह आवश्यक है कि हम खुशी के मुख्य निर्धारकों को समझ सकें, न कि केवल यह कि लोगों को कौन-सी चीज खुशी देती है, और क्यों। हमें खुशी के परिणामों पर भी एक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ताकि संभावित आत्म-विनाशकारी प्रभावों का पता लगाया जा सके और अन्य मूल्यों के साथ तालमेल का मूल्यांकन किया जा सके। खुशी को समझने के लिए मनुष्य ने काफी विचार-विमर्श किया है। प्रारंभिक यूनानी दर्शन और बाद के कई दार्शनिक सिद्धांतों में खुशी एक प्रमुख मुद्दा था। जीवन की गुणवत्ता एक व्यापक चीज है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक स्थिति, सामाजिक संबंध, व्यक्तिगत विश्वास और पर्यावरण जैसे जीवन के कई पहलुओं को संदर्भित करती है, न कि केवल अंतिम पैमाने के गुणों को। यानी खुशी जीवन की गुणवत्ता का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह एकमात्र पहलू नहीं है। वर्तमान में यह विषय सामाजिक विज्ञानों में, विशेष रूप से सामाजिक संकेतक अनुसंधान में ध्यान आकर्षित कर रहा है।

जीवन का मूल्यांकन कमोबेश एक सचेतन मानसिक प्रक्रिया है और इसमें इस बात का आकलन शामिल है कि जीवन के बारे में उसकी धारणाएं किस हद तक व्यक्ति के जीवन के मानकों से मेल खाती हैं। जितना बेहतर तालमेल होगा, उतना ही अधिक सुखी व्यक्ति होगा। जब आप अपनी पसंद का जीवन जीते हैं, तभी आप खुश होते हैं। आपको चीजों को आजमाना होता है। कई बार आप जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं, जिनसे आपके विचार मेल नहीं खाते। सफलता से ज्यादा आपको ठोकरें मिलती हैं, तो भी आप अंततः एक ऐसे पेशे या दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो आपको रास आने लगता है। जीवन में मिलने वाली ठोकरों से ही हम सीखते हैं। इसलिए हर चीज को आजमाने का साहस होना चाहिए। यह साहस ही खुशी की ओर ले जाता है।

सोचने का काम तो चैटजीपीटी पर न छोड़िए

एआई टूल्स सावधानीपूर्वक डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन ये तब मददगार नहीं रह जाते, जब वे बच्चों के लिए सोचने का काम शुरू कर देते हैं।

जेनी एंडरसन

-साथ में रिबेका विन्थ्रॉप
द न्यूयॉर्क टाइम्स

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर अपना प्रभाव छोड़ने को तैयार है। इस उम्मीद में कि एआई के टूल्स बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, बड़ी व्यावसायिक कंपनियां भी इस दिशा में जुटी हैं। बीते जून में गूगल ने अपने एआई जेमिनी पर तीस नए शैक्षिक टूल्स शुरू किए, तो जुलाई के अंत में ओपन एआई ने भी चैटजीपीटी का स्टूडेंट-ट्यूटर स्टडी मोड पेश किया है।

माता-पिता को सतर्क रहना चाहिए कि नई डिजिटल तकनीक बच्चों को सही ढंग से मिल पा रही है अथवा नहीं। 20 वर्ष से भी पहले सोशल मीडिया के आगमन के तुरंत बाद इसने युवाओं की भावनात्मक स्थिति पर कहर बरपा दिया था। एआई के साथ, बच्चों का केवल भावनात्मक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि उनका संज्ञानात्मक विकास भी खतरे में है। जब बात सोचने से बचने के लिए टूल्स के इस्तेमाल की हो, तो इसमें तो इन्सान माहिर है। सही भी है, जब जीपीएस नेविगेट कर सकता है, तो मैप का उपयोग क्यों किया जाए? जब चैटजीपीटी व जेमिनी सोचने के लिए उपलब्ध हों, तो छात्र अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों करें? लेकिन, जब बात सीखने की आती है, तो उसमें सोचना व संघर्ष करना अहम हो जाता है। इससे ही तो आलोचनात्मक ढंग से सोचने का कौशल आता है। जैसे कसरत करने से शरीर बनता है, वैसे ही सोचने से दिमाग का विकास होता है। यह खासकर उन छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, जो शारीरिक-मानसिक विकास के दौर से गुजर रहे हैं।

कुछ एआई टूल सावधानीपूर्वक डिजाइन किए गए हैं और वे बच्चों को उनकी जिज्ञासा को समझने और सीखने की प्रक्रिया में निहित कमियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ओपनएआई का दावा है कि चैटजीपीटी में स्टडी मोड इसी तरह से काम करता है। लेकिन ये टूल्स तब मददगार नहीं रह जाते, जब वे बच्चों के लिए सोचने का काम शुरू कर देते हैं। दिक्कत यह है कि कई बच्चे और युवा इसी उद्देश्य के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। जब छात्र अपने निबंध या ऐसे ही किसी दूसरे काम के लिए चैटजीपीटी का उपयोग करते हैं, तो वे सीखने की क्षमता को कम कर रहे होते हैं। अगर कोई साइकिल, बच्चे को अपने ऊपर बैठाए और पैडल व हैंडल का नियंत्रण खुद ही करे, तो कोई बच्चा साइकिल चलाना कैसे सीखेगा? जब छात्र इतिहास के होमवर्क को पूरा करने के लिए जेमिनी या डीपसीक का उपयोग कर रहे होते हैं, तो वे उक्त ढंग की साइकिल की सवारी ही कर रहे होते हैं।

एमआईटी के शोधकर्ताओं ने शोध किया कि एआई लेखन कौशल को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने 18 से 39 वर्ष की आयु के विश्वविद्यालय के छात्रों को तीन समूहों में विभाजित किया। एक ने शुरू से चैटजीपीटी के साथ लिखा, दूसरे ने खुद लिखा, लेकिन वे गूगल सर्च का उपयोग कर सकते थे और तीसरे समूह को किसी भी टूल का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। बाद में, सभी छात्रों ने मदद के लिए चैटजीपीटी का उपयोग करके अपने लेखन को संशोधित किया। जिन लोगों ने शुरू से ही चैटजीपीटी के साथ लिखा, उनका लेखन सबसे खराब था। मस्तिष्क की जांच से पता चला कि उनके मस्तिष्क के सीखने से जुड़े हिस्से कम सक्रिय थे। उन्हें अपने लेखन को संशोधित करने में कठिनाई हुई, क्योंकि यह शुरू से ही उनका नहीं था। जिन प्रतिभागियों ने बगैर किसी सहायता के अपना काम तैयार किया, उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इस शोध ने यह दिखाया कि जब विश्वविद्यालयों के छात्र एआई के जोखिम से नहीं बच पा रहे, तो उनका क्या होगा, जिन्होंने अभी अपने सोचने का कौशल पूरी तरह से विकसित तक नहीं किया है। सीखने की एक प्रक्रिया होती है। सातवीं कक्षा में शिक्षक छात्रों को निबंध लेखन इस उम्मीद में नहीं सिखाते कि वे उच्च स्तरीय कला का सृजन करेंगे। छात्र निबंध लिखकर अपने विचारों को व्यवस्थित करना, साक्ष्यों का मूल्यांकन करना, तर्क गढ़ना और थीसिस प्रस्तुत करना सीखते हैं। जब एआई इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तब छात्र को एहसास तक नहीं होता कि एआई उनके आईक्यू का कितना नुकसान कर रहा है। माता-पिता की नजर ग्रेड पर होती है, लेकिन ग्रेड सीखने की क्षमता की आंशिक तस्वीर है और एआई इसे और कमजोर कर रहा है। अगर हम बच्चों को एआई का सही ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सिखा रहे हैं, तो हम उनमें एक नए तरह की कमी को पैदा कर रहे हैं।

ग्रामरली

ग्रामरली एआई टूल मशीन लर्निंग व डीप लर्निंग की मदद से भाषा का विश्लेषण करता है। यह चौबीस घंटे एक शिक्षक के तौर पर यूजर की मदद के लिए तैयार रहता है। यह यूजर को अपनी भाषा शैली को समायोजित करने की सुविधा देता है, और जटिल वाक्यांशों को सरल बनाने के लिए शॉर्टकट सुझाता है। बुनियादी व्याकरण, वर्तनी और विराम चिह्नों की जांच के अलावा, यह संक्षिप्तता, लहजे और स्पष्टता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है तथा विचार-मंथन और प्रारूपण में भी मदद करता है। इसमें ढेरों एक्सटेंशन और इंटीग्रेशन हैं, इसलिए यूजर इसे लगभग हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी टेक्स्ट बॉक्स का विकल्प हो।

©The New York Times 2025

t.me/AllNewsPapersPaid1

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

सिरप की शिकायत

कफ सिरप संबंधी शिकायतों का फिर उठना न केवल दुखद, बल्कि शर्मनाक भी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो शिकायतें आई हैं, वो काफी गंभीर किस्म की हैं। अब तक करीब 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और अगर ये मौतें नकली या खराब कफ सिरप की वजह से हुई हैं, तो फिर दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। कफ सिरप की शिकायत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये जेनेरिक श्रेणी की है और इसका वितरण सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए हुआ है। ऐसे में, यह विवाद या त्रासदी बहुत संगीन हो जाती है। क्या जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है? क्या सरकारी स्तर पर होने वाली खरीद में नकली या फर्जी दवाओं को खपाया जा रहा है? ध्यान देने की बात है कि जेनेरिक दवाओं का वितरण करने वाले औषधि केंद्रों की संख्या पूरे देश में बढ़ रही है। ऐसे केंद्रों की संख्या करीब 16 हजार हो गई है। सरकार इन केंद्रों की संख्या को 25 हजार तक पहुंचाने की कोशिश में है। ऐसे केंद्रों की लोकप्रियता इसलिए भी बढ़ रही है कि कम कीमत पर अच्छी दवाओं का वितरण इनके जरिए हो रहा है। ऐसे में, साजिश वाले कोण से भी इस शिकायत पर रोशनी डालने की जरूरत है।

कफ सिरप संबंधी शिकायतों पर राजस्थान सरकार ने ज्यादा मुस्तैदी से कदम उठाए हैं। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित दवा के 22 बैचों पर प्रतिबंध लगाए हैं। यह ध्यान देने की बात है कि सिरप की सुरक्षा साबित करने की कोशिश में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने दवा का सेवन किया और बेहोश हो गए। बेहोश होने के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों के मन में शक ने जन्म लिया है और इस शक को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश के अन्य राज्यों में भी दवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी वाली संस्थाएं सतर्क हो गई होंगी। जगह-जगह कफ सिरप को ही नहीं, अन्य दवाओं की गुणवत्ता को भी परखा जा रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा नमूनों का परीक्षण होना चाहिए। दवाओं के साथ खिलवाड़ से बड़ा अपराध कोई दूसरा हो नहीं सकता। ऐसे अक्षम्य अपराधियों को कतई छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इस सिरप का प्रयोग बच्चों में नहीं किया जाना था, तो फिर यह देखना होगा कि दवा लिखने वाले चिकित्सकों की गलती है या दलाली के भूखे दवा विक्रेताओं की। अनेक सिरप होते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं होते। गौरतलब है कि सीकर जिले में पांच साल के बच्चे और भरतपुर में दो साल के बच्चे की सिरप पीने से मौत हुई है। मध्य प्रदेश में ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि सिरप से बच्चों की किडनी खराब हो गई थी। ऐसे में, स्पष्ट है कि दवाओं की ईमानदार जांच होनी चाहिए।

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित कफ सिरप की वजह से मौत चिंताजनक है। अगर ये मौतें नकली या खराब सिरप की वजह से हुई हैं, तो दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए।

कफ सिरप की शिकायत का मामला तीन साल पहले भी सामने आया था। कथित रूप से अफ्रीकी देशों में भारतीय कफ सिरप की वजह से 50 से ज्यादा बच्चों की मौत बताई गई थी। तब भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए थे, उससे भी कड़े कदमों की आज जरूरत है। यह दवाओं का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण करने वाले देश भारत पर दुनिया के यकीन से जुड़ा मामला भी है। दुर्भाग्य से नकली दवाओं के मामले में चीन के साथ भारत का भी नाम लिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में बेची जाने वाली 5 से 25 प्रतिशत दवाएं नकली या घटिया हो सकती हैं। देश के जो इलाके नकली दवाओं के लिए जाने जाते हैं, वहां अब युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है। कड़े से कड़े कदमों के अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 04 अक्तूबर, 1950

कस्तूरबा ग्राम का शिलान्यास

कस्तूरबा ग्राम का शिलान्यास सरदार पटेल के हाथों मध्यभारत में इन्दौर के निकट सम्पन्न हुआ। मध्यभारत को उसके मौजूदा रूप में, अस्तित्व में लाने का श्रेय भी सरदार पटेल को ही है। मध्यभारत के निर्माण के बाद उसकी उन्नति और विकास की गुरुतर जिम्मेदारी वहां के जन-नायकों और जन-प्रतिनिधियों पर आई है। इस जिम्मेदारी को उन्हें संयुक्त रूप में उठाना था। तभी वह सफलतापूर्वक उठाई जा सकती थी। किन्तु वे आपसी झगड़ों में उलझ गये। इस कारण सरदार पटेल को इन्दौर जाने में बहुत खुशी नहीं थी। फिर भी वह वहां गये; क्योंकि कस्तूरबा ग्राम का शिलान्यास करने का एक महत्वपूर्ण काम सम्पादित करना था। कस्तूरबा स्मारक ट्रस्ट के सरदार अध्यक्ष हैं और गांधीजी खुद उसकी देखरेख और संचालन की जिम्मेदारी उनके सिर पर डाल गये हैं।

कस्तूरबा ट्रस्ट एक अखिल भारतीय संस्था है और उसकी स्थापना राष्ट्रमाता कस्तूरबा की याद को जीवित रखने के लिए हुई है। देशवासियों ने राष्ट्रमाता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लगभग सवा करोड़ रुपया जमा किया और इसी धन-राशि को उचित ढंग से व्यय करने के लिए कस्तूरबा ट्रस्ट की स्थापना हुई है। ट्रस्ट का उद्देश्य स्वयं गांधीजी ने ही निर्धारित कर दिया था। वह यह कि इस कोष का उपयोग भारत के देहातों में रहने वाली स्त्रियों और बच्चों के लिए किया जाये। यह उद्देश्य उन आदर्शों के सर्वथा अनुकूल है, जो राष्ट्रमाता कस्तूरबा को अत्यन्त प्रिय थे। सरदार पटेल ने ठीक ही कहा कि असली भारत देहातों में रहता है। नगरों में लोगों को जीवन की कुछ आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध भी हैं, किन्तु देहातों में रहने वालों को अभी तक उनसे वंचित ही रहना पड़ रहा है। देहातों की पीड़ित और उपेक्षित मानवता की सेवा सचमुच एक पुण्य कार्य है और कस्तूरबा ट्रस्ट का केन्द्रीय प्रधान कार्यालय अपने बीच में लाने का गौरव और सौभाग्य मध्यभारत में इन्दौर की निकटवर्ती भूमि को प्राप्त हुआ है। कस्तूरबा ग्राम को आत्म निर्भर बनाने की कल्पना की गई है।... ग्राम सेविकाओं को शिक्षण देने की व्यवस्था की जायेगी। एक आधुनिक अस्पताल और प्रसूतिगृह भी खोला जायेगा। गौशाला भी होगी और खेती बाड़ी भी की जाएगी। ग्राम के लिए मध्यभारत सरकार ने 250 एकड़ भूमि प्रदान की है। सरदार पटेल इस स्थान की रमणीयता पर मुग्ध हुए हैं।

अमेरिका में भारतवंशियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा है। फॉर्च्यून 500 में शामिल कई कंपनियों के सीईओ के रूप में दुनिया भर में इस समुदाय की प्रतिष्ठा है। मगर जब ट्रंप प्रशासन भारत के खिलाफ एक के बाद एक घातक कदम उठा रहा है, तब भारतीय डायस्पोरा खामोश है। आखिर क्यों नहीं इस समुदाय के लोग भारत के हितों के बचाव में वैसे मुखर हो रहे, जैसे इजरायल के हक में दुनिया भर के यहूदी होते हैं?

आमने-सामने

दुनिया से मजबूत रिश्ते जोड़ते प्रवासी भारतीय

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

- विदेश में भारतीय समुदाय को 'मॉडल डायस्पोरा' के रूप में पेश किया जाता है।
- इन्हें परिश्रमी, अनुशासित, कानून का पालन करने वाला माना जाता है।
- देश की अर्थव्यवस्था के विकास में इनके द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा अहम।

दुनिया भर में 3.21 करोड़ भारतवंशी विभिन्न देशों में रहते हैं। अकेले अमेरिका में ही 50 लाख से अधिक भारतवंशी हैं। मगर इस समय प्रवासी लोगों के बारे में नजरिया बदल रहा है। इसका मुख्य कारण प्रवासियों की गतिविधियां और उनके विकास के साथ ही संबंधित देशों में हो रहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव हैं। दुनिया में, खासकर विकसित देशों में जिस तरह के आर्थिक बदलाव हमें नजर आ रहे हैं या उनके यहां राजनीतिक, सामाजिक बदलाव नजर आ रहे, उसके कारण एक हद तक प्रवासी विरोधी भावनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं।

इसको थोड़ा और विस्तृत करके देखें, तो उन देशों में अब तक प्रवासी भारतीयों को लेकर जो कहानियां कही जाती थीं, वे सकारात्मक होती थीं। गौर करने वाली बात यह है कि इन देशों में अभी तक जो प्रवासी भारतीय थे, जो भारतीय समुदाय था, उनके बारे में वहां पर जो धारणा बनी हुई थी, वह यही थी कि भारत से एक ऐसा डायस्पोरा है, जो परिश्रमी, अनुशासित, कानून मानने वाले लोगों का है और वह न सिर्फ यहां की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करता है, बल्कि वह उच्च कोटि का है, उच्च शिक्षित है और वह भारत व दूसरे देशों के बीच सेतु का काम भी करता है।

अगर हम प्रवासी भारतीयों वाले प्रमुख देशों का जिक्र करें, तो इनमें अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के अलावा खाड़ी के देशों का नाम मुख्य रूप से आता है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति है। और यह उपस्थिति अब कई देशों में अपना राजनीतिक प्रभाव दर्ज कराने लगी है। खासकर, अमेरिका में हमने देखा है कि कैसे परमाणु समझौते के समय से ही वहां मौजूद भारतीय प्रवासियों ने प्रखर तौर पर भारत के हितों को बढ़ाने का काम किया। कनाडा में भी हमने देखा है कि किस तरह से वहां जो खालिस्तानी उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ भारतीय प्रवासियों ने बहुत सख्त आवाज उठाई और उनके खिलाफ कनाडा में माहौल तैयार किया। प्रवासी भारतीय दुनिया भर में हमारे राजनयिक और सांस्कृतिक पक्ष को मजबूत करने में जो योगदान कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। जहां कहीं भी वह जाते हैं, वहां के भारतीय प्रवासियों को 'लिविंग ब्रिज' का नाम देते हैं।

हमने यह भी देखा है कि प्रवासी भारतीयों का उन देशों की आर्थिक नीतियों, सफलता में भी बड़ा योगदान है, चाहे वह अमेरिका की सिलिकॉन वैली हो या अमेरिका व यूरोपीय देशों का आईटी सेक्टर। खाड़ी के देशों में हमने देखा कि प्रवासी भारतीय पहले वहां श्रमिक बनकर गए और बाद में पेशेवर तबके के तौर पर उनकी अर्थव्यवस्था का उत्थान किया। इसके अलावा, उनकी कमाई का जो हिस्सा भारत आता है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए पिछले कुछ सालों से भारत सरकार की लगातार कोशिश रही है कि प्रवासियों को भारत के आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाए। उनके साथ भारत सरकार सीधे संवाद करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कहीं भी जाते हैं, वहां के भारतीय समुदाय के साथ जुड़ते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं। पिछले कुछ सालों में या कहें, तो पिछले दशक में यह प्रवृत्ति हमें उभरती हुई नजर आई है। इसका उपयोग भारत ने भी अपनी विकास-यात्रा को गति देने के लिए किया है।

मगर आज स्थिति कुछ बदली-बदली नजर आ रही है। आज उनके बारे में वही कहानियां थोड़ी समस्याओं से घिरी हुई नजर आ रही हैं। भारतीय प्रवासियों के आगे ऐसे मुद्दे उभर रहे हैं, जो उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका में ट्रंप प्रशासन अपनी प्रवासी विरोधी नीतियों को और कसता जा रहा है। पहले उसने भारतीय उत्पादों के अमेरिका में आयात पर 50 प्रतिशत तक का टैरिफ लगाया, अब एच1 बी वीजा की फीस अप्रत्याशित रूप से एक लाख डॉलर (लगभग 90 लाख रुपये) कर दी है। दूसरी ओर, इंग्लैंड जैसे पश्चिमी देश हैं, वहां भी एक प्रवासी विरोधी, विशेष रूप से भारतीयों के खिलाफ एक भावना भड़क रही है। इसकी एक झलक पिछले महीने वहां 'इंग्लिश डिफेंस लीग' के बैनर तले ब्रिटेन के दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी राबिन्सन द्वारा आयोजित रैली में देख सकते हैं। 'यूनाइट द किंगडम' नाम से आयोजित इस रैली में करीब डेढ़ लाख ब्रिटिश नागरिक जुट गए और उन्होंने प्रवासियों के खिलाफ अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। इस हुजूम को न केवल ब्रिटेन के दक्षिणपंथियों ने, बल्कि अमेरिका से एलन मस्क और जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के नेता ने भी ऑनलाइन संबोधित किया। इससे पश्चिम के विकसित देशों में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ भड़क रही भावनाओं का पता चलता है। इस रैली में अनेक लोगों ने 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की टोपी पहन रखी थी। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार के खिलाफ 'रिफॉर्म यूके पार्टी' नामक दल भी खड़ा हो गया है, जो लगातार मुख्यधारा के दलों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इन घटनाओं से पूरे यूरोप और अमेरिका में भारतीय प्रवासी विरोधी भावनाओं का भी पता चलता है।

दुनिया के देशों में जो भारतीय समुदाय है, वह अपने आप को एक चौराहे पर खड़ा पा रहा है। क्योंकि जिन देशों को उसने अपनाया है और आज वहां जिस तरह से व्यापक स्तर पर प्रवासी विरोधी भावनाएं उभर रही हैं, उससे यह समुदाय कुछ परेशान है। इस समय जरूरत है कि भारत और भारतीय उनकी परेशानियों को समझें, उन गए प्रवासियों की भावनाओं को समझें और अब जो लोग वापस आना चाहते हैं, उनका स्वागत करें। ऐसा करना भारत की प्रगति के हित में है।

भारत से जो 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा का पलायन) हुआ है, वह अगर वापस आना चाहता है, तो भारत के नव-उत्थान में उन प्रतिभाओं के सकारात्मक योगदान की संभावना को देखते हुए दिल खोलकर अपनाएं और आगे बढ़ें। क्योंकि समस्याएं भारतीय प्रवासियों के कुछ करने या न करने से नहीं आ रही हैं, बल्कि वहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के कारण उपस्थित हुई हैं, जिससे उन पर भारी दबाव पड़ रहा है। इसलिए वे खामोश दिख रहे हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आज प्रवासियों की चुप्पी कहीं भारी न पड़ जाए

यहां स्कैन करें

संजय के भारद्वाज | प्रोफेसर, जेएनयू

- कई भारतवंशी अपने स्वार्थवश ट्रंप की वीजा नीति का समर्थन तक कर रहे।
- मजबूत राजनीतिक ताकत होते हुए भी वे इसका फायदा नहीं उठाना चाहते।
- प्रवासी भारतीय पश्चिम में खालिस्तानी दुष्प्रचार के मुकाबले में भी विफल रहे हैं।

यह बार-बार दिखा है कि जब विदेश में भारतवंशियों से भारतीय हितों के पक्ष में मुखर होने की अपेक्षा की गई, तो हमें निराशा हाथ लगी। अमेरिका में ही जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नीतियों से भारत के खिलाफ हमलावर रहे हैं, भारतवंशी अमेरिकी उन प्रशासनिक कदमों की मुखालफत नहीं कर सके। इससे भारत में कुछ हद तक भारतवंशी प्रवासियों के खिलाफ नाराजगी भी दिखने लगी है।

ऐसा क्यों है? पहले कुछ बुनियादी वजहों की चर्चा। वहां सफलता बनाम मौन का एक विरोधाभास रहा है। अमेरिका में सबसे सफल प्रवासी समुदाय होने के बावजूद भारतवंशी चुनिंदा मसलों पर ही मुखर होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान तो वे भारतीय विरासत का जमकर जश्न मनाते हैं, पर जब उनके सामने मातृभूमि के खिलाफ नीतिगत चुनौतियां पेश आती हैं, तो वे अपने कदम वापस खींच लेते हैं। वे राजनीतिक ताकत के रूप में मजबूत होने के बावजूद अपनी हैसियत का पूरा फायदा नहीं उठाना चाहते और भारत के रणनीतिक हितों के लिए खुद को संगठित नहीं कर पाते।

अगर इनकी तुलना अन्य देशों के प्रवासी तबकों से करें, तो कई परतें हमारे सामने खुलती हैं। जैसे- अमेरिका में रहने वाले यहूदियों को देखें। यह समुदाय इजरायल के लिए नियमित तौर पर प्रभावी ढंग से लामबंद होता है। अपने हितों की वकालत यह जितनी कुशलता से करता है, उससे भारतवंशियों को सीखना चाहिए। 1980 के दशक में चीन के प्रवासियों ने भी अपने देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी कंपनियों को साझेदारी के साथ निवेश के लिए प्रोत्साहित किया था। इसी तरह, अमेरिका में रहने वाले क्यूबा के लोगों ने दशकों से हवाना के प्रति अमेरिकी नीति को आकार देने में मदद की है। उन्होंने लगातार अपना जुड़ाव दिखाया है। इन सबके बरअक्स भारतीय प्रवासियों में समन्वित प्रयासों का अभाव रहा है और वे क्षेत्र, धर्म व राजनीतिक रुझान के आधार पर बंटे हुए दिखते हैं।

इसकी एक बड़ी वजह आर्थिक विरोधाभास है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगा दिया, जबकि पाकिस्तान को व्यापार में छूट दे दी। अमेरिका ने लोकतंत्र और आतंकवाद के मुद्दे को हमेशा अपने रणनीतिक हितों से जोड़कर देखा है, इसलिए वह हमेशा पाकिस्तान को वरीयता देता है। पाकिस्तान भी अमेरिका व चीन में चल रही प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाता रहता है, साथ ही ईरान-अमेरिकी विवाद में इस्लामिक कार्ड खेलता रहता है। बेशक, अमेरिका में टैरिफ ही नहीं, एच-1बी वीजा शुल्क में बढ़ोतरी करके भारत को निशाने पर लेने का प्रयास किया गया है, लेकिन 70 प्रतिशत भारतीय वीजाधारकों के प्रभावित होने के बावजूद भारतवंशी अमेरिकी इस मसले पर चुप हैं। अलबत्ता, कई भारतवंशी इस नीति का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस सख्ती में अपने बच्चों के रोजगार के सुखद अवसर दिख रहे हैं।

प्रवासी भारतीय राजनीतिक रूप से भी कई बार विफल साबित हुए हैं। खालिस्तान का ही मुद्दा लीजिए। भारतीय संप्रभुता के लिए यह सीधा-सीधा खतरा है, फिर भी प्रवासी भारतीय पश्चिमी देशों में खालिस्तानी अलगाववादियों के दुष्प्रचार का मुकाबला करने में विफल रहे हैं। इसी तरह, भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर हमले, मंदिरों में तोड़फोड़ या भारत के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों का भी कोई संगठित जवाब नहीं दिया जा सका है। वैसे, पश्चिम की सरकारें अलगाववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई से बचने के प्रयास करती हैं और इसके लिए वह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का राग अलापती हैं। मगर ऐसा कहकर हम अपनी गलतियां नहीं छिपा सकते।

प्रवासी भारतीयों की एक शिकायत रही है कि उनसे अपेक्षा तो खूब की जाती है, मगर उनकी उम्मीदों पर उस कदर खरा उतरने की कोशिश नहीं की जाती है। यह समुदाय भारत से दोहरी नागरिकता के अधिकार, कर छूट और निवेश संबंधी विशेषाधिकारों की मांग करता है। यह तबका राजनीतिक भागीदारी के अधिकार के साथ-साथ संपत्ति के स्वामित्व में लाभ व नियामक लाभों की भी अपेक्षा करता है। हालांकि, ऐसी अपेक्षा रखते हुए वह अपने कर्तव्यों की ज्यादा वकालत नहीं करता।

प्रवासियों की बेरुखी के कुछ मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं। जिस मुल्क में वे प्रवासी बनकर रहते हैं, वह उनको स्वीकार कर ले, यह डर कमोबेश सभी प्रवासियों में देखा गया है। चूंकि भारत की सशक्त वकालत करने पर उनकी यह मंशा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए वे चुप्पी साध जाते हैं। इसी तरह, उनकी सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वे स्थानीय सांस्कृतिक गौरव को कितना स्वीकार कर पाते हैं, इसलिए वे राजनीतिक जोखिम उठाने से बचना चाहते हैं। उनको खुद को 'वफादार' (यानी, आपकी वफादारी किस तरफ है) भी साबित करना होता है, इसी चिंता में कभी-कभी वे विवादित मसलों पर मौन रह जाना बेहतर समझते हैं।

कुछ पीढ़ीगत मुद्दे भी हैं। मसलन, दूसरी-तीसरी पीढ़ी के भारतवंशी प्रवासी भारत से उस कदर नहीं जुड़े हैं, जिस तरह पहली पीढ़ी के भारतवंशी हैं। वे भारत से अपने जुड़ाव को स्मृति के रूप में याद करना पसंद करते हैं, वर्तमान में उसे जीना नहीं चाहते। इसी तरह, वे अमेरिकी राजनीति को तो तवज्जो देते हैं, पर दक्षिण एशियाई भू-राजनीतिक मुद्दों को महत्व नहीं देना चाहते। ऐसा नहीं है कि उनकी चुप्पी का असर नहीं पड़ता। कभी-कभी यह रणनीतिक रूप से नुकसानदेह भी होता है। प्रवासियों के चुप रहने से भारत के खिलाफ नकारात्मक बातें शुरू हो जाती हैं। इसका दुष्प्रभाव यह भी होता है कि एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के उदय को कूटनीतिक धक्का लगता है।

बहरहाल, प्रवासियों के महत्व को कोई दरकिनार नहीं कर सकता, लेकिन कभी-कभी उनकी सोच देश-हित पर भारी पड़ जाती है। आज जब दुनिया कई ध्रुवों में बंटती दिख रही है, तब प्रवासियों से ठीक उसी तरह भारत के हितों की वकालत करने की अपेक्षा की जाती है, जिस तरह 2005 में उन्होंने भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु संधि के समय की थी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

भक्ति और समर्पण

आत्मनिर्भरता को अपार साहस की आवश्यकता पड़ती है। समर्पण के लिए कम साहस चाहिए। मगर जो व्यक्ति समर्पित नहीं हो सकता, वह आत्मनिर्भर भी नहीं बन सकता। जैसे पचास रुपये में दस रुपये निहित हैं, वैसे ही आत्मनिर्भरता में समर्पण निहित है। यदि तुम्हारे पास सौ रुपये नहीं हैं, तो तुम्हारे पास हजार रुपये भी नहीं हो सकते हैं। यदि तुममें समर्पण के लिए साहस नहीं, तब तुम्हारे लिए आत्मनिर्भर होना भी संभव नहीं। जो व्यक्ति समर्पण से डरते हैं, वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि लेशमात्र भय भी आत्मनिर्भरता में बाधक है।

प्रायः लोग समर्पण को जिम्मेदारियों से बचने का रास्ता मानते हैं और अपनी सभी समस्याओं के लिए ईश्वर को दोषी ठहराते हैं। वास्तव में, सच्चा समर्पण है संपूर्ण जिम्मेदारी लेना। कैसे? जिम्मेदारी लो और सहायता के लिए प्रार्थना करो। यही तुम्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है, क्योंकि आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं।

इसी तरह, भक्ति तुम्हारा पोषण करती है, तुम्हें मुक्त करती है, भक्ति ही ज्ञान का माध्यम भी है। जहां भक्ति होती है, वहां पर संशय नहीं होता। भक्ति सबसे अधिक ऊर्जा देती है। मनोभावों के उथल-पुथल से व्यक्ति इसलिए व्यथित होता है, क्योंकि उसमें भक्ति का अभाव है। एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और एक नदी में क्या अंतर है? जब पानी नदी के किनारों के बाहर बहता है, तो यह बाढ़ है। जब पानी तट के भीतर, एक विशेष दिशा में बहता है, तो यह नदी है। मनोभावों की बाढ़ में तुम्हारा मन अस्त-व्यस्त हो जाता है। परंतु जब भावनाओं का वेग एक दिशा में बहता है, तो यह भक्ति है। भक्ति और समर्पण बुद्धिमत्ता के लक्षण हैं।

श्री श्री रविशंकर

डोनाल्ड ट्रंप | अमेरिकी राष्ट्रपति

हमारे पास मध्य-पूर्व में युद्ध समाप्त कराने का एक बेहतरीन मौका है। हम सब पहली बार कोई खास काम करने के लिए तैयार हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसे जरूर पूरा करेंगे!

अमेरिकी शटडाउन का दुनिया पर होगा असर

सात वर्षों के बाद अमेरिका फिर से संघीय शटडाउन की चपेट में आ गया है। कांग्रेस (अमेरिकी संसद) द्वारा बजट पास न होने और रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सरकार के वीटो से लाखों सरकारी कर्मचारी वेतन रहित छुट्टी पर भेज दिए गए हैं। वहां राष्ट्रीय उद्यान, संग्रहालय और गैर-आवश्यक सेवाएं रोक दी गई हैं। 2018-19 के 35 दिनों के शटडाउन की तरह इस बार भी अर्थव्यवस्था को 10-11 अरब डॉलर के नुकसान का आकलन है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव गंभीर पड़ेगा। भारत इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप की 'अमेरिका प्रथम' नीति के तहत अगस्त 2025 से लागू 50 प्रतिशत टैरिफ से पहले ही यहां के 56 अरब डॉलर के निर्यात पर संकट आ चुका है। वस्त्र, रत्न-आभूषण, मसाले, झींगा और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों में 70 प्रतिशत तक की गिरावट का खतरा है, जिससे जीडीपी को लगभग 0.9 प्रतिशत (36 अरब डॉलर) का झटका लग सकता है। ऐसी सूरत में, शटडाउन के कारण व्यापार वार्ताएं और एच-1बी वीजा प्रक्रियाएं रुक सकती हैं, जिससे हम पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जिन सेवाओं को अमेरिका में रोका गया है, उससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात-आयात, कस्टम्स आदि में देरी हो सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि इस शटडाउन से अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के चेहरे पर चिंताएं पसर गई हैं। लिहाजा, उम्मीद यही है कि अमेरिका जल्द इस समस्या से बाहर निकलेगा और शटडाउन खत्म होगा।

आरके जैन 'अरिजीत', शिक्षाविद

अमेरिका में शटडाउन लागू हो गया है। इसके कारण लगभग साढ़े सात लाख कर्मचारी अब बिना तनख्वाह के हो गए हैं। केवल आपातकालीन सेवाओं में तनख्वाह दी जाएगी। कुछ विभागों में कर्मचारी बिना तनख्वाह काम कर सकते हैं, लेकिन उनको वेतन कब मिलेगा, यह तय नहीं है। नतीजतन, ट्रंप के विरोधी अब सड़कों पर हंगामा करने की तैयारी में हैं। यह अमेरिका के पतन की शुरुआत है। दुनिया को युद्ध में फंसाने वाला यह देश अब खुद परेशान है। ऐसी सूरत में अमेरिका में रह रहे सभी भारतीयों को अब वापस स्वदेश लौट आना चाहिए, अन्यथा उनके लिए अमेरिका में रहना आत्मघाती साबित हो सकता है। अमेरिका की यह दशा बता रही है कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। वह निस्संदेह एक बड़ी आर्थिक ताकत है, लेकिन इन दिनों वह अंदर से खोखला हो चुका है। अमेरिका की यह स्थिति वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी।

मनीष सिंह परमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

अमेरिकी शटडाउन

इससे बाजार में बड़ी गिरावट नहीं होगी

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) और व्हाइट हाउस में फंडिंग पर सहमति नहीं बनी, इसलिए अमेरिका में सरकार का कुछ काम बंद हो गया है। इससे कई एजेंसियों का कामकाज रुक सकता है। शेयर बाजार पर अभी बड़ा असर नहीं दिखा है, बल्कि वॉल स्ट्रीट ऊपर ही बंद हुआ, क्योंकि पिछली बार की तरह निवेशक इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे। मगर शटडाउन लंबा चला, तो महत्वपूर्ण आंकड़े (जैसे- नौकरियों की रिपोर्ट, मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े) समय पर नहीं आएंगे, और इससे विदेशी मुद्रा व ब्याज दरों में अस्थिरता आ सकती है। फिलहाल, सोना व यूरो मजबूत हुए हैं, डॉलर थोड़ा कमजोर रहा है। वोलैटिलिटी इंडेक्स 17 के आसपास है, यानी निवेशकों में थोड़ी बेचैनी है। एशियाई बाजार मिले-जुले रहे, जापान और यूरोप में दरें बढ़ने का डर बना हुआ है। मतलब, फिलहाल निवेशकों का मूड बेपरवाह है, पर शटडाउन लंबा चला, तो आंकड़ों की कमी और आर्थिक अनिश्चितता से बाजार में झटके आ सकते हैं। पिछली बार अमेरिका में शटडाउन जनवरी 2019 में हुआ था और वह 35 दिनों तक चला था, जो अब तक का सबसे लंबा शटडाउन था। उस दौरान सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुकी, कई एजेंसियों का काम ठप हुआ और आर्थिक आंकड़े समय पर जारी नहीं हो पाए। मगर शेयर बाजार की बात करें, तो शुरू में गिरावट जरूर आई थी, पर बड़ी गिरावट नहीं हुई, क्योंकि निवेशकों को भरोसा था कि यह अस्थायी स्थिति है। एसऐंडपी 500 उस समय कुछ दिनों तक दबाव में रहा, पर शटडाउन खत्म होते-होते उसने फिर से तेजी पकड़ ली। कुल मिलाकर, पिछली बार भी शॉर्ट-टर्म में बाजार पर सीमित असर पड़ा था, जबकि असली दिक्कत अर्थव्यवस्था के आंकड़ों की कमी और सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में देरी जैसी थी। इतिहास बताता है कि शटडाउन से बाजार में बड़ी गिरावट कम ही देखने को मिलती है, पर अगर लंबा चलता है, तो अस्थिरता बढ़ सकती है।

मार्केट मंथन पेज से

जिस तरह की नीति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, उससे व्हाइट हाउस और कांग्रेस में टकराव तय था। और, वही हुआ है। व्हाइट हाउस जिस बिल पर सहमत है, कांग्रेस उस पर अपनी आपत्ति जता रही है। इस कारण बिल पास नहीं हुए और अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ रहा है। यह कितना लंबा चलेगा, यह तो अभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अतीत को देखते हुए यह कह सकते हैं कि इसे लोग, खासकर निवेशक अब ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अमेरिका शायद ही आर्थिक रूप से ढह पाएगा।

कल्पना कुमारी, टिप्पणीकार

परिवर्तन के अनुसार ढलने से ही जीवन सुगम बनता है

कोलंबिया में राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर यह कहा कि भारत में लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इस बार उन्होंने कोलंबिया में लोकतंत्र पर कथित हमलों को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। वैसे तो राहुल गांधी एक अर्से से भारतीय लोकतंत्र को खतरे में पड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वे इस खतरे को कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हैं। वे इसके पहले भी अपनी विदेश यात्राओं में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भय का भूत खड़ा कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और बड़े लोकतांत्रिक देश इसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं। इधर उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर ही उछाला हुआ है, लेकिन इस मुद्दे की हवा निकलती दिख रही है। बिहार में मतदाता सूची का अंतिम मसौदा जारी हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन वोट चोरी का दावा करने वाले ऐसे लोगों को सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो बिहार के नागरिक हों और जिनका नाम वोटर लिस्ट से सभी वैध दस्तावेज होते हुए भी कट गया हो। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तब तक भारतीय लोकतंत्र को खतरे में पाएंगे, जब तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं आ जाती। क्या लोकतंत्र के सुरक्षित होने की गारंटी यही है कि दल विशेष यानी कांग्रेस लगातार चुनाव जीते और वह देश पर शासन भी करे? क्या देश पर शासन करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है? यदि राहुल गांधी यह समझ रहे हैं कि किसी मिथ्या आरोप को दोहराते रहने से वह सच की शक्ल ले लेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है, भले ही वे दुनिया भर में घूम-घूम कर अपने आरोप दोहराते रहें। राहुल गांधी की समस्या केवल यह नहीं है कि वे निराधार आरोपों को तूल देते हैं और फिर उन पर टिके रहने की सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, बल्कि यह भी है कि उनकी ओर से कई बार ऐसी गूढ़ या फिर पहेलीनुमा बातें कर दी जाती हैं, जिन्हें न तो समझा जा सकता है और न ही किसी को समझाया जा सकता है। कई बार तो उनके साथियों के लिए भी उनकी बातों का मतलब बता पाना कठिन होता है। उन्होंने कोलंबिया में इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच कार और मोटरसाइकिल के इंजन के भार में अंतर को लेकर जो विचित्र एवं अबूझ व्याख्या प्रस्तुत की, वह यदि हास-परिहास का विषय बनी तो इसके लिए वे किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। अपने आरोपों पर कायम न रह पाने और रह-रह कर अबूझ बातें करने के कारण ही राहुल गांधी की छवि परिपक्व नेता की नहीं बन पा रही है। यदि इससे किसी को सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए तो कांग्रेस को। इसलिए और भी, क्योंकि राहुल गांधी ही अघोषित रूप से उसका संचालन कर रहे हैं।

कहां गई दलीय प्रतिबद्धता

चुनाव के मौसम में टिकट न मिलने की भनक पाते ही जिस तरह से राजनीतिक दलों से जुड़े लोग दल बदल करने लगते हैं, उससे लगता है कि दलीय प्रतिबद्धता समाप्त हो गई है। अपवाद के तौर पर अब भी कुछ लोग बचे हुए हैं, जिन्हें टिकट या पद मिले न मिले, अपनी मान्यताओं पर कायम रहते हुए दल में जीवन खपा देते हैं। नई राजनीति की प्रतिबद्धता केवल टिकट के लिए रह गई है। इससे भी आश्चर्य का विषय यह है कि दलों को भी दल बदल की यह प्रवृत्ति स्वीकार्य है। कोई नया आदमी दूसरे दल से आए और अगले दिन टिकट लेकर चुनाव मैदान में चला जाए, यही चल रहा है। उम्मीदवारों को जिस तरह जीत की गारंटी चाहिए, वैसी ही गारंटी राजनीतिक दलों को भी सरकार बनाने के लिए चाहिए। नतीजा सबके सामने है। वर्षों तक किसी क्षेत्र में जान खपाने वाले कार्यकर्ता घर बैठे रह जाते हैं, दूसरे दल से आए सज्जन माननीय बन जाते हैं। वाम दलों को छोड़ दें तो सत्ता की दौड़ में शामिल सभी दलों की यही नीति बन गई है। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाला आदमी चाहिए। चाहे एक दिन पहले तक वह दल की आलोचना ही क्यों न करता रहा हो। कुछ ऐसे भी नेता हैं, जिन्हें यह याद नहीं कि कब किस दल में कितने दिन थे। इनमें कई विधायक, सांसद और मंत्री तक रह चुके हैं।

> उम्मीदवारों को जिस तरह जीत की गारंटी चाहिए, वैसी ही गारंटी राजनीतिक दलों को भी सरकार बनाने के लिए चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या शटडाउन संकट डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाएगा?

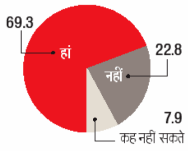

आज का सवाल

क्या आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पहुंचाए गए नुकसान की जानकारी उसी दौरान सार्वजनिक करना बेहतर होता?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बिगड़ैल पड़ोसी को काबू में करना होगा

ए. सूर्यप्रकाश

पाकिस्तान की पूरी ऊर्जा केवल भारतीयों के प्रति जहर उगलने में खर्च हो रही है

इस साल अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में मजहब पूछकर 26 गैर-मुस्लिमों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। पूरा देश इस घटना से शोक और आक्रोश में डूबा हुआ था, जबकि अधिकांश पाकिस्तानी इस बर्बर कृत्य की सराहना में लगे हुए थे। असल में अधिकांश पाकिस्तानी हिंदुओं के प्रति कुंठा और नफरत से भरे हुए हैं। चूंकि उनका वजूद ही नफरत पर टिका हुआ है, इसलिए वे इस भाव से बाहर निकल पाने में असमर्थ हैं। उनकी अशिष्ट भाषा भी उनकी अशिक्षा और हताशा को ही दर्शाती है। पढ़े-लिखे टेलीविजन एंकर, सैन्य जनरल से लेकर क्रिकेटर तक भी इसी नफरती आग के शिकार हैं। इस निर्लज्ज व्यवहार का ताजा नमूना बीते दिनों तब देखने को मिला, जब भारतीय टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी कार्यक्रम में अपमानजनक शब्द कहे। इस पर एंकर या अन्य प्रतिभागी भी उन्हें टोकने के बजाय खुद भी बेशर्मी से हंसने लगे। यह पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाता है कि यह देश पूरी तरह अमानवीय है और उसकी ऊर्जा केवल भारतीयों के प्रति जहर उगलने में खर्च हो रही है।

एशिया कप में तीन बार भारत के हाथों मुंह की खाकर तिलमिलाने वाले पाकिस्तान का दामन अतीत से ही दागदार रहा है। खुद की अलग पहचान को मुद्दा बनाकर भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान निर्माण से भी यह तबका संतुष्ट नहीं हुआ। अपने अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान का ध्यान अपनी तरक्की पर कम, भारत को नुकसान पहुंचाने पर अधिक रहा है। वह भारत से बदला लेने के लिए इतना जुनून से भरा है कि अपने लोगों के भी निर्ममतापूर्वक दमन से बाज नहीं आता। इसका उदाहरण पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में देखने को मिल रहा है। वहां लोग बगावत की राह पर हैं। भारत को पाकिस्तान के बिगड़ते हालात से सतर्क रहना होगा।

पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितना भी जहर उगले, उसे भारत के खिलाफ लड़ी सभी लड़ाइयों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 1965 के युद्ध में हारने के बाद वह हाजी पीर पास वापस करने के लिए गिड़गिड़ाया। फिर 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा और शर्मनाक आत्मसमर्पण था। शिमला में समझौते की मेज पर भुट्टो ने इन सैनिकों और कुछ अन्य इलाके वापस करने की भीख मांगी। 1999 के कारगिल संघर्ष में घुसपैठ के उसके मंसूबों पर भारतीय सैनिकों ने पानी फेर दिया।

अवधेश राजपूत

पाकिस्तान की अमानवीयता उस समय भी उजागर हुई थी, जब उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों के शव तक स्वीकार करने से उसने इन्कार कर दिया था। इस मामले में 2025 की कहानी भी अलग नहीं, जब पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है और पाकिस्तान को उसकी करतूत की कीमत भुगतनी ही होगी। आपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में स्थित लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। फिर भारतीय वायु सेना ने नूर खान एयर बेस सहित कई पाकिस्तानी एयर बेस और एयर स्ट्रिप्स को भी नष्ट किया। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो गई कि उसने युद्धविराम की गुहार लगाई। यह बात अलग है कि उसकी धमकियों और ढोंग का सिलसिला आज तक जारी है।

पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बेशर्मी से दावा किया कि इसे भारत के अपने लोगों ने ही अंजाम दिया और इसमें पाकिस्तानियों का कोई हाथ नहीं। पहले आतंकी हमला करना और फिर उससे पल्ला झाड़ना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। मुंबई हमले के बाद भी पाकिस्तान उसके पीछे अपनी भूमिका से कन्नी काटता रहा, पर अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही जनरल आसिम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था। जबकि पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि पाकिस्तान के पास भारत को निशाना बनाने के लिए चिह्नित 130 परमाणु वारहेड हैं। परमाणु युद्ध की विभीषिका को समझने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बातें नहीं करेगा।

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के साथ मैच न खेलकर उसके बहिष्कार की मांग भी उठी थी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए भारतीय टीम उसके खिलाफ खेलने उतरी। हालांकि भारतीय टीम ने पहले से तय कर लिया था कि पाकिस्तानियों से कोई संपर्क-शिष्टाचार नहीं रखना है। कप्तान ने टास के दौरान पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया। खिलाड़ियों ने भी मैच के बाद विरोधियों से हाथ मिलाने के पारंपरिक शिष्टाचार से किनारा किया। उसके बाद पाकिस्तानियों की बेचैनी देखने को मिली। उन्होंने शिकायती लहजे में हाथ-पैर तो खूब मारे, पर कहीं कोई राहत नहीं मिली। फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी गृहमंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्राफी नहीं लेने का फैसला किया। तब नकवी निर्लज्जता दिखाते हुए ट्राफी-पदक लेकर वहां से निकल गए। फाइनल में जीत के बाद जब पीएम मोदी ने यह पोस्ट किया कि 'खेल के मैदान में भी आपरेशन सिंदूर जारी है और परिणाम भी वैसा ही रहा' तो यह साफ हो गया कि यह मामला महज खेल तक सीमित नहीं रहा। इस पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का जवाब भी बहुत कुछ कहता है कि 'जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है, तो अच्छा लगता है।'

एशिया कप में सहभागिता का निर्णय लेने के बाद उसे जीतना देश के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। खासतौर से पहलगाम हमले के बाद खेल के मैदान में भी उसका बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान को कुचलना बेहद जरूरी था। इसके बावजूद भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने इस बिगड़ैल पड़ोसी के साथ अपने समीकरणों को नए सिरे से तय करे। उसे केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त नहीं। भारत को 1965 और 1971 जैसी उदारता नहीं दोहरानी चाहिए। तभी हम सीमापार की चुनौतियों से निपट सकेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सीट बंटवारे पर टिका महागठबंधन

राज कुमार सिंह

यदि कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की जिद करेगी तो महागठबंधन में मुश्किलें बढ़ेंगी

कार्यसमिति की बैठक के लिए 85 साल बाद बिहार लौटी कांग्रेस के इरादे को लेकर कोई संदेह था भी तो उसे पार्टी महासचिव नासिर हुसैन ने दूर कर दिया। उनका दावा है कि कांग्रेस जल्द ही घोषित होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रचार अभियान का नेतृत्व करेगी। पटना के सदाकत आश्रम में पांच घंटे चली कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्तावों में उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन असल मकसद विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और महागठबंधन में जीत की संभावनाओं वाली ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव ही है। कांग्रेस की चुनावी उम्मीदें भी राहुल द्वारा उठाए जा रहे सामाजिक न्याय और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर ही टिकी हैं। बैठक में पारित 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प' कांग्रेस की चुनावी रणनीति का ही संकेत है।

जाति-संप्रदाय में बंटी बिहार की राजनीति में अपना वोट बैंक बनाए या बढ़ाए बिना आगामी चुनाव में बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। लगभग साढ़े तीन दशक पहले मंडल-कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में ज्यादातर ओबीसी और अल्पसंख्यक लालू यादव के पक्ष में गोलबंद हो गए तो सवर्ण जातियां भाजपा के साथ। दलितों का बड़ा हिस्सा रामविलास पासवान के साथ जुड़ गया। अपनी राजनीतिक संभावनाओं के लिए नीतीश कुमार को अति पिछड़े और महादलित का समीकरण बनाना पड़ा, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक वर्ग भी जुड़ा। इसी प्रक्रिया में लालू यादव के राजद का मुख्य जनाधार यादव-मुस्लिम गठजोड़ तक सिमट गया, जो अब विजयी समीकरण नहीं बनाता। दूसरी ओर, तमाम विस्तार के बावजूद भाजपा ओबीसी और दलित वर्ग में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई। अल्पसंख्यकों में भी भाजपा की पहुंच पसमांदा वर्ग तक ही सीमित है। इसीलिए दोनों पक्षों को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के जदयू की जरूरत पड़ती है, जिसकी ईबीसी, महादलित और अल्पसंख्यक वर्ग में स्वीकार्यता है। अब जब नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन ढलान पर है, कांग्रेस ईबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को आकर्षित कर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के 10 सूत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास को ही लक्षित करते हैं, जिनमें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने से लेकर शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और सरकारी ठेकों तक में भी 50 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे वादे शामिल हैं।

कांग्रेस को पुराने अनुभव से लेनी होगी सीख • फाइल

राहुल के आरोपों की सत्यता तो किसी निष्पक्ष जांच से ही पता चल पाएगी, लेकिन कई बार सच से ज्यादा जनधारणा निर्णायक साबित होती है। वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में राहुल ने अभी तक कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं। जीत की संभावना के बीच हरियाणा में हार जाने की चर्चा भी वह करते रहे हैं। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) में लाखों वोट काटे जाने को लेकर उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार में निकाली। इससे कांग्रेस का खस्ताहाल संगठन सक्रिय हुआ। कार्यसमिति की बैठक के जरिये कांग्रेस ने उस माहौल को बनाए रखते हुए सीट बंटवारे में मजबूत दावेदारी पेश की है। चर्चा है कि कांग्रेस ने 76 विधानसभा सीटों की सूची भी तेजस्वी यादव को इस संदेश के साथ सौंप दी है कि अगर सीट शेयरिंग में विलंब हुआ तो वह 30 सीटों पर प्रचार शुरू कर देगी। राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। फिर भी कांग्रेस उपमुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में टालमटोल कर रही है।

2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजग और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। राजग में सबसे शानदार प्रदर्शन भाजपा ने किया था, जबकि जदयू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन राजद ने किया, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 70 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई। छोटे-छोटे वाम दलों का प्रदर्शन भी कांग्रेस से बेहतर रहा। ऐसे में बिहार चुनाव में सबसे अहम दोनों गठबंधनों में सीटों का बंटवारा होगा। अतीत का अनुभव बताता है कि भाजपा अपना गठबंधन बेहतर ढंग से संभाल लेती है, पर ऐसा महागठबंधन या आइएनडीआइए के बारे में नहीं कहा जा सकता।

हरियाणा में आप अलग लड़ी तो कांग्रेस एक प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई। प्रतिशोधस्वरूप दिल्ली में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ी। कांग्रेस जीत तो एक भी सीट नहीं पाई, पर आप को सत्ता से बाहर करा दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले महाविकास आघाड़ी ने चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया होता तो वैसी दुर्दशा नहीं होती। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किस तरह हो पाता है। यदि जाति जनगणना और वोट चोरी जैसे मुद्दों से उत्साहित कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ने की जिद करेगी तो महागठबंधन में मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर दबाव की रणनीति तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा न घोषित करने तक आगे बढ़ी, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र से कोई सबक नहीं सीखा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईर्ष्या की अग्नि

मनुष्य स्वयं की उन्नति पर हर्ष एवं गर्व का अनुभव करता है। उसे तब भी अच्छा लगता है जब कोई दूसरा उसकी सफलता की चर्चा करता है। उसके परिश्रम और समर्पण को प्रेरणा बताता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति की सफलता की प्रशंसा होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अच्छाई को प्रोत्साहित करें। उसकी प्रशंसा एवं पुरस्कृत कर उसका मनोबल बढ़ाएं, लेकिन प्रायः ऐसा कम दिखाई देता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या हमें ऐसा करने से रोक लेती है। ईर्ष्या का जन्म ही दूसरे की प्रगति अथवा सफलता पर होने वाली पीड़ा से होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता पर विचलित होने लगता है, उसे उसकी उन्नति रास नहीं आती तो उसके भीतर ईर्ष्या का प्रस्फुटन होने लगता है। यह ईर्ष्या अग्नि के रूप में उस व्यक्ति के भीतर जलने लगती है। ईर्ष्या की अग्नि अत्यंत भयावह होती है, जो भीतर से हमारी क्षमताओं को भी जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं अपनी उन्नति के द्वार बंद कर लेता है। वह अपनी सामर्थ्य का उपयोग नकारात्मक कार्यों में करने लगता है।

ईर्ष्या से ही घृणा जन्म लेती है, जो हमारे संबंधों को दीमक की तरह चट करने लगती है। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। यह प्रवृत्ति व्यक्ति की अलोकप्रियता का कारण बनती है। हमारे ऋषियों ने हमें समभाव एवं समदृष्टि की प्रेरणा दी है। किसी दूसरे की सफलता को भी यदि हम स्वयं की सफलता मानकर प्रसन्न होने लगें तो ईर्ष्या भाव आसपास भी नहीं फटकेगा। जिस तरह तेजाब त्वचा पर गिरने पर उसे जलाने लगता है, पीड़ा देता है, त्वचा की रंगत खत्म कर देता है, वैसे ही ईर्ष्या भी हमारे व्यक्तित्व की आभा को खत्म कर देती है और हमें भीतर से जलाकर पीड़ा का अनुभव कराती है। हमें ईर्ष्या की अग्नि से बचकर आत्मीयता की सरिता में गोते लगाने चाहिए।

ललित शौर्य

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

सुधारों में निरंतरता आवश्यक

'सुधारों से सुनिश्चित होगी सुरक्षा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जीएन वाजपेयी ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है कि अब श्रम सुधारों और न्यायिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जाए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी स्थायित्व से ओतप्रोत दिख रही है तो इसके पीछे उन सुधारों की बड़ी भूमिका रही है, जो पिछले कुछ समय में किए गए हैं। सुधारों के आधार पर उपजने वाले विश्वास के चलते ही निवेशक अपनी पूंजी लगाने की तत्परता दिखाते हैं। निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत दिख रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से लेकर तमाम समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं, उसमें भारत के लिए नई संभावनाएं और अवसर सृजित होते दिख रहे हैं, जिन्हें भुनाने के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित कदम उठाने अपरिहार्य हैं। लेखक महोदय ने उचित ही कहा है कि तमाम अनुकूल पहलुओं के बावजूद भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाई है तो उसके कारण तलाशने के साथ ही उनका निवारण भी करना होगा। इस दिशा में बातें तो काफी समय से हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति होती नहीं दिख रही है। इसलिए समय आ गया है कि श्रम सुधारों पर सहमति बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और न्यायिक सुधारों में भी विलंब न किया जाए। सुधारों की गति एवं प्रकृति में निरंतरता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी सिद्ध होगी। इस दिशा में ध्यान देना होगा।

अमन वर्मा, वीवीआइपी होम्स सोसायटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट

प्रतिबंध और सकारात्मकता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना की सौवीं वर्षगांठ मना रहा है। इस सौ वर्ष की यात्रा में संगठन ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज भी संगठन अपनी विचारधारा पर आगे बढ़ रहा है। आरएसएस पर तीन बार प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन हर बार प्रतिबंध के उपरांत और अधिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्र सेवा में समर्पित रहा। इन सौ वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने केवल शाखाओं तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत और सामाजिक सदभाव जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसका कार्यक्षेत्र गांव से लेकर महानगर तक फैला है और लाखों स्वयंसेवक राष्ट्रहित में सेवा कर रहे हैं। आरएसएस ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने में अहम योगदान दिया है। संगठन ने यह संदेश दिया कि समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति राष्ट्रनिर्माण में भागीदार है। शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत राष्ट्र के समावेशी विकास एवं स्वावलंबन पर बल दिया है। आरएसएस ने हमेशा अपनी विचारधारा को महत्व दिया है, जो राजनीतिक दल उसकी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं, आरएसएस उन्हें अपना समर्थन देता है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

गांधी के विचार आत्मसात करें युवा

महात्मा गांधी के विचार हर युग में आदर्श हैं। वह सत्य और अहिंसा के साथ जीवन जीने की सलाह देते हैं। उनका मानना है व्यक्ति लालच, हिंसा से गलत रास्ते पर चला जाता है, वह जीवन के सकारात्मक विचार एवं लक्ष्य से दूर हो जाता है। व्यक्ति को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ईमानदार, अहिंसक, नैतिक व शुद्ध आचरण से परिपूर्ण होना चाहिए। आज के युवा देश के भविष्य हैं, उनमें बड़ी संख्या में मदिरापान, धूम्रपान व ड्रग्स के शिकार हो गए हैं, यह लत युवाओं को बर्बादी की ओर ले जा रही है। ऐसे युवा समाज से कट जाते हैं। उनका नैतिक पतन हो जाता है। वे परिवार और समाज के के प्रति जिम्मेदार होने की बजाए समाज को खंडित करने व अपराध को बढ़ावा देने में भूमिका निभाने लगते हैं। युवा पीढ़ी को बर्बादी से रोकने के लिए गांधी के विचारों को आत्मसात करना होगा। पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक व व्यावहारिक स्तर पर उन्हें नैतिक मूल्य का पाठ पढ़ाना होगा। युवाओं में कल्याणकारी मनोभाव विकसित करना होगा। सरकार को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। इन सभी के संयुक्त मिश्रण से युवाओं को समाज के लिए मूल्यवान बनाया जा सकता है, जो परिवार, समाज एवं राष्ट्र को संपूर्ण योगदान देकर देश के सुखद भविष्य की पटकथा बुन सकता है।

देव कुमार राय, सोनपुर, सारण

पोस्ट

अगर भारतीय उत्पाद गुणवत्ता की कसौटी पर खरे उतरें तो प्रत्येक भारतीय उनके पक्ष में ही आवाज बुलंद करेगा। अधिकांश भारतीय पहले से ही काफी स्थानीय उत्पाद खरीद रहे हैं, लेकिन कई पैमानों पर ये 'स्वदेशी' वस्तुएं टिक नहीं पातीं? इसके कारण और निवारण तलाशने होंगे।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

वायु सेना प्रमुख ने कहा कि आपरेशन सिंदूर में एफ-16 भी मार गिराए गए। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि दुनिया में कुछ दिग्गज क्यों भारत के प्रति इतने बौखलाए हुए हैं। आखिर वायुसेना ने यह बात पहले ही क्यों नहीं बताई। वैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ सूचनाएं वर्षों या दशकों बाद सामने आती हैं और कुछ तो कभी जाहिर नहीं होतीं। मामला बस टाइमिंग का है।

स्मिता प्रकाश@smitaprakash

केएल राहुल के प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है कि वरिष्ठ खिलाड़ी के रूप में अधिक जिम्मेदारी उन्हें रास आ रही है। जुरैल ने भी विशुद्ध बल्लेबाज के रूप में खिलाए जाने को लेकर अपना दावा ठोका है। बल्ले के साथ जडेजा का जादू भी कायम है। इरफान पठान@IrfanPathan

जनपथ

'आई लव भारत' कहो तो घिसती है जीभ,
मौलाना जी आपकी फितरत बड़ी अजीब।
फितरत बड़ी अजीब ढूंढ नित नया बहाना,
आप चाहते रोज देश में आग लगाना!
बदल चुका है दौर बदल लो खुद को भाई,
यदि ना बदले आप समझ लो शामत आई!!

– ओमप्रकाश तिवारी

https://t.me/AllNewsPapersPaid

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 171

****

कल्पमेधा

एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है, पर उसमें खुशबू नहीं है। ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं, अगर वह उनको अमल में नहीं लाता।

– महात्मा बुद्ध

सहयोग का सफर

अमेरिका ने जब अपनी शुल्क नीति की घोषणा की, तो उसका मकसद जितना अपने आर्थिक हित सुनिश्चित करना था, उससे ज्यादा इसे प्रभावित होने वाले देशों पर दबाव बनाने के तौर पर देखा गया। सवाल है कि क्या अमेरिका की ओर से पहले पच्चीस और फिर पचास फीसद तक शुल्क लगाने की घोषणा का कारण यह था कि व्यापार वार्ता में भारत को अपनी शर्तों पर सहमत किया जाए? यह बेवजह नहीं है कि भारत ने अमेरिका के इस रवैये के सामने समर्पण करने के बजाय विकल्प की राह तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी और अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को अपनी सरकार को निर्देश दिया कि वह कच्चे तेल के भारी आयात की वजह से भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए तत्काल उपाय करे। अमल के स्तर पर यह फैसला भारत से अधिक कृषि उत्पाद और दवाओं की खरीद के स्तर पर सामने आ सकता है। इस वर्ष के आखिर में पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा के मद्देनजर उनके इस निर्देश की अहमियत समझी जा सकती है।

दरअसल, अमेरिका ने न केवल शुल्क नीति की घोषणा की, बल्कि भारत पर दबाव बढ़ाने की मंशा से रूस से तेल आयात करने पर जुर्माना लगाने की भी बात कही। इसका आशय साफ था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे। इसके पीछे उद्देश्य चाहे जो हो, आज बहुध्रुवीय होते विश्व में इस तरह भारत जैसे एक संप्रभु और वैश्विक साख वाले देश को अपनी शर्तों पर संचालित कर पाना संभव नहीं हो सकता। यह विचित्र है कि अमेरिका ने इस मसले पर सहयोग और साझेदारी को केंद्र में रख कर नए विकल्प निकालने, द्विपक्षीय हित और सम्मान आधारित आर्थिक संबंध पर विचार करने का रास्ता अख्तियार न करके, दबाव की रणनीति का सहारा लिया। मगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के संदर्भ में अमेरिका और नाटो देशों की ओर से रूस को अलग-थलग करने के लिए जो रणनीति अपनाई जा रही थी, भारत ने प्रकारांतर से उसमें शामिल होने या किसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया और रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा। यों भी, तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों में अमेरिका के हर फैसले को मानने के बजाय भारत के लिए अपने हित को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी है।

जाहिर है, भारत की यह दृढ़ता रूस की नजर में महत्त्वपूर्ण होगी और इसीलिए उसने व्यापार संतुलन कायम करने की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से आकार देने की ओर कदम बढ़ाया है। भारत और रूस के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का एक लंबा दौर रहा है। विकट स्थितियों में भी दोनों देशों के बीच कभी कोई समस्या या तनावपूर्ण स्थिति नहीं आई, जिसमें किसी पक्ष के भीतर संबंधों को लेकर कोई दुविधा हुई हो। बल्कि कूटनीतिक से लेकर सांस्कृतिक या आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों ने एक-दूसरे की प्राथमिकताओं, जरूरत पर आधारित नीतिगत फैसलों की संवेदनशीलता का हमेशा ध्यान रखा और अपनी सीमा के भीतर हर स्तर पर सहयोग किया। अमेरिका की ओर से दबाव बनाए जाने के बावजूद रूस से कच्चे तेल के आयात को लेकर भारत का नहीं डिगना उसी कड़ी का एक हिस्सा है। रूस ने भारत के इस फैसले की अहमियत को समझा है और व्यापार संतुलन के लिए पुतिन के निर्देश को इसका संकेत माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए अध्याय शुरू होंगे।

हादसे का सबक

बिहार में पूर्णिया के पास ट्रेन की चपेट में आकर चार किशोरों की मौत की घटना ने एक बार फिर से यह रेखांकित किया है कि जोखिम वाली संवेदनशील जगहों पर बरती जाने वाली लापरवाही कैसे एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। खबरों के मुताबिक, पूर्णिया और कस्बा रेलवे स्टेशनों के बीच एक स्थान पर पांच किशोर जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गए। उनमें से चार की मौत हो गई और एक बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना को भले ही एक हादसे के तौर पर ही देखा जाएगा, लेकिन इस क्रम में एक बार फिर यह ध्यान रखने की जरूरत है कि तेज रफ्तार ट्रेनों की आवाजाही के रास्ते पर बहुत मामूली असावधानी भी नाहक जान जाने की वजह बन सकती है। हालांकि इस घटना के संबंध में आई खबरों में रेलवे के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि हादसे के वक्त पांचों किशोर रेलवे की पटरी पार कर रहे थे। इसी क्रम में वे तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गए।

हालांकि इस हादसे की जांच के बाद ही पूरे तथ्य सामने आएंगे, लेकिन पटरी पार करने के क्रम में हादसा होने को लेकर तथ्य की पुष्टि होती है, तो आज यह एक दुखद सच्चाई बन चुकी है। दरअसल, लापरवाही की यह प्रवृत्ति हादसे से आगे एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रही है। जबकि ट्रेन की पटरियों को पार करते हुए थोड़ी-सी चूक का नतीजा क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें रेलवे के फाटक बंद होने के बावजूद पटरी पार करने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि ट्रेन आने वाली है, फिर भी वह कुछ पलों का धीरज नहीं रख पाता है। जबकि ट्रेन कोई ऐसा वाहन नहीं है कि किसी पर नजर पड़ने के बाद तुरंत रुक सके। पूर्णिया की यह घटना एक तरह से सभी के लिए सबक है कि ट्रेनों के गुजरने के रास्तों के आसपास किसी भी स्तर की लापरवाही न बरती जाए। खासतौर पर पटरी को पार करते समय हर स्तर पर निश्चिंत हो जाने की जरूरत है कि किसी तरफ से कोई ट्रेन नहीं आ रही है।

नई तकनीक के नए आयाम

अब वैज्ञानिक एक नई खोज की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वे तकनीक का हिस्सा बन जाएंगे।

ऋतुपर्ण दवे

एक समय आएगा जब बिना किसी उपकरण के किसी इंसान के बारे में शरीर में मौजूद कुछ सूक्ष्म जीवों से पता लगाया जा सकेगा। कौन कब और कहां था या अब कहां है, पता लग जाए, तो यह कैसा होगा! आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कोई मनुष्य वास्तविक रूप से किस समय कहां है, इसका पता लगाना आसान हो जाए, तो दुनिया एक नए दौर में होगी। विज्ञान हमारे जीवन को बदल चुका है। रोज नए बदलाव सामने आ रहे हैं। तकनीक विज्ञान का हिस्सा है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसके विकास और विस्तार ने नया संसार खोल दिया है। नई-नई तकनीक हर दिन लोगों को अचरज में डाल देती है। एक तकनीक आई नहीं कि उससे भी एक कदम आगे दूसरी तकनीक उसको बहुत जल्द पुराना कर देती है।

तकनीक की क्रांति ने मानव जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ऐसी ही एक तकनीक है जीपीएस यानी 'ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम' जो एक उपग्रह आधारित प्रणाली है। जीपीएस तकनीक अब दुनिया भर में किए जाने वाले तमाम कार्यों का अभिन्न अंग भी बन गई है। यह हमारे मोबाइल, वाहन, घड़ी और अब तो बच्चों के स्कूल बैग में भी उपयोग होने लगी है। एक तरह से यह वह दौर है, जहां जीपीएस के बिना काफी कुछ असंभव-सा लगता है। इसीलिए इसके नाम और काम से आज हर कोई परिचित है।

इस बीच अब वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती यह है कि क्या इंसान की कहीं भी मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? इसको लेकर अब तक अलग-अलग विचार और प्रयोग सामने आए, लेकिन ये अव्यावहारिक ही रहे। पहनने योग्य जीपीएस उपकरण और 'रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' यानी 'आरएफआइडी' प्रत्यारोपण जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे चिप को शरीर में लगाया जा सकता है। मगर वह व्यक्ति कहां है, इसकी जानकारी यह नहीं देती। सिर्फ पहचान बताती है। जीपीएस चिप को काम करने के लिए बाहरी उपग्रहों से संकेत की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे संकेत त्वचा के नीचे नहीं पहुंचते हैं। वहीं ऐसी चिप को ऊर्जा के लिए बैटरी की भी जरूरत होगी जो स्वाभाविक रूप से छोटी होगी और सीमित समय तक ही चलेगी। इसे बार-बार बदलना भी कठिन होगा।

अब वैज्ञानिक एक नई खोज की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु, जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, वे तकनीक का हिस्सा बन जाएंगे। शरीर में लाखों की संख्या में अलग-अलग प्रकार के बैक्टीरिया यानी जीवाणु होते हैं। इनमें से कई शरीर में अंदर और बाहर पाए जाते हैं। ये अपनी प्रकृति अनुसार फायदेमंद और नुकसानदेह, दोनों ही होते हैं। मगर यही बैक्टीरिया जीपीएस का काम करने लगें, तो क्या होगा! स्वीडन के शोध दल ने एक कृत्रिम मेधा उपकरण विकसित कर 'माइक्रोबायोम जियोग्राफिक पापुलेशन स्ट्रक्चर' यानी 'एमजीपीएस' से यह पता लगाने में सफलता पाई है कि व्यक्ति किन स्थानों पर गया है। इसमें जीवाणुओं का विश्लेषण कर उन स्थानों के बारे में मालूम किया सकता है। यह कृत्रिम मेधा उपकरण जीवाणुओं को भौगोलिक फिंगरप्रिंट के रूप में उपयोग करते हुए यह पहचान कर सकता है कि कोई व्यक्ति

कहां-कहां गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि कई स्थानों पर जीवाणुओं की विशिष्ट आबादी होती है, इसलिए जब कोई, किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी सतह को छूता है, तो उस सतह पर मौजूद जीवाणु के संपर्क में आ जाता है। जिनका उपयोग उसे, उस सटीक स्थान तक वापस जोड़ने के लिए किया जा सकता है। मानव डीएनए के विपरीत जीवाणुओं का समूह विभिन्न वातावरण के संपर्क में आने पर लगातार बदलता रहता है।

मनुष्य के भीतर सूक्ष्मजीव स्वयं को जब-तब बदलते रहते हैं। विशेषकर तब, जब हम अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं तो उसी वातावरण में ढल जाते हैं। इससे तकनीक यह बताने में मददगार होती है कि सूक्ष्मजीव कुछ समय पहले कहां थे। इससे कई तरह की मदद मिलेगी। पहला किसी बीमारी के फैलाव और संक्रमण के स्रोत का पता चल जाएगा। दूसरा, आपराधिक जांच में भी सहयोग मिल सकेगा और अपराधी की पहचान करना आसान होगा। कोरोना के समय यह तकनीक होती, तो इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। संक्रमण के स्रोत का पता लगाना नामुमकिन नहीं होता।

यह जिज्ञासा भी स्वाभाविक है कि जीवाणुओं के उपयोग से कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति कहां-कहां गया था। अपने अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने उन बैक्टीरिया पर ध्यान केंद्रित किया जो सूक्ष्म रूप से अंगुलियों पर निशान की तरह काम करते हैं। शहरी परिवेश, मिट्टी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों से 'माइक्रोबायोम' के नमूनों के व्यापक डेटासेट का विश्लेषण किया और अंगुली के निशान की पहचान करने और उन्हें भौगोलिक निर्देशों से जोड़ने के लिए जब एक एआइ माडल को प्रशिक्षित किया, तो सकारात्मक नतीजे आए। स्रोत स्थल की सटीकता भी सही निकली। निश्चित रूप से 'माइक्रोबायोम डेटा' ही इसके पीछे था। इस नए शोध की सफलता का पता इससे चलता है कि जब विभिन्न वातावरणों से मिले 'माइक्रोबायोम डेटा' का परीक्षण किया गया तो वे कसौटी पर खरे उतरे। शोध दल ने बानबे फीसद शहरी नमूनों में सही शहर की पहचान करने में सफलता पाई।

यकीनन, यह एक बहुत बड़ी तकनीक बन कर सामने आई है जो स्रोत का सटीक पता लगाने में सफल रही है। इससे चिकित्सा, महामारी विज्ञान और फारेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इतना ही नहीं इस कृत्रिम मेधा उपकरण को चुनौती देते हुए हांगकांग में शोध दल ने 82 फीसद सटीकता के साथ उस भूमिगत स्टेशन का पता भी लगा लिया जहां से नमूने आए थे। जबकि न्यूयार्क में तो एक मीटर से कम दूरी पर भी परीक्षण किया गया, तो भी विश्वसनीयता की कसौटी पर विभिन्न स्थानों के अंतर को इसने बखूबी पहचान लिया।

इसे इस तरह भी समझा जा सकता है। सूक्ष्मजीव स्वयं को जब-तब बदलते रहते हैं। विशेषकर तब, जब हम अलग-अलग स्थानों पर जाते हैं तो उसी वातावरण में ढल जाते हैं। इससे तकनीक यह बताने में मददगार होती है कि सूक्ष्मजीव कुछ समय पहले कहां थे। इससे कई तरह की मदद मिलेगी। पहला किसी बीमारी के फैलाव और संक्रमण के स्रोत का पता चल जाएगा। दूसरा, आपराधिक जांच में भी सहयोग मिल सकेगा और अपराधी की पहचान करना आसान होगा। कोरोना के समय यह तकनीक होती, तो इतनी बड़ी त्रासदी से बचा जा सकता था। संक्रमण के स्रोत का पता लगाना नामुमकिन नहीं होता। 'एमजीपीएस' एआइ उपकरण हाल के स्थानों का पता लगाता है तथा जीवाणुओं को विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ कर फारेंसिक और महामारी विज्ञान में सहायता करता है।

अब वैज्ञानिक अपने इस शोध की सफलता के बाद इस एआइ का उपयोग करने के लिए उपकरणों को सक्षम या उन्नत बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। स्मार्ट फोन की स्क्रीन को अब और आधुनिक बनाया जाएगा, जिससे वह उपयोक्ता की अंगुलियों पर मौजूद बैक्टीरिया की पहचान कर ले और पता लगा सके कि वह किस जगह पर है। वैज्ञानिक आश्वस्त हैं कि भविष्य में जब यह तकनीक स्मार्टफोन में होगी, तो इससे हर किसी को फायदा मिल सकेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे जीवाणुओं का पता लगाने के लिए विशेष सेंसर लगेंगे, जिससे स्क्रीन, उपयोक्ता की अंगुलियों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों की पहचान कर सकेगा और यह बता पाएगा कि वह कहां है। इस तकनीक से न केवल बीमारी फैलने पर रोक लग सकेगी, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारियां मिलेंगी। विज्ञान और तकनीक की यह उपलब्धि जीवन के विभिन्न पहलुओं को बदलने की क्षमता रखेगी। नई खोज मनुष्यों के जीवन में नया गुल खिलाने वाली है।

सरलता की जटिलता

खुशी श्रीवास्तव

दार्शनिक और धार्मिक परंपराओं के इतिहास में एक स्थायी विरोधाभास बार-बार मुखर हुआ है। एक ओर वह मूल, सरल और सर्वसुलभ साधना, जो सहज नियमों, संयम और स्वाध्याय पर आधारित है। तो दूसरी ओर वे मार्ग, जो अपने को 'विशेष' और 'गुह्य' कहकर प्रस्तुत करते हैं और जिनका आकर्षण उनकी जटिलता, नाटकीयता तथा वर्जना-भंग में निहित होता है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक विचार पर गौर किया जा सकता है, जिसमें वे कहते हैं- 'कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो,'गुह्य' और 'रहस्य' के प्रवेश से वह विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है'। इसी सिरे से क्रिया-प्रतिक्रिया के सिद्धांत को केंद्र में रख कर एक बड़े फलक पर भी विचार की संभावना बनती है।

इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति शिखर को लक्ष्य करके पहाड़ की ओर जाती पगडंडी पकड़े चला जा रहा था, मगर उसे मार्ग नहीं पता था। थोड़ी देर चलकर उसे एक और व्यक्ति मिला, उसे भी रास्ता नहीं पता था। दोनों साथ चलने लगे। वे दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते थे, पर उनका लक्ष्य एक था। फिर उन दो लोगों को एक और व्यक्ति मिला, जिससे रास्ता पूछने पर उसने उसी ऊसर वाले रास्ते पर सीधा चलते जाने को कहा। वे दोनों फिर चलने लगे। एक आदमी रेशम के कपड़े पहने चला आ रहा था। उन्हें देखकर उसके भीतर कुछ जिज्ञासा हुई और तत्काल वह जिज्ञासा मुंह पर आ गई। उसने उनसे मंजिल पूछी। जानने पर उसने उन्हें उल्टी दिशा की ओर जाती पगडंडी दिखाई, पगडंडी से लगती बस्ती-बाजार का फायदा गिनाया, फिर आती गाड़ी में बैठ कर चला गया। वे दो लोग उसी पगडंडी की ओर निकल पड़े। हाट की तस्वीर से एक को समोसों की और दूजे को जलेबी की याद आ गई। साथ में दोनों को चाय की तलब हुई। चाय की दुकान पर गजलें बजाते रेडियो से चाय का पूरा पैसा वसूल हो गया। और सफर यहीं पूरा हो गया।

संदेश स्पष्ट है कि शरीर और मन का संतुलन, आहार-विहार की मर्यादा, कर्म का अनुशासन आदि। यही योग की आधारभूमि है। यह सरल प्रतीत होता है, पर यही कठिन है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमयी अनुष्ठान नहीं, कोई मंचित विस्मय नहीं। मगर जनमानस का मन विचित्र है। वह अक्सर उस ओर आकृष्ट होता है, जो असामान्य हो, जो मंच पर खेल-सा प्रतीत हो, जहां प्रतीक, गूढ़ भाषा और इंद्रिय-उत्तेजक प्रयोग किसी 'उच्चतर अनुभूति' का आभास दे। ऐसे मार्ग, जो आरंभ में आत्म के विस्तार का वचन देते हैं, अक्सर अंत में आत्म की विस्मृति की ओर ले जाते हैं। इतिहास के अनेक उदाहरण इस सत्य के प्रमाण हैं, जहां आरंभिक करुणा और तप की धारा बाद में रस, राग और रहस्य के चक्रव्यूह में उलझकर अपना मूल स्वर खो बैठी।

वास्तविक साधना में कोई प्रवेश शुल्क नहीं, न उसे हर बार केवल कोई दूरस्थ स्थान या कोई विशिष्ट स्वीकृति चाहिए। वह तो हमारे घर के एकांत में, हमारे भीतर के मौन में, श्वास की लय और आचरण की मर्यादा में निहित है। मगर शायद इसी कारण वह भीड़ की आंखों में फीकी पड़ जाती है। भीड़ के लिए आध्यात्मिकता अक्सर एक तमाशा होती है, जिसे वे देखना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और जिसके माध्यम से वे यह अनुभव कर सकें कि वे किसी असाधारण शक्ति के साक्षी बन रहे हैं। यह तमाशा चाहे चमत्कारिक उपचार हो या किसी परंपरा-विरुद्ध आचरण का सार्वजनिक प्रदर्शन, उसमें नाटकीयता का तत्त्व ही उसका मुख्य आकर्षण बन जाता है।

यही कारण है कि इतिहास में अत्यधिक भव्य और वर्जना-भंग करने वाले आंदोलनों की लोकप्रियता साधारण, लेकिन गहन मार्गों की अपेक्षा कहीं अधिक रही है। यह प्रवृत्ति केवल धर्म में ही नहीं, बल्कि साहित्य, राजनीति और कला में भी दिखाई देती है। जहां गंभीर और संयत विचार धीमी गति से फैलते हैं, वहीं उग्र और असामान्य विचार, भीतर की अपेक्षा बाहर अधिक शोर करते हैं और इसी कारण तेजी से भीड़ को आकर्षित करते हैं। मनुष्य का मन अद्भुत विरोधाभासों से भरा है। वह शांति चाहता है, पर शांति की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने के लिए अक्सर उसका धैर्य और संयम नहीं टिकता।

दुनिया मेरे आगे

वास्तविक साधना में कोई प्रवेश शुल्क नहीं, न उसे हर बार केवल कोई दूरस्थ स्थान या कोई विशिष्ट स्वीकृति चाहिए। वह तो हमारे घर के एकांत में, हमारे भीतर के मौन में, श्वास की लय और आचरण की मर्यादा में निहित है। मगर शायद इसी कारण वह भीड़ की आंखों में फीकी पड़ जाती है।

दुनिया भर के महान ग्रंथों ने बार-बार यह संदेश दिया है कि धर्म का सार त्याग, आत्मसंयम और सत्य में निहित है। फिर भी, 'गुप्त रहस्य' और 'विशेष योग' का प्रलोभन लोगों को इस विश्वास की ओर खींचता है कि साधारण मार्ग पर्याप्त नहीं, उन्हें कुछ असाधारण चाहिए। यही वह बिंदु है, जहां साधना साधक के लिए साध्य न रहकर दृश्य-प्रदर्शन में बदल जाती है। इस विषय पर एक और गहन प्रश्न उठता है कि क्या यह प्रवृत्ति मात्र अज्ञान का परिणाम है, या इसमें सामाजिक-मानसिक संरचनाओं की भी भूमिका है! संभव है, समाज में 'असाधारण' से प्रभावित होने की यह प्रवृत्ति मानव इतिहास के पुराने दौर से जुड़ी हो, जब समूह-नेतृत्व के लिए किसी विशेष या 'दैवी' शक्ति का प्रदर्शन अनिवार्य माना जाता था। उस काल के 'चमत्कार' आज के मंचीय आयोजनों में परिवर्तित हो गए हैं, पर मूल मनोवृत्ति वैसी की वैसी है।

अगर हम इस मानसिक प्रवृत्ति को पहचान लें और समझ लें तो शायद हम अपने समय के अनेक अनावश्यक भ्रमों और पाखंडों से बच सकते हैं।

चौपाल

समानता के बजाय

सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के स्वाभिमान से जीवनयापन के लिए पेंशन की शुरुआत पहले की सरकारों ने सोच-समझ कर की होगी। आज भी यह कुछ हद तक जारी है। मगर हाल के वर्षों में पुरानी पेंशन बंद कर नई पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू कर दिया गया। संतोषजनक न होने पर जब इसके विरोध में आवाज उठी, तो कुछ सुधार कर दूसरी योजना (यूपीएस) लागू की गई। अब इसमें भी कर्मचारियों को योजना बदलने के लिए सरकार ने विकल्प दिया है। पहले जून 2025 तक समय दिया गया था। इसके बाद फिर बढ़ाया गया। एनपीएस और यूपीएस दोनों ही कर्मचारियों में भ्रम पैदा कर रही है। वे विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं। समझ में नहीं आता कि सरकार 'ओपीएस' के लिए राजी क्यों नहीं हो रही। जब नेताओं को पांच साल के कार्यकाल पर ही पेंशन मिलती है, तब कर्मचारियों को ऐसी सुविधा क्यों नहीं, जिन्होंने अपने जीवन के 35-40 वर्ष देश की सेवा में दिए। विचित्र बात है कि एक नेता जो पार्षद, विधायक और सांसद पांच-पांच साल के लिए बन जाता है, तो उसे तीन पेंशन जीवन भर मिलती है। सुख-सुविधा से जीने का अधिकार क्या केवल नेताओं को ही है, कर्मचारियों को नहीं?

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

प्रदूषण की परतें

दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। यहां बढ़ते प्रदूषण के अनेक कारण हैं, लेकिन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने से भी समस्या बढ़ी है। इसको लेकर राज्य सरकारें समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती हैं। धान की फसल कटने के बाद अवशेषों को जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ जाता है। आने वाले समय में दिल्ली की हवा खतरनाक रूप से प्रदूषित हो जाएगी। प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन दिनों सांस के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ जाती है। पर्यावरण विज्ञानियों को पराली के उपयोग पर अनुसंधान करने चाहिए और सरकार को खेतों से ही पराली खरीद पर उचित दाम दे देना चाहिए, ताकि किसानों को इसे जलाने की आवश्यकता ही न पड़े। उन पर सख्ती से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। उत्तर भारत के राज्यों में पराली के वैकल्पिक उपयोग की आवश्यकता है। इस पर राज्य सरकार को गंभीरता से सोचना होगा।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

एकजुटता का संदेश

आतंकवाद के खतरे के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को एकजुट होने की जरूरत है। भारत ने इस खतरे के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को एकजुट होने का संदेश दिया है। इस विषय पर यूरोपीय संघ से भी विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा यह दर्शाती है कि धर्मनिरपेक्षता को हमारा देश महत्त्व देता है। ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता है। आतंकवाद समर्थक देश यही चाहते है कि यहां अशांति बनी रहे। पूर्व में भी जम्मू में आतंकी हमलों में पाकिस्तानी सेना की संलिप्तता के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अक्सर देखा गया कि भारत में ये आतंकी अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। इस समय घने जंगलों में आतंकियों को मार गिराने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी है। पाकिस्तान आतंकियों को प्रशिक्षित कर भारत की सीमा में घुसपैठ करता है। इस पर सख्ती दिखाने की जरूरत है। आतंकवाद रोकने के लिए एकजुटता का फार्मूला अपनाना होगा, तभी विश्व में शांति कायम रह सकती है।

– संजय वर्मा 'दृष्टि', धार

मार्गदर्शन का महत्त्व

दुनिया के हर रिश्ते की अपनी एक पहचान होती है, लेकिन पिता और बेटी का रिश्ता सबसे खास होता है। यह रिश्ता विश्वास और सुरक्षा की नींव पर टिका होता है। पिता बेटी के लिए सिर्फ अभिभावक ही नहीं, बल्कि उसका पहला दोस्त, पहला आदर्श और मार्गदर्शक भी होता है। चलना सीखते समय उसकी अंगुली थाम कर आगे बढ़ाने वाला, स्कूल के पहले दिन हिम्मत देने वाला और कठिनाइयों में ढाल बन कर खड़ा रहने वाला पिता ही होता है। उसका स्नेह बेटियों को आत्मविश्वास देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह हमेशा साथ है। बेटियां भी पिता के जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर आती हैं। उनकी मुस्कान पिता की दिनभर की थकान मिटा देती है। उनका स्नेह दिल को गर्व से भर देता है। इसीलिए कहा जाता है- बेटियां पिता की दुआओं का सबसे खूबसूरत तोहफा होती हैं।

– रागिनी कुशवाहा, सिंगरौली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

अभिमत

हम सब जानते हैं हमारे जंगल बहुत कम हो गए हैं। इससे भूस्खलन व भूक्षरण ज्यादा हो रहा है। पानी को स्पंज की तरह अपने में समाने वाले जंगल कट गए हैं। जंगलों के कटान के बाद झाड़ियां और चारे जलावन के लिये काट ली जाती हैं। जंगल और पेड़ बारिश के पानी को रोकते हैं। वह पानी को बहुत देर तो नहीं थाम सकते लेकिन पानी के वेग को कम करते हैं।

बाढ़ की समस्या का मुकाबला कैसे करें?

नवाचार

■ बाबा मायाराम

पिछले दिनों देश के कई कोनों से लगातार बाढ़ से तबाही की खबरें आई हैं। अब यह समस्या स्थायी सी हो गई है। हर साल बाढ़ आती है, तबाही की खबरें आती हैं, लेकिन उसके बारे में पूर्व तैयारी नहीं होती। एक समग्र सोच का अभाव सभी जगह दिखाई देता है। आज बाढ़ पर थोड़ी चर्चा करना उचित होगा, जिससे इसे समग्रता में देख सकें। इसके समाधानों के बारे में सोच सकें।

हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि पहले भी बाढ़ आती थी लेकिन वह इतने व्यापक कहर नहीं ढाती थी। इसके लिए पूरी तरह लोग व गांव तैयार रहते थे। बल्कि इसका उन्हें इंतजार रहता था। खेतों को बाढ़ के साथ आई नई मिट्टी मिलती थी, भरपूर पानी लाती थी जिससे प्यासे खेत तर हो जाते थे। पीने के लिये पानी मिल जाता था, भूजल ऊपर आ जाता था, नदी नाले, ताल-तलैया भर जाते थे। समृद्धि आती थी। बाढ़ आती थी, मेहमान की तरह जल्दी ही चली जाती थी। पर यह बाढ़ तबाही मचाती है।

हम सब जानते हैं हमारे जंगल बहुत कम हो गए हैं। इससे भूस्खलन व भूक्षरण ज्यादा हो रहा है। पानी को स्पंज की तरह अपने में समाने वाले जंगल कट गए हैं। जंगलों के कटान के बाद झाड़ियां और चारे जलावन के लिये काट ली जाती हैं। जंगल और पेड़ बारिश के पानी को रोकते हैं। वह पानी को बहुत देर तो नहीं थाम सकते लेकिन पानी के वेग को कम करते हैं। वे स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। लेकिन पेड़ नहीं रहेंगे तो बहुत गति से पानी नदियों में आएगा और इधर-उधर बह जाएगा, और बर्बादी करेगा। और यही हो रहा है।

यह भी देखा जा रहा है कि पहले नदियों के आस-पास बहुत पड़ती जमीन होती थी, नदी-नाले होते थे, लम्बे-लम्बे चारागाह होते थे, दूब और घास होती थी, उनमें पानी थम जाता था। बड़ी नदियों का ज्यादा पानी छोटे- नदी नालों में भर जाता था। लेकिन अब उस जगह पर भी या तो खेती होने लगी है या वह जमीन का उपयोग किसी और कामों के लिए होने लगा है। यानी इसमें कमी आ गई है।

एक और कारण है- लगातार बढ़ता शहरीकरण और विकास कार्य भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतें, सड़कों राजमार्गों का जाल बन गया है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह अवरुद्ध हो गए हैं। जहां पानी निकलने का रास्ता नहीं रहता है, वहां दलदलीकरण की समस्या हो जाती है। इससे न केवल फसलों को नुकसान होता है बल्कि बीमारियां भी फैलती हैं। जो तटबंध बने हैं, वे टूट-फूट जाते हैं जिससे लोगों को बाढ़ से बाहर निकलने का समय भी नहीं मिलता। इससे जान-माल की हानि होती है।

इसी प्रकार वेटलैंड (जलभूमि) की जमीन पर भी अन्य गतिविधियां होने लगी हैं। इससे पर्यावरणीय और जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो गया है। शहरों में तो यह समस्या बड़ी है। पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है। सब जगह पक्के कांक्रीट के मकान, हाईवे और सड़कें हैं। जैसे कुछ सालों पहले मुंबई की बाढ़ का किस्सा सामने आया था। वहां मीठी नदी ही गायब हो गई, और जब पानी आया तो शहर जलमग्न हो गया। ऐसी हालत ज्यादातर शहरों की हो जाती है।

लेकिन बाढ़ के कारण और भी हैं। जैसे बड़े पैमाने पर रेत खनन। रेत पानी को स्पंज की तरह जज्ब करके रखती है। रेत खनन किया जा रहा है। रेत ही नहीं रहेगी तो पानी कैसे रुकेगा, नदी कैसे बहेगी, कैसे बचेगी। अगर रेत रहेगी तो नदी रहेगी। लेकिन जैसे ही बारिश ज्यादा होती है, वेग से पानी बहता है, उसे ठहरने की कोई जगह नहीं रहती।

कई बांध व बड़े जलाशयों में नदियों को मोड़ दिया जाता है, उससे नदी ही मर जाती है। नदियां बांध दी जाती हैं। लोग समझते हैं कि यहां नदी तो है नहीं, क्यों न यहां खेती या इस खाली पड़ी जमीन का कोई और उपयोग किया जाए, तभी जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और यही पानी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है इससे बर्बादी होती है।

कई बांध व बड़े जलाशयों में नदियों को मोड़ दिया जाता है, उससे नदी ही मर जाती है। नदियां बांध दी जाती हैं। लोग समझते हैं कि यहां नदी तो है नहीं, क्यों न यहां खेती या इस खाली पड़ी जमीन का कोई और उपयोग किया जाए, तभी जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं मिलता। और यही पानी बाढ़ का रूप धारण कर लेती है इससे बर्बादी होती है। मौसम बदलाव भी एक कारण है।

मौसम बदलाव भी एक कारण है। पहले सावन-भादो में लंबे समय तक झड़ी लगी रहती थी। यह पानी फसलों के लिये और भूजल पुनर्भरण के लिये बहुत उपयोगी होता था। फसलें भी अच्छी होती थी और धरती का पेट भी भरता था। पर अब बड़ी-बड़ी बूंदों वाला पानी बरसता है, जिससे कुछ ही समय में बाढ़ आ जाती है। वर्षा के दिन भी कम हो गए हैं।

बीज बचाओ आंदोलन व चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता रहे विजय जडधारी बताते हैं कि आजकल उत्तराखंड की पहचान अतिवृष्टि और तबाही से बन रही है लेकिन यदि 50-100 साल पहले की बात करें तो यहां इससे भी ज्यादा बारिश होती थी। सावन के महीने को अंधियारा महीना कहते थे, तब सावन के महीना दिन में सूरज के दर्शन नहीं होते थे। न रात में तारे दिखते थे, चौमासा यानी चार महीने बारिश के लिए थे। लेकिन तब कहीं प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती थी। बादल फटना शब्द कहीं नहीं था। न भू स्खलन होता था। उच्च हिमालय से इक्का-दुक्का घटनाएं हुई हैं। लेकिन आज चारों ओर तबाही ही तबाही हो रही है और प्रकृति को दोष दे रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हिमालय दुनिया की छत है। हिमालय पर हो रही आपदाएं प्राकृतिक नहीं है, यह मानव निर्मित है। हिमालय कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, हिमालय और गंगा हमारी सभ्यता व संस्कृति का आधार है इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उत्तराखंड हिमालय को देवभूमि कहा है।

इसके अलावा पानी के परम्परागत ढांचों की भी भारी उपेक्षा हुई है। ताल, तलैया, तालाब, खेतों में मेड़ बंधान आदि से भी पानी रुकता है। हर गांव में तालाब थे। आज भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में तालाब की पानीदार परंपराएं हैं, जिनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। यह तालाब गांव के लोगों ने बनाए और बचाए हैं।

कुछ समय पहले मैं राजस्थान गया था। और वहां कुछ जिलों में घूमा, और देखा कि वहां सैकड़ों साल पुराने तालाब हैं। आज भी स्थानीय लोग उनका पानी पीते हैं। उन्होंने उनकी सार-संभाल की है। और आज भी कर रहे हैं।

लेकिन आज हम इन पर ध्यान न देकर भूजल के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। हमारी बरसों पुरानी परम्पराओं में ही आज की बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के सूत्र छिपे हैं। अगर ऐसे समन्वित विकल्पों पर काम किया जाए तो न केवल बाढ़ जैसी बड़ी समस्या से निजात पा सकते हैं। पर्यावरण, जैव-विविधता और बारिश के पानी का संरक्षण कर सकेंगे। लेकिन क्या हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे?

बीता सप्ताह

27 सितम्बर

- वायुसेना से लड़ाकू विमान मिग-21 को विदाई दी गई।
- डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं पर लगाया 100 प्रतिशत टैरिफ।
- शेनचोउ-20 अंतरिक्ष यात्री दल ने अपनी चौथी बाध्यान गतिविधि को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
- लद्दाख में पर्यावरण विद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वायचुंग की गिरफ्तारी के बाद हालत नाजुक।

28 सितम्बर

- तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ होने से 40 लोगों की मौत हो गई।
- वरिष्ठ पत्रकार और द स्टेट्समैन के पूर्व संपादक एम एल कोटरू का निधन हो गया।
- बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकवादी परमिंदर सिंह पिंडी को यूएई से भारत लाया गया।
- कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दक्षिण अमेरिका के चार देशों की यात्रा पर रवाना हुए।

29 सितम्बर

- विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सदस्यता की दावेदारी की।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर नौ मिनट में टीबी से एक इंसान की मौत होती है।
- इरान पर संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रतिबंध फिर से लागू हो गए। जो ईरान के परमाणु संवर्धन पर प्रतिबंध है।
- एलओसी पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश करने वाले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में दो आतंकी मारे गए।

30 सितम्बर

- जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या का आरोपी है।
- केरल विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ।
- केन्द्र सरकार ने शिरीष चंद मुर्मू को तीन साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया।
- गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने विकसित भारत दौड़ आयोजित कर वैश्विक शांति का दिया संदेश।

1 अक्टूबर

- आरबीआई ने नए दिशा निर्देश जारी कर कहा कि स्मॉल बिजनेस को कर्ज नियमों में छूट दी जाएगी।
- पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके से दस लोगों की मौत हो गई।
- जम्मू कश्मीर में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने केन्द्र सरकार से बातचीत पर इंकार कर दिया।
- राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है।

2 अक्टूबर

- केन्द्र सरकार ने गेहूं सहित 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी किया।
- एम-3 एम हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार भारत में तेजी से बढ़ रही है अरबपतियों की संख्या। 1687 कारोबारियों में 1000 करोड़ से अधिक संपत्ति।
- भारत-रूस की अहम बैठक अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुद्दे पर वार्ता हुई।
- आरबीआई का रेपोर्ट पूर्व की भांति 5.50 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

समाचार मीडिया और गांधी

■ राजेश बहुगुणा

समाचार पत्रों के माध्यम से ही गांधी सफल जन नेता के रूप में उभरे थे। दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्रों में प्रवासी भारतीयों के पक्ष में आवाज उठाने की कार्यवाही गांधी निरन्तर करते थे।

समाचार पत्रों में पत्र लिखने के दौरान ही गांधी को भारतीयों की आवाज रखने के लिए अपने समाचार पत्र की जरूरत महसूस हुई जिसका परिणाम 'इंडियन ओपिनियन' समाचार पत्र था। दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा और अपनी दूसरी पुस्तक 'दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास' दोनों ही में इंडियन ओपिनियन पर एक अध्याय लिखा। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस अखबार के द्वारा मुझे मनुष्य के रंग-बिरंगे स्वभाव का बहुत ज्ञान मिला। संपादक और ग्राहकके बीच निकट का और स्वच्छ सम्बन्धं स्थापित करने की ही धारणा होने से मेरे पास हृदय खोलकर रख देने वाले पत्रों का ढेर लग जाता था। उसमें तीखे, कड़वे, मीठे यों भांति-भांति के पत्र मेरे नाम आते थे। उन्हें पढ़ना, उन पर विचार करना, उनमें से विचारों का सार लेकर उत्तर देना यह सब मेरे लिए शिक्षा का उत्तम साधन बन गया था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो इसके द्वारा मैं समाज में चल रही चर्चाओं और विचारों को सुन रहा होऊं। मैं संपादक के दायित्व को भली-भांति समझने लगा और मुझे समाज के लोगों पर जो प्रभुत्व प्राप्त हुआ, उसके कारण भविष्य में होने वाली लड़ाई संभव हो सकी, वह सुशोभित हुई और उसे शक्ति प्राप्त हुई।

दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक भारतीयों के हितों के लिए दक्षिण अफ्रीका की उपनिवेशी रंगभेदी सरकार के खिलाफ गांधी ब्रिटिश सरकार के न्याय पर भरोसा कर रहे थे। भारत में इसी ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध गांधी की सीधी लड़ाई थी। प्रेस पर नियंत्रण का अनुभव गांधी को दक्षिण अफ्रीका में नहीं हुआ था। भारत में दक्षिण अफ्रीका की तुलना में अधिक शिक्षित एवं जागरूक भारतीयों को ध्यान में रखते हुये प्रेस पर नियंत्रण 18वीं सदी के अंत में ही प्रारम्भ हो गये थे किन्तु 1835 में मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस पर सरकारी नियंत्रण भारतीय समाज के राजनैतिक जागरण के साथ बढ़ता ही गया। वायसराय कर्जन के बंगाल के विभाजन के निर्णय के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रेस पर नियंत्रण के कानूनों को कठोरता से लागू किया था।

गांधी पाठकों से प्राप्त होने वाले पत्रों को न केवल समाचार पत्र में स्थान देते वरन पाठकों के पत्रों के आधार पर समाचार पत्र में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए आलेख भी लिखते थे। गांधी ने समाचार पत्र के सामाजिक क्लब बनाने का सुझाव दिया जिसमें एक समाचार पत्र से ही समाज के अनेक लोगों को समाचार पढ़ने में कोई आर्थिक बोझ नहीं हो सकता था। इसी तरह पढ़े-लिखे पाठकों को भी गांधी सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाते हुए यह सुझाव भी देते हैं कि वे निरक्षर लोगों को समाचार पढ़कर सुनायें और उन्हें जागरूक करें। आजादी की लड़ाई के दौरान जब कुछ अखबार साम्प्रदायिक तनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय गांधी पाठकों को यह भी चेतावनी देते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ लोग कहें उसे बिना जांचें हरगिज न माने।

भारत आने पर कुछ वर्षों तक गांधी ब्रिटिश सरकार से न्यायोचित व्यवहार की ही आशा कर रहे थे, लेकिन पंजाब में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया। जनता को जागरूक करने में समाचार पत्रों की भूमिका दक्षिण अफ्रीका में ही अनुभव करते हुये गांधी ने भारत आने के कुछ वर्षों के भीतर ही 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया कुलीन वर्ग में सीमित कांग्रेस के दरवाजे उन्होंने आम जनता के लिये खोल दिये। इसी भारतीय जनता को जागरूक करने में गांधी के सम्पूर्ण भारत में दौरे एवं भाषणों का असर तो था ही, लेकिन 'यंग इंडिया' एवं 'नवजीवन' ने भी बड़ी भूमिका निभायी थी।

अपने जीवन में चार समाचार पत्रों 'इंडियन ओपीनियन' यंग इण्डिया नवजीवन और हरिजन के संचालन एवं सम्पादन के दौरान गांधी ने सैकड़ों आलेख लिखे हैं। समाचार पत्रों के साथ उनके पचास वर्ष से भी अधिक के संबंध के दौरान लिखे गये इन आलेखों के माध्यम से गांधी ने मीडिया के प्रत्येक पक्ष पर न केवल अपने विचार रखे हैं, वरन इन वर्षों में समाचार पत्र के स्वामी, सम्पादक या पत्रकार के रूप में सत्ता एवं जनता के साथ उनके कार्य व्यवहार से समाचार मीडिया पर उनकी दृष्टि भी पाठकों को स्पष्ट हो जाती है।

गांधी के लिए समाचार पत्र सदैव आम जनता को शिक्षित करने और आम जनता अथवा पत्र के पाठकों के हित व दृष्टिकोण को सत्ता और सत्ता से जुड़े अन्य संस्थान के सामने रखना रहा। इसलिये गांधी जनता को सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक सभी स्तरों पर बेहतर एवं जागरूक करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील दिखते हैं। गांधी की यह स्पष्ट राय है कि अखबारों के माध्यम से ही शासन को जनता के अभिमत का पता चलता है और यदि समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू की जाती है तो फिर शासन केवल अपने अधीनस्थों की सूचना पर ही निर्भर रह जाएगा और वास्तविक जानकारी से अपरिचित रहेगा जो स्वयं शासन के लिए ही हितकर नहीं है। समाचार पत्रों की विश्वसनीयता के लिए गांधी स्पष्ट थे कि समाचार पत्र में सच्ची और विश्वसनीय खबरों को ही स्थान मिलना चाहिए। एक जगह उन्होंने यह भी कहा कि यदि खबर जिसे समाचार पत्र आवश्यकता पड़ने पर स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते लेकिन उनके अखबार में छपती है तो वह वास्तव में अपराध ही करते हैं। समाचार पत्र अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तब ही बनाये रख सकता है जबकि किसी अन्य संस्था से प्राप्त होने वाली राशि पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं हो इसलिए गांधी अखबारों को चलाने के लिए आय के स्त्रोत के रूप में विज्ञापनों का सहारा लेना उचित नहीं मानते। गांधी के अनुसार समाचार पत्र अपने पाठकों के नियमित ग्राहक शुल्क पर ही चलाया जाना चाहिए और यह समाचार पत्र के पाठकों की जिम्मेदारी है कि यदि वे अपने समाचार पत्र को पसंद करते हैं तो उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रखने के लिए नियमित रूप से ग्राहक शुल्क प्रदान करें।

गांधी को समाचार पत्रों पर सरकार की ओर से नियंत्रण का अनुभव भारत आकर ही हुआ था। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के लिए मुम्बई में आयोजित एक विशाल सार्वजनिक सभा में गांधी ने प्रगतिशील राज्य के लिए स्वतंत्र सार्वजनिक पत्र की आवश्यकता स्पष्ट करते हुए अपने भाषण में कहा कि-

'एक स्वस्थ और प्रगतिशील राज्य के लिए स्वतंत्र सार्वजनिक पत्रों का होना पहली आवश्यक शर्त है और यह बात सभ्य लोगों के उचित राजनीतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है; एवं सार्वजनिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वतन्त्रता का प्रवेश और उसका कायम रखा जाना लोगों के उत्थान, और सन्तोष तथा सरकार और लोगों के पारस्परिक विश्वास की अचूक गारंटी है।'

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गांधी इतने उच्चतम स्तर तक रखना चाहते हैं कि उनके अनुसार- 'भाषण स्वातंर्त्य का मतलब तो यही है कि हमारे वचन कितने ही कठोर और चोट पहुंचाने वाले क्यों न हो, फिर भी उस स्वतन्त्रता पर आक्रमण न किया जाये।'

समाचार पत्रों की तरह ही गांधी सम्पादक पद को भी आजीविका के लिए नहीं बल्कि लोकसेवा के लिये मान्य करते हैं। गांधी सम्पादक को यह भी सलाह देते हैं कि विरोधी पक्ष को भी अखबार में स्थान दिया जाए। गांधी समाचार पत्र को लोकप्रिय बनाये रखने के लिये स्थानीय समाचारों को भी अखबार में रखने की सलाह देते हैं। गांधी विश्वसनीय खबरों को ही समाचार पत्र में स्थान देने के लिए जोर देते हैं और यदि खबर के कारण कतिपय पक्ष से निंदा अथवा शासन पक्ष से रोष की स्थिति भी हो तो सम्पादक को निर्भीक रहने की सलाह देते हैं। पत्रकारों की विषम स्थिति से भी गांधी अपरिचित नहीं हैं। एक जगह गांधी ने पत्रकारों की विषम स्थिति के संबंध में लिखा है कि-

'पत्रकार का जीवन कभी सुख-चैन का जीवन नहीं होता। उस पर वे जिम्मेदारियां होती है जिनका शायद जनता को समुचित खयाल भी नहीं होता। एक तरफ तो उसे अपने मालिकों को खुदा रखना पड़ता है और दूसरी ओर लोकमत का प्रतिनिधित्व करना होता है। ऐसा करने में उसे बड़ा त्याग करना पड़ सकता है। उसको अक्सर परस्पर विरोधी स्वाथों से निबटना पड़ता है और उसके सामने जो मामले आते हैं उन पर जनता के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि अपने दृष्किोण से भी विचार करना पड़ता है और जब उसके अपने ही शुद्ध अन्त:करण से मान्य विचार किसी खास मामले में लोकमत के विपरीत होते हैं तब स्थिति बड़ी नाजुक हो जाती है।'

यह स्थिति आज भी समाचार मीडिया में अनुभव की जा सकती है। गांधी के साथ अनेक घटनाएं हुईं जिनमें पत्रकारों के द्वारा गांधी के कहे को उनकी भावना के अनुरूप प्रकाशित नहीं किया गया और गांधी को इसके लिए सफाई देना पड़ी। उस समय भी गांधी पत्रकारिता के गिरते स्तर से चिंतित थे और उनके अनुसार भारत में जिसे कोई दूसरा काम नहीं मिलता और थोड़ा भी पढ़ना लिखना जानता है, वह अखबार नवीसी करने लगता है। इसे आज भी अनुभव किया जा सकता है। गांधी देशी भाषा के समाचार पत्र एवं पत्रकारिता के सदैव पक्षधर रहे क्योंकि देशी भाषा को समझने वाले भारतीयों की संख्या अंग्रेजी समझने वालों की तुलना में बहुत अधिक थी और अखबार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना ही रहता है। गांधी के अनुसार पत्रकार की समाज में भूमिका जनता को सही दिशा की ओर ले जाना है हालांकि गांधी कतिपय पत्रकारों द्वारा पीत पत्रकारिता के अन्तर्गत झूठी शिकायतों के सहारे पैसा वसूलने की घटनाओं से भी परिचित थे। ऐसी पत्रकारिता से इससे बचने का एक ही उपाय गांधी बताते हैं कि ऐसे असत्य लेखों की कोई चिन्ता ही न की जाए। आजादी के समय बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव में पत्रकारों एवं समाचार पत्रों द्वारा असत्य खबरों के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने को लेकर भी गांधी बहुत चिंतित रहे।

गांधी पाठकों से प्राप्त होने वाले पत्रों को न केवल समाचार पत्र में स्थान देते वरन पाठकों के पत्रों के आधार पर समाचार पत्र में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए आलेख भी लिखते थे। गांधी ने समाचार पत्र के सामाजिक क्लब बनाने का सुझाव दिया जिसमें एक समाचार पत्र से ही समाज के अनेक लोगों को समाचार पढ़ने में कोई आर्थिक बोझ नहीं हो सकता था। इसी तरह पढ़े-लिखे पाठकों को भी गांधी सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाते हुए यह सुझाव भी देते हैं कि वे निरक्षर लोगों को समाचार पढ़कर सुनायें और उन्हें जागरूक करें। आजादी की लड़ाई के दौरान जब कुछ अखबार साम्प्रदायिक तनाव बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय गांधी पाठकों को यह भी चेतावनी देते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ लोग कहें उसे बिना जांचें हरगिज न माने। प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस का नियंत्रण किये जाने की स्थिति पर गांधी पाठकों को चलता-फिरता समाचार पत्र बनकर समाचार एक दूसरे को सुनाने की सलाह देते हैं। आजादी के बाद भी अखबार में साम्प्रदायिक सदभाव को बिगाड़ने वाली असत्य घटनाओं के प्रकाशन से चिंतित होकर गांधी पाठकों से यह अपील करते हैं कि-

'आज़ादी के जमाने में तो यह पब्लिक का फर्ज हो जाता है कि गन्दे अखबारों को न पढ़ें, उनको फेंक दें। जब उन्हें कोई लेगा नहीं तो वे अपने-आप ठीक रास्ते पर चलने लगेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो अखबार अपना सच्चा धर्म का पालन करेंगे।'

राजनीति से प्रेरित है गांधी से नफ़रत का अभियान

संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर 'अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में घोषित किया है। दुनिया ने गांधी को शांति के दूत के रूप में मान्यता दी है। अहिंसा और शांति के वैश्विक प्रतीक के रूप में गांधी के सम्मान में कुल 102 देशों ने उनकी प्रतिमाएं स्थापित की हैं। वे पिछली दो सहस्राब्दियों में जन्म लेने वाले 10 उत्कृष्ट व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनके बारे में सबसे अधिक लिखा गया है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि, 'गांधीजी एक वैश्विक प्रतीक हैं और अहमदाबाद में उनके निवास साबरमती आश्रम को एक विश्व स्तरीय स्मारक में बदल दिया जाएगा।' 1200 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी योजना पर काम चल रहा है। भारत का शीर्ष नेतृत्व गांधीजी को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। यह स्पष्ट रूप से समझा जाता है कि गांधीजी भारत का वैश्विक चेहरा हैं। इसलिए उनका निरतंर उल्लेख किया जाना जारी है।

प्रधानमंत्री ने नवंबर, 2014 से सितंबर, 2025 तक विदेशी संसदों में दिए 17 भाषणों में से 6 में महात्मा गांधी का सीधे उल्लेख किया है। उन्होंने कई अन्य अवसरों पर अप्रत्यक्ष रूप से गांधीजी का उल्लेख किया है। उन्होंने बापू को अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया है। स्थिरता और समानता के बारे में बात करते हुए उन्होंने गांधी के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है। मोदी के अंतरराष्ट्रीय भाषणों में अक्सर गांधी के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के संदेश का उल्लेख होता है। उनके राजनयिक उद्देश्यों में यह संदेश उनकी अच्छी मदद कर रहा है।

डा. सुदर्शन अयंगर

अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गांधीजी ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ स्पष्टऔर संरचनात्मक दोनों तरह से बिताया। दलितों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के संघर्ष का नेतृत्व करने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर के साथ अपने तीखे मतभेदों के बावजूद लोगों के दिलो-दिमाग से अस्पृश्यता को दूर करने के अपने अभियान को गांधीजी ने जारी रखा था।

उन्होंने देश में भी 2 अक्टूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत अभियान' की शुरुआत की। हाल ही में वे स्वदेशी पर मुखर रहे हैं। प्रतीकवाद अपने चरम पर है। दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 में चेक-इन सेक्शन में प्रवेश करते हुए कोई भी व्यक्ति एक विशाल चरखा देख सकता है। यह हस्तचालित चरखा बर्मा सागौन से बना है और इसका वजन चार टन है। द्वार 4 और 5 के बीच चरखे के नीचे स्थापित पट्टिका में गांधीजी के योगदान का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। स्थापना के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था-'चरखा आईजीआई हवाई अड्डे पर यात्रियों को भारत की कालातीत विरासत तथा स्थिरता और सद्भाव के मूल्यों की याद दिलाने का काम करेगा और इसी उद्देश्य से इसे बनाया गया है।' उन्होंने देश के नागरिकों से खादी को अपनाने की अपील की है। दुनिया के किसी भी कोने से आने वाला यात्री अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 'गांधीजी के पदचिह्न' नामक एक छोटी सी प्रदर्शनी को देखने का अवसर नहीं छोड़ता है।

इसके बावजूद जिस देश में वे पैदा हुए, रहे और अपना बलिदान दिया, वहां उनके खिलाफ पिछले 25 वर्षों के दौरान एक घृणा अभियान तेज हो गया है। गांधी नफरत करने लायक व्यक्ति बन गए हैं। मुसलमानों के प्रति उनके कथित पक्षपात के लिए उनसे नफरत की जाती है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए उनके 15 साल के अथक प्रयत्नों का मजाक उड़ाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाषचंद्र बोस की अनदेखी करने के लिए उनकी निंदा की जाती है। भगत सिंह की फांसी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान हाशिए पर है। बोस द्वारा उन्हें दी गई 'राष्ट्रपिता' की उपाधि का उपहास उड़ाया जाता है। सोशल मीडिया ने हम भारतीयों के मन में गांधी की छवि को नष्ट कर दिया है।

'गांधी का गुजरात' आज एक बुरा शब्द है। जहरीली नफ़रत के साथ प्रकट और छिपी हुई हिंसा ने लोगों के दिलो-दिमाग पर कब्जा कर लिया है। कट्टरपंथी हिंदू भीड़ बेहिचक आगे बढ़ रही है और कानून के रक्षक भी उन पर विशेष रोक-टोक नहीं करते। यह जानकर दुख होता है कि कट्टरपंथियों की भीड़ नवरात्रि गरबा महोत्सव के आयोजकों से कड़ी पूछताछ करती है कि मुसलमानों को कितने पास और टिकट जारी किए गए हैं। एक तरफ गरबा नृत्य चल रहा है तो उसी समय भीड़ मुस्लिम प्रतिभागियों की जांच करती है।

इस साल की शुरुआत में राजनीतिक रैलियों, धार्मिक जुलूसों, विरोध मार्च और सांस्कृतिक समारोहों जैसे कार्यक्रमों में हुए भाषणों में अभद्र भाषा के उपयोग की संख्या बढ़ी है। 2024 में 1,165 मामले सामने आए जबकि एक साल पहले इनकी संख्या 668 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल चुनाव अभियान के दौरान नफ़रत फैलाने वाले भाषण चरम पर थे।

अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गांधीजी ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ स्पष्ट और संरचनात्मक दोनों तरह से बिताया। दलितों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के संघर्ष का नेतृत्व करने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर के साथ अपने तीखे मतभेदों के बावजूद लोगों के दिलो-दिमाग से अस्पृश्यता को दूर करने के अपने अभियान को गांधीजी ने जारी रखा था। क्या अंबेडकर और गांधी दोनों के प्रयासों को हम भारतीय विफल नहीं कर रहे हैं? 2025 में भी तथाकथित उच्च और श्रेष्ठ जाति के लोगों ने दलितों का अपमान करने, निंदा करने, शोषण, बलात्कार, घायल करने और मारने का कोई मौका नहीं छोड़ा।

गांधी के प्रति नफ़रत का अभियान सुनियोजित और राजनीति से प्रेरित है। इस तरह के प्रायोजित हमले के पीछे का दिमाग धोखेबाज है। जातिगत मानसिकता पूरी तरह से खेल खेलती है। नफ़रत करने वाले लोग भारत में मुसलमानों को 'सबसे निचली जाति' बनाना चाहते हैं जिसे समाज में हलके दर्जे के काम करने के लिए मजबूर किया जाए। ये तत्व चाहते हैं कि उन्हें गरीबी और दरिद्रता में सड़ना और दबाव में आकर इस देश को छोड़ देना चाहिए। हम भारत के नागरिक क्या इस बात को समझते हैं कि हम नफ़रत, निंदा व भेदभाव कर, चोट पहुंचाकर और हत्या करके दुश्मनी का माहौल बना रहे हैं? कोई भी प्रत्यक्ष, छिपी हुई और संरचनात्मक हिंसा मजबूत भावनाओं और कड़वाहट को जन्म देती है जो हिंसा की जड़ है।

हमें समझना चाहिए कि जब किसी वर्ग को निशाना बनाया जाता है और उसका बहिष्कार किया जाता है तथा जब लोग सीधे तौर पर व राज्य धोखे से यह खेल खेलते हैं, तो पीड़ित समूह नाराज होकर बदला लेने पर उतारू हो जाता है। ऐसे समुदायों में रोटी कमाने वालों को उचित अवसर नहीं दिए जाते। वे ऐसी मुश्किल या कठिन परिस्थितियों में डाल दिए जाते हैं जहां से उनके पास निकलने का कोई विकल्प नहीं रह जाता। यह परिस्थिति नफ़रत और हिंसा के एक नए चक्र को जन्म दे सकती है जो भारत को बर्बाद कर देगी।

अहिंसा के वैश्विक प्रतीक महात्मा गांधी ने जाति आधारित हिंसा को समाप्त करने और हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर भी आधुनिक भारत में उनकी विरासत को षड्यंत्रपूर्वक रचे घृणा अभियानों के माध्यम से बदनामी का सामना करना पड़ता है। अस्पृश्यता को मिटाने और समानता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के बावजूद 2025 में भी दलितों और मुसलमानों को भेदभाव, शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है जो गांधी और डॉ. अंबेडकर दोनों के दृष्टिकोण को धोखा दे रहा है।

सामाजिक और राजनीतिक ताकतें अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डाल देती हैं, बहिष्कार एवं प्रतिरोध के माध्यम से उन्हें 'सबसे निचली जाति' के रूप में मानती हैं जिससे दुश्मनी और संभावित प्रतिशोध का माहौल पैदा होता है। सत्य, अहिंसा और वैश्विक एकता पर जोर देने वाले गांधी के सत्याग्रह के दर्शन ने दुनिया भर के आंदोलनों को प्रेरित किया लेकिन संकीर्ण लाभ के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने वालों से भारत को खतरा है। गांधी की 156वीं जयंती पर भारत को नफ़रत को अस्वीकार करना चाहिए, अंतरधार्मिक संवाद को अपनाना चाहिए और अलगाव को दूर करने तथा शांतिपूर्ण भविष्य को सुरक्षित करने के लिए न्याय को बनाए रखना चाहिए।

(लेखक महात्मा गांधी द्वारा 1920 में स्थापित गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कुलपति हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

चिंतन

पुतिन ने ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़क दिया

अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनाने की कोशिशों में जुटा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद ऐसे फैसले ले रहे हैं, जिससे भारत के हितों को सीधा नुकसान हो। पहले अमेरिका जाने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद एचबी-1 वीजा नियमों को दुश्वर कर सीधे-सीधे भारत को प्रभावित करने का ही प्रयास था। इसके अलावा दवाओं पर टैरिफ और फिल्मों पर टैक्स लगाने के पीछे भी भारत को नुकसान पहुंचाने का ही इरादा नजर आता है, लेकिन भारत ने ट्रंप प्रशासन के हर कदम पर संतुलित टिप्पणी की। अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तब तक भारत पर लगे टैरिफ वापस नहीं होंगे। अब ट्रंप के इन कदमों का जवाब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत झुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे, जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए, तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। पुतिन केवल यही तक नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि रूस भारत और चीन जैसे देशों का आभारी है जिन्होंने ब्रिक्स की स्थापना की। ये ऐसे देश हैं जो किसी का पक्ष नहीं लेते और सच में ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, जहां सबको न्याय मिले। पुतिन का यह कथन भारत का समर्थन करने वाला तो है, साथ ही अमेरिका और ट्रंप प्रशासन को खीजाने वाला भी है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर शांति का नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। ट्रंप के पिछले कई बयानों से साफ नजर आ रहा है कि वह नोबेल प्राइज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग भी पुतिन इसलिए शांत कराना चाहते हैं कि इसका क्रेडिट लेकर वह नोबेल पुरस्कार के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सकें, लेकिन पुतिन ट्रंप की किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन से जंग पुतिन अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इसके लिए राजी नहीं है। उधर इजराइल-फिलीस्तीन जंग रुकवाने पर हमास भी उनकी शर्तें मानने को तैयार होता नजर नहीं आ रहा। यहां भी उन्हें जोर का झटका लगता नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने तो उनका नाम नोबेल के लिए प्रस्तावित किया है, ये दोनों युद्ध उनके सपने को चूर-चूर करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में पुतिन के कड़वे कथन जले पर नमक छिड़कने जैसे हैं। इससे ट्रंप कुछ और कदम उठा सकते हैं, जैसे यूरोपीय देशों पर इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि वे भी भारत पर टैरिफ लगाएं। इसके पीछे ट्रंप ये वजह बता सकते हैं कि रूस अब खुलकर भारत का समर्थन कर रहा है। पहले ही नाटो चीफ भारत के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। वैसे भी वो यूरोपियन देशों को पत्र लिखकर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आग्राह कर चुके हैं। अब भारत को भी वो साथ लपेट सकते हैं। हां, पुतिन ने एक बात बिलकुल सही कही कि अमेरिका भारत जैसे देशों पर रूसी ऊर्जा न खरीदने का दबाव डालता है, जबकि खुद यूरेनियम के लिए रूस पर निर्भर है। अमेरिका ने इसका जवाब ही नहीं दिया। अब जबकि पुतिन ने कहा है तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि अमेरिका हर काम केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है। इसके अलावा कुछ नहीं।

सलाह

डॉ. मोनिका शर्मा

मैट्रिमोनियल साइट्स पर सजगता आवश्यक

हाल ही में बिलासपुर में एक उनतीस वर्षीय इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना वैवाहिक रिश्ते जोड़ने वाली साइट्स पर सतर्कता बरतने की चेतावनी देती है। आत्महत्या करने वाले युवा के पास मिले सुसाइड नोट में लिखा था कि उसे प्यार में धोखा मिला। झूठे दुष्कर्म के मामले ने उसके जीवन को बिखेर दिया। ध्यातव्य है कि मैट्रिमोनियल साइट शादी डॉट कॉम के जरिए दिल्ली की एक युवती से पहचान के बाद दोनों में करीबी रिश्ता बना था। नजदीकियां बढ़ने के बाद अचानक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाकर केस दर्ज करा दिया था। दुष्कर्म के मामले में युवक को जेल जाना पड़ा। जमानत पर छूटने के बाद से ही वह गहरे तनाव में था। परिचितों के अनुसार जमानत के बाद से ही मिलनसार और सहज व्यक्तित्व वाले इस युवा को मानसिक रूप से बेहद परेशान, उदास और अकेलेपन के घेरे में देखा।

ऐसे में सम्बन्धों के जुड़ने या टूटने के दौर में मानसिक उलझनों के घेरे से लेकर झूठे आरोपों के जाल तक, यह मामला सतर्क रहने की बात लिए है। वस्तुतः, मैट्रिमोनियल साइट्स पर धोखाधड़ी, शोषण और झूठी पहचान के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी ठगी का शिकार बनती हैं। बीते दिनों पुणे में पच्चीस वर्षीय महिला डॉक्टर ने भी शादी का झूठा वादा करने वाले व्यक्ति के झांसे में आकर आत्महत्या की थी। ज्ञात हो कि पहले से शादीशुदा आरोपी ने जीवनसाथी डॉट कॉम पर खुद को अविवाहित बताकर अपनी प्रोफाइल बनाई और महिला के साथ संबंध बनाए। साथ ही झूठे झांसे में लेकर उससे 10 लाख रुपये भी ऐंठ लिए। मैट्रिमोनियल साइट्स पर युवतियों के साथ झूठी पहचान बताकर शोषण और पुरुषों के साथ ठगी एवं झूठे मामले दर्ज करवाने के वाकये इन साइट्स पर होने वाली जालसाजी को स्पष्ट रूप से सामने रखते हैं। कई लोग तो छल-कपट कर शादी तक कर लेते हैं। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि मैट्रिमोनियल साइट पर जानबूझकर वैवाहिक स्थिति को गलत तरीके से पेश करना शादी को रद्द करने का एक वैध आधार है। इस मामले में एक महिला की याचिका में कहा गया था कि पति ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर 'कभी विवाहित नहीं' बताकर न केवल अपने पहले विवाह की बात छिपाई बल्कि अपनी कमाई भी बढ़ा-चढ़ाकर बताकर धोखाधड़ी की। विवाह को रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी की मैरिटल हिस्ट्री को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करना कोई मामूली चूक नहीं है, बल्कि विवाह की जड़ तक पहुंचने वाले तथ्यों को स्पष्ट रूप से छिपाना है।' बीते कुछ वर्षों में बिखरती सामाजिक-पारिवारिक व्यवस्था के चलते बड़ी संख्या में लोग मैट्रिमोनियल साइट्स के माध्यम से जीवनसाथी की तलाश करने लगे हैं। परिचित सगे-संबंधियों से अलग ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप रूपी वैवाहिक साइट्स पर अनजाने चेहरों के लिए सच छिपाना आसान होता है। इसी के चलते वर्चुअल संसार में झूठी घोषणाएं कर ख़ूब जालसाजी की जाती हैं। इतना ही नहीं, बहुत से मैट्रिमोनियल साइट्स डेटिंग एप्स भर बनकर रह गए हैं।

कई युवक-युवतियां इरादतन दूसरों को गुमराह करने के लिए ही अपनी प्रोफाइल बनाते हैं। विवाह जैसे संवेदनशील मामले में भावनात्मक मोर्चे पर भी लोगों के साथ खूब फरेब किया जाता है। कुछ समय पहले पुणे की एक उच्च शिक्षित युवती से शादी के नाम पर 3.16 करोड़ रुपये की ठगी की गई। मैट्रिमोनियल साइट पर पहचान होने के बाद आरोपी ने खुद को विदेश की नामी कंपनी का सीईओ बताया और व्हाट्सएप कॉल्स के माध्यम से नजदीकियां बढ़ाईं। युवती द्वारा शादी का फैसला किए जाने के बाद भरोसे का फायदा उठाकर बीमारी और कर्ज चुकाने के नाम पर रुपए ऐंठने की यह जालसाजी की। असल में वैवाहिक संबंध जोड़ने वाले हर प्लेटफॉर्म पर जीवनसाथी ढूंढते हुए सजग रहना बेहद आवश्यक है।

इन वर्चुअल मंचों पर मौजूद हर प्रोफाइल विश्वसनीय नहीं होती। आरोप-प्रत्यारोप के खेल से बचने के युवक-युवतियां अपने परिजनों को भी मैट्रिमोनियल साइट्स पर किसी के साथ हो रही बातचीत की जानकरी दें। इतना ही नहीं, बात आगे बढ़ने पर व्यक्तिगत रूप मिलने के दौरान भी अपनों का साथ आवश्यक है। वैवाहिक सम्बन्धों के मामले में स्वजनों का साथ न केवल सुरक्षा, संबल और सही सलाह के लिए बल्कि किसी तरह की जालसाजी से बचने के लिए भी जरूरी है।

(लेखिका प्रसिद्ध स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आर्थिकी

दिनेश शर्मा 'दिनेश'

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी 'शटडाउन'

अमेरिका शटडाउन से गुजर रहा है, जिससे विश्वभर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आमतौर पर शटडाउन राजनीतिक गतिरोध या बजट विवाद के कारण होता है और इसका प्रभाव न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है, बल्कि आम जनता और व्यापार पर भी देखने को मिलता है। शटडाउन की स्थिति अमेरिका में बार-बार आती है, क्योंकि वहां का संघीय बजट पूरी तरह से कांग्रेस के अनुमोदन पर निर्भर करता है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब अमेरिका का शटडाउन केवल उसकी आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है।

अमेरिका शटडाउन से गुजर रहा है, जिससे विश्वभर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल, शटडाउन वह स्थिति है जब सरकार अपने खर्चों के लिए आवश्यक बजट पास नहीं कर पाती और उसके कई विभाग तथा सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी जाती हैं। इस दौरान केवल जरूरी सेवाएं जैसे सुरक्षा, आपातकालीन अस्पताल, और सेना चालू रहती हैं, जबकि गैर-जरूरी सरकारी कार्यालय और योजनाएं बंद हो जाती हैं। सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के छुट्टी पर चले जाते हैं और जनता को भी कई सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलता। आमतौर पर शटडाउन राजनीतिक गतिरोध या बजट विवाद के कारण होता है और इसका प्रभाव न केवल देश की आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है, बल्कि आम जनता और व्यापार पर भी देखने को मिलता है। दुनिया में ऐसा अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हुआ है। ये अलग बात है कि शटडाउन की स्थिति अमेरिका में बार-बार आती है, क्योंकि वहां का संघीय बजट पूरी तरह से कांग्रेस के अनुमोदन पर निर्भर करता है। अन्य देशों में ऐसी स्थिति कम होती है या इसे वित्तीय गतिरोध का नाम दिया जाता है।

अमेरिका में शटडाउन का इतिहास काफी लंबा है। पहली बार 1980 में यह स्थिति बनी थी और उसके बाद से कई बार सरकारें बंद होने के कगार पर पहुंची या वास्तविक रूप से ठप हुई हैं। वर्ष 1995-96 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और रिपब्लिकन पार्टी के बीच टकराव इतना गहरा गया कि 21 दिनों तक सरकारी कामकाज प्रभावित रहा। यह उस समय तक का सबसे लंबा शटडाउन था, जिसने अमेरिकी जनता को झकझोर दिया। इसके बाद 2013 में बराक ओबामा के कार्यकाल में स्वास्थ्य बीमा योजना 'ओबामाकेयर' को लेकर विवाद हुआ और 16 दिनों तक सरकारी तालेबंदी चली। फिर 2018-19 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विपक्ष के बीच मैक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के लिए फंडिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि सरकार 35 दिनों तक बंद रही। यह अब तक का सबसे लंबा और सबसे महंगा शटडाउन साबित हुआ, जिससे न केवल अमेरिकी कर्मचारियों की जेब खाली हुई, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी हिल गई थी। शटडाउन केवल बजट का संकट नहीं है, बल्कि अमेरिकी राजनीति की खींचतान और समझौते की विफलता का प्रतीक है। 2018-19 के शटडाउन में आठ लाख से अधिक कर्मचारियों पर सीधा असर पड़ा था। इस बार अमेरिका में संघीय सरकार का शटडाउन 1 अक्टूबर, 2025 को सुबह 12:01 बजे शुरू हुआ। यह शटडाउन कांग्रेस में बजट को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जारी गतिरोध के कारण हुआ। रिपब्लिकन ने स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी में कटौती और विदेशी सहायता में कमी की योजना बनाई थी, जबकि डेमोक्रेट्स ने इन प्रस्तावों का विरोध किया। इस राजनीतिक असहमति के कारण सरकार का बजट पास नहीं हो सका, जिससे शटडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप लगभग 800,000 संघीय कर्मचारी अस्थायी रूप से छुट्टी पर भेजे गए, जबकि 700,000 से अधिक कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह शटडाउन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति सप्ताह $7 से $15 बिलियन का

नुकसान पहुंचा सकता है, जिसमें जीडीपी में 0.1% की गिरावट और 43,000 अतिरिक्त बेरोजगार शामिल हैं। यदि यह शटडाउन लंबा चलता है, तो यह उपभोक्ता खर्च, निवेशक विश्वास और नीति निर्माण पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। इस तरह के शटडाउन का असर केवल अमेरिकी समाज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। सबसे पहले तो वहां के कर्मचारी और आम लोग प्रभावित होते हैं, जहां लाखों परिवारों का मासिक बजट डगमगा जाता है। कई छोटे व्यवसाय, जो सरकारी अनुबंधों पर निर्भर हैं, दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और नागरिक सुविधाएं ठप हो जाती हैं। शिक्षा और अनुसंधान जैसे क्षेत्र बुरी तरह बाधित होते हैं, नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के मिशन स्थगित हो जाते हैं तथा पासपोर्ट और वीज़ा सेवाएं रुकने से विदेश यात्रा पर असर पड़ता है। जैसे-जैसे शटडाउन लंबा चलता है, अमेरिका की जीडीपी पर नकारात्मक असर बढ़ने लगता है। अमेरिकी कांग्रेस की बजट ऑफिस के आंकड़े बताते हैं कि 2019 के शटडाउन में ही देश को लगभग 11 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था। विदेशी निवेशक असमंजस में रहते हैं और वॉल स्ट्रीट में गिरावट या उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर शटडाउन तीन सप्ताह से अधिक चलता है, तो यह तिमाही जीडीपी वृद्धि दर को आधा प्रतिशत तक घटा सकता है, लेकिन यह प्रभाव केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और आयात-निर्यात का प्रमुख केंद्र है। वहां का संकट वैश्विक बाजार को झकझोर देता है। जब अमेरिकी शेयर बाजार नीचे जाता है, तो उसकी गूंज यूरोप और एशिया तक सुनाई देती है। डॉलर की अस्थिरता अन्य मुद्राओं को भी प्रभावित करती है। तेल के दामों पर असर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विकासशील देशों में आईटी, निर्यात और सेवा क्षेत्र अमेरिका पर निर्भर रहते हैं। भारत की आईटी कंपनियां, जो अमेरिकी अनुबंधों पर आधारित हैं, भुगतान और परियोजनाओं में देरी से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा, वीज़ा और इमिग्रेशन सेवाओं के ठप होने से छात्रों और पेशेवरों को परेशानी झेलनी पड़ती है। विदेशी निवेश की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। भारत जैसे देश के लिए यह स्थिति इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि यहां का बड़ा आईटी उद्योग अमेरिकी कंपनियों से जुड़ा हुआ है। जब अमेरिका में शटडाउन होता है, तो सरकारी अनुबंधों पर काम करने वाली भारतीय कंपनियों को भुगतान मिलने में देर होती है। यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था भी परोक्ष रूप से इस संकट से प्रभावित होती है। जब अमेरिका आंतरिक संकट में उलझता है, तो उसकी वैश्विक सक्रियता घट जाती है। शटडाउन से बचने के उपायों पर लगातार चर्चा होती रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका को अपनी बजट प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए और अस्थायी फंडिंग के बेहतर इंतजाम करने चाहिए, ताकि गैर-जरूरी सेवाएं भी रुकें नहीं। इस पूरे परिदृश्य से यही संदेश मिलता है कि शटडाउन अमेरिकी लोकतंत्र का वह चेहरा है, जहां राजनीति और प्रशासन आमने-सामने आ जाते हैं और जनता के हित पीछे छूट जाते हैं। अस्थायी समझौते निकल भी जाएं, लेकिन समस्या की जड़ तब तक बनी रहती है, जब तक कि राजनीतिक इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होगी। अमेरिका वैश्विक नेतृत्व करता है, इसलिए वहां का संकट दुनिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को प्रभावित करता है। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब अमेरिका का शटडाउन केवल उसकी आंतरिक समस्या नहीं, बल्कि वैश्विक चिंता का विषय बन जाता है।

(लेखक शिक्षाविद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है

संकलित

दर्शन

साधक दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के साधक का स्वभाव बंदर के बच्चे की तरह होता है, दूसरे प्रकार के साधक का स्वभाव बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े हुए उससे लिपटा रहता है, पर बिल्ली का बच्चा स्वयं मां को नहीं पकड़ता, मां उसे जहां छोड़ दे, वहीं पड़ा रहता है। बंदर का बच्चा स्वयं अपनी मां को पकड़े रहता है, इसलिए अगर कभी उसका हाथ छूट जाए तो वह गिर पड़ता है और उसे चोट पहुंचती है। पर बिल्ली के बच्चे को यह भय नहीं है, क्योंकि उसे उसकी मां स्वयं पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी प्रकार, ज्ञानयोगी या कर्मयोगी साधक बंदर के बच्चे की तरह स्वयं के प्रयत्न से मुक्तिलाभ करने का प्रयास करता है, परंतु भक्त साधक ईश्वर को ही एकमात्र कर्ता जानकर बिल्ली के बच्चे की तरह उन्हीं के चरणों में निर्भय होकर निश्चित पड़ा रहता है। ज्ञानी कहता है सोहम्। मैं ही वह शुद्ध आत्मा हूं। परंतु भक्त कहता है, अहा, यह सब उनकी ही महिमा है। यह सब कुछ मैं हूं, यह सब कुछ तुम हो, तुम स्वामी हो, मैं सेवक-इन तीन भावों में से किसी भी एक में दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित होने पर ही भगवत्प्राप्ति होती है। शिव के अंश से जन्म होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। उसका मन सदा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, इसी बोध की ओर जाता है। विष्णु के अंश से जन्म हो तो प्रेम-भक्ति होती है। उसके मन से प्रेम-भक्ति कभी नहीं जाती।

मृत्यु के बाद के साथी

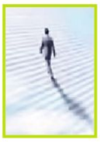

संकलित

प्रेरणा

एक व्यक्ति के तीन घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने जीवन भर उसका साथ निभाया। जब वह मरने की अवस्था के निकट पहुँचा तो अपने मित्रों को पास बुलाकर बोला- अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है। मृत्यु के बाद भी क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला- मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया। लेकिन अब मैं बेबस हूँ। इससे आगे अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। दूसरा मित्र बोला- मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन तुम्हारा हर परिस्थिति में साथ दिया है। तुम्हारे जाने के बाद, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि तुम्हारी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यथावत संपन्न हो। तीसरा मित्र बोला- मित्र! तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूँगा, तुम जहाँ भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मनुष्य के ये तीन घनिष्ट मित्र हैं- धन, परिवार एवं कर्म। इन तीनों में से मनुष्य के कर्म ही मृत्यु के बाद भी उसका साथ निभाते हैं। धन समय को साथ यहां छूट जाता है। उसे मनुष्य मृत्यु के बाद अपने साथ नहीं ले जा सकता। यही स्थिति परिवार की होती है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी नहीं जाता। सिर्फ इस संसार में किए गए अच्छे कर्म ही मृत्यु के उपरान्त उसके साथ जाते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

महात्मा गांधी जी के आदर्श

राजनेताओं और अन्य लोगों ने विभिन्न तरीकों से गांधी जयंती मनाई और दूसरों को नसीहत देते हुए कहा कि हमें गांधी की शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। लेकिन इनमें से ही कई राजनेता और अन्य लोग गांधी जी की राह पर नहीं चलते होंगे। महात्मा गांधी सभी पंथों का सम्मान करते थे, तभी तो कहते थे कि 'ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।' उन्होंने हर धर्म, जाति को आपस में जोड़ने का काम किया था। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने राष्ट्रवाद पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवादी होना गर्व की बात है। उनके अनुसार राष्ट्रवादी हमेशा जात, धर्म और नस्ली भेदभाव से ऊपर की सोच रखता है। हमारे देश में बुराइयों की मुख्य वजह हमारा स्वार्थ भी है। - प्रकाश पटेल, धमतरी

करंट अफेयर

लंदन में गांधीजी की विरूपित प्रतिमा फिर से हुई पूर्व जैसी

लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के चबूतरे को कुछ दिन पहले नुकसान पहुंचाये जाने के बाद, गुरुवार को गांधी जयंती पर वार्षिक समारोह के आयोजन से ठीक पहले फिर से पूर्व जैसा कर दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने कहा कि प्रतिमा को विरूपित करने के बाद स्थानीय समुदाय का एकजुट होना, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के समय एक प्रेरणादायक संदेश का प्रतीक है। इस घटना की सूचना रविवार शाम मेट्रोपोलिटन पुलिस को दी गई थी। दोरईस्वामी के साथ, 50 वर्ष पहले इस प्रतिमा की स्थापना में सहयोग करने वाले 'इंडिया लीग' के सदस्य तथा स्थानीय

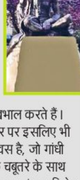

कैमडेन काउंसिल के मेयर भी थे जो इस स्मारक की देखभाल करते हैं। दोरईस्वामी ने कहा, ''यह कार्यक्रम आज होना खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बृहस्पतिवार को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, जो गांधी जयंती भी है। साथ ही, कुछ दिन पहले प्रतिमा और उसके चबूतरे के साथ जो कुछ किया गया, वह भी इसका कारण है।'' उन्होंने कहा, /"यह विशेष रूप से दुखद है, क्योंकि यह प्रतिमा इस स्थान पर 50 वर्षों से अधिक समय से है और यह भारत-ब्रिटेन मैत्री का हिस्सा रही है।/"

ऑफ बीट

हमें युवाओं को एआई युग में देखना सिखाना होगा

बच्चे शब्दों को दृश्यों के साथ जोड़ना, अमूर्त अवधारणाओं को व्यक्त करना, और यह पहचानना सीखते हैं कि विभिन्न स्थितियों में चित्र, प्रतीक और डिज़ाइन कैसे

अर्थ रखते हैं। लेकिन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के संकेतों के आधार पर सामग्री बनाता है। जेनरेटिव एआई अब इन मूलभूत कौशलों को नया रूप दे रहा है। एआई लोगों के टेक्स्ट और चित्र दोनों को बनाने, संपादित करने और प्रस्तुत करने के तरीके को बदल रहा है। दूसरे शब्दों में, यह हमारे देखने के तरीके को बदलता है - और यह भी कि हम कैसे तय करते हैं कि क्या वास्तविक है। उदाहरण के लिए, तस्वीरों को पहले वास्तविकता का "दर्पण" माना जाता था। अब अधिक से अधिक लोग इन्हें एक "निर्मित" यथार्थ के रूप में देख रहे हैं। इसी तरह, जनरेटिव एआई ने छवियों की प्रामाणिकता को लेकर लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती दी है। ऐसी एआई निर्मित तस्वीरें फोटोरियलिस्टिक लग सकती हैं, लेकिन वे घटनाएँ या वस्तुएँ वास्तव में अस्तित्व में नहीं होतीं। जर्नल ऑफ विज़ुअल लिटरेसी में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने एआई आधारित छवि निर्माण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में आवश्यक प्रमुख साक्षरताओं की पहचान की है — एआई टूल के चयन से लेकर सामग्री निर्माण और परिष्करण तक।

ट्रेंड

स्वदेशी तकनीक

तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या प्रचंड हेलीकॉप्टर- हमारी सेनाओं की ताकत स्वदेशी तकनीक से निरंतर बढ़ रही है। भारत अब रक्षा निर्यात में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज भारत विश्व का उभरता हुआ हथियार सप्लायर बन रहा है।

- राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

मेरी संवेदनाएं

भोपाल, मध्यप्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।

- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

दिल्ली को कूड़े से आज़ादी

'दिल्ली को कूड़े से आज़ादी' अभियान ने हमें यह सिखाया है कि स्वच्छता सिर्फ कचरा हटाने का काम नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी संस्कृति और जिम्मेदारी का हिस्सा है। दिल्ली की यह जागृति ही आगे विकसित भारत का मार्ग बनेगी।

- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

भाजपा सरकार नाकाम

आगरा में मूर्ति विसर्जन जैसे पावन अवसर पर एक बार फिर से सरकारी व्यवस्था की कमी की वजह से कई लोगों को अपनी जान गँवानी पड़ी है। बड़े आयोजनों से इंतज़ाम करने में भाजपा सरकार हमेशा नाकाम क्यों रहती है।

- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

गांधी का अपमान

मानवता का अपमान

लोकप्रिय व्यंग्यात्मक हिंदी फि ल्म ₹लगे रहो मुन्ना भाई में मुन्ना कहता है, गांधी की हर मूर्ति तोड़ दो, उनकी तस्वीरें हटा दो और सड़कों से उनका नाम मिटा दो; अगर तुम उन्हें सम्मान देना चाहते हो, उनके मूल्यों को संजोना चाहते हो, उनके आदर्शों पर जीना चाहते हो। यह बात बेशक एक ऐसे किरदार से आई है जो खुद एक गैंगस्टर था और प्रोफेसर का वेश धारण करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संदेश फिर भी जोरदार और स्पष्ट था, हमें गांधी के मूल्यों की जरूरत है, भले ही आप उन्हें पसंद न करें, क्योंकि अहिंसा, करुणा और सहानुभूति कभी भी चलन से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन दुर्भाग्य से, दुनिया इन मूल्यों से दूर होती जा रही है।

हर साल 2 अक्टूबर को, भारत मोहनदास करमचंद गाँधी, महात्मा के जन्मदिवस को याद करने के लिए रुकता है, जिनके सत्य और अहिंसा के विचारों ने न केवल एक राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम को आकार दिया, बल्कि दुनिया को एक नैतिक दिशा भी प्रदान की। यह कोई संयोग नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है। फिर भी, जैसे-जैसे दुनिया इस अवसर को मनाने की तैयारी कर रही है, लंदन से आई एक खबर एक काली छाया डाल रही है। गांधी जयंती से कुछ ही दिन पहले, टैविस्टॉक स्क्वायर पर स्थित गांधी की कांस्य प्रतिमा–जिसे फ्रेडा ब्रिलियंट ने गढ़ा था और जिसका अनावरण 1968 में हुआ था–को भारत विरोधी विचलित करने वाले भित्तिचित्रों से विकृत पाया गया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने सही ही कहा है कि यह कृत्य केवल तोड़फोड़ नहीं, बल्कि गांधी की विरासत और अहिंसा के मूल विचार पर एक हिंसक हमला है। यह घटना लंदन के एक ऐसे चौराहे पर हुई जिसे शांति पार्क के नाम से जाना जाता है, यह विडंबनापूर्ण और चिंताजनक दोनों है।

गांधी की प्रतिमा का अपमान उन मूल्यों के प्रति सम्मान के क्षरण का प्रतीक है जो कभी मानवता को एक सूत्र में पिरोते थेः सहिष्णुता, करुणा और बिना आक्रामकता के मतभेदों को सुलझाने की क्षमता। गांधी का मानना था कि अहिंसा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। गांधी को मिटाकर, हम शांति की संभावना को ही नष्ट करने का जोखिम उठा रहे हैं। दुख की बात है कि आज हमारे आसपास की दुनिया विपरीत दिशा में जा रही है। यूक्रेन में युद्ध जारी है। गाजा लगातार संघर्ष में जल रहा है। दक्षिण एशिया भी संघर्ष से मुक्त नहीं है। बांग्लादेश और नेपाल में अशांति देखी गई है, जबकि अन्य जगहों पर हिंसक बयानबाजी तेजी से राजनीति का रूप ले रही है।

महाद्वीपों में, आक्रामकता एक नई सामान्य बात बनती जा रही है, जहाँ राष्ट्र एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और लोगों को सुनने के बजाय चिल्लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लंदन में हुई बर्बरता, इस प्रकार, एक व्यापक बीमारी का लक्षण है। यह दशार्ता है कि अब क्रोध कितनी आसानी से सार्वजनिक जीवन में फैल रहा है, असहिष्णुता कैसे अपवित्रीकरण और हिंसा में अभिव्यक्त होती है।

गाँधी का अहिंसा पर जोर कोई भोला-भाला आदर्शवाद नहीं था, बल्कि यह गहरी मान्यता थी कि हिंसा हिंसा को जन्म देती है, और अपने पीछे केवल कड़वाहट ही छोड़ती है। आज उनका सम्मान करना केवल मूर्तियों पर माल्यार्पण करना या भजन गाना नहीं है, बल्कि क्रोध के आगे झुके बिना अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के उनके साहस को आत्मसात करना है। लंदन में क्षतिग्रस्त मूर्ति को जल्द ही उसकी गरिमा वापस दिलाई जाएगी, लेकिन बड़ी चुनौती हमारे सामने है - सार्वजनिक जीवन की गरिमा को बहाल करना, भिन्नता के प्रति सम्मान का पुनर्निर्माण करना, और इस विश्वास को फिर से स्थापित करना कि अगर हम चाहें तो शांति संभव है।

ट्रंप को नोबल पुरस्कार की तलाश

ट्रम्प उन लोगों में सबसे कम दोषी हो सकते हैं जिन्होंने प्रभाव की तलाश में इतिहास के गलियारों में कदम रखा है, और उनकी पुष्टि की प्यास न केवल समझ में आती है, बल्कि अपरिहार्य भी हो जाती है। ट्रम्प की महत्वाकांक्षा, हस्तक्षेप और दुस्साहस निर्विवाद हैं। जैसा कि एक पुर्तगाली कहावत है, सूरज पर भी धब्बे होते हैं, फिर भी वह धरती को गर्म करता है।

नीलांत इलांगमुआ
लेखक, स्तम्भकार हैं।

नेतन्याहू के पूर्व दाहिने हाथ और मोसाद के पूर्व निदेशक योसी कोहेन ने पिछले हफ़्ते प्रकाशित अपने संस्मरण, द स्वॉर्ड ऑफ फ़्रीडम, का अधिकांश भाग डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा में समर्पित किया है, और उन्हें एक ऐसे कट्टर कूटनीतिक व्यवधानकर्ता के रूप में चित्रित किया है जिसके दुस्साहस ने मध्य पूर्व को पूरी तरह से बदल दिया। कोहेन लिखते हैं, राष्ट्रपति के मध्य पूर्व दूत, स्टीव विटकॉफ ने एक दृढ़ और दृढ़ मध्यस्थ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने में जरा भी समय नहीं गंवाया। वे खोखली बातचीत में उलझने या पुराने तर्कों को दोहराने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने गति और फोकस में एक बुनियादी बदलाव का संकेत दिया। वे ट्रंप प्रशासन की विशिष्ट पहचान रही जानबूझकर की गई तेजी और निर्णायकता पर जोर देते हैं। कोहेन पूर्व राष्ट्रपति को एक विलक्षण शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए आगे कहते हैंः सब कुछ राष्ट्रपति ट्रम्प की एक अपरंपरागत शांतिदूत के रूप में विरासत पर आधारित था। वह खुद को साहसी, दूरदर्शी वैश्विक नेताओं की श्रेणी में स्थापित करना चाहते हैं। उनकी विलक्षण, अपरंपरागत सोच ने गाजा के भविष्य पर एक मृतप्राय बहस को नई गति और एक अतिरिक्त आयाम दिया है।

वह ट्रम्प की तुलना उनके पूर्ववर्तियों से करते हैंः राष्ट्रपति ओबामा के साथ संबंध इजराइल के लिए कठिन और चुनौतीपूर्ण थे, और हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन इजराइल के सच्चे मित्र थे, फिर भी इस क्षेत्र में उनकी विरासत अवास्तविक है। राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ काम करने का मेरा अनुभव एक ऐसे व्यक्ति का है जो नेतृत्व और निष्ठा को महत्व देता है, और वह बदले में ऐसा करने के लिए तैयार हैं। कोहेन का मूल्यांकन, भले ही यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगे, नोबेल शांति पुरस्कार के प्रति ट्रम्प के जुनून को उजागर करता है। रूजवेल्ट कक्ष में थियोडोर रूजवेल्ट के 1905 के पदक का प्रदर्शन सजावट से कहीं अधिक हो जाता है; यह एक ताबीज है, एक निरंतर याद दिलाता है कि निर्णायक, साहसी नेतृत्व की वैश्विक मान्यता संभव है। ट्रंप की बार-बार की सार्वजनिक घोषणाएँ एक ऐसे व्यक्ति को उजागर करती हैं जिसके लिए प्रतीकात्मक पुष्टि ऐतिहासिक महत्व की उनकी अवधारणा से अविभाज्य है। उन्होंने खुद को समाधान के वाहक, एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया है जिसकी उपस्थिति संघर्ष को फैलने से रोकती है, और नोबेल पुरस्कार के लिए उनकी महत्वाकांक्षा कम और सत्ता और कुख्याति के एक-दूसरे से जुड़े होने के दावे से ज्यादा है।

फिर भी, उनके द्वारा उद्धृत संघर्षों की एक गंभीर जाँच कहानी को जटिल बना देती है। दक्षिण काकेशस में, ट्रंप प्रशासन ने तथाकथित ₹ट्रंप रूट₹ का प्रस्ताव रखा, जो अजरबैजान को नखचिवन से जोड़ने वाला एक गलियारा है, जिसका उद्देश्य आर्मेनिया और तुर्की के साथ संबंधों को सामान्य बनाना था। हालाँकि, वास्तविकता कठोर हैः अजरबैजान ने 2023 में नागोर्नो-काराबाख पर कब्जा कर लिया, जिससे उसकी बहुसंख्यक अर्मेनियाई आबादी को खदेड़ दिया गया और जातीय सफाए के आरोप लगे। ट्रंप जिसे कूटनीति कहते हैं, वह वास्तव में एक मानवीय आपदा है, जो सुर्खियाँ बटोरने वाले सौदों और स्थायी शांति के बीच के अंतर को उजागर करती है। इसी तरह, कश्मीर में, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच घातक झड़पों के बाद युद्धविराम कराने का दावा किया।

पाकिस्तान ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने उनकी भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया, और जॉन बोल्टन जैसे पर्यवेक्षकों ने अमेरिकी प्रभाव की धारणा पर भारतीय अधिकारियों में व्यापक आक्रोश देखा। यहाँ, ट्रंप का कथन वास्तविकता से ज्यादा धारणा को तरजीह देता है, और उन्हें उन जगहों पर अपरिहार्य बनाता है जहाँ उनकी भागीदारी सीमित थी। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और रवांडा में, ट्रंप संसाधन-समृद्ध किवु क्षेत्र में अमेरिकी निवेश के वादों के जरिए शत्रुता समाप्त करने का श्रेय खुद को देते हैं। फिर भी, संघर्ष का लंबा इतिहास, जिसमें रवांडा समर्थित एम23 विद्रोहियों का हाथ है, समाधान के किसी भी दावे को अनिश्चित बना देता है। दक्षिण पूर्व एशिया में, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच अस्थायी युद्धविराम टैरिफ में कटौती और व्यक्तिगत कूटनीतिक पहल के जरिए कराया गया था, लेकिन छिटपुट झड़पें जारी रही हैं। इन सभी उदाहरणों में, यह पैटर्न स्पष्ट हैः ट्रम्प खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करते हैं, लेकिन परिणाम नाजुक, आकस्मिक और अक्सर प्रतीकात्मक ही रहते हैं। पश्चिम एशियाई संघर्ष इसका और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ट्रम्प अपनी कूटनीतिक कुशलता के प्रमाण के रूप में अब्राहम समझौते का हवाला देते हैं, फिर भी गाजा का जारी मानवीय संकट सार्थक समाधान के दावों को झुठलाता है। शत्रुताएँ समाप्त हो जाती हैं, युद्धविराम विफल हो जाते हैं, और नागरिक अभाव और मृत्यु का सामना करते हैं। यहाँ तक कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध ट्रम्प के कथित हस्तक्षेप भी वास्तविक से ज्यादा दिखावटी हैं; कोई बड़ा सैन्य अभियान नहीं हुआ, फिर भी वे काल्पनिक सटीकता के स्मरणार्थ ओवल ऑफिस में बी-2 बमवर्षकों के मॉडल स्थापित करते हैं।

इसी प्रकार, कोसोवो-सर्बिया और मिस्र-इथियोपिया के संबंध में दावे निर्णायक संघर्ष समाप्ति के बजाय दिखावे की कूटनीति को दशार्ते हैं। समझौते हुए, विवादों का निपटारा हुआ, लेकिन युद्ध न तो वास्तव में लड़े गए और न ही निर्णायक रूप से समाप्त हुए। इसलिए टाले गए या समाप्त हुए ₹सात युद्धों₹ का उनका लेखा-जोखा साहसिक और विवादास्पद दोनों है, एक ऐसी सूची जो निर्विवाद प्रशंसा के बजाय गहन जाँच को आमंत्रित करती है।

इससे जो व्यापक प्रश्न उठता है वह केवल यह नहीं है कि क्या ट्रंप नोबेल के योग्य हैं, बल्कि यह है कि क्या पुरस्कार में स्वयं कोई स्थायी नैतिक अधिकार है। ऐतिहासिक रूप से, इस पुरस्कार का राजनीतिकरण किया गया है, यह ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी नैतिक साख अस्पष्ट होती है। हेनरी किसिंजर, जिन्हें 1973 में पेरिस शांति समझौते के लिए मान्यता प्राप्त हुई, ने बमबारी अभियानों और गुप्त हस्तक्षेपों का निरीक्षण किया, फिर भी वे पुरस्कार विजेता बने रहे। बराक ओबामा को 2009 में यह पुरस्कार, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के एक वर्ष से भी कम समय में प्रदान किया गया, बाद में यूक्रेन, सीरिया और पश्चिम एशिया में संकटों को देखते हुए अपरिपक्व प्रतीत हुआ। अल्फ्रेड नोबेल की रचना योग्यता और प्रतीकवाद के बीच झूलती रही है, अक्सर महत्वाकांक्षा और प्रभाव को मूर्त शांति के समान ही पुरस्कृत करती रही है। इस संदर्भ में, क्या पुरस्कार के लिए ट्रंप की चाहत को महज दिखावा कहकर खारिज किया जा सकता है?

यदि नोबेल ने ऐतिहासिक रूप से नैतिक रूप से विवादास्पद रिकॉर्ड वाले पुरस्कार विजेताओं को अपनाया है, तो नैतिक शुद्धता का मानदंड अक्सर कल्पना से कम कठोर है। लगभग हर प्राप्तकर्ता ने नैतिक रूप से अस्पष्ट आधार पर काम किया है; नेल्सन मंडेला, दलाई लामा और मार्टिन लूथर किंग जूनियर, सभी ने ऐतिहासिक परिस्थितियों में, कभी-कभी अनिच्छा से, समझौते किए। यदि इतिहास पुरस्कार विजेताओं का आकलन अपूर्ण रूप से करता है, और यदि नैतिक समझौता प्रभाव के लिए एक पूवार्पेक्षा है, तो ट्रम्प के मान्यता के अधिकार का प्रश्न सीधा नहीं है। उनके हस्तक्षेप, भले ही ढीठ और चुनिंदा ढंग से किए गए हों, पूर्व में प्रतिष्ठित लोगों के कार्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम दोषपूर्ण हो सकते हैं।

ट्रम्प का प्रयास व्यापक अर्थों में भी शिक्षाप्रद हैः यह दशार्ता है कि मान्यता और शक्ति कैसे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार केवल कार्यों की स्वीकृति के रूप में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक महत्व को प्रस्तुत करने के एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। पुतिन, जेलेंस्की, नेतन्याहू और एशिया भर के नेताओं के साथ ट्रम्प की बैठकों का आयोजन जितना बातचीत से जुड़ा है, उतना ही कथात्मक नियंत्रण से भी जुड़ा है। सात युद्धों में जीत का दावा करके, चाहे वे कितने भी विवादास्पद क्यों न हों, वह वैश्विक मामलों में अपनी अजेय उपस्थिति का दावा करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ प्रभाव सफलता की धारणा से अविभाज्य है, और जहाँ प्रसिद्धि अक्सर उसे हथियाने वालों को मिलती है, ट्रम्प की भूख एक मूलभूत मानवीय सत्य को दशार्ती हैः यदि आप पहचान अर्जित नहीं करते हैं, तो आप उसे तब प्राप्त करते हैं जब सत्ता हाथ में होती है।

सारांशः ट्रम्प और नोबेल शांति पुरस्कार पर बहस नैतिकता, उपलब्धि और विरासत से जुड़ी असहज सच्चाइयों से टकराव को जन्म देती है। यह पुरस्कार कभी भी सद्गुणों का शुद्ध प्रतिबिंब नहीं रहा है; यह महत्वाकांक्षा, विचारधारा और दिखावे का गठजोड़ है। ट्रम्प के हस्तक्षेप, जो निरंतर संघर्ष और मानवीय पीड़ा के विरुद्ध हैं, महत्वाकांक्षा और ठोस प्रभाव के बीच की खाई को उजागर करते हैं। शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल यह उठता हैः यदि प्रत्येक पुरस्कार विजेता ने ऐसे अपराध किए हैं जिन्हें इतिहास क्षमा करता है या अनदेखा करता है, यदि सभ्यता का निर्माण दोषों से उतना ही होता है जितना गुणों से, तो कौन घोषित करेगा कि ट्रम्प गलत हैं? इस दृष्टिकोण से, नोबेल के लिए उनका प्रयास केवल अहंकार नहीं है, बल्कि शक्ति और नैतिक मूल्यांकन के मूल में मौजूद चिरस्थायी अस्पष्टता की मान्यता है। इस तर्क से, ट्रम्प उन लोगों में सबसे कम दोषी हो सकते हैं, जिन्होंने प्रभाव की तलाश में इतिहास के गलियारों में कदम रखा है, और उनकी पुष्टि की प्यास न केवल समझ में आती है, बल्कि अपरिहार्य भी हो जाती है। ट्रम्प की महत्वाकांक्षा, हस्तक्षेप और दुस्साहस निर्विवाद हैं। जैसा कि एक पुर्तगाली कहावत है, सूरज पर भी धब्बे होते हैं, फिर भी वह धरती को गर्म करता है।

प्रौद्योगिकी में नेतृत्व से स्टार्टअप के केंद्र तक

अभूतपूर्व तकनीकों से लेकर कई वैश्विक तकनीकी दिग्गजों, जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, में भारतीय मूल के सीईओ तक, भारत ने दुनिया को उल्लेखनीय नवाचार और नेतृत्व दिया है।

संदेश शारदा
लेखक वाशिंगटन डीसी में निवेशक हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने दुनिया को उल्लेखनीय नवाचार और नेतृत्व दिया है, अभूतपूर्व तकनीकों से लेकर कई वैश्विक तकनीकी दिग्गजों, जैसे कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, में भारतीय मूल के सीईओ तक। देश अब केवल घरेलू खपत के लिए नवाचार नहीं कर रहा है; यह दुनिया के लिए भी नवाचार और समाधान तैयार कर रहा है।

कोविड-19 महामारी के दौरान, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में उभरा, जिसने वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तेजी से विस्तार का प्रदर्शन किया। एक अन्य उदाहरण रक्षा का स्वदेशीकरण और पिछले दशक में रक्षा निर्यात में 31 गुना की प्रभावशाली वृद्धि है। आज, भारतीय रिफाइनरियां दुनिया को रिफाइंड तेल का निर्यात कर रही हैं। भारतीय स्टार्टअप एक दशक पहले केवल 400 से बढ़कर आज 1.3 लाख हो गए हैं, और इनमें से लगभग 50% टियर 2 और टियर 3 शहरों में उभर रहे हैं। आज, गुड़गांव में ड्रोन निर्माण कंपनियाँ हैं, उत्तर प्रदेश चमड़ा निर्यात का केंद्र है और देश भर में सौर ऊर्जा कंपनियाँ तेजी से उभर रही हैं।

सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में भारी निवेश कर रही है, जिसका मुख्य ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), बिग डेटा, ऊर्जा परिवर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनोमिक्स, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, अंतरिक्ष और समुद्री अन्वेषण पर है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलें सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, जो दशार्ती हैं कि सरकार जानती है कि भविष्य किस ओर जा रहा है।

सरकार के मार्गदर्शन में, नवाचार तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले 2024 तक, भारतीय स्टार्टअप्स ने 12 अरब डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है, और इसका लगभग 75 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से आया है। भारत हर साल लगभग 24,000 पीएचडी स्नातक तैयार करता है और इनमें से कई उद्योग की जरूरतों से जुड़े अभूतपूर्व शोध कर रहे हैं। बैंगलोर, मुंबई और नोएडा की कई कंपनियाँ पहले से ही अपने कामकाज में एआई को शामिल कर रही हैं। इन फर्मों में परामर्शदात्री फर्म, वित्तीय फर्मों के लिए काम करने वाली फर्म और रक्षा उपकरण बनाने वाली फर्में शामिल हैं। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, जो दुनिया भर में सेवाओं का निर्यात करती है, भारत दुनिया का अग्रणी स्टार्टअप इकोसिस्टम बनने की राह पर भी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्नातक कौशल विकास कार्यक्रम, युवाओं के लिए इंटर्नशिप और क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर्स में निवेश, ये सभी ऐसे कदम हैं जो भारत को आगे ले जाएंगे और उसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगे। ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर, जब भारत यूरोपीय संघ और जापान सहित दुनिया भर के देशों के साथ प्रमुख व्यापार समझौते कर रहा है, भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र, युवा, तकनीक-प्रेमी आबादी और तेजी से मजबूत होती स्टार्टअप संस्कृति द्वारा संचालित, अमेरिका के विशाल पैमाने और बाजार पहुंच के साथ मिलकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सौहार्द ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान उनके द्विपक्षीय संबंधों की परिभाषित विशेषताओं में से एक था। 2019 में ह्यूस्टन में आयोजित प्रसिद्ध हाउडी मोदी रैली, जहाँ दोनों नेताओं को एक मंच पर देखने के लिए 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, से लेकर 2020 में भारत के अहमदाबाद में आयोजित ₹नमस्ते ट्रंप₹ कार्यक्रम तक, सार्वजनिक रूप से उनकी सौहार्दपूर्ण उपस्थिति साफ दिखाई दी। मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत तालमेल एक मजबूत कूटनीतिक बंधन में तब्दील हो गया, जहाँ दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों और आपसी सम्मान पर जोर दिया।

दोनों नेताओं के बीच की यह मित्रता दोनों देशों के बीच, विशेष रूप से रक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में, गहरे सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक रही है। ट्रंप के प्रति मोदी के गर्मजोशी भरे रवैये ने भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया है, जिससे आतंकवाद-निरोध, क्षेत्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आगे सहयोग की नींव रखी गई है।

दोनों देशों ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार और रक्षा संबंधों को काफी मजबूत किया है, और यह साझेदारी भारत और अमेरिका दोनों के लिए अपार संभावनाएँ रखती है। भारत के लिए, अमेरिका के साथ गहरे आर्थिक संबंध प्रौद्योगिकी, निवेश और बाजारों तक पहुंच बढ़ा सकते हैं, साथ ही अमेरिकी कंपनियों को एक बड़ा और बढ़ता हुआ उपभोक्ता आधार भी प्रदान कर सकते हैं।

रक्षा मोर्चे पर, संयुक्त सैन्य अभ्यास, साझा खुफिया जानकारी और उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियां भारत की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, जबकि अमेरिका को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार होने का लाभ मिलता है।

आप की बात

अमेरिका में आर्थिक संकट

अमेरिका इस समय एक भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। सरकार का शटडाउन जारी है और इसके परिणाम इतने गंभीर हैं कि हर बीतता दिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर करोड़ों डॉलर का बोझ डाल रहा है। द गार्डियन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्टों के मुताबिक, शटडाउन से हर सप्ताह अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद को 7 से 15 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि हर दिन लगभग 8,800 करोड़ रुपये का नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार को बंद करके जीडीपी को घटाना बातचीत का सही तरीका नहीं है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की हठ ने इसे एक राजनीतिक सौदेबाजी का औजार बना दिया है। इसका खामियाजा न सिर्फ संघीय कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि बाजार की मांग, सेवाओं की आपूर्ति और आम नागरिकों की जीवनशैली पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। ईवाई-पार्थेनॉन की रिपोर्ट के अनुसार शटडाउन के चलते हर सप्ताह चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर में 0.1% की गिरावट आएगी। छुट्टी पर गए कर्मचारियों को पिछला वेतन तो मिल जाएगा, आर्थिक झटका नहीं भर पाएगा। लंबे समय तक यह स्थिति बनी रही तो अमेरिकी विकास दर धीमी, बेरोजगारी तेज और उपभोक्ता खर्च बुरी तरह प्रभावित होगा।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

पर्यावरणविदों की राय

इस साल हमारे देश के पर्वतीय प्रदेशों में 100 से भी ज्यादा आपदाएं आई। इसमें प्रमुख रूप से भूस्खलन, बाढ़ एवं बादल फटने जैसी घटनाएं शामिल है। इन हादसों के कारण जन धन की भारी हानि हुई है। पर्वतीय प्रदेशों के लोगों का जीवन साल दर साल असुरक्षित होता जा रहा है। वर्षा का पैटर्न पूरे देश में चेंज हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एवं अनियोजित विकास का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में नित नए निर्माण, बढ़ती बसाहट और पर्यावरण के अनुकूल विकास नहीं होने से आपदाओं का खतरा भविष्य में और भी खतरनाक मोड़ ले सकता है। उत्तराखंड में धार्मिक महत्व के स्थलों पर पर्यटकों की संख्या को सीमित किया जाना चाहिए। इस हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की अवधारणा पर सरकारों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए एवं पर्यावरणविदों एवं वहां की जनता की राय तथा मतानुसार ही नयी परियोजनाओं पर कार्य होना चाहिए ताकी भविष्य में आने वाली आपदाओं को नियंत्रित किया जा सके। पर्वतीय क्षेत्रों में वहां के नेचर के अनुकूल पर्यावरण हितैषी माहौल का निर्माण करने के लिए सरकार को हर संभव कदम उठाना चाहिए।

– **ललित महालकरी**, इंदौर

गांधी के विचारों को अपनाने की जरूरत

महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था जिसे सम्मानपूर्वक राष्ट्र पिता का दर्जा दिया गया गांधी के विचार आज के युग में आदर्श है कि वह वे सत्य और अहिंसा के साथ जीवन को जीने की सलाह देते हैं उनका मानना है व्यक्ति लालच, हिंसा से गलत रास्ते पर चला जाता है जिससे वह जीवन के सकारात्मक विचार एवं लक्ष्य से दूर हो जाए व्यक्ति को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए ईमानदार, अहिंसा, नैतिक व्यवहार, शुद्ध आचरण से परिपूर्ण होना चाहिए जो उनके जीवन को नई दिशा, नए विचार में आगे ले जाकर सफलता की राहों में मिल का पत्थर साबित हो लेकिन कुछ लोग आज ज्यादातर युवा प्रीति है जो देश के भविष्य हैं गलत रास्ते मदिरापान, शराब, धूम्रपान, गांजा -बीड़ी, स्नेक, सुलेशन पीना इत्यादि का शिकार हो गए हैं जो बड़े पैमाने पर युवाओं को बबार्दी की ओर ले जा रहा है, ऐसे युवा सामाजिक पहल से कट जाते हैं उनका नैतिक पतन खत्म हो जाता है वे परिवार और समाज के बारे में जिम्मेदार होने की बजाए समाज को खंडित, अपराध को बढ़ावा देने में भूमिका निभा रहे हैं युवा पीढ़ी देश का भविष्य है किसी के बदौलत समाज की बुनियाद टिकी हुई है , इसे बर्बाद होने से बचने के लिए आवश्यक कदम हर हाल में उठाने की जरूरत है।

– **डीके राय, सोनपुर**, सारण

चौंकाने वाला खुलासा

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में नौ बच्चों की मौत ने चौंकाने वाले खुलासा किया है इसके मुताबिक खांसी की जो सिरप उन्हें बीमार होने के बाद पिलायी गई उसमें व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल एथलीन ग्लाइकाल और डायएथिलीन ग्लाइ काल मिला हुआ था जो गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है।इसकी थोड़ी सी भी मात्रा से किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है ऐसा एक्सपर्ट का कहना है।आश्चर्य तो ये है कि सरकारी डॉक्टर ने इन कफ सिरप कोल्डड्रिफ और नेक्सा डीएस को पर्ची पर लिखा था।सिर्फ ठंडक और मिठास की वजह से केमिकल को दवा में मिलाया जाता है जिससे ये ज्यादा बिक सके और निमार्ताओं का मुनाफा बढ़े।ये दोनों केमिकल बैन है फिर भी इनका उपयोग किया जा रहा है। वस्तुस्थिति क्या है इसकी रिपोर्ट आने पर पता चलेगा लेकिन जान से खिलवाड़ करने वालों पर कानूनी कारवाई होना चाहिए।

– **भगवानदास छारिया**, सोमानी नगर, इंदौर

पाठकगण अपने विचार **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 4 अक्टूबर, 2025

दैनिक जागरण

परिवर्तन के अनुसार ढलने से ही जीवन सुगम बनता है

कोलंबिया में राहुल गांधी

राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती पर यह कहा कि भारत में लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इस बार उन्होंने कोलंबिया में लोकतंत्र पर कथित हमलों को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। वैसे तो राहुल गांधी एक अर्से से भारतीय लोकतंत्र को खतरे में पड़ा हुआ देख रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वे इस खतरे को कुछ ज्यादा ही तूल दे रहे हैं। वे इसके पहले भी अपनी विदेश यात्राओं में भारतीय लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भय का भूत खड़ा कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है और बड़े लोकतांत्रिक देश इसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं। इधर उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा भी लोकतंत्र के लिए खतरे के तौर पर ही उछाला हुआ है, लेकिन इस मुद्दे की हवा निकलती दिख रही है। बिहार में मतदाता सूची का अंतिम मसौदा जारी हुए कई दिन बीत गए हैं, लेकिन वोट चोरी का दावा करने वाले ऐसे लोगों को सामने नहीं ला पा रहे हैं, जो बिहार के नागरिक हों और जिनका नाम वोटर लिस्ट से सभी वैध दस्तावेज होते हुए भी कट गया हो। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी तब तक भारतीय लोकतंत्र को खतरे में पाएंगे, जब तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में नहीं आ जाती। क्या लोकतंत्र के सुरक्षित होने की गारंटी यही है कि दल विशेष यानी कांग्रेस लगातार चुनाव जीते और वह देश पर शासन भी करे? क्या देश पर शासन करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है? यदि राहुल गांधी यह समझ रहे हैं कि किसी मिथ्या आरोप को दोहराते रहने से वह सच की शक्ल ले लेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है, भले ही वे दुनिया भर में घूम-घूम कर अपने आरोप दोहराते रहें।

राहुल गांधी की समस्या केवल यह नहीं है कि वे निराधार आरोपों को तूल देते हैं और फिर उन पर टिके रहने की सामर्थ्य भी नहीं जुटा पाते, बल्कि यह भी है कि उनकी ओर से कई बार ऐसी गूढ़ या फिर पहेलीनुमा बातें कर दी जाती हैं, जिन्हें न तो समझा जा सकता है और न ही किसी को समझाया जा सकता है। कई बार तो उनके साथियों के लिए भी उनकी बातों का मतलब बता पाना कठिन होता है। उन्होंने कोलंबिया में इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच कार और मोटरसाइकिल के इंजन के भार में अंतर को लेकर जो विचित्र एवं अबूझ व्याख्या प्रस्तुत की, वह यदि हास-परिहास का विषय बनी तो इसके लिए वे किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। अपने आरोपों पर कायम न रह पाने और रह-रह कर अबूझ बातें करने के कारण ही राहुल गांधी की छवि परिपक्व नेता की नहीं बन पा रही है। यदि इससे किसी को सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए तो कांग्रेस को। इसलिए और भी, क्योंकि राहुल गांधी ही अघोषित रूप से उसका संचालन कर रहे हैं।

निशाने पर युवा

तस्करी के नेटवर्क से युवाओं का जुड़ना निस्संदेह चिंता का विषय है। अमृतसर में हाल में पुलिस ने तस्करी के नेटवर्क से जुड़े कुछ लोगों को 12 पिस्तौल और डेढ़ किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। चिंताजनक यह है कि गिरफ्तार युवकों में एक नाबालिग है और अन्य की आयु भी महज 18 से 22 वर्ष के मध्य है। इससे तो यही संकेत मिलता है कि तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, खासकर पाकिस्तान से जुड़े गिरोह पंजाब के युवाओं को अपने षड्यंत्र के लिए तस्करी के दलदल में धकेल रहे हैं। बेरोजगारी, सामाजिक दबाव और नशे की लत के कारण युवा भी इनके जाल में फंसकर अपने ही देश के विरुद्ध गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। इन युवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों के साथ ही घातक हथियारों की तस्करी भी करवाई जा रही है। यह न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी छिन्न-भिन्न करने वाला है। इसे रोकने के लिए समाज और खासकर परिवारों को जागृत होना होगा। बच्चों की गतिविधियों पर माता-पिता को सतर्क निगरानी रखनी होगी। स्कूलों और कालेजों में नशा विरोधी अभियान भी चलाने की आवश्यकता है। साथ ही युवाओं को रोजगार, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, तभी उन्हें मार्ग से भटकने से रोका जा सकता है।

युवाओं के माध्यम से नशीले पदार्थों एवं घातक हथियारों की तस्करी करवाई जा रही है। यह कानून-व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है

बिगड़ैल पड़ोसी को काबू में करना होगा

ए. सूर्यप्रकाश

पाकिस्तान की पूरी ऊर्जा केवल भारतीयों के प्रति जहर उगलने में खर्च हो रही है

इस साल अप्रैल में पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में मजहब पूछकर 26 गैर-मुस्लिमों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। पूरा देश इस घटना से शोक और आक्रोश में डूबा हुआ था, जबकि अधिकांश पाकिस्तानी इस बर्बर कृत्य की सराहना में लगे हुए थे। असल में अधिकांश पाकिस्तानी हिंदुओं के प्रति कुंठा और नफरत से भरे हुए हैं। चूंकि उनका वजूद ही नफरत पर टिका हुआ है, इसलिए वे इस भाव से बाहर निकल पाने में असमर्थ हैं। उनकी अशिष्ट भाषा भी उनकी अशिक्षा और हताशा को ही दर्शाती है। पढ़े-लिखे टेलीविजन एंकर, सैन्य जनरल से लेकर क्रिकेटर तक भी इसी नफरती आग के शिकार हैं। इस निर्लज्ज व्यवहार का ताजा नमूना बीते दिनों तब देखने को मिला, जब भारतीय टी-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने एक टीवी कार्यक्रम में अपमानजनक शब्द कहे। इस पर एंकर या अन्य प्रतिभागी भी उन्हें टोकने के बजाय खुद भी बेशर्मी से हंसने लगे। यह पाकिस्तान के चरित्र को दर्शाता है कि यह देश पूरी तरह अमानवीय है और उसकी ऊर्जा केवल भारतीयों के प्रति जहर उगलने में खर्च हो रही है।

एशिया कप में तीन बार भारत के हाथों मुंह की खाकर तिलमिलाने वाले पाकिस्तान का दामन अतीत से ही दागदार रहा है। खुद की अलग पहचान को मुद्दा बनाकर भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान निर्माण से भी यह तबका संतुष्ट नहीं हुआ। अपने अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान का ध्यान अपनी तरक्की पर कम, भारत को नुकसान पहुंचाने पर अधिक रहा है। वह भारत से बदला लेने के लिए इतना जुनून से भरा है कि अपने लोगों के भी निर्ममतापूर्वक दमन से बाज नहीं आता। इसका उदाहरण पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में देखने को मिल रहा है। वहां लोग बगावत की राह पर हैं। भारत को पाकिस्तान के बिगड़ते हालात से सतर्क रहना होगा।

पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितना भी जहर उगले, उसे भारत के खिलाफ लड़ी सभी लड़ाइयों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। 1965 के युद्ध में हारने के बाद वह हाजी पीर पास वापस करने के लिए गिड़गिड़ाया। फिर 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सेना का सबसे बड़ा और शर्मनाक आत्मसमर्पण था। शिमला में समझौते की मेज पर भुट्टो ने इन सैनिकों और कुछ अन्य इलाके वापस करने की भीख मांगी।

अवधेश राजपूत

1999 के कारगिल संघर्ष में घुसपैठ के उसके मंसूबों पर भारतीय सैनिकों ने पानी फेर दिया। पाकिस्तान की अमानवीयता उस समय भी उजागर हुई थी, जब उस संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों के शव तक स्वीकार करने से उसने इन्कार कर दिया था। इस मामले में 2025 की कहानी भी अलग नहीं, जब पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने तय कर लिया कि अब बहुत हो चुका है और पाकिस्तान को उसकी करतूत की कीमत भुगतनी ही होगी। आपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में स्थित लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। फिर भारतीय वायु सेना ने नूर खान एयर बेस सहित कई पाकिस्तानी एयर बेस और एयर स्ट्रिप्स को भी नष्ट किया। पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो गई कि उसने युद्धविराम की गुहार लगाई। यह बात अलग है कि उसकी धमकियों और ढोंग का सिलसिला आज तक जारी है।

पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने बेशर्मी से दावा किया कि इसे भारत के अपने लोगों ने ही अंजाम दिया और इसमें पाकिस्तानियों का कोई हाथ नहीं। पहले आतंकी हमला करना और फिर उससे पल्ला झाड़ना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। मुंबई हमले के बाद भी पाकिस्तान उसके पीछे अपनी भूमिका से कन्नी काटता रहा, पर अजमल कसाब के जिंदा पकड़े जाने से उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले ही जनरल आसिम मुनीर ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था। जबकि पाकिस्तान के मंत्री हनीफ अब्बासी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि पाकिस्तान के पास भारत को निशाना बनाने के लिए चिह्नित 130 परमाणु वारहेड हैं।

एशिया कप से पहले पाकिस्तान के साथ मैच न खेलकर उसके बहिष्कार की मांग भी उठी थी, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण को देखते हुए भारतीय टीम उसके खिलाफ खेलने उतरी। हालांकि भारतीय टीम ने पहले से तय कर लिया था कि पाकिस्तानियों से कोई संपर्क-शिष्टाचार नहीं रखना है। कप्तान ने टास के दौरान पाकिस्तानी समकक्ष से हाथ नहीं मिलाया। खिलाड़ियों ने भी मैच के बाद विरोधियों से हाथ मिलाने के पारंपरिक शिष्टाचार से किनारा किया। उसके बाद पाकिस्तानियों की बेचैनी देखने को मिली। उन्होंने शिकायती लहजे में हाथ-पैर तो खूब मारे, पर कहीं कोई राहत नहीं मिली। फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी गृहमंत्री और एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों ट्राफी नहीं लेने का फैसला किया। तब नकवी निर्लज्जता दिखाते हुए ट्राफी-पदक लेकर वहां से निकल गए। फाइनल में जीत के बाद जब पीएम मोदी ने यह पोस्ट किया कि 'खेल के मैदान में भी आपरेशन सिंदूर जारी है और परिणाम भी वैसा ही रहा' तो यह साफ हो गया कि यह मामला महज खेल तक सीमित नहीं रहा। इस पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का जवाब भी बहुत कुछ कहता है कि 'जब देश का नेता खुद फ्रंटफुट पर बल्लेबाजी करता है, तो अच्छा लगता है।'

एशिया कप में सहभागिता का निर्णय लेने के बाद उसे जीतना देश के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। खासतौर से पहलगाम हमले के बाद खेल के मैदान में भी उसका बदला चुकाने के लिए पाकिस्तान को कुचलना जरूरी था। इसके बावजूद भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने इस बिगड़ैल पड़ोसी के साथ अपने समीकरणों को नए सिरे से तय करे। उसे केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त नहीं। भारत को 1965 और 1971 जैसी उदारता नहीं दोहरानी चाहिए। तभी हम सीमापार की चुनौतियों से निपट सकेंगे।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

सीट बंटवारे पर टिका महागठबंधन

राजकुमार सिंह

यदि कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर लड़ने की जिद करेगी तो महागठबंधन में मुश्किलें बढ़ेंगी

कार्यसमिति की बैठक के लिए 85 साल बाद बिहार लौटी कांग्रेस के इरादे को लेकर कोई संदेह था भी तो उसे पार्टी महासचिव नासिर हुसैन ने दूर कर दिया। उनका दावा है कि कांग्रेस जल्द ही घोषित होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रचार अभियान का नेतृत्व करेगी। पटना के सदाकत आश्रम में पांच घंटे चली कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्तावों में उठाए गए मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन असल मकसद विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना और महागठबंधन में जीत की संभावनाओं वाली ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए दबाव ही है। कांग्रेस की चुनावी उम्मीदें भी राहुल द्वारा उठाए जा रहे सामाजिक न्याय और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर ही टिकी हैं। बैठक में पारित 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प' कांग्रेस की चुनावी रणनीति का ही संकेत है।

जाति-संप्रदाय में बंटी बिहार की राजनीति में अपना वोट बैंक बनाए या बढ़ाए बिना आगामी चुनाव में बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। लगभग साढ़े तीन दशक पहले मंडल-कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया में ज्यादातर ओबीसी और अल्पसंख्यक लालू यादव के पक्ष में गोलबंद हो गए तो सवर्ण जातियां भाजपा के साथ। दलितों का बड़ा हिस्सा रामविलास पासवान के साथ जुड़ गया। अपनी राजनीतिक संभावनाओं के लिए नीतीश कुमार को अति पिछड़े और महादलित का समीकरण बनाना पड़ा, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक वर्ग भी जुड़ा। इसी प्रक्रिया में लालू यादव के राजद का मुख्य जनाधार यादव-मुस्लिम गठजोड़ तक सिमट गया, जो अब विजयी समीकरण नहीं बनाता। दूसरी ओर, तमाम विस्तार के बावजूद भाजपा ओबीसी और दलित वर्ग में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाई। अल्पसंख्यकों में भी भाजपा की पहुंच पसमांदा वर्ग तक ही सीमित है। इसीलिए दोनों पक्षों को सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार के जदयू की जरूरत पड़ती है, जिसकी ईबीसी, महादलित और अल्पसंख्यक वर्ग में स्वीकार्यता है। अब जब नीतीश कुमार का राजनीतिक जीवन ढलान पर है, कांग्रेस ईबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग

कांग्रेस को पुराने अनुभव से लेनी होगी सीख। फाइल

को आकर्षित कर अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प के 10 सूत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अति पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास को ही लक्षित करते हैं, जिनमें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने से लेकर शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने और सरकारी ठेकों तक में भी 50 प्रतिशत आरक्षण देने जैसे वादे शामिल हैं।

राहुल के आरोपों की सत्यता तो किसी निष्पक्ष जांच से ही पता चल पाएगी, लेकिन कई बार सच से ज्यादा जनधारणा निर्णायक साबित होती है। वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में राहुल ने अभी तक कर्नाटक और महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्रों के उदाहरण दिए हैं। जीत की संभावना के बीच हरियाणा में हार जाने की चर्चा भी वह करते रहे हैं। विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) में लाखों वोट काटे जाने को लेकर उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' बिहार में निकाली। इससे कांग्रेस का खस्ताहाल संगठन सक्रिय हुआ। कार्यसमिति की बैठक के जरिये कांग्रेस ने उस माहौल को बनाए रखते हुए सीट बंटवारे में मजबूत दावेदारी पेश की है। चर्चा है कि कांग्रेस ने 76 विधानसभा सीटों की सूची भी तेजस्वी यादव को इस संदेश के साथ सौंप दी है कि अगर सीट शेयरिंग में विलंब हुआ तो वह 30 सीटों पर प्रचार शुरू कर देगी। राजद बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। फिर भी कांग्रेस उपमुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी को आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में टालमटोल कर रही है।

2020 में हुए विधानसभा चुनाव में राजग और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था। राजग में सबसे शानदार प्रदर्शन भाजपा ने किया था, जबकि जदयू का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन राजद ने किया, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 70 सीटें लड़ने वाली कांग्रेस मात्र 19 सीटें जीत पाई। छोटे-छोटे वाम दलों का प्रदर्शन भी कांग्रेस से बेहतर रहा। ऐसे में बिहार चुनाव में सबसे अहम दोनों गठबंधनों में सीटों का बंटवारा होगा। अतीत का अनुभव बताता है कि भाजपा अपना गठबंधन बेहतर ढंग से संभाल लेती है, पर ऐसा महागठबंधन या आइएनडीआइए के बारे में नहीं कहा जा सकता।

हरियाणा में आप अलग लड़ी तो कांग्रेस एक प्रतिशत से भी कम मतों के अंतर से चुनाव हार गई। प्रतिशोधस्वरूप दिल्ली में कांग्रेस सभी सीटों पर लड़ी। कांग्रेस जीत तो एक भी सीट नहीं पाई, पर आप को सत्ता से बाहर करा दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले महाविकास आघाड़ी ने चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया होता तो वैसी दुर्दशा नहीं होती। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा बिहार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किस तरह हो पाता है। यदि जाति जनगणना और वोट चोरी जैसे मुद्दों से उत्साहित कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ने की जिद करेगी तो महागठबंधन में मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर दबाव की रणनीति तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा न घोषित करने तक आगे बढ़ी, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र से कोई सबक नहीं सीखा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

ईर्ष्या की अग्नि

मनुष्य स्वयं की उन्नति पर हर्ष एवं गर्व का अनुभव करता है। उसे तब भी अच्छा लगता है जब कोई दूसरा उसकी सफलता की चर्चा करता है। उसके परिश्रम और समर्पण को प्रेरणा बताता है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति की सफलता की प्रशंसा होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अच्छाई को प्रोत्साहित करें। उसकी प्रशंसा एवं पुरस्कृत कर उसका मनोबल बढ़ाएं, लेकिन प्रायः ऐसा कम दिखाई देता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या हमें ऐसा करने से रोक लेती है। ईर्ष्या का जन्म ही दूसरे की प्रगति अथवा सफलता पर होने वाली पीड़ा से होता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सफलता पर विचलित होने लगता है, उसे उसकी उन्नति रास नहीं आती तो उसके भीतर ईर्ष्या का प्रस्फुटन होने लगता है। यह ईर्ष्या अग्नि के रूप में उस व्यक्ति के भीतर जलने लगती है। ईर्ष्या की अग्नि अत्यंत भयावह होती है, जो भीतर से हमारी क्षमताओं को भी जलाकर राख कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वयं अपनी उन्नति के द्वार बंद कर लेता है। वह अपनी सामर्थ्य का उपयोग नकारात्मक कार्यों में करने लगता है।

ईर्ष्या से ही घृणा जन्म लेती है, जो हमारे संबंधों को दीमक की तरह चट करने लगती है। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। यह प्रवृत्ति व्यक्ति की अलोकप्रियता का कारण बनती है। हमारे ऋषियों ने हमें समभाव एवं समदृष्टि की प्रेरणा दी है। किसी दूसरे की सफलता को भी यदि हम स्वयं की सफलता मानकर प्रसन्न होने लगें तो ईर्ष्या भाव आसपास भी नहीं फटकेगा। जिस तरह तेजाब त्वचा पर गिरने पर उसे जलाने लगता है, पीड़ा देता है, त्वचा की रंगत खत्म कर देता है, वैसे ही ईर्ष्या भी हमारे व्यक्तित्व की आभा को खत्म कर देती है और हमें भीतर से जलाकर पीड़ा का अनुभव कराती है। हमें ईर्ष्या की अग्नि से बचकर आत्मीयता की सरिता में गोते लगाने चाहिए।

ललित शौर्य

बच्चों को प्यार से सिखाने की जरूरत

सुनीता मिश्रा

अगर छोटे बच्चे से स्कूल में कोई गलती हो जाए तो शिक्षकों को उन्हें शारीरिक दंड देने के बजाय समझाना चाहिए

हाल में पानीपत के एक निजी स्कूल में बच्चों को पीटने के दो अलग-अलग मामले के वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले सात वर्षीय बच्चे के साथ स्कूल बस चालक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने रस्सी से पैर बांधकर खिड़की पर उल्टा लटका कर बच्चे को बेरहमी से पीटा। बच्चे का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया। दूसरे वीडियो में इसी स्कूल की प्रिंसिपल दो छोटे बच्चों को अन्य छात्रों के सामने गाल पर जोर-जोर से थप्पड़ मारते हुए दिख रही है। अनुशासन सिखाने के लिए हिंसा का उपयोग असंवैधानिक है। बच्चों का इस उम्र में गलतियां करना स्वाभाविक है। वे मासूम होते हैं, उन्हें सही गलत की पहचान नहीं होती है। मारने बच्चे स्कूल जाने से डरेंगे। उन्हें मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचेगा।

अगर छोटे बच्चे होमवर्क न करें या फिर स्कूल में उनसे कोई गलती हो जाए तो शिक्षकों को उन्हें शारीरिक दंड देने के बजाय प्यार से समझाना चाहिए। उनके होमवर्क न करने का कारण जानना चाहिए। उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। शारीरिक दंड देने से बच्चों के मानसिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक जिन बच्चों को स्कूल में पीटा जाता है, उन पर दीर्घकालिक असर पड़ते हैं। पिटाई के कारण बच्चे बड़े होने पर शारीरिक और मानसिक बीमारी के शिकार हो जाते हैं। भय की वजह से बच्चे अपने मन की बात माता-पिता के साथ साझा करने से घबराने लगते हैं। स्कूल, घर में पड़ने वाली मार की वजह से बच्चों का आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ताउम्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ बच्चे तो हिंसा को किसी भी गलती की एक स्वीकार्य प्रतिक्रिया समझकर खुद भी इस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर तल्ख टिप्पणी कर चुका है कि स्कूलों में शारीरिक दंड का कोई स्थान नहीं है।

बच्चों को मारना, प्रताड़ित करना या डराकर पढ़ाना पूरी तरह गैरकानूनी और दंडनीय अपराध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें बच्चों की गरिमा और सुरक्षा भी शामिल है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17 शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। इसके तहत किसी भी छात्र को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना देने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षक की लापरवाही या हिंसा के कारण अगर बच्चे की मौत हो जाती है तो बीएनएस की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत 10 वर्ष तक जेल हो सकती है। केंद्र के साथ राज्य सरकारों को सभी स्कूलों में शारीरिक दंड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

(लेखिका सामाजिक मामलों की जानकार हैं)

मेलबाक्स

सुधारों में निरंतरता आवश्यक

'सुधारों से सुनिश्चित होगी सुरक्षा' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में जीएन वाजपेयी ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है कि अब श्रम सुधारों और न्यायिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जाए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और वैश्विक अस्थिरता के दौर में भी स्थायित्व से ओतप्रोत दिख रही है तो इसके पीछे उन सुधारों की बड़ी भूमिका रही है, जो पिछले कुछ समय में किए गए हैं। सुधारों के आधार पर उपजने वाले विश्वास के चलते ही निवेशक अपनी पूंजी लगाने की तत्परता दिखाते हैं। निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद बहुत मजबूत दिख रही है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से लेकर तमाम समीकरण जिस तरह से बदल रहे हैं, उसमें भारत के लिए नई संभावनाएं और अवसर सृजित होते दिख रहे हैं, जिन्हें भुनाने के लिए आवश्यक एवं अपेक्षित कदम उठाने अपरिहार्य हैं। लेखक महोदय ने उचित ही कहा है कि तमाम अनुकूल पहलुओं के बावजूद भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पाई है तो उसके कारण तलाशने के साथ ही उनका निवारण भी करना होगा। इस दिशा में बातें तो काफी समय से हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस प्रगति होती नहीं दिख रही है। इसलिए समय आ गया है कि श्रम सुधारों पर सहमति बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए और न्यायिक सुधारों में भी विलंब न किया जाए। सुधारों की गति एवं प्रकृति में निरंतरता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी सिद्ध होगी। इस दिशा में ध्यान देना होगा।

अमन वर्मा, वीवीआइपी होम्स सोसायटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट

आपदाओं से सबक लेने का समय

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए प्राकृतिक आपदाएं कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2023 की रिपोर्ट ने एक चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट बताती है कि आकस्मिक मौतों में बड़ी हिस्सेदारी अब भी प्राकृतिक आपदाओं और मानव-वन्यजीव संघर्ष की है। यह न केवल जन-जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे प्रशासनिक तंत्र और नीतियों की कमियों को भी उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में प्राकृतिक कारणों से 6,444 मौतें दर्ज की गईं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बिजली गिरने से हुई 2,560, जो कुल मौतों का लगभग 40 प्रतिशत है। हीट स्ट्रोक से 804 और ठंड से 733 लोगों की मौत दर्ज हुई। यह आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन अब प्रत्यक्ष रूप से जीवन के लिए खतरा बन चुका है। कार्यशील आयु वर्ग (30-60 वर्ष) के लोग इनका सबसे बड़ा शिकार हुए हैं जिससे सामाजिक-आर्थिक स्तर पर भी भारी असर पड़ा है। इतना ही नहीं, मानव-वन्यजीव संघर्ष भी गंभीर चिंता का विषय है। केवल सांप के काटने से 10,144 लोगों की मौत हुई, जबकि जंगली जानवरों के हमलों से 1,739 लोगों ने प्राण गंवाए। यह संख्या प्राकृतिक कारणों से हुई मौतों से कहीं अधिक है। स्पष्ट है कि गांवों और कृषि आधारित इलाकों में लोग दोहरी मार झेल रहे हैं एक ओर जलवायु का कहर, दूसरी ओर वन्यजीवों से संघर्ष। इन आंकड़ों का संदेश साफ है जलवायु परिवर्तन और वन्यजीवों से टकराव भारत के लिए गहरी चुनौती बन चुके हैं। पर सवाल यह है कि क्या हमारे उपाय पर्याप्त हैं? पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बातें वर्षों से हो रही हैं, लेकिन हर साल हजारों लोग असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता और प्राथमिक उपचार सुविधाओं की कमी सांप के काटने जैसी घटनाओं को जानलेवा बना देती है। इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी है कि आपदा प्रबंधन तंत्र को स्थानीय स्तर तक मजबूत किया जाए। बिजली और हीट वेव जैसी घटनाओं के लिए त्वरित अलर्ट प्रणाली गांव-गांव तक पहुंचे। वन्यजीव संघर्ष को केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा मानने के बजाय पर्यावरणीय दृष्टि से हल किया जाए। वन क्षेत्रों के चारों ओर सुरक्षित जोन और लोगों को जागरूक करने की योजनाएं तत्काल लागू करनी होंगी।

अमन सिंह गौर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****